राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का नौवां दिवस [संख्या: 04

मंगलवार,

31 जनवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

साइबर क्राइम के दर्ज प्रकरण

67. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में ऑनलाइन धोखाधड़ी व साइबर क्राइम के कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त दर्ज कितने प्रकरणों का पुलिस द्वारा खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने प्रकरणों में एफआर लगाई गई तथा कितने मामलों में चालान पेश किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या-क्या निर्णय लिए गये तथा उनमें से कौन-कौनसे कार्य पूरे कर लिए गये? साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन यूनिट के गठन के पश्चात् उक्त अपराधों में कितनी कमी आयी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के 2427 प्रकरण और साइबर क्राइम के 4,405 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के दर्ज

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रकरणों में 260 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 253 प्रकरणों में चालान व 1,841 प्रकरणों में एफआर पेश की गई तथा साइबर अपराध के दर्ज प्रकरणों में 1,474 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व 1,443 प्रकरणों में चालान व 2,278 प्रकरणों में एफआर पेश की गई है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) साइबर अपराध को रोकने के लिए किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन यूनिट का गठन करने के पश्चात् विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप साइबर अपराधों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिन्दु संख्या-2 में परिशिष्ट-ब पर अंकित कोटा शहर में 129 में से मात्र 8 अपराधी गिरफ्तार होना बताया है तथा 107 में एफआर लगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन ठगी के इन मुक़दमों में क्या टैक्निकली ट्रेंड व्यक्तियों से जांच कराई जाती है अथवा सामान्य पुलिस अधिकारी इन जांचों को करते हैं? प्रदेश में वर्तमान में कितने टैक्निकली क्वालीफाइड इन्वेस्टीगेशन आफिसर हैं? इनकी योग्यता के लिए क्या मापदण्ड हैं? विदेशों में होने वाली ठगी है, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई अथवा कोई कार्रवाई हुई? इसका भी मंत्री जी बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कोई लिमिट है? प्लीज बैठें, ऐसे नहीं। आप कितने क्वेश्चन पूछेंगे? कितने क्वेश्चन पूछेंग? एक, दो, तीन, चार तो हो चुके हैं। आप एक-एक का जवाब आने दो। आप बैठें। फिर आपका जवाब ही नहीं आएगा, आप जो चाह रहे हैं उसका।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि इन प्रकरणों की जांच किससे करवाई जाती है, जांच करवाने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को, जिनको प्रशिक्षण दे दिया गया है, उनके द्वारा जांच करवाई जाती है। यह साधारण पुलिस से जांच नहीं करवाई जाती है। इन्होंने बाकायदा साइबर थाने की व ऑनलाइन दोनों की ट्रेनिंग ली है। दोनों के प्रकरणों की, तो उनसे जांच करवाई जाती है। पहली बात तो यह है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दूसरा, आपने कहा कि मापदण्ड क्या हैं? मापदण्ड तो सीधा-सीधा यही है कि इनकी ट्रेनिंग होती है। अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही उनको पदस्थापित किया जाता है। पदस्थापित करने के बाद ही उनको तफ्तीश दी जाती है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि 107 केसेज में एफआर लगी है। दूसरा, साइबर क्राइम के मामले में कोटा शहर में दर्ज 86 प्रकरणों में से अधिकांश किस प्रकृति के अपराध थे, या टिप्पणी करने पर या जिन लोगों के कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होने के बाद भी इन 86 प्रकरणों में से अधिकांश को आपने जेल भेजा, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में आपने अपराधियों को सज़ा दिलाई? ऐसे कितने प्रकरण हैं जिसमें अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले, 260 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और 333 प्रकरणों में जांच चल रही है। इसी प्रकार साइबर क्राइम के मामलों में 1,474 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 684 प्रकरणों में जांच चल रही है। आपको ध्यान होगा कि 03 नवम्बर, 2022 को यह घोषणा की गई थी कि 32 थाने खोले जाएंगे। 32 थानों में से 18 थाने खोल दिये गये हैं, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। जैसे-जैसे आदमी मिलते जा रहे हैं, विंग मिलती जा रही है, वहां थाने स्थापित किये जा रहे हैं। जहां सवाल इस बात का है कि क्राइम में 135 अधिकारी और कर्मचारी आलरेडी लगाये गये हैं। इन्वेस्टीगेशन यूनिट के पश्चात्, वह अलग है।

अब सवाल यह है, आपने कहा कि एफआर देने के क्या कारण रहे? एफआर देने के मोटे-मोटे चार-पांच कारण होते हैं। सीधी बात यह है कि अदम पता माल मुलजिम आरोपियों के बैंक खाते में दिये गये गलत व उपयोग में लाई गई मोबाइल सिम दूसरे के नाम से जारी होना पाई जाती है तो भी, अदम वकू झूठ, मतलब परिवादी ने जानबूझकर आरोपी के खिलाफ, आरोपी को फंसाने के लिए असत्य प्रकरण दर्ज कराने के कारण, इसके लिए भी एफआर की जाती है। तथ्य की भूल, परिवादी ने आरोपियों के विरुद्ध, जिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया है, वह तथ्य परिवादी की गलत जानकारी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के आधार पर प्राप्त होना पाया गया, उसमें भी एफआर लगा दी जाती है। सिविल नेचर के कई केसेज होते हैं। सिविल नेचर के केसेज होते हैं, उनमें भी एफआर लगा दी जाती है।

आपने यह पूछा कि कोटा ज़िले में, तो मैंने कोटा ज़िले के आंकड़े तो आपको दे दिए, लेकिन आपने यह नहीं पूछा कि कोटा ज़िले का विस्तार से बताया जाए, तो मेरे पास वह इंफोर्मेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिन आंकड़ों को आपने देखा है, ऑनलाइन ठगी का मामला है वह 2,427 हैं। आपने चालान पेश किया है वह 253 हैं, लगभग एक पाइंट समथिंग परसेंट ही आप उसमें चालान पेश करते हैं। बाकी आपकी एफआर लगी है, ¾ से भी ज्यादा एफआर लगी है। धोखाधड़ी में सबसे ज्यादा पैसा इन्वाल्व होता है, लाखों रुपये। क्या आप यह बता सकेंगे कि इस धोखाधड़ी के तीन साल के प्रकरण में कितनी राशि इन्वाल्व थी और उसमें से आपने वापस कितनी रिकवर की? जो आपका चालान आ रहा है वह केवल और केवल एक परसेंट चालान आ रहा है। यह विभाग की सफलता है या असफलता है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चालान उसी में पेश किया जाता है जिसमें तफ्तीश पूरी होने के बाद में मामला दिखता है, मोटी बात यह है। चाहे एक परसेंट हो, दो परसेंट हो या दस परसेंट हो, यह आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है, 2014 से लेकर 2018 तक यही हालत थी, आज भी यही हालत है। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है।

दूसरी बात, आपने कहा कि कितना पैसा आपने वसूल कर लिया, तो यह तो सवाल था नहीं। अगर यह सवाल होता तो मैं इसका भी जवाब दे देता। सवाल से रिलेटेड बात आप पूछेंगे तो जरूर जवाब मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कुल 2,427 हुए और तीन साल हो गए। यह आंकड़े तीन साल के हैं। तीन साल में अगर सरकार एक परसेंट ही चालान कर सके, तो यह विभाग की सफलता है या असफलता है, इतना तो बताओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विभाग लगातार काम कर रहा है। थाने खुलते जा रहे हैं। पकड़े भी जा रहे हैं। जो-जो पकड़े जा रहे हैं और जिन केसेज में नहीं लगता उनमें एफआर भी लगाई जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री का उत्तर नहीं सुनना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चालान भी पेश होता है। आप मुझे एक प्रकरण ऐसा बता दो जिसमें चालान पुटअप होना चाहिए था और चालान पुटअप नहीं किया पुलिस ने, या कोई गलत तफ्तीश कर दी हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चालान पेश करने वाली ऑथोरिटी मैं नहीं हूं, मेरे पास कागज नहीं है जो मैं आपको बता दूं। मैं तो आपसे पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, होम की डिस्कशन में, होम की डिमांड भी आयेगी, उसमें करें डिस्कस।

प्रश्न संख्या 68

अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी नगरपालिका में सफाई शुल्क की वसूली

69. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा की किन-किन नगरपालिकाओं में सफाई शुल्क की वसूली की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका रामगंज मण्डी (कोटा) द्वारा दुकानदारों एवं ठेलेवालों (स्ट्रीट वेंडर) से सफाई शुल्क के नाम से पैसा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो दिनांक 01 जनवरी, 2021 से दिनांक 17 जनवरी, 2023 तक उक्त से कितनी राशि वसूल की गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त वसूल की जा रही राशि के लिए कोई आदेश, निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध रूप से

(श्री मदन दिलावर)

वसूल की जा रही राशि पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, मदन दिलावरजी का प्रश्न है। धारीवाल साहब।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह तो सरकार की कंडिशन है, साहब।

श्री अध्यक्ष: अपनी कंडिशन तो ठीक है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। कोटा जिले की किसी भी नगरपालिका द्वारा सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा सफाई शुल्क वसूल किये जाने बाबत कोई आदेश या निर्देश पृथक् से जारी नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अब उत्तर मिल गया, अब कोई बाकी बचा ही नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो फिर यह तय बाजारी शुल्क क्या है और इसका क्या प्रावधान राजस्थान नगरपालिका एक्ट, 2009 में है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, be relevant to the question. I will not allow it.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): शुल्क से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: उसमें जी नहीं, जी नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह तय बाजारी का बतायें।

श्री अध्यक्ष: तय बाजारी का आपने प्रश्न पूछा है क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने प्रश्न पूछा है न।

श्री अध्यक्ष: यह क्या पूछा है, पढ़ो आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यही है।

श्री अध्यक्ष: जब यह तीनों का जवाब दे चुके हैं तो फिर इसमें क्या पूछ रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह कह रहे हैं कि यह नहीं है, तो फिर यह तय बाजारी क्या है? उसी के नाम पर वसूला जा रहा है। तय बाजारी

(श्री मदन दिलावर)

शुल्क क्या है और क्या इसका प्रावधान राजस्थान नगरपालिका एक्ट, 2009 में है और है तो फिर आप पढ़कर बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नगरपालिका एक्ट, 2009 में जो प्रावधान है वह प्रावधान है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 की उपधारा 4, धारा 339 और 340 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, परिषद्, पालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को रेगुलेट करने के प्रयोजनार्थ जनहित के लिए सरकार के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा उप विधियां (बाईलॉज) बनायी गयीं। बाईलॉज सरकार भी बनाती है और बाईलॉज नगरपालिका भी बनाती है। नगर परिषद् भी बनाती है और नगर निगम भी बनाती है अपने-अपने। जो बाईलॉज बने हुए हैं उनको पढ़कर बता देता हूं मैं आपको। समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने स्थान से उपसृजित नगरीय ठोस अपशिष्ट के उद्गम स्थल पर ही पृथक्-पृथक् सूखा व गीला कचरा उपयुक्त ढक्कनों का कचरा-पात्र में भंडारित करना होगा। दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उसको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध करवायी गयी सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण करना, मासिक शुल्क देकर निस्तारण करना सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों और निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी व कूड़ा-कंकर नहीं फैले। इसको कैरिंग चार्ज कहते हैं। कैरिंग चार्ज उसको कहते हैं कि आपने कचरा डाल दिया और डालने के बाद में नगर निगम ने उस कचरे को उठाकर लैंड-फिल पर डाल दिया। ठीक है, साहब? तो वह जो कैरिंग चार्जेज होगा वह वसूल किया जाता है।

जहां तक सफाई शुल्क का मामला है, प्रोविजन जरूर है लेकिन राजस्थान की किसी भी नगरपालिका में, किसी भी नगर परिषद् में, किसी भी नगर निगम में इस प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जा रहा है लेकिन इस नियम के तहत वहां के चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर को आथोराइज्ड जरूर कर रखा है कि वह चाहे तो लगा सकता है लेकिन लगाया नहीं गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो फिर रामगंज मण्डी नगरपालिका में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मदनजी, एक मिनट, कटारियाजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, शब्दों के जाल में उलझ गये आप और हम सब लोग। सफाई शुल्क नहीं लगता है यह तो स्पष्ट है पर यूजर चार्ज के नाम से जो कचरा आपने गीला और सूखा कहा है उसको लोड करके ले जाने के लिए कई शहरों में इस प्रकार का चार्ज ठेलों पर भी लगा हुआ है, दुकानों पर भी लगा हुआ है और डोर टू डोर कलेक्शन पर भी लगा हुआ है। इनके पूछने का मतलब जहां तक मैं समझता हूं कि उनका मतलब यही है कि प्रत्येक घर से सफाई कर्मचारी यूजर चार्ज का जो पैसा कलेक्ट करता है उसके बारे में है, तो क्या राजस्थान में गीला और सूखा कचरे को ढोने के लिए किसी प्रकार का चार्ज लगा हुआ है? अगर है तो आप बता दीजिए और नहीं है तो वह बता दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको यह निवेदन कर चुका। प्रश्न के खण्ड 1 में ही मैंने इसका जवाब दे दिया कि कोटा जिले में, कोटा जिले में नहीं, यह तो कोटा जिले की थी बात, सॉरी।

दूसरी बात, आपने यह बताया कि साहब, सफाई शुल्क, यूजर चार्ज लिया जा रहा है। यूजर चार्ज सफाई शुल्क को ही कहते हैं। यूजर चार्ज कोई अलग नहीं होता है। सफाई शुल्क को अंग्रेजी में यूजर चार्ज बोलते हैं, एक बात।

दूसरी बात यह है कि इस नियम के तहत यह अधिकार चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर को दे रखा है कि वे चाहे तो अपने यहां पर लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इन्फोर्मेशन नहीं है कि किसी ने कहीं पर भी लगाया हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पूछने का मतलब यही है कि इनके रामगंज मण्डी में यह लोगों से वसूल हो रहा है। उसकी जानकारी ये चाह रहे थे कि हमारे यहां पर रामगंज मण्डी छोटी नगरपालिका है फिर भी प्रत्येक कंज्यूमर से जो यूजर चार्ज के नाम से, सफाई के नाम से या ढोने के नाम से पैसे ले रहा है, उसका उन्होंने हिसाब पूछने का प्रयत्न किया है कि वर्ष में इससे कितना कलेक्शन हो रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इस बात का जवाब दे चुका कि रामगंज मण्डी में कोई

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सफाई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या लिया जा रहा है? सवाल यह है कि किसी ने कचरा डाल दिया तो उस पर जुर्माना किया जाता है, शास्ति की जाती है। शास्ति चीज अलग है, सफाई शुल्क अलग है और कैरिंग चार्जेज अलग है।

जहां तक आपने पूछा है, जुर्माने का प्रावधान है इसमें तो वह जुर्माना लिया जा रहा है। ये उस जुर्माने को गलत समझ रहे हैं कि यह क्या चीज है। यह बाकायदा जुर्माना है, शास्ति है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चन्द्रभानजी, आप तो रामगंज मण्डी जाकर आये हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह शास्ति है, साहब। शास्ति है। लिखा हुआ है बाकायदा, इनको जो नोटिस दिया गया है उसमें शास्ति लिखा हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो लिखा हुआ है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, यही तो वे दर्द बता रहे हैं, और तो कोई बात है नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं-नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना। हो गया आपका। प्लीज, क्वेश्चन की भी लिमिट है, कोई घंटे भर थोड़े ही डिस्कस होगा इसमें?

सोरसन अभयारण्य समिति का गठन

70. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सोरसन अभयारण्य समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब से तथा इसके वर्तमान में क्या-क्या कार्यकलाप हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरक उत्पादक कम्पनी चम्बल फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि. (सीएफसीएल) के निर्माण के समय उक्त क्षेत्र में गोडावण (Birds) बहुतायत में विचरण किया करते थे तथा उनके प्रजनन का यह प्रमुख केन्द्र था? यदि हां, तो दुर्लभतम श्रेणी में

(श्री रामनारायण मीना)

गिने जाने वाले गोडावण को प्रजनन एवं विचरण को नुकसान पहुंचाने वाले उक्त उद्योग की स्थापना क्यों की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। वर्ष 1992 में सोरसन ब्रम्हाणी अभयारण्य विकास समिति (जिला बारां) का गठन किया गया था, जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत 13.03.1992 से पंजीकृत है। उक्त संस्था के वर्तमान कार्यकलाप क्षेत्र में उपस्थित वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्राकृतिक भोजन व पानी की सुविधा सुलभ कराना है। इस हेतु संस्था द्वारा क्षेत्र में जल संरक्षण गतिविधियां, पिंच पीरियड में बाहर से पानी व भोजन उपलब्ध कराना आदि कार्यकलाप किये जाते हैं।

(2) वर्ष 1990 में सोरसन क्षेत्र में गोडावण की संख्या वन्य जीव गणना अनुसार 24 थी जो वर्ष 1993 में 11 तथा 1998 में 01 रह गई। गोडावण की संख्या/प्रजनन तथा विचरण में कमी चम्बल फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड की स्थापना के कारण हुई है, इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि गोडावण हमारा दुर्लभ राज्य पक्षी है, क्या यह सही है कि आम जन की जानकारी के मुताबिक 1990 के पहले 300 इनकी संख्या थी? ज्यों ही यह चम्बल फर्टिलाइजर्स गठित हुआ तो कुछ लाख रुपये देकर उन्होंने सोरसन गोडावण समिति बनायी, उन्होंने कोई कार्यकलाप नहीं किया और इनकी संख्या धीरे-धीरे खतम हो गयी है। आज भी क्या इस उर्वरक कारखाने के बंद होने पर, इनकी तेज लाइटों के बंद होने पर और चिमनी से निकलनी वाली धुआं बंद होने के बाद गोडावण आगे बढ़ सकता है?

नम्बर तीन, क्या इस सोरसन अभयारण्य समिति के कार्यकलाप शून्य होने से और वहां पर जो गलत गतिविधियां चल रही हैं, जिसके लिए सांगोद से आने वाले माननीय विधायक भी संघर्षरत हैं, उनके खतम होने के बाद में गोडावण पक्षी को दुबारा से पुनर्स्थापित किया जा सकेगा?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सोरसन वन क्षेत्र में गोडावण संरक्षण हेतु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार, पर्यावरण वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान के मध्य त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 30.05.2018 को सम्पन्न हुआ था, जिसके

(श्री हेमाराम चौधरी)

अनुसार केन्द्र की स्थापना तथा प्रशासनिक आधारभूत ढांचा निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवायी जानी थी, जो उन्हें वर्ष 2019 में उपलब्ध करवा दी गयी है।

राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के रामदेवरा में कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, जिसमें गोडावण के चूजों का पालन पोषण किया जा रहा है और सोरसन क्षेत्र में गोडावण प्रजनन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान के पत्र क्रमांक 742 दिनांक 07.10.2022 एवं 784 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को पत्र लिख दिया गया है और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा डीपीआर भी तैयार कर ली गयी है किन्तु अभी तक भौतिक रूप से कोई कार्य नहीं करवाया गया है। संभवत: दो वर्ष कोरोना के कारण प्रगति धीमी रही है इसलिए भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को फिर से पत्र लिख देंगे, जिससे कि यहां पर गोडावण के प्रजनन की प्रक्रिया हो सकती है तो करेंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्षजी, वहां पर बहुत सारी गलत गतिविधियां चल रही हैं, इसके लिए विधान सभा के बहुत से माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि वह गतिविधियां बन्द हों, वह बन्द नहीं हो पा रही हैं। वहां तेज प्रकाश, चिमनियों का धुआं और लगातार यूनिट्स की इजाजत दी जा रही है, इसके कारण गोडावण नहीं आ पा रहा है। सारी कहानी मैं जानता हूं। जब तक आप इन गलत गतिविधियों और रासायनिक कारखानों की गन्दी हवा को खतम नहीं करेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ रहे हो या सोल्यूशन दे रहे हो आप?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सोरसन ग्रामीण अभरण्य विकास समिति का गठन सोरसन शिकार निषेध क्षेत्र में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किया गया था, जिसको 13.03.1992 को पंजीबद्ध कर दिया था। इस संस्था के अध्यक्ष जिला कलेक्टर बारां हैं और सदस्य सचिव उप वन संरक्षक हैं। जिला कलेक्टर, बारां को इसकी मीटिंग बुलानी थी, यह बात सही है कि उन्होंने अभी तक मीटिंग नहीं बुलायी। पहले 28.05.2018 को एक बैठक की थी, उसके बाद 30.10.2019 को फिर एक बैठक हुई। उसके बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई इसलिए जिला कलेक्टर, बारां को निर्देशित करेंगे कि वह इसकी बैठक आयोजित करके इस पर आगे की कार्रवाई करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं यह चाहता हूं कि गलत गतिविधियां और उद्योग से कलेक्टर मिला हुआ है या नहीं है, यह सारी जानकारी आप कब तक कर लोगे? अवगत करायें।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): कलेक्टर मिला हुआ है या नहीं, यह तो नहीं पता लेकिन यह बात सही है कि लम्बे अन्तराल के बावजूद भी कलेक्टर ने उसकी मीटिंग नहीं बुलायी है। उस मीटिंग में एमपी, एमएलए, स्थानीय सरपंच और दूसरे भी बहुत सारे सदस्य हैं, उनको बुलाकर आगे की कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति होगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्षजी, उत्तर मिल चुका है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सात वर्ष से यह पद रिक्त है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है क्या? यह प्रश्न काल है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सात वर्षों से यह पद रिक्त है, कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, मान्यवर। उत्तर ही देंगे वह।

श्री बिहारीलाल (नोखा): उत्तर तो आ गया। मैं आपका समय बचाना चाह रहा था हुकम।

श्री अध्यक्ष: उत्तर के लिए ही मंत्री खड़े होते हैं। प्रश्न पूछो।

नोखा में उप पंजीयक का रिक्त पद

71. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नोखा में उप पंजीयक का पद कब से रिक्त है? क्या सरकार उक्त रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): नोखा उप पंजीयक का पद दिनांक 01.10.2015 से रिक्त है। वर्तमान में तहसीलदार नोखा को उप पंजीयक नोखा का चार्ज दिया जाकर कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है।

उप पंजीयक पद हेतु पात्र तहसीलदार उपलब्ध होने पर यथासंभव रिक्त पद पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य समय के लिए पूछ रहे हैं कि कब तक कर देंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी चयन प्रक्रिया हर साल होती है। अभी 2022 में की है। राजस्थान में कुल 113 पद उप पंजीयक के हैं। हमारे पास 130 पात्र कार्मिक आये हैं। धारा 16 सीसी, 17 सीसी तथा ऐसे मापदण्ड हैं जिसके कारण से हमारे पास कुल 83 तहसीलदार ही उपलब्ध हो पाये हैं उस पात्रता में। हमने 13 अपाइन्ट कर दिये। 13 आरएएस बन गये थे। फिर 70 ही रह गये। इसमें से कुछ रिटायर हो गये। अब नयी भर्ती में इन्टरव्यू बाकी रहे हैं। जिस तरीके से 124 नायब तहसीलदारों की हमने ज्वाइनिंग करवायी, 111 के इन्टरव्यू और बाकी हैं, जल्दी ही इस साल की पात्रता बनेगी, उसमें इनके पद को भर दिया जायेगा लेकिन इनका काम बाधित नहीं है। 2013 के 8वें महीने में इनके यहां पद स्वीकृत हुआ। उस समय तहसीलदार अपाइन्ट हुआ था उसके बाद 2015 में वह रिटायर हो गया, तब से ही यह पद खाली चल रहा है। फिर भी इनका काम बाधित नहीं कर रखा है, इनके तहसीलदार को चार्ज दे रखा है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्षजी, 147 रेवेन्यू विलेज हैं, 57 पटवार मण्डल हैं और प्रति माह 900 प्रकरण पंजीबद्ध के लिए आते हैं। नियमानुसार 30 और 40 मिनट में हो जाने चाहिए, सात-सात दिन और दस-दस दिन लगते हैं। किसानों के म्युटेशन और रहन के प्रकरण दर्ज नहीं होते। सात वर्ष से उपयुक्त तहसीलदार नहीं मिला है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए वहां उपयुक्त तहसीलदार लगायें। तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी है, वह नगरपालिका का ई.ओ. भी है, वह अपने तीनों कामों के प्रति न्याय नहीं कर पाता इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उपयुक्त व्यक्ति वहां लगायें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जल्दी भर देंगे। वैसे इसकी पात्रता के लिए 58 साल की उम्र चाहिए। पहले लम्बे टाइम से तहसीलदारों की भर्ती नहीं हुई इसलिए गैप आ गया। अभी बजट में मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, उसके अनुसार भर्तियां हुईं, इन्टरव्यू हुए काफी संख्या में। बहुत जल्दी ही इस पद को भर देंगे। बाकी इनका काम बाधित नहीं है, यह मैं कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: काम बाधित नहीं है। उस आदमी से बाधित हैं। 2015 से

(श्री अध्यक्ष)

वह पद खाली है। भर्ती भी हुई है फिर भी वह पद अभी तक खाली है। इतने लम्बे समय से पद खाली है तो वहां पर प्राथमिकता के आधार पर तहसीलदार लगाने का काम करें, यह उनके मन की इच्छा है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): बिलकुल सर, आपका हुकम माथे है लेकिन कुछ पात्रताएं हैं। सदन में अगर मैं कोई असत्य आश्वासन दे दूंगा तो रिकार्ड में चीज आयेगी। तहसीलदार की उम्र 58 साल होनी चाहिए। इन्होंने भर्ती नहीं की। 58 साल का तहसीलदार आयेगा तब ही तो कर पायेंगे। दो साल का तहसीलदार का अनुभव होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, नियम तो अपन बनाते हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): फिर भी आपका आदेश सिर माथे है, हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: जब अपने को मालूम है कि ऐसा नियम है और तकलीफ आ रही है तो नये नियम बनाकर या रिलैक्सेशन देकर इसका रास्ता निकालें। नियम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बनाते हैं। जैसाकि आपने बताया कि नियम के कारण समस्या आ रही है। भर्ती नहीं हुई है, 58 की एज है। यह प्रेक्टिकल प्रॉब्लम है। जब यह प्रेक्टिकल प्रोब्लम है तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए नियमों में यदि परिवर्तन करना हो तो सरकार को इस बारे में देखना चाहिए।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जरूर, साहब। राठौड़ साहब, आप ताली बजा रहे हो। 16 सीसी, 17 सीसी, एन्टीकरप्शन को भी अलाउ कर देंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने नहीं किया इसीलिए तो इधर बैठे हैं। आप करके जाओ न।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): 2015 में आपने किया नहीं। आपने भर्ती भी एक नहीं की, भर्तियां इस सरकार ने की हैं। आप लांछन ही इसी पर लगा रहे हो। पद भी हमने स्वीकृत किया 2013 के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। बैठो आप आराम से। उस काम को अच्छा करने के लिए नियमों में रिलैक्सेशन करो।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): बिलकुल कर रहे हैं, सर। कर देंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): ....(व्यवधान) नियमों में संशोधन करवा देंगे साहब।

श्री अध्यक्ष: आपका काम बाकी रहेगा। थोड़ा इन्तजार करो। बहुत ज्यादा उत्सुकता से काम नहीं होता है। इस असेम्बली में जो ज्यादा उत्सुक थे वह दुबारा आये नहीं हैं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): चन्द्रभानजी, आप पानी को 'पो' कहते थे मम्पी को, तब राजेन्द्र राठौड़जी हाउस में थे। आप गरिमा रखा करो। राठौड़ साहब बोल रहे हैं तो आपको बैठना चाहिए।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

आर.टी.डी.सी. की होटलों का निजीकरण

72. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा RTDC की मुनाफे वाली कौन-कौनसी होटलों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त होटलों पर RTDC द्वारा नौ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री मुरारी लाल) (1) सरकार द्वारा RTDC की मुनाफे वाली होटलों को निजी क्षेत्र में देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) RTDC की 6 इकाइयों के रिनोवेशन हेतु राशि रुपये 908.76 लाख स्वीकृत किये गये हैं। उक्त कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त RTDC की चार हेरिटेज श्रेणी की इकाइयों के जीर्णोद्धार हेतु राशि रुपये 4 करोड़ स्वीकृत कर राशि रुपये 1.22 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। उक्त इकाइयों का रिनोवेशन कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त इकाइयों की सूची मय स्वीकृत/व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि सरकार ने बजट घोषणा संख्या 212 वर्ष 2021 -22 के क्रम में सात मिडवे के उन्नयन व संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की थी? यदि हां, तो सात मिडवे कौन-कौन से हैं और स्वीकृत बजट राशि का दूसरे स्थान पर खर्च करने के क्या कारण हैं?

(श्री कालीचरण सराफ)

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि ये जो छह इकाइयां हैं, इनके लिए आपने 09 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, 10 करोड़ में सात मिडवे करने थे, वह तो आपने बदल लिया और यह 09 करोड़ स्वीकृत कर दिया, इसके क्या कारण हैं? सर्विसेज और आउटसोर्स पर इनका रिनोवेशन करवाकर आप क्यों देना चाहते हैं? जब आप आउटसोर्स के जरिये देंगे तो निजी कम्पनियों को देंगे या किसको देंगे?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, बजट में जो घोषणा की गई थी, यह सही है कि सात इकाइयों की जगह छह इकाइयों का रिनोवेशन किया जा रहा है। इसमें होटल गणगौर, जयपुर, होटल खादिम, अजमेर, होटल कजरी, उदयपुर, होटल शिखर, माउण्ट आबू, होटल फोरेस्ट लॉज, भरतपुर और होटल टाइगर डेन सरिस्का।

जहां तक इसका आउटसोर्स निजी क्षेत्रों को देने की बात है, जैसे मैंने पहले मना किया था कि निजी क्षेत्रों को देने का कोई विचार नहीं है। केवल आउटसोर्सिंग के लिए उसमें यह कंडिशन लगायी गयी थी कि इनको रिनोवेशन के बाद में आउटसोर्सिंग के लिए, आउटसोर्सिंग का मतलब निजी क्षेत्रों को देने का नहीं होता है, उसमें कुछ कर्मचारी हम हायर कर सकते हैं, मैन पावर ले सकते हैं, केवल उसके लिए लेंगे। हम आपकी तरह नहीं, आपने पूरा का पूरा एयरपोर्ट 400-400 करोड़ लगाकर अडाणी को दे दिया, कोई किसी को दे दिया। ऐसा हम नहीं दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मुझे यह बताओ, साहब, यह बजट घोषणा की थी तब मुख्य मंत्रीजी ने बोला कि RTDC द्वारा संचालित मिडवे यात्रियों में काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें से 6 महत्वपूर्ण मिडवे इकाइयों-पाली, बहरोड़ (अलवर), रतनगढ़ (चूरू), पोकरण (जैसलमेर), फलौदी (जोधपुर), देवगढ़ (राजसमंद) ऐसे 10 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार कर सुचारु संचालन किया जायेगा। इसको बदलकर, क्या कारण था कि आपने यह 6 होटल आउटसोर्सिंग पर देने के लिए रिनोवेशन किया है? यह बताओ आप।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): ऐसा है, चेंज करने के पीछे आपको पता है, जैसे आपने बहरोड़ का नाम लिया है, बहरोड़ में जब से फ्लाई-ओवर बन गया तो वह जो मिडवे है, इस कारण से बंद था, तो उसमें पैसा लगाना बेकार है। ऐसी हमारी 26 यूनिट्स हैं जो बंद हैं और 9 यूनिट्स

(श्री मुरारी लाल)

घाटे में चल रही हैं। उनके ऊपर हमारे संचालक मंडल ने, 90वीं मीटिंग में फैसला होना था कि इन पर विचार किया जायेगा कि इनको हम निजी क्षेत्र में दें या नहीं दें, अभी फैसला नहीं किया है। जिन यूनिट में हमने पैसा लगाया, उनको भी हम प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे हैं। एक को भी निजी क्षेत्र में नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका प्रश्न यह है कि सरकार ने अमुक-अमुक को काम करने के लिए रखा, उसकी जगह बदल दी, उसका कारण पूछ रहे हैं कि क्या कारण है? मुख्य प्रश्न यही है इनका।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): संचालक मण्डल की जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह विचार-विमर्श किया गया था कि यदि अपन इसमें पैसा लगायेंगे तो भी वह यूनिट्स शायद प्रोफिट में नहीं आयेंगी। इस वजह से उस पैसे को चेंज करके अदर यूनिट्स, जिनको हम अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं, उनमें पैसा लगाया जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फिर यह बजट घोषणा क्यों की थी? मुख्य मंत्रीजी बजट घोषणा कर रहे हैं सदन में, इसका मतलब है कि आप सदन को गुमराह करना चाहते हो? यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने उत्तर पढ़ा और समझा है। मुख्य मंत्रीजी अगर हाउस में कोई घोषणा करते हैं, उसको आप और हम सब पास करते हैं और उसको कोई कमेटी जाकर बदल देती है।

दूसरा, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इन्होंने एक परिशिष्ट-अ लगाया है, इस परिशिष्ट-अ को आपने देखा होगा कि यह जो हेरिटेज है, जिसमें होटल लेक पैलेस है अलवर की, 88 लाख रुपया इसके लिए स्वीकृत था 2021-22 के बजट में, केवल 15 हजार रुपया खर्च हुआ। इसी तरह से नाथद्वारा की होटल गोकुल, नाथद्वारा (राजसमंद) में 99 लाख रुपया स्वीकृत है, उसमें से अभी तक इनका खर्चा हुआ 01 लाख 38 हजार। नीचे जो इन्होंने जवाब दिया, केवल एलोकेशन दिया है। प्रश्न यह नहीं था, प्रश्न यह था कि कहां-कहां खर्च किया? एक में तो यह पैसा भी बता रहे हैं और खर्च बता रहे हैं। दूसरे में केवल और केवल अलाटमेंट बता रहे हैं कि यह दिया। इसका मतलब खर्चा कुछ भी नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि जिन इकाइयों की बजट में घोषणा की गयी थी, संचालक मण्डल ने उसका पूरा गहन अध्ययन किया और उसको यह लगा कि इन इकाइयों में पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह जगह बदली गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर तो पूरा सुन लें। उत्तर सुन लें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): यह संचालक मण्डल है और संचालक मण्डल का फैसला था हमारा, इस वजह से उस जगह को चेंज किया गया और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से बाकायदा अनुमति लेकर उन जगहों को चेंज किया गया है।

दूसरा, आपको यह कहना चाहूंगा कि इस वजह से जो खर्चा कम हुआ है, उसका कारण भी यही है कि इस प्रक्रिया में टाइम लग गया, इसलिए खर्चा कम हुआ। आने वाले टाइम में सबका रिनोवेशन करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि फिर बजट घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। मुख्य मंत्रीजी यहां पर घोषणा कर रहे हैं, हम बजट पास कर रहे हैं और संचालक मण्डल मुख्य मंत्रीजी से ऊपर हो गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, कटारिया जी खड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप ही हमको बतायें, मैं यह सोचता हूं यह बजट केवल मुख्य मंत्रीजी का नहीं रहता यह बजट हाउस के अनुमोदन से आगे बढ़ता है। इसका मतलब तो हमारे हाउस के द्वारा किये गये निर्णय का कोई अर्थ नहीं है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और अगर इस प्रकार के जवाब दिये जाते हैं और जिस प्रकार से अधिकारी जवाब बना लाते हैं, अब इसमें तो हमको आप ही बचा सकते हो और तो कोई नहीं बचा सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना से सहमत हूं, पर आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि बजट आने के बाद भी उसमें री-एप्रोप्रिएशन करने का अधिकार सरकार के पास है। इसलिए सरकार ने पहले 6 आइडेंटिफाई किये कि हम खर्च करेंगे, फिर सरकार ने बोर्ड से फैसला करवाकर

(श्री अध्यक्ष)

उसमें चेंज कर दिया, तो मैं समझता हूं यह जरूरी नहीं कि वहां पर खर्च किया जाये। सरकार कोम्पीटेंट है, सरकार पास करने के बाद इन चीजों को बदलती है। आप भी सरकार में रहे हैं। यह सरकार की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप यह थोड़े कह सकते हैं कि जो घोषणा की गयी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता।

मैं समझता हूं कि प्रश्न के उत्तर में आपने जो बात पूछी है, उस रिलेवेंट में जवाब देना चाहिये कि सरकार ने हमारे यह प्रस्ताव लिए थे और हमारे बोर्ड आफ डायरेक्टर ने यह बदले, इसके बाद यह खर्च किया। यह उत्तर ढंग से आता तो मैं समझता हूं कि आपकी क्वेरी में ज्यादा एंग्जाइटी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जो प्रश्न का उत्तर है, उसमें मैं यह मानता हूं कि जहां बजट की घोषणा हो, उस बजट की घोषणा में यदि री-एप्रोप्रिएशन किया गया है तो उत्तर में उस बात को मेंशन किया जाये, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।

मंत्रीगण भविष्य में जो जवाब दें, इस बात का ध्यान रखें कि बजट की सेंक्टिटी खतम हो जाएगी, बजट में यदि हमने कोई चीज की घोषणा की है तो सरकार को पूरा अधिकार है उसमें बदलाव करने का, लेकिन जब हम उत्तर दें तो इस इफेक्ट को हाउस के अंदर लायें। दैट्स आल।

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

बारां में बाढ़ से प्रभावितों को सहायता

73. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में जिला बारां में बाढ़ व जल भराव के कारण कितनी जान-माल का नुकसान हुआ है तथा कितने प्रभावित लोगों को अब तक कितनी सहायता दी गयी? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कुल कितनी सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान हुआ है? क्या बाढ़ से नष्ट हुई सड़कों व पुलिया के जीर्णोद्धार व नव निर्माण का कार्य बजट के अभाव के कारण नहीं हो रहा है?

(3) क्या सरकार जिला बारां में बाढ़ से प्रभावितों को सहायता एवं नष्ट हुई सरकारी सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए कोई आर्थिक पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जिला बारां में विगत 3 वर्षों में बाढ़ और जल भराव के कारण मानव क्षति-24, पशु क्षति-1,945, मकान क्षति (कच्चे/पक्के)-16,016, अन्य क्षति (कपड़ा-बर्तन, शेड)-947 हुई है। 13,431 प्रभावित लोगों को राशि रुपये 6.18 करोड़ की सहायता दी गई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में बाढ़ से 1,408 परिसम्पत्तियों का नुकसान हुआ है। विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

विगत 03 वर्षों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करा दी गई है।

जिला बारां से वर्ष 2021-22 में 162 पुलिया कार्य हेतु 3,195.65 लाख रुपये एवं 2022-23 में 27 पुलिया कार्य हेतु 1,423.00 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलियाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु 60 हजार रुपये प्रति कि.मी. दिये जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रस्तावों में एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स से अधिक राशि की मांग किये जाने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु वर्ष 2020 में राशि रुपये 287.02 लाख, वर्ष 2021 में राशि रुपये 1,125.56 लाख एवं वर्ष 2022 में राशि रुपये 1,631.25 लाख कुल राशि रुपये 3,043.83 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं।

(3) बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता देने एवं क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत का कार्य एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार किये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालये में रखे गये)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि बारां जिले में बाढ़ आती है और परिसम्पत्तियों का नुकसान होता है, पशुधन की हानि होती है और मनुष्य की जान जाती है। इन्होंने बताया है कि 60 हजार रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से सड़कों की मरम्मत के लिए काम दिया जाता है। अब उसमें पुलिया का निर्माण भी होना है और एक किलोमीटर सड़क का निर्माण भी होना है। पूरी की पूरी पुलिया और सड़क जब बह जाती है तो क्या 60 हजार रुपये में

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

पुलिया और सड़क का निर्माण होना सम्भव है? साथ ही, जिस गरीब आदमी का मकान गिरता है, उसको आप सहायता के रूप में 04 हजार रुपये देते हो, तो 04 हजार रुपये में तो एक लोहे की टिन भी नहीं आती है, तो 04 हजार रुपये की जगह ज्यादा पैसा देने का क्या आप विचार रखते हो?

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो आपके नियम हैं, यह नियम कब के बने हैं? इन नियमों में संशोधन करने का अधिकार आपको है क्या? उस गरीब व्यक्ति का जो झोंपड़ा गिरता है, उसको बनाने के लिए हम ज्यादा कितनी सहायता दे सकते हैं और जो परिसम्पत्तियां एक किलोमीटर की जो सड़क बहती है, जिसको PWD 60 लाख रुपये में बनाती है, आप उसको मात्र 60 हजार रुपये में बनाकर जनता को राहत देने का प्रयास करते हैं।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ नोर्म्स चेंज हुए हैं। पहले कच्चे मकान का हमारा था 95 हजार, अब 01 लाख 20 हजार हो गये। झोंपड़े का पहले था 04 हजार, अब 8 हजार रुपये हो गये। एस.डी.आर.एफ. में केन्द्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाये हुए हैं, हम उन्हीं नोर्म्स के आधार पर जो सड़क की मरम्मत है, उसमें हम 60 हजार ही दे सकते हैं। पुलिया में इसीलिए हमने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि 60 हजार से ज्यादा हमारे नोर्म्स से हम दे नहीं सकते।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि 2020 में 482 किलोमीटर की सड़कें बारां जिले में बही, 2021 में 1,208 किलोमीटर की सड़कें बही, 2022 में 3,218 किलोमीटर की सड़कें बही। अब इतनी सड़कें बहने के बाद, इतनी पुलिया बहने के बाद भी आपने एक रुपया भी अभी तक पुलिया के लिए नहीं दिया। वह पुलिया ऐसी की ऐसी ही खड़ी है। वहां पर लोगों का आना-जाना मुश्किल है। बच्चे पैदल नहीं जा सकते हैं, मोटर साइकिल नहीं जा सकती, फोर व्हीलर नहीं जा सकते। वहां के लोगों को उस पुलिया के अभाव में 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या आप आगे इस प्रकार का कोई प्रावधान करना चाहते हैं ताकि उन पुलियाओं की मरम्मत होकर लोगों को मदद मिल सके?

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही इन्होंने प्रश्न संख्या 1 में जवाब दिया कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार पशुपालक लघु एवं सीमान्त कृषक नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सकता।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

मेरे गांव में 2 व्यक्तियों की 45 बकरियां बिजली गिरने से खतम हो गयी थीं, उनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं थी। इनके नियम हैं कि वह लघु एवं सीमान्त कृषक होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास एक बीघा जमीन नहीं है, उसकी 45 बकरियां बिजली गिरने से मर चुकी हैं, उसको आपने 3 साल में एक रुपया नहीं दिया। यह कौनसे नियम हैं? आप क्या उसको सहायता देने की इच्छा रखते हो?

मेरे गांव में पक्का मकान था। चन्द्रकान्ता एमएलए साहब भी वहां बैठने गयी थीं। मकान में रिश्तेदार आये हुए थे। पक्का मकान गिरा, उसके नीचे 3 व्यक्तियों की दबने से मौत हो गयी। मरे हुए व्यक्तियों को तो पैसे मिल गये लेकिन जिस व्यक्ति का मकान गिरा, 4 साल से उसको एक रुपया नहीं मिला। क्या आप नियमों में संशोधन करके लोगों को राहत देने का प्रयास करेंगे?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस मकान में 3 आदमी दबकर खतम हो गये, उसकी मैं जानकारी ले लेता हूं कि उसको क्यों पेमेंट नहीं मिला। जो भी इन्होंने 46 बकरियों की बात कही है, जो कि इस प्रश्न का पार्ट नहीं है, मैं माननीय सदस्य से पूरी जानकारी लेकर के संबंधित कलेक्टर्स से और जो भी पुलिया के नुकसान हुए हैं, उस संबंध में भी हम लोग चिंतन करेंगे, लेकिन जो हमारे नोर्म्स हैं, उसके तहत हम पुलिया में कुछ नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): मंत्री महोदय, आपने प्रश्न का जवाब दिया कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार पशुपालक, लघु सीमान्त कृषक नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया। मेरे जिले में 2 व्यक्तियों की 45 बकरियां मरीं, उनके पास एक बीघा जमीन नहीं है, उनका पूरा परिवार उस पर निर्भर करता है और आप कह रहे हैं कि वह नियमों में नहीं आता है। वह गरीब आदमी कहां जायेगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसमें इन्होंने चार्ट लगाया है, 24 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। 24 में से 13 लोगों को इन्होंने पैसा नहीं दिया और उसके लिए लिख रहे हैं कि आश्रितों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन किया था। मैं यह नहीं समझ पाया कि जब आपने बाकी को एसडीआरएफ में से या सीएमआरएफ से पैसा दे दिया तो इन 13 लोगों के लिए ही इस चिरंजीवी योजना में इसको कवर करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? नंबर एक।

दूसरा यह है कि एसडीआरएफ के नोर्म्स के तहत पशु के लिए सीमान्त और लघु का कोई आधार नहीं है। पशु का अगर आपदा राहत में है तो उसका 02 लाख रुपया जो तय है, वह हरेक को मिलता है। लेकिन इन्होंने 1995 पशुओं की जो डैथ हुई है उसमें से कुछ ही पशुओं को देकर बाकी को छोड़ा है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा एसडीआरएफ में कौनसी जगह लिखा है कि इनको इस कारण से नहीं दिया जाता है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह तो लघु और सीमान्त कृषक ही नहीं हैं। यह डिपार्टमेंट जब उत्तर देता है, तब देखते समय यह सब सवाल उनसे पूछने चाहिए, जो हमें यहां पूछने की जरूरत पड़ रही है।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चिरंजीवी योजना में 05 लाख रुपये हैं। हम 04 लाख रुपये देते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो कटारिया साहब एवं माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, हम इसकी जानकारी करके इनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जानकारी अलग पार्ट है। एसडीआरएफ के नोर्म्स तो अपन बनाते हैं। जब वह कह रहे हैं कि आपने लिखा कि लघु सीमान्त कृषक के अलावा जिसके जमीन नहीं है, उसको जानवरों का कंपनसेशन देंगे ही नहीं। यह तो आपके नोर्म्स बने हुए हैं। इन नोर्म्स को बदलने के लिए क्या सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि ऐसे बहुत से पशुपालक हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, उनकी यदि मौत हो जाती है तो वह किसमें कवर होंगे? एसडीआरएफ के नोर्म्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

एसडीआरएफ के नोर्म्स में इस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं कि जहां उस आदमी की 45 बकरियां मर गयीं, वह उस कैटेगरी में नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। एसडीआरएफ के नोर्म्स हमने किसके लिए बनाये हैं? नोर्म्स जनता को रिलीफ के लिए बनाये हैं। उस नोर्म्स को बदलने के लिए कोई आदमी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता है? कोई रास्ता निकालने में क्या तकलीफ है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया है, हम उसकी पालना करते हुए इसमें संशोधन करेंगे। जिस गरीब की 45 बकरियां मरी हैं, उसको हम लाभ पहुंचायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में किसानों को देय मुआवजा

74. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में विगत चार वर्षों में कितने किसानों की कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने पर मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है व कितनों को दिया जाना शेष है? उक्त के शेष रहने के क्या कारण हैं? उपखण्डवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना (उपखण्ड-असनावर, अकलेरा एवं मनोहर थाना) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से 25 जनवरी 2023 तक की अवधि के दौरान किसानों की कृषि कार्य करते हुए मृत्यु होने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत कुल 150 प्रकरणों में 300.00 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त अवधि में कुल 35 प्रकरण निरस्त किये गये एवं शेष 64 प्रकरण लम्बित हैं। उपखण्डवार लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

उक्त अवधि में उपखण्डवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

1	असनावर	9	3
2	अकलेरा	70	35
3	मनोहर थाना	71	26
	योग	**150**	**64**

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शेष लम्बित जो 64 प्रकरण हैं, इनका निस्तारण कब तक कर देंगे?

दूसरा, कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत मृत्यु प्रकरणों में आवेदन करने की क्या समयावधि होती है? यह भी मुझे बताने का कष्ट करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, जो केस हमारे पेंडिंग हैं वह कुछ डायरेक्टर स्तर पर हैं और कुछ एफएसएल की रिपोर्ट्स के कारण हैं, उनका हम अतिशीघ्र निस्तारण कर देंगे। समय-समय पर आपको अवगत भी कराते रहेंगे।

दूसरा, पेंडिंगों का कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। एप्लाई करने का जरूर टाइम होता है। मंडी स्तर पर 6 माह का टाइम होता है, उसके बाद डायरेक्टर स्तर पर 9 माह का होता है। फिर भी कोई केस डिले हो जाता है तो सरकार के स्तर पर उसका 15 माह का टाइम होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

गंगापुर में खेल स्टेडियम की स्थापना

75. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में सरकार द्वारा कितने स्टेडियम व खेल मैदान बनाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शहर के मध्य में स्थित सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास पर्याप्त भूमि होने के उपरान्त भी वहां पर खेल मैदान व स्टेडियम विकसित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त विद्यालय की रिक्त भूमि पर खेल मैदान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में स्थित एक मात्र खेल स्टेडियम की विभागीय स्वीकृति जारी कर खेल सुविधाओं का विकास किया गया।

(2) सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल गंगापुर सिटी के पास उपलब्ध भूमि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद/युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व में नहीं है एवं इस पर खेल मैदान बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गंगापुर के गांव डिपसा में 21.11.2011 को 8 हैक्टेयर भूमि का खेल मैदान के लिए आबंटन हुआ था, उसका काम

(श्री रामकेश)

आरएसआरडीसी के माध्यम से किया जा रहा था, किन कारणों की वजह से वह काम रोका? उसके बाद में अभी तक वह काम पेंडिंग पड़ा हुआ है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि हमारे शहर के बीचों-बीच सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में भी 7 हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई है क्या सरकार उस पर कोई खेल मैदान विकसित करने की योजना रखती है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में एकमात्र खेल स्टेडियम हेतु 2015-16 की बजट घोषणा में 160 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां जब आरएसआरडीसी से काम की स्वीकृति हुई पहली किस्त एक करोड़ दी, दूसरी किस्त 60 लाख रुपये दी गयी, लेकिन गांव वालों के आब्जेक्शन की वजह से निर्माण नहीं होने दिया। तत्कालीन जिला कलेक्टर, एसडीएम सभी लोगों को यहां से आरएसआरडीसी ने भी चिट्ठी लिखी, खेल विभाग ने भी लिखी। उसी समय कुछ काम 50 लाख रुपये का हुआ। गांव वालों के एतराज की वजह से 16.11.2017 को माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर उस काम को डि-सैंक्शन कर दिया गया। ऐसे कोई 4-5 काम थे। वह काम वहीं ड्राप हो गया। उसका पैसा दूसरी जगह लगाने के लिए प्रस्ताव बन गया। वह काम इस वजह से रुका।

अन्य संसाधनों से जैसे नरेगा है, और कई स्टेडियम बने हैं। खेल विभाग में अभी मुख्य मंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्कीम के अंतर्गत जो घोषणा की उसमें सीएसआर, एमएलए, एमपी फंड या जन सहभागिता से जितनी राशि आप देते हैं, उतनी राशि खेल विभाग देकर स्टेडियम बनायेगा।

आपका दूसरा प्रस्ताव भी हमारे विभाग स्तर पर नहीं है, फिर भी आप हमें मेजर ध्यानचंद योजना में भेजते हैं तो हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे कि बच्चों को खेल सुविधा प्रदान करने की जैसी आपकी मंशा है, वह पूरी की जाएगी।

श्री रामकेश (गंगापुर): मेरा मात्र यह कहना है कि वर्ष 2015-16 में एक करोड़ 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, किस कारण से यह काम रोका? अब सरकार पुन: इसको चालू कराना चाहती है या नहीं? दूसरा है, खेल मैदान के लिए सीनियर हायर सैकंडरी स्कूल में जमीन खाली पड़ी हुई है क्या सरकार का इरादा उसमें खेल मैदान विकसित करने का है या नहीं है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जमीन जो खेल विभाग के नाम है, उस जमीन पर रास्ते का विवाद है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो जमीन स्कूल के नाम है। स्कूल की एनओसी मेजर ध्यानचंद स्कीम में आ जाती है तो हम बना देंगे, अगर उसमें नहीं आती है और आप मुख्य मंत्रीजी को और लिखकर दें तो उसका ध्यान रखवाएंगे, मैं भी सिफारिश करूंगा। जो पुराना स्टेडियम रास्ते के विवाद से, गांव के एतराज की वजह से रुका, उसी समय 2017 में खेल मंत्रीजी के स्तर पर मीटिंग होकर, सारे अधिकारी बैठे, एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी का निर्णय है। मैं उसको पूरा पढ़कर सुना दूं। उस कमेटी में आठ लोग थे, जे.सी. मोहंती, नारायण सिंह, सचिव, वीणा गुप्ता, शैलेंद्र माथुर, मनोज गुप्ता, पंकज गर्ग, तिलवानिया परियोजना अधिकारी, अखिलेश मित्तल, इन 8 लोगों की मंत्रीजी के स्तर पर मीटिंग होकर उसको 16.11.2017 को सैंक्शन कर दिया गया। इसमें पैसा भी दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, अभी पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट में लेकिन फिर भी यदि आप उस स्कीम में आते हो तो हम उसको लगाने को तैयार हैं।

श्री रामकेश (गंगापुर): आपका खेल अधिकारी लिखकर दे रहा है कि कोई रास्ते का विवाद नहीं है। अब यह रास्ते का विवाद बनाकर बीजेपी की सरकार के समय जो पैसा मंजूर हुआ, इनका काम यह था कि मंजूर करो और उसको निरस्त कर दो। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया, आप इसमें क्या करना चाहते हैं? अब कोई विवाद नहीं है, खेल अधिकारी का लिखकर दिया हुआ है। आप उस मैदान को विकसित करना चाहते है या नहीं करना चाहते हैं? जो राशि आपके पास पड़ी हुई है उसको वहां उपयोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? यदि आप नहीं करना चाहते हो तो जो 8 हैक्टेयर जमीन खेल मैदान के लिए आबंटित कराई है, क्या आप उसको वापस निरस्त कराना चाहते हो?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): इसमें जिला कलेक्टर आनन्दी की चिट्ठी भी है कि स्टेडियम शिलान्यास के दौरान ग्रामवासियों ने उन्हें अवगत कराया कि गांव में आने-जाने हेतु मार्ग विकसित किये जाने तक निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामवासियों की समस्या का लैटर है, उस वजह से रोका गया है और वह सैंक्शन खतम हो गई है, नई सैंक्शन का मैं बता रहा हूं कि मेजर ध्यानचंद स्कीम में आप आएं, इसमें पैसा है, हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस स्कीम में आ जाएं तो अच्छा रहेगा। बनाने के लिए मनाही नहीं है लेकिन वो स्वीकृति कैंसिल 2017 में ही हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती गंगा देवी।

इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा (जयपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

76. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जयपुर के इन्दिरा गांधी नगर में वर्ष 2023 में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राजकीय महाविद्यालय के लिए भवन बनाया हुआ है? यदि हां, तो उक्त भवन कितने क्षेत्रफल में किन-किन सुविधाओं के साथ कितनी लागत से बनाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) वर्तमान में इन्दिरा गांधी नगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर 2 में निर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करवाया गया था। उक्त विद्यालय भवन को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर के परिवर्तन/परिवर्धन हेतु मण्डल द्वारा प्रथम मंजिल पर रुपए 30 लाख 23 हजार का अतिरिक्त निर्माण करवाया गया। परिसर का कुल क्षेत्रफल 20,800 वर्ग मीटर है तथा निर्मित क्षेत्रफल 1,322 वर्ग मीटर है। भवन निर्माण पर कुल राशि 01 करोड़ 28 लाख 80 हजार व्यय किये गये है। इस भवन में अक्टूबर, 2013 से अगस्त, 2016 तक विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से संचालित था।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर अग्रिम निर्णय लिया जाएगा।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): अगर मंत्रीजी की मेहर हो जाए तो दो विधान सभा क्षेत्र न वंडे लाभ मिल जाएला, सरकारी बिल्डिंग है, कालेज खोल दें तो, अर उधर जगतपुरा में, इंदिरा गांधी नगर में बढ़ती हुई जनता है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): विधायक महोदया, वहां उस क्षेत्र में अगर विद्यालय में हमारे पास सीनियर स्कूल के स्टूडेंट्स की संख्या देखकर अगर वाजिब होगा तो निश्चित तौर पर वहां खोल दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

श्रम कल्याण की योजना में मजदूरों का पंजीयन

77. **श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रम कल्याण की योजनाओं में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरों का पंजीयन करने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक उक्त योजना के तहत जिला उदयपुर की सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा पंचायत समितियों के अधीन आने वाले राजस्व ग्रामों में कुल कितने मजदूरों का पंजीयन किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पंजीकरण के पश्चात् उक्त पंचायत समितियों के अधीन आने वाले राजस्व ग्रामों में कितने मजदूरों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में पंजीकृत मजदूरों को किस बीमा योजना का लाभ दिया गया है? क्या सरकार उक्त योजना में उक्त की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। दिनांक 01.09.2016 से ही सम्पूर्ण प्रदेश में ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा है एवं श्रमिक स्वयं अथवा निकट के ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीयन हेतु आवेदन कर सकता है। 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में उदयपुर जिले की सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा पंचायत समितियों में हुए पंजीयन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 की अवधि में योजनावार लाभांवितों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मण्डल की निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों द्वारा पीएमजेजेबीवाई अथवा पीएमएसबीवाई हेतु कराये

(राज्य मंत्री, श्रम)

गये बीमा की प्रीमियम राशि का क्रमश: 50 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाता है।

पंजीकृत श्रमिकों की संतानों की उच्च शिक्षा हेतु मण्डल की निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ-साथ मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा पंचायत समिति में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2022 के बीच जब पंजीकृत श्रमिक परिशिष्ट-1 में 12 हजार 104 हैं और आपने दूसरे में दिया है, जो पेमेंट किया है, परिशिष्ट-2 में 12 हजार 331, जब फार्म 12 हजार 104 के हुए तो आपने 12 हजार 331 में कैसे पेमेंट किया, यह बताया जाए। किनके खाते से किया? मंत्रीजी के खाते से किया? यह बताएं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): दिखवा लेंगे, आपको जानकारी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जब प्रश्न आता है तो पूरे सेक्रेटरी लेवल पर, मंत्री लेवल पर स्क्रूटनी होती है। माननीय सदस्य का प्रश्न बिलकुल वाजिब है। आप लिख रहे हैं पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 12 हजार 104 और उत्तर दे रहे हो, 12 हजार 331 को बेनिफिट किया, तो 12 हजार 104 से जो बढ़ गए हैं, उनको किस हैड से मिला, किसने किया, इसकी कोई स्क्रूटनी हो रही है या नहीं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): जानकारी लेकर, गलती है तो उनको नोटिस देकर कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: जानकारी नहीं, (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से सरकार के मंत्री और सारे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि विधान सभा में इस तरह से गैर जिम्मेदारी से प्रश्न का उत्तर आना हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि सदन में जो जवाब आए उस जवाब को मंत्रीगण पूरा स्क्रूटनी करके उसके बाद सदन में जवाब दें अन्यथा सदन की गरिमा खतम हो जाएगी।

(श्री अध्यक्ष)

जिस अधिकारी ने इस सूचना को सही नहीं दिया है, मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मंत्रीजी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

माननीय अमृतलाल जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): हां, कार्रवाई करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) एक मिनट। आप सुन लो मंत्रीजी क्या कह रहे हैं। मंत्रीजी, बताएं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): स्पष्ट नहीं लिखा है, लिखकर दो इस पर क्या है? इस पर लिखवा लो। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप आफिसर गैलरी में बात नहीं कर सकते, यह सदन के नियम हैं। मंत्रीजी आफिसर गैलरी में पुकार कर बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको प्रताड़ित करिये, विधान सभा के सारे नियम और प्रक्रिया तार-तार हो रही है। सीधा आफिसर गैलरी में बात कर रहे हैं मंत्री।

श्री अध्यक्ष: आपके रहते हुए सब दिख रहा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप भी जाते थे गैलरी में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अमृतलाल जी, दूसरा प्रश्न पूछिए। (व्यवधान) कटारियाजी, आप पूछिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपने अपनी भावना प्रकट कर दी। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्नों को देखने के बारे में इनके जो भी सेक्रेटरी होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। फाइल केवल एक मंत्री के द्वारा ही नहीं निकलती है, बाकी नीचे से सब लोगों के द्वारा आती है, तो इतनी बड़ी भूल अगर हो जाए और उसके लिए जो सम्बन्धित सेक्रेटरी है वो इसके लिए लायबल नहीं है? विधान सभा में भेज रहा है तो कम से कम मंत्रीजी के साथ-साथ उनको भी ताड़ना जानी चाहिए कि क्या हो रहा है, यह तमाशा तो नहीं है?

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष जी, एक लेबर को दो या तीन योजनाओं का फायदा दिया जा सकता है। जो सात

(श्री सुखराम विश्नोई)

योजनाएं दी हैं, उसे भविष्य निधि का फायदा दिया जा सकता है, श्रमिक औजार भी दिये जा सकते हैं, उसे प्रसूति सहायता दी जा सकती है। वह संख्या कम और सहायता ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न में आप और प्रोब्लम में आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न जिसमें 1,231 का जो फिगर है, वह भी सही नहीं आएगा। 12 हजार जो आदमी हैं, उनमें से कितने आदमी डबल हुए, कितने दिन आये, उसकी जानकारी आएगी। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं यह एक गम्भीर प्रश्न है और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसे स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष: क्या इसे स्थगित करने से कोई रास्ता निकलेगा? मंत्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप अपने सेक्रेटरी से जानकारी लेकर विधान सभा सेक्रेटेरिएट को इन्फार्म करें कि वस्तुस्थिति क्या है। यह मेरी आपसे अपेक्षा है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): मैं जानकारी लेकर पूरी इत्तला करूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में कान्तिलाल उर्फ कार्तिक भील की हत्या पर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़-बीदासर स्टेट हाईवे स्थित श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, यूं बैठे-बैठे नहीं बोलें। माननीय मंत्री जी, आवाज यहां तक आती है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जब स्पीकर खड़ा होकर बोले तो कम से कम इस बारे में अटेंशन रखें।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा के न्यू

(श्री अध्यक्ष)

मेडिकल चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री समाराम गरासिया, सदस्य एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से सिरोही जिला मुख्यालय में दिनांक 28 जनवरी, 2023 को शहीद स्मारक उद्घाटन के उपरान्त राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरड़ा में वर्षों से निवासरत गाड़ोलिया लोहारों को पट्टे दिलवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में अघोषित विद्युत कटौती से आम उपभोक्ताओं एवं किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में भू-माफिया एवं पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा में अघोषित विद्युत कटौती एवं ट्रिपिंग समस्या से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पुलिस थाना ब्यावर सदर को सीओ, सर्किल मसूदा में शामिल करने से नागरिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्थित वीर हनुमान मन्दिर सामोद का रोप-वे पुनः संचालित करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नव-संचालित वरुण बेवरेजेज लिमिटेड कम्पनी में

(श्री अध्यक्ष)

स्थानीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नागौर पंचायत समिति मूण्डवा के सरपंचों का भुगतान रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नव-संचालित अल्ट्राटैक सीमेंट में स्थानीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य, श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य व उन्नीस अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा फर्जी डिग्री दिये जाने में गिरोहों की लिप्तता से प्रदेश के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से कोटा एवं सूरतगढ़ थर्मल की यूनिटों को बन्द करने के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजस्थान टैक्निकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश परमार द्वारा छात्रा पर फेल करने का भय दिखाकर अवैध सम्बन्ध बनाने के दबाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा विधायकों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा आबंटित अरावली एनक्लेव, मानसरोवर, जयपुर के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अघोषित विद्युत कटौती से विद्यार्थियों एवं किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(20) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के पीपली अहिरान में जल जीवन मिशन योजना की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(21) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा अजमेर शहर में यूजर चार्ज वसूले जाने से व्यापारियों में उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल, श्री अविनाश, श्री रामप्रताप कासनियां एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली में जलदाय विभाग की पाइप लाइनों से जल-रिसाव के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों का प्रभावित परिवारों को समुचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा जारी अफीम डोडा चूरा निस्तारण के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल को उदयपुर सम्भाग से हटाने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से रावणा राजपूत व अन्य पिछड़ा वर्ग को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बनाकर अलग से आरक्षण देने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जैन समुदाय के साधु-साध्वियों के आहार-विहार में उत्पन्न बाधाओं एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु प्रदेश में श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में बढ़ते मेडिकल नशे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में हो रहे अन्धाधुन्ध अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से हनुत्या एवं जयस्थल के मध्य कुरल नदी पर पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज कोटा का नामकरण डा. बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री जगदीश चन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

व्यवस्था का प्रश्न

विधान सभा सदस्यों के त्यागपत्रों का प्रकरण प्रिमेच्योर स्टेज पर न्यायपालिका ले जाने से विधायिका की आहत गरिमा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। राजस्थान विधान सभा के 81 सदस्यों के इस्तीफों का जो प्रकरण है, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने किसी तरह का कोई निर्णय नहीं किया और प्रीमैच्योर स्टेज पर सदन के एक सदस्य के द्वारा राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष की गरिमा को आहत किया गया, राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों को आहत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। विधान सभा अध्यक्ष के निर्णय और सदस्यों के इस्तीफों के बारे में अनेक विधान सभा अध्यक्ष पहले निर्णय दे चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है कि प्रीमैच्योर स्टेज पर किसी भी तरह से विधान सभा से सम्बन्धित प्रकरण को हाई कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन मैंने प्रमुख सचिव के माध्यम से प्रस्ताव लिया हुआ है..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषयवस्तु रख रहे हैं। प्रिविलेज मोशन अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप फैसला कर रहे हैं? यहां मैं खड़ा हुआ हूं। आप क्यों उत्तर दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, यह मेरा काम है, आपका नहीं। आपके कहने से नहीं होगा। क्या मेरा काम भी आप करेंगे? मैं खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) वे इतनी देर से बोले जा रहे हैं। उनकी बात को रिकार्ड पर रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: I am on legs. माननीय सदस्य, आप जीरो आवर के बाद इस बात को उठाएं। जीरो आवर समाप्त हो जाए, उसके बाद उठाएं। उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा।

माननीय गिरधारीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीडूंगरगढ़-बीदासर स्टेट हाईवे स्थित श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कालू बीदासर वाया श्रीडूंगरगढ़ स्टेट हाईवे पर श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले श्रीडूंगरगढ़ में चालीस से अधिक गांव के आमजन पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में स्टेट हाईवे का निर्माण अन्तिम चरण में है और इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा आवागमन होने की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां पर हर 15-20 मिनट बाद सवारी गाड़ी, मालगाड़ी चलती है और एम्बुलेंस, मरीज की गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं तो दुर्घटना में मरीज की मौत होने की भी सम्भावना रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि स्टेट हाईवे पर लगातार जो मांग चल रही है, उसके लिए मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि सरकार केन्द्र को, रेल मंत्रालय को ओवरब्रिज बनाने की इस मांग को आगे भेजे। अध्यक्ष महोदय, यह मांग एक साल से उठ रही है और अभी कड़ाके की सर्दी में 20 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपका और राज्य सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहूंगा कि जो लोग सड़क पर धरने पर बैठे हैं उनकी मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा ओवरब्रिज बनाने के लिए लिखित में रेल मंत्रालय को भेजा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

जैतारण में नव-संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में स्थानीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सीमेंट के तीन बड़े प्लांट पहले से संचालित हैं और चौथा प्लांट अभी नया आया है जो

(श्री अविनाश)

अल्ट्राटेक सीमेंट का बलाड़ा-टूंकड़ा में बनने वाला है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि हम फैक्टरी के खिलाफ नहीं हैं फैक्टरी लगे, लोगों को रोजगार मिले, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन यह जो सरकार है वह इन फैक्टरी संचालकों से अपने दामाद की तरह व्यवहार करती है। उसका कारण यह है कि आज लगभग तीन-चार साल हो गये, पहले जब यह फैक्टरी बनी तो इस फैक्टरी ने एल. एण्ड टी. को फैक्टरी के निर्माण का ठेका दिया था। फैक्टरी का ठेका भी पूरा हुआ और फैक्टरी अब जब शुरू हो रही है, सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है तो हमारी, पूरे जैतारण क्षेत्रवासियों की मांग रही है और मैं पिछले चार सालों से यह डिमांड कर रहा हूं कि हमारे इन प्लांटों के अन्दर स्थानीय व्यक्ति जो हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। यह जो प्लांट लगेगा उसमें मिनरल्स हमारा, पानी हमारा काम में लेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट हमारा काम में लेंगे, पोल्यूशन हमें देंगे, लैण्ड एक्विजिशन हमारी करेंगे तथा और तो और 91 की जमीनों को जिन पर 50-50 साल से ग्रामवासियों का कब्जा था, उन्हें पुलिस से मिलीभगत करके उनसे जबरदस्ती कब्जा छुड़वाया गया तथा जो गरीब लोग थे, गांव वाले थे, उनको बेदखल किया गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो एप्रेंटिस किये हुए लड़के हैं जो योग्यता लिए हुए हैं आईआईटी किये हुए हैं आईटीआई किये हुए हैं डीजल के अन्दर हैं, मैकेनिक के अन्दर हैं और सारी की सारी योग्यता वाले लोग हैं, लेकिन आज भी फैक्टरी ने तय कर रखा है कि 50 किलोमीटर से बाहर के जो लोग होंगे उनको लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश दें कि इन प्लांटों में जो जैतारण क्षेत्र के लोग हैं उनको योग्यता के अनुसार दें, जिनकी जमीन ली उनको प्राथमिकता के आधार पर एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दें, ताकि मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है वह खतम हो जाएगी।

एक निवेदन और करूं कि पूर्व में इन्हीं फैक्टरियों वालों ने पुलिसकर्मियों के साथ में मिलीभगत करके 91 की जमीन से जिस महिला को बेदखल किया था उसने आत्महत्या कर ली है और 134 निर्दोष लोगों के खिलाफ में मुकदमा किया, जिनको हाई कोर्ट से जमानत मिली है, ये ऐसे लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर समय रहते आपने फैक्टरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए पाबन्द नहीं किया तो बहुत जल्दी मैं विधान सभा में आने से तो वंचित रहूंगा लेकिन

(श्री अविनाश)

मैं उन लोगों के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में फैक्टरी का गेट ताला लगाकर बन्द करूंगा और स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के लिए जो मेरी आवाज है, वह रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार के सामने इस बात को रखें और स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के लिए पाबन्द करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, इन्होंने सरकार के लिए दामाद शब्द इस्तेमाल किया है उसको डिलीट करवाओ।

श्री अध्यक्ष: यह काम मेरा है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): डिलीट तो कराओ।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम कुछ लोग वैसे ही कर लेते हैं। श्री रामप्रताप कासनियां।

कोटा एवं सूरतगढ़ थर्मल की यूनिटों को बन्द करने के निर्णय की समीक्षा

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ थर्मल की यूनिटों को बन्द करने के निर्णय की समीक्षा करवाने हेतु एनर्जी असेसमेंट कमेटी (ईएसी) के द्वारा दिनांक 07.01.2022 को कोटा थर्मल की यूनिट 1 से 4, 640 मेगावाट व सूरतगढ़ थर्मल की यूनिट 1 से 5 तक, 1,250 मेगावाट को पुरानी होने के कारण से बन्द करने का निर्णय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके स्थान पर बचे हुए कोयले का उपयोग कर नई सुपर क्रिटिकल यूनिट को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में लेख है कि सूरतगढ़ की सभी यूनिट बहुत अच्छी परफार्मेंस में हैं अच्छी तरह से काम कर रही हैं और इनकी री-शिड्यूल लाइफ का असेसमेंट 2-3 वर्ष पूर्व में करवाया गया था जिसके अनुसार इन यूनिट को आगामी 30 वर्ष से अधिक समय तक काम में लिया जा सकता है तो फिर नई इकाई लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सिर्फ नई इसलिए कि प्रदूषण हो रहा है, जिसके लिए नये इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी की बात है और इससे जनता को कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, राज्य सरकार को लाभ होने वाला नहीं है।

कोटा की चार इकाइयों और सूरतगढ़ की पांच इकाइयों को इस सरकार ने बन्द करने का निर्णय किया है। पूर्व में आप बीजेपी सरकार को कह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रहे थे कि इन यूनिटों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचेगी, पर बेचने की तो कोई बात नहीं हुई, परन्तु आपने 1 से 5 और 1 से 4 कोटा की इकाइयां बन्द करने का जो निर्णय किया है, वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): इसमें राजस्थान का हित नहीं होगा, अहित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर शहर में यूजर चार्ज की वसूली

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 2019 को एक अधिसूचना जारी कर नगर निगम को यूजर चार्ज वसूलने सम्बन्धी निर्देश जारी किये। इस अधिसूचना के अनुसार नगर निगम को साधारण सभा में प्रस्ताव रखकर सदन के सदस्यों द्वारा इसके गुणावगुण पर चर्चा कर इसे लागू किये जाने का प्रावधान है। इस क्रम में निगम में 21.04.2022 को आयोजित साधारण सभा में इसे प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इसमें इसे बिना पारित हुए वहां के आयुक्त ने अपनी हठधर्मिता के कारण व्यापारियों से जबरन वसूलना प्रारम्भ कर दिया जो सदन की अवमानना व शहर की जनता के साथ धोखा है। इसकी लाइव वीडियो रिकार्डिंग इसका प्रमाण है।

आयुक्त जनता से मनमानीपूर्वक वसूलने और नहीं देने वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहां तक कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनवाने या अन्य किसी काम से जो आते हैं, उनसे पहले तीन माह का यूजर चार्ज जमा कराने को कहते हैं और नहीं देने पर प्रमाण पत्र रोक लेते हैं। यूजर चार्ज वसूलने हेतु सफाई कर्मचारियों को भेजकर नोटिस भी थमा रहे हैं और जो जमा नहीं करा रहे हैं, उनके मकान को अवैध बताकर तोड़ने की धमकी तक भी दी जा रही है। इस तरह से जजिया कर लिया जा रहा है। इससे आम जनता और व्यापारियों में रोष है। इस कारण से अजमेर बन्द भी किया जा चुका है तथा जनता व व्यापारी सड़क पर हैं। अभी हाल ही में 12.01.2023 को निगम की साधारण सभा में सर्वसम्मति से इसे नहीं लिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उस पर नोट आफ डिसेंट लगाकर आयुक्त निरस्त करने को तैयार नहीं है और इस हेतु उन्होंने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल आयुक्त को निर्देश दे कि आदेश को निरस्त करे और यह यूजर चार्ज नहीं लिया जाए, जिससे व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता जी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में रखा है वह बहुत ही गम्भीर है। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वे होटल व्यवसायी हैं, चाहे वे बड़े कामर्शियल अपार्टमेंट संचालित करते हैं, चाहे वे 2x2 की दुकान संचालित करते हैं, हर किसी से 250 रुपये फिक्स करके हर महीने यह यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान कमिश्नर द्वारा किया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नगर परिषद् की साधारण सभा में पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सभी माननीय सदस्यों ने एक राय होकर एक साथ इस प्रस्ताव को साधारण सभा में निरस्त किया है। उसके बावजूद अजमेर नगर निगम के कमिश्नर महोदय ने इस पर डिसेंट नोट लगाकर सरकार को भेजा है।

मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि चूंकि अजमेर के सभी दल इस पर सहमत हैं और प्रभारी मंत्री माननीय मालविया जी ने भी इस बात को कहा कि कमिश्नर इसको कैंसिल करे, कलेक्टर इसको कैंसिल करे, पर इसके बावजूद हठधर्मिता की जा रही है। व्यापारियों ने एक दिन पूरा बन्द रखा, एक दिन पूरा अजमेर बन्द सफल रहा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को आग्रह है। माननीय मंत्री महोदय ने सुबह प्रश्न के जवाब में कहा कि हम कहीं पर भी वसूल नहीं कर रहे हैं, हम पूरे राजस्थान में कहीं पर भी यूजर चार्ज नहीं वसूल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बात हो गई। देवनानी जी ने बोल दिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो फिर अजमेर में किस तरह से वसूल रहे हैं? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: 295, जे.पी. चन्देलिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पिलानी में ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु बजट प्रावधान

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन है कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क बहुत कमजोर है तथा आपस में गांवों में आने-जाने के लिए कई गांवों में तो सड़क मार्ग उपलब्ध ही नहीं है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में मैंने अपने पत्र क्रमांक MLA PILANI 2018/2022-23/3785 दिनांक 26.12.2022 से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय तथा अपने पत्र क्रमांक MLA PILANI 2018/2022-23/3786 दिनांक 26.12.2022 से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 41 सड़कों की सूची प्रेषित कर निवेदन किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन 41 सड़कों के 109 किमी के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाये गये एस्टीमेट के अनुसार मात्र 28 करोड़ रुपये का बजट पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृत कर अनुगृहीत करें, ताकि इस विधान सभा क्षेत्र के गांवों में आवागमन सड़क मार्ग से सुगम हो सके और इस क्षेत्र के विकास को गति मिले।

साथ ही, मेरे द्वारा अपने पत्र क्रमांक MLA PILANI 2018/2022-23/3903 दिनांक 11.01.2023 से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरे विधान सभा क्षेत्र की 80 किमी लम्बाई की क्षतिग्रस्त (नोन-पेचेबल) हेतु 1,617.50 लाख रुपये का बजट सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित करने हेतु निवेदन किया था, ताकि इन सड़कों को सही रूप में लाकर इन्हें सुगम आवागमन हेतु तैयार की जा सके तथा इस क्षेत्र का विकास हो सके।

मेरी उपरोक्त गम्भीर समस्याओं के निदान हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि प्राथमिकता से उपरोक्त अंकित सड़क नेटवर्क की गम्भीर समस्याओं के निदान हेतु आगामी बजट वर्ष 2023-24 में प्रावधान कर अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन खां। श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में राजकीय विद्यालयों में रिक्त पद

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295

(श्री जोराराम कुमावत)

के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 63 ग्राम पंचायत व सुमेरपुर तथा तखतगढ़ दो नगरपालिका क्षेत्र हैं। इनमें 82 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 508 प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल I, II, शारीरिक शिक्षक के पद रिक्त हैं। साथ ही, राजकीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शारीरिक शिक्षकों के 112 पद रिक्त हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पोमावा में 2, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, चाणोद में 6, कोसेलाव में 10, सांडेराव में 5 व विवेकानन्द मॉडल स्कूल, सुमेरपुर में 2 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में 137 विद्यालयों में 645 पद रिक्त हैं। ये पद रिक्त होने से विद्यालयों में विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित होता है, रिजल्ट भी प्रभावित हो रहा है। अध्यापकों, विशेषकर विषय अध्यापकों की कमी से राजकीय विद्यालयों से विद्यार्थी अध्ययन हेतु प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं। विद्यार्थियों का रुझान प्राइवेट विद्यालयों की तरफ हो रहा है। अध्यापकों के रिक्त पद भरने, विषय अध्यापक लगाने हेतु विधान सभा के विभिन्न सत्रों में मांग की, शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार रिक्त पद भरने की मांग की, लेकिन 04 वर्षों में आज भी अध्यापकों के रिक्त पद पूर्ण रूप से नहीं भरे गये। विद्यार्थियों का पलायन रोकने व विद्यार्थी हित में उपरोक्त सभी पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के करीब 137 विद्यालयों में लगभग 645 अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में जलदाय विभाग की पाइप लाइनों से जल रिसाव

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पाली के भैरूघाट, सोमनाथ मन्दिर, धौला चौंतरा के आसपास सूरजपोल घाचियों के दोनों मोहल्ले के कई पक्के मकानों में सीवरेज एवं पानी की पाइप लाइन के लीकेज के कारण भारी दरारें आ गई हैं। कई मकान तो रहने लायक भी नहीं हैं।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

क्षेत्रवासी कई दिनों से प्रशासन को इसकी जानकारी दे रहे हैं। रूडिप द्वारा पेयजल हेतु नई पाइप लाइन बिछाई गई, परन्तु जलदाय विभाग की पुरानी पाइप लाइनों को इससे नहीं जोड़ा गया। सीवरेज एवं पाइप लाइन बिछाते समय पहले की पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं एवं सीवरेज के जोइंट भी सही नहीं लगाने से उनमें भी रिसाव हो रहा है। बिछाई गई पाइपों को बिना जांच किये, वहां सीमेंट की सड़कें बना दीं जिससे क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों से होने वाले रिसाव से मिट्टी धसने से मकानों की नीवों को नुकसान हुआ एवं मकान क्षतिग्रस्त हो गये।

(समय: 12.24 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

जलदाय विभाग द्वारा पाइप लाइनों को चैक करने हेतु गड्ढे खोदे गये तो उसमें बड़ी मात्रा में रिसाव आना पाया। बन्द पड़े मकानों में सीवरेज की कुण्डियों की जांच में भी उनमें पीछे की ओर से तेजी से पानी आता पाया। इन सारे मकानों का क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण सीवरेज एवं पाइप लाइन का क्षतिग्रस्त होना है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए, वे परिवार कमजोर वर्ग के हैं। इन्होंने अपनी सारी कमाई मकान निर्माण में लगा दी थी। अब मकान क्षतिग्रस्त होने से ये बेघर हो गये हैं। कुछ परिवारों को 15 से 20 लाख तक का नुकसान हुआ है। ऐसे में वे सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं।

प्रभावित परिवारों के हुए नुकसान का आकलन करवा उन्हें समुचित मुआवजा दें। अत्यधिक क्षतिग्रस्त मकानों को सरकारी स्तर पर गिराने की व्यवस्था करें एवं इनके अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करें। सम्पूर्ण क्षेत्र की सीवरेज एवं पाइप लाइनों की गहन जांच कर इन्हें दुरुस्त करावें।

श्री सभापति: अमीन खां।

शिव के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख कर निवेदन है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी विशाल 9,000 वर्ग किलोमीटर शिव विधान सभा क्षेत्र में लगातार करीब 800 अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं। कई बार प्रयास किये गये, मगर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

(श्री अमीन खां)

है। ऐसी हालत में रेगिस्तानी एरिया शिक्षा से वंचित रह रहा है तथा आपसे विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस आधुनिक युग में इतने भारी पद रिक्त रखना अन्याय है। इसको शीघ्र भरने की व्यवस्था करवाई जाए।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

अफीम डोडा चूरा निस्तारण का आदेश

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि डोडा चूरा नष्टीकरण की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की थी, परन्तु बारिश के मौसम में डोडा चूरा की दुर्गन्ध व कीड़े पड़ने से बीमारी व महामारी की आशंका के चलते किसानों द्वारा खाद के रूप में डोडा चूरा को खेत में डालकर नष्ट कर दिया गया। अपवादवश कुछ किसानों द्वारा तस्करी हेतु डोडा चूरा का दुरुपयोग किया गया, जिस कारण सरकार द्वारा 4 वर्ष का डोडा चूरा नष्टीकरण का आदेश जारी किया गया है, जो कि अफीम उत्पादक किसानों को परेशान करने वाला है एवं किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 19.01.2023 को दैनिक अखबारों में जारी की गई सूचना, दिनांक 18.01.2023 द्वारा अफीम काश्तकारों को सूचित किया गया कि अफीम फसल वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के डोडा चूरा निस्तारण हेतु नियत तिथि को निर्धारित कैम्प स्थल पर पहुंचने के लिए काश्तकारों को आदेशित किया गया है। यह गौरतलब है कि डोडा चूरा समय के साथ स्वत: खराब हो जाता है तथा चोर और लुटेरों के डर के कारण लम्बे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। विशेष रूप से बारिश के दिनों में नमी से सड़ने पर कीड़े-मकोड़े, जहरीले जीव-जन्तु पनपने लगते हैं, जो मानव जीवन के लिए अति घातक है।

ऐसी स्थिति में विगत चार वर्षों से फसल का डोडा चूरा उपरोक्त परिस्थितियों में काश्तकारों ने अपने स्तर पर खेतों में जलाकर एवं बिखेरकर नष्ट कर दिया है। अफीम काश्तकार चाहते हैं कि उनको डोडा चूरे का मुआवजा मिले, इसके लिए रुपये 1,200/- प्रति किलो के हिसाब से खरीद की मांग कर रखी है। पूर्व में डोडा चूरा ठेकेदार द्वारा 125/- प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता था, जो किसान के जीविकोपार्जन में लाभकारी होता था।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

किसान चाहते हैं कि डोडा चूरा जलाने के बजाय खेतों में ही डाला जाए, ताकि इसकी वर्मी कम्पोस्ट खाद बन सके, जिससे अगली फसल अच्छी गुणवत्तापूर्ण पैदा हो सके।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि अफीम काश्तकार की पीड़ा को महसूस करते हुए फसल वर्ष 2018-19 से 2021-22 के सम्बन्ध में पारित राज्यादेश को जल्द से जल्द पुन: प्रत्याहरित कराया जाकर किसानों को राहत प्रदान करवायें।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

प्रस्तावित पुनर्गठन में बांसवाड़ा को सम्भाग बनाया जाना

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल से, सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान में राज्य सरकार चित्तौड़ जिले को संभाग बनाने का प्रस्ताव ला रही है, जिसमें बांसवाड़ा जिले को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में उदयपुर सम्भाग बांसवाड़ा से 130 किमी. दूरी पर है, जबकि चित्तौड़-बांसवाड़ा की दूरी 200 किमी. है। ऐसे में मेरी मांग है कि सम्भाग बनाना है तो बांसवाड़ा जिले को सम्भाग बनाया जावे।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

रावणा राजपूत व अन्य पिछड़ा वर्ग को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग समूह बनाकर अलग से आरक्षण

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि रावणा राजपूत समाज सहित माली, कुम्हार, स्वामी, वैष्णव, दर्जी, नाई, घांची आदि अन्य पिछड़ा वर्ग की मूल अत्यन्त पिछड़ी जातियां हैं, जिनका शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। रावणा राजपूत समाज सहित अन्य अत्यन्त पिछड़ी जातियों के लिए गुर्जर जाति सहित अन्य जातियों की तरह एक नया समूह "अत्यन्त पिछड़ा वर्ग" बनाकर अलग से आरक्षण दिया जावे।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

यह अलग से आरक्षण देने की मांग इसलिये की जा रही है, क्योंकि मण्डल आयोग की सिफारिश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 1993 से उनकी संख्या के आधे से भी कम मात्र 21 प्रतिशत आरक्षण मिला। इस 21 प्रतिशत आरक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मात्र 52 जातियां शामिल थीं। जैसे-जैसे आरक्षण का महत्व समझ आया, वैसे-वैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में कई जातियां और जोड़ दी गईं जिनकी संख्या 91 तक पहुंच गई, लेकिन आरक्षण 21 प्रतिशत ही रहा। जुलाई, 2001 में अन्य पिछड़ा वर्ग के 21 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश रणवीर सहाय वर्मा आयोग ने की, लेकिन दुर्भाग्य से वह रिपोर्ट लागू नहीं हो पायी। तत्पश्चात् गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग को स्वीकार करते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों का अति पिछड़ा वर्ग बनाकर 5 प्रतिशत आरक्षण देने का साहसिक निर्णय कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया।

वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध मानकर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत को पार कर सकने का रास्ता खोल दिया है। चूंकि रावणा राजपूत समाज सहित अन्य माली, कुम्हार, स्वामी, वैष्णव, दर्जी, नाई, घांची आदि अन्य पिछड़ा वर्ग की मूल अत्यन्त पिछड़ी जातियों को ओबीसी से अलग गुर्जर सहित पांच जातियों की तरह ही एक नया समूह अत्यन्त पिछड़ा वर्ग बनाकर अलग से आरक्षण देने हेतु राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अध्ययन करवाकर अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों का नियमन

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसी अनेक कालोनियां हैं जो कृषि भूमि पर बसी हुई हैं जिनमें से बोरखेडा एवं रायपुरा क्षेत्र में अधिक हैं, इनमें से कई कालोनियां ऐसी हैं जहां पर 60-80 प्रतिशत तक मकानों का निर्माण हो चुका है एवं 15-20 सालों से लोग यहां निवास कर रहे हैं। कई कालोनियों के निवासियों ने समितियां बनाकर 90-बी एवं ले-आउट अनुमोदन हेतु कार्रवाई के लिए आवेदन किये हैं, किन्तु 90-बी एवं ले-आउट प्लान पास

(श्रीमती कल्पना देवी)

नहीं होने की वजह से यहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यहां कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और मेरा विधायक कोष का पैसा भी नहीं लग पा रहा है। सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। यदि सरकार इन सभी कालोनियों की 90-बी एवं ले-आउट प्लान पास कर दे तो यहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी एवं कालोनियों में विकास कार्य भी हो सकेंगे।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसी ऐसी कालोनियों की 90-बी एवं ले-आउट प्लान पास कर इनके पट्टे जारी किये जायें, जिससे कालोनीवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें एवं कालोनियों में विकास कार्य हो सकें।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से निवेदन करता हूं कि प्रदेश का अल्पसंख्यक जैन समुदाय आज पसोपेश में है। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे जैन समुदाय की सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास हुए हैं, साथ ही साधु-साध्वियों के आहार-विहार में भी बाधा उत्पन्न करने की कोशिशें हुई हैं।

अतएव लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर मांग है कि जैन समुदाय की संस्कृति, धार्मिक सम्पत्तियों, जैसे अतिशय क्षेत्र, स्थानक, मंदिर, नसियां, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि की सुरक्षा एवं संरक्षण, जैन आचार्य, संतों और साधु-साध्वियों की सुरक्षा तथा चर्या का संरक्षण करने हेतु प्रदेश में श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

आहोर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पद

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव

(श्री छगनसिंह)

के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा आहोर में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा लड़खड़ाए रहती हैं। आहोर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 02 सीएचसी हैं, एक आहोर तथा दूसरी सियाणा। इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में मात्र दो सीएचसी हैं, उनमें भी डाक्टर के सभी पद लगभग रिक्त हैं। आहोर सीएचसी की बात करें तो इस सामुदायिक अस्पताल में गाइनोकोलोजी चिकित्सक, दन्त रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, सर्जन, नेत्र रोग सहायक के पद रिक्त हैं। इस प्रकार सियाणा में शारीरिक रोग विशेषज्ञ, प्रसूता एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग, सर्जन, चिकित्सा अधिकारी, सीनियर नर्सिंग अधिकारी आदि सभी लगभग पूरी सियाणा सीएचसी खाली है।

अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात करें, चान्दराई, हरजी, भूती घाणा, भाद्राजून एवं कई पीएचसी पर चिकित्सक के पद रिक्त हैं। जिस चिरंजीवी योजना का ढोल पीटा जा रहा है या मुफ्त इलाज का ढोल पीटा जाता है, उस सीएचसी में उसका फायदा आम आदमी को कैसे पहुंचेगा? जब भी रोगी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाते हैं तो उन्हें यह कहकर भेज दिया जाता है कि यहां पर इस बीमारी का डाक्टर नहीं है तथा अन्य अस्पताल में इसका इलाज कराओ। आज प्रत्येक परिवार के घर में स्त्रियों के संबंध में डिलीवरी केसेज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाना होता है, लेकिन प्रसूता एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने की वजह से उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। चूंकि पूर्व की सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रसूता एवं आंखों का आपरेशन, मुफ्त में इलाज होता था, जबकि अब चिरंजीवी योजना में ये जुड़े हुए नहीं हैं, जिससे निजी अस्पताल में आम आदमी को भारी भरकम बिल चुकाना पड़ता है। इसलिये आहोर एवं सियाणा सीएचसी में जितने भी रिक्त पद हैं, उन्हें तुरन्त प्रभाव से भरे जाएं।

इसी प्रकार भाद्राजून तहसील मुख्यालय पर मात्र पीएचसी है और बागरा आर.आई. सर्किल में सीएचसी की सख्त आवश्यकता है। इसलिये भाद्राजून, बागरा, चान्दराई, गुढाबालोतान, भवरानी, हरजी के पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करावें और इसी प्रकार उम्मेदपुर ऊण, शंखवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सख्त आवश्यकता है, इन गांवों में पीएचसी एवं सीएचसी की घोषणा करावें। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में बढ़ती मेडिकल नशे की प्रवृत्ति

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में मेडिकल नशा (स्मैक, चिट्टा, हेरोइन, नशीली गोलियां आदि) काफी बढ़ रहा है। जितनी तेजी से यह नशा बढ़ रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि ऐसा एक भी घर नहीं बचेगा जिस पर नशे का प्रकोप न हो। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पीलीबंगा में हुई कुछ घटनाओं पर दिलाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी 19 जनवरी को सुबह 5.00 बजे इस नशे के कारण पीलीबंगा के वार्ड 9 में रहने वाले जसवीर सिंह व उसकी पत्नी मनजीत कौर तथा 6 वर्षीय बालक को एक जोत पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसमें पति-पत्नी झुलस गये तथा बच्चे की मृत्यु हो गई और दो दिन बाद पत्नी मनजीत कौर की भी मृत्यु हो गई। यह सब कार्य पुलिस की नाक के नीचे हो रहे हैं।

इसी प्रकार पीलीबंगा थाने की जाखडावाली चौकी में बड़ी संख्या में नशीली गोलियां पकड़ी गईं और आश्चर्य की बात है कि पुलिस चौकी से गोलियां गायब हो जाती हैं और अभी तक उन गोलियों का कोई अता-पता नहीं है व स्कूल में बच्चे टीका लगाते हुए पकड़े जाते हैं।

सभापति महोदय, पीलीबंगा विधान सभा सहित हनुमानगढ़ जिले में यह हालत है कि सब्जी की तरह आप खुलेआम मेडिकल नशा खरीद सकते हैं और सबसे बड़ी विडम्बना है कि पुलिस द्वारा जब नशे के आरोपियों को पकड़ा जाता है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, यह सोचकर कि कहीं नशेड़ी मर न जाये। हम व आप सभी को इस गंभीर विषय पर गंभीरता दिखाते हुए यह विचार करना चाहिये कि यह नशा कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है? क्या यह पुलिस और शासन की कमी है?

इस नशे को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा तथा इसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों से लेकर पुलिस अधीक्षकों तक को गंभीर होना पड़ेगा ताकि नशे की रोकथाम हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ (अलवर) स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में अवैध खनन

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अलवर जिले की अरावली श्रृंखलाओं की पर्वत श्रेणियां राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की अति प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की पर्वत श्रृंखलाओं में खनन माफियाओं द्वारा अंधाधुंध अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके कारण पौराणिक प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हो रही है। रामगढ़ की पहाड़ियों में वन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते बेखौफ अवैध खनन, अवैध कटाई के चलते पहाड़ियों का सौंदर्य भी नष्ट होता नजर आ रहा है। वन विभाग के कर्मचारी अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। सीमावर्ती गांवों के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अवैध खनन कर रहे हैं। माफिया मजदूरों को भेजकर ट्रैक्टर-ट्राली से दिन-रात क्लोजर के पत्थरों को भी यहां से ले जा रहे हैं। इसके बाद यहां पर क्लोजर में लगाये गये पेड़-पौधों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को हर महीने लाखों रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है। यहां तक कि पत्थरों को ओवरलोड कर ट्रैक्टर और डंपर फर्राटेदार दौड़ते हैं, जिसके कारण रामगढ़ एवं नौगावां के इलाकों में कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और जान-माल का नुकसान भी हो रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि यहां की खदानों को आबंटित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पौराणिक संपदाएं नष्ट हो रही हैं, जिसके कारण जन जीवन और पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता पर भी काफी असर पड़ रहा है।

अत: मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए रामगढ़ (अलवर) की इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को अवैध खनन से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये एवं पौराणिक सम्पदा को नष्ट होने से बचाने के लिए यहां की खानों का आबंटन भी रद्द करने की कृपा करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

हनुत्या (बूंदी) एवं जयस्थल (केशोरायपाटन) के मध्य कुरल नदी पर पुलिया निर्माण

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम

(श्री रामनारायण मीना)

295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बूंदी जिले के ग्राम हनुत्या (ख्यावदा) से पुराने रियासतकालीन व्यापारिक केन्द्र जयस्थल मार्ग के मध्य बहने वाली कुरल नदी के कारण रियासतकालीन आम रास्ता बन्द हो जाने से करीब 60 गांवों को पारस्परिक आवागमन का सैकडों वर्षों पुराना मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे वर्तमान में 30-40 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करके यात्रा करनी पड़ रही है। इस कारण क्षेत्र के आमजन के समय एवं धन की हानि होने के साथ ही विकास अवरुद्ध हो गया है। जयस्थल बूंदी जिले का महत्वपूर्ण एवं पुराना बड़ा कस्बा है। पुलिया निर्माण मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर कराया जायेगा। इस पुलिया के निर्माण के पश्चात् इस क्षेत्र के गांव राज्य राजमार्ग संख्या 125, 129, 34, 37ए एवं 33 के माध्यम से एक-दूसरे से जुड सकेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग पर हनुत्या एवं जयस्थल के मध्य कुरल नदी पर पुलिया निर्माण कराये जाने से जिला मुख्यालय बूंदी के लिए कापरेन होते हुए मध्यप्रदेश तक जाने के लिए पारस्परिक आवागमन सीधा एवं सुगम हो जायेगा एवं ग्रामवासियों को चिकित्सा एवं शिक्षा केन्द्रों पर पहुंच हेतु सुगम तथा लघु मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। पुलिया निर्माण नहीं होने से सीधे मार्ग के अभाव में क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों में जाने तथा तैयार कृषि उपज को घर एवं मण्डी तक ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह जनहित की अत्यंत गंभीर ज्वलंत समस्या है।

(समय: 12.45 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अत: जनहित में अनुरोध है कि इस क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्र के सामाजार्थिक विकास की दृष्टि से ग्राम हनुत्या (बूंदी) एवं जयस्थल (केशोरायपाटन) के मध्य पुराने रियासतकालीन मार्ग पर कुरल नदी पर पुलिया निर्माण कार्य करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पानाचन्द मेघवाल।

डा. भीमराव अम्बेडकर के नाम से मेडिकल कालेज, कोटा का नामकरण

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि वर्ष 2007 से पहले मेडिकल कालेज, कोटा का नाम डा.बी.आर. मेडिकल

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

कालेज था। इस अवधि में सरकार ने मेडिकल कालेज, कोटा से जो भी पत्राचार किया उन सभी पत्रों में मेडिकल कालेज, कोटा का नाम डा. बी.आर. मेडिकल कालेज, कोटा अंकित था, लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के अधिकारियों ने मिलीभगत कर इस नाम का प्रयोग करना बंद कर दिया।

कोटा संभाग के एस.सी., एस.टी, ओबीसी और अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग इस बात से बड़े आहत हैं तथा किसी भी कीमत पर बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहेब के नाम पर पूरे कोटा सम्भाग में अब एक भी संस्थान नहीं है। डा. अम्बेडकर भारत देश का गौरव हैं, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी का सम्मान बना रहे, यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर में आवारा पशुओं से उत्पन्न समस्या

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आवारा पशुओं की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। आये दिन आवारा पशुओं के कारण रोड दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम जन को मौत का शिकार होना पड़ रहा है। सर्दियों में इस क्षेत्र में अत्यधिक कोहरा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। खेतों में कोहरा रहने के कारण आवारा पशुओं को सड़कों की तरफ खदेड़ दिया जाता है, जिस कारण से दुर्घटनाएं आये दिन बढ़ती जा रही हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त स्थिति का निवारण करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

विशेषाधिकार प्रश्न

विधान सभा सदस्यों के त्याग पत्रों का प्रकरण प्रिमेच्योर स्टेज पर न्यायपालिका ले जाने से विधायिका की आहत गरिमा

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही की जनता के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है अगर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

'privilege motion' मूव करना है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह पूरा मामला सबजुडिस है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे अधिकार को चैलेंज न करें ...(व्यवधान) I have allowed it. I have allowed it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) आप इनको अनुमति प्रदान कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I have allowed it. मैंने अलाउ किया है, आप मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपके अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते ...(व्यवधान) पढ़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मामला सबजुडिस है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) आप चैलेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैं नियम के अंतर्गत काम कर रहा हूं। (व्यवधान) I will not allow it. I will not tolerate it. You cannot dictate me. Mr. Rathore, you cannot dictate me. I am within the rules. मैं रूल के अंतर्गत अलाउ कर रहा हूं। I say, you cannot dictate me. मिस्टर कटारिया जी, मैं अपने संविधान में

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका अधिकार है, इसमें हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। क्या मैं सदन को चलाने के नियम के अंतर्गत पावर नहीं रखता हूं? कोई सदस्य मेरे पास लेकर आयेगा तो रूल 157 कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा। यह भी राजेन्द्र राठौड़ डिसाइड करेंगे? हाउस कैसे चलेगा, कोर्ट कैसे चलेगी, यह भी राजेन्द्र राठौड़ डिसाइड करेंगे? You have no right to decide it. I am doing this as an individual case. I have no right to decide it?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) मैं कोर्ट में जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: जाइए, मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मेरा हाउस चल रहा है, हाउस में ऐसे ही चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता। हाउस नियम से चलता है, हाउस नियम से चलता है। (व्यवधान) आपकी मर्जी से नहीं चलता ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) The House is supreme and स्पीकर हाउस के लिए सुप्रीम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाउस नियम से चलता है। (व्यवधान) आपकी मर्जी से नहीं चलता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये पहले ही खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष: मैं हाउस को नियम से चलाता हूं। एक मिनट रुकें। मिस्टर, तानाशाही बाकी है। माननीय कटारिया जी, मैं सदन का अध्यक्ष हूं। नियम और कानून के अन्तर्गत कार्य करने का मेरा अधिकार है। आप लीडर आफ अपोजिशन हैं। मुझे बतायें कि क्या 157 के अन्तर्गत मैं अपने नियम के अन्तर्गत किसी चीज को डिस्टर्ब कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? पहले आप इसका जवाब दे दें। आप पढ़ लीजिये। मिस्टर राठौड़, सेमी लिट्रेट होने से काम नहीं चलता है, लिट्रेट होना पड़ेगा। आप पढ़कर बता दीजिये, मैं मंजूर करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप एक सैकण्ड बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आप 157 पढ़ लें। 157 को कोट करें। आप खड़े होकर बोलें कि नियम 157 क्या बोलता है? Please go and see 157. मैं आपकी बात को मान लूंगा। 157 क्या बोलता है? एक मिनट, कटारिया जी, let him speak. What is 157? आप बोलिये, 157 क्या बोलता है? Please quote 157. No this and that way.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: Can you just quote 157? This is my right as a Speaker. You cannot dictate me. You just quote 157.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जब आप नाराज हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: You please quote 157. नाराजगी का सवाल नहीं है। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, but you cannot take it for granted कि आप चाहो वैसे इंटरप्रेट हो। Please quote 157 and I am within the right to conduct this house.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्याय 19 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: You please quote 157. I will agree with it, if I have committed wrong! But you cannot dictate me. मिस्टर राठौड़, मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूं, पर मैं भी अपने नियम और कानून को जानकर यहां बोलता हूं। Please quote 157 and मेरा नहीं है तो मैं विद्ड्रा कर लूंगा। Please quote 157. What is 157? Please quote 157 in front of everyone.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: Please quote 157 in front of everyone.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का अध्याय 19 है और अध्याय 19 में 163 पर...

श्री अध्यक्ष: Only 157. Don't divert it. इधर-उधर नहीं। आप बैठें, मैं पढ़ देता हूं। मैं नियम देखकर बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने मुझे अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, मैं किताब देखकर पढ़ रहा हूं। मान्यवर, आप बैठें। I am on legs. I am a parliamentarian and I am on legs. Are you a parliamentarian? Please be seated.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते।

श्री अध्यक्ष: Please be seated. I am on legs. मैं गुस्से में नहीं हूं। I am on legs.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं कह रहा हूं, मेरे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I am on legs. जेंटलमैन, आप बैठें। मैं आपकी जानकारी के लिए 157 पढ़ देता हूं, ज्यादा बैटर रहेगा।

'157. विशेषाधिकार प्रश्न.- कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सदन के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो।

(श्री अध्यक्ष)

158. विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना - जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।

159. विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें- विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्

(1) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा

(2) विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

160. विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति.- (1) अध्यक्ष यदि नियम 157 के अन्तर्गत सम्मति दे और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य सूची का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा।'

What is wrong in it, जो मैं नहीं कर रहा हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप 161 पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें ...(व्यवधान) You have no right to dictate me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नियम 161 पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष: You have no right ...(interruptions) कौनसा बोलें, मैं अनपढ़ नहीं हूं। आप बोलें, मुझे कौनसा पढ़ना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पेज नम्बर 68 पर रूल नम्बर 161- विशेषाधिकार के प्रश्न पर सदन...

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, मैं पढ़ता हूं। 160 के बाद 161 आता है। पहले 160 पढ़ लूं, 161 बाद में आता है। कूदने से काम नहीं चलता। मैं 160 पढ़ता हूं।

'परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझे, उस विशेषाधिकार प्रश्न की

(श्री अध्यक्ष)

सूचना पढ़कर सुना सकेगा और कह सकेगा कि वह सम्मति देने से इंकार करता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराता' मुझे यह भी अधिकार है कि पूरा का पूरा पढ़कर सदन को सुनाऊं यदि मैं रिएक्ट करता हूं तो। यह भी अधिकार मेरे पास है।

'परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह प्रश्नों के निपटाये जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा'

यह 160 है, आप आगे कूद रहे हैं। आप पढ़ लीजिये, अगले वाला पार्ट आयेगा, तब आपका अधिकार है। मैं जोर से पढ़ रहा हूं।

'यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, उनको अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा, और तदनुसार यदि कम से कम दस सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि दस से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करे, ताकि सदन की अनुमति नहीं दी जाये' मैं अभी इस स्टेज पर आया ही नहीं हूं।

Please understand it. आपने प्रेक्टिस नहीं की है। मेरा काम है हाउस को नियमों के अनुसार चलाने का। मुझे मिला है, मैं उनको बोलने का मौका दे रहा हूं। बोलने के बाद आपको आब्जेक्शन है, आपको पूरा अधिकार है। फिर मैं पूछूंगा कि सदस्य के पक्ष में खड़े होंगे, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि आज डिबेट करनी है या कल डिबेट करनी है, प्रिविलेज को भेजना है। इसमें हल्ला करने की कहां जरूरत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है?

श्री अध्यक्ष: अधिकार नहीं है। अभी आपका अधिकार कहां है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनके बोलने के बाद?

श्री अध्यक्ष: आप आब्जेक्शन करें, कौन मना कर रहा है? आपको आब्जेक्शन में इतना ही कहना है कि होगा या नहीं होगा। क्या बोलना है या नहीं बोलना है, यह मुझे आप डिक्टेट नहीं करा सकते हैं। मैं डिसाइड करूंगा कि आप क्या बोलेंगे। आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकते कि मुझे क्या बोलना है? मैं फिर दोबारा पढ़ता हूं। मैं फिर दोबारा पढ़ लेता हूं। आपका स्कोप नहीं है। Please understand it. Please understand it thoroughly.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप 161 पढ़ें। मेरी यही प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: आप फिर 161 पर आ गये। मैं 160 पर आया ही नहीं हूं। आप प्लीज दूसरों को समझायें। Don't challenge my ruling. Please be seated. (interruptions) Don't challenge my ruling. मैं अभी 161 पर आया ही नहीं हूं। 160 की पालना ही नहीं हो रही हो, आप 161 पर आ गये। 157 के अन्तर्गत मुझे जो अधिकार हैं, मैंने 159 को देख लिया। 160 में मैं माननीय सदस्य को अलाउ कर रहा हूं। अभी मैं इतना ही काम कर रहा हूं। आप 161 पर कहां जा रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आप अपनी बात पर क्यों डर रहे हैं? जबरदस्ती अपनी पंचायत कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, अपनी बात कहें। माननीय सदस्य, संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे अनुमति देंगे न?

श्री अध्यक्ष: मैं कब दूंगा, which I will decide it. जब मैं हाउस में डिस्कस कराउंगा, तो सबको दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसका मतलब, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सबको अनुमति दूंगा। आज नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह कभी नहीं हुआ। टुकड़ों में विशेषाधिकार प्रस्ताव कभी नहीं आया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: You cannot throw your arguments by mouth. Please be seated. प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आर्ग्यूमेंट मैं कर ही नहीं सकता। 13 तारीख को फैसला हुआ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज बैठें। मान्यवर, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप फैसले को प्रभावित करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आपको हाउस नहीं चलाना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप हाउस को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। रूल के अन्तर्गत, आपको रूल नहीं, फिर कोर्ट में जाना। यह भी आपको अधिकार है। यदि मैं गलत रूल्स से हाउस चला रहा हूं तो यह आपको अधिकार है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको मना थोड़े ही कर रहा हूं। आपको पूरा अधिकार है। आपको लगता है कि मैं गलत रूल से हाउस चला रहा हूं। आपको पूरा अधिकार है, कोर्ट में जाकर उस रूल्स से हाउस चलाने का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं आपका सम्मान करता हूं। आप टुकड़ों में कैसे ले सकते हैं, आप 161 पढ़िये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। Kataria Ji, I will not allow it. मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। एक मिनट, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, आप सुन लें। मैं आपकी सब बात सुनूंगा, पर मैं किसी सदस्य को सीनियरटी के नाम पर यह हाउस चलाने या डिक्टेट करने का अधिकार नहीं दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकार हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। 157 में विशेषाधिकार प्रस्ताव कैसे मूव होगा, वह भी है। आपको स्वीकार करने के लिए मेरा और हमारे सदस्य का कहना यह है कि जब आप इस पर डिस्कशन करें, स्वीकार करें या न करें, वहां प्रोसीजर तक जाने का अधिकार आपका है। या दस लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, या तो वह सीधा कमेटी के पास चला जाता है या हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं तो हाउस के डिस्कशन के लिए जब अलाउ करते हैं तब हमारा भी पक्ष रखने का अधिकार है।

(समय: 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, पूरा अधिकार है। आपका ही नहीं, राजेन्द्र राठौड़ को दो घंटे का और आप सबको सब घंटे का अधिकार है। वह स्टेज तो आने दीजिए पहले। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मूव करने की बात है, ये तो भाषण टेक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कौन होते हैं? वे क्या बोल रहे हैं, यह भी आप डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे? प्लीज, आपको अलाउ नहीं है। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं मेरी जगह बैठ जाता हूं, परंतु इस तरह का मैं पहली बार देख रहा हूं। (व्यवधान) आप आज ही मूव कराएं 161 में।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मदन दिलावर जी, आपको जरूरत नहीं है। एक वकील ही काफी है। आप कोई असिस्टेंट हैं वकील के साथ? वकील काफी है एक ही। माननीय संयम लोढ़ा जी। मैं उनको कह रहा हूं असिस्टेंट की जरूरत नहीं है राजेन्द्र राठौड़ को। आपको जरूरत है असिस्टेंट की? राठौड़ साहब इतने इन्कॉम्पीटेंट है, असिस्टेंट की जरूरत है। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मुझे इस सदन में आने का मौका मिला और मैं कानून का विद्यार्थी भी हूं, लेकिन आज मन बहुत भारी है। बाड़ ही खेत को खा रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव को पढ़ दें, उसकी स्वीकृति हो...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप पढ़ लें इसको। मैं नियम में काम कर रहा हूं। यह नहीं है, नियम मैं पुकारूंगा, वह बोलेगा। आप फिर पढ़ लें। ये राजेन्द्र राठौड़ जी आपको आधी बात बता रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इन्होंने जो...

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ लें, प्लीज। माननीय कटारिया जी..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इन्होंने जो लिखित सूचना दी है, उसको पढ़ दें। यह उनको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बात समझाता हूं। बैठिए, आप बैठिए। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। मैंने आपकी बात मानी। आपने पहले टोका, मैंने रोक दिया। पहले भी प्रश्न काल के बाद उठाने का था, आपने कहा तो मैंने रोक दिया कि आप सीनियर आदमी हैं। नियम यह कहता है कि प्रश्न काल समाप्त होते ही मैं अलाउ करता, तब भी मैंने आपकी बात मानी कि बात ठीक है। मैं अभी-भी इस बात को मान रहा हूं कि जब हमें एडमिट करने की स्टेज आ जाए, चाहे मैं कमेटी को भेजूं, चाहे हाउस में डिस्कस करूं, तब आपको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं मना नहीं कर रहा हूं। उसके पहले क्या स्टेज होगी, उसके लिए तो आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। मैं आपको एक बार फिर दोबारा पढ़ देता हूं। मैं पढ़ देता हूं "अध्यक्ष यदि नियम 157 के अंतर्गत सम्मति दे और यह ठहराए कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है तो वह प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची का

(श्री अध्यक्ष)

कार्य प्रारम्भ करने से पहले, सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा" प्लीज आप वकील है, मैं पढ़ रहा हूं, भाई, मैं अपने मन से थोड़े ही पढ़ रहा हूं, "सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा।" यही तो अलाउ कर रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप फिर बीच में आ गये। प्लीज, मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने नियमानुसार मान लिया इसको?

श्री अध्यक्ष: किसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने नियमानुसार मान लिया न इसको, परमिशन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यही कह रहा हूं। नियमों के अनुसार मान लिया। नियमों के अनुसार मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं अलाउ कर रहा हूं, आप बैठिए। प्लीज, आप नीचे बैठिए। मैं आपको अलाउ करूंगा। मैं हाउस में किसको अलाउ करूं, पहले मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष जी, इस खेल से सरकार के अंतर्द्वंद्व को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: नियम नहीं कहता। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय,

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान) आपको तकलीफ है क्या कुछ?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठिए, माननीय सदस्य। आप नीचे बैठिए। हाउस ऐसे नहीं चलेगा। कटारिया जी, अब लिमिट है इसकी। एक मिनट रुकिए, संयम लोढ़ा जी। आप बैठिए। कटारिया जी, चाहे आप पढ़ लें, मुझे क्या करना है, आप बता दीजिए। मैं आपकी बात मानूंगा। मैं नियम के विपरीत जा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): संक्षिप्त में..

श्री अध्यक्ष: क्या संक्षिप्त में, एक मिनट रुकिए प्लीज।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): राठौड़ साहब, इतने सीनियर आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष: रामलाल जी, आप बैठिए प्लीज। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत कर रहा हूं। मुझे पढ़कर बता दें अगर मैं गलत कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी बात में, आप कह रहे हैं वह सही है। संक्षिप्त वक्तव्य का मतलब जो प्रस्ताव उन्होंने लिखा है, जो बात आप तक वह उस प्रस्ताव के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, उसको पढ़कर आपके ध्यान में लाएं कि मेरा प्रस्ताव ये है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ये ही बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये नहीं है कि भाषण ठोकने का..

श्री अध्यक्ष: किसने कहा आपको, ...(व्यवधान) आपको कैसे एप्रिहेंशन है कि भाषण देगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नीचे बैठिए। अपने आपको बहुत सीनियर समझने लग गये हैं क्या आप? आपको कटारिया से ज्यादा अनुभव है क्या? आपका हाइपोथेटिकल उत्तर है, ये भाषण ठोकेंगे, फलानां ठोकेंगे, ... (व्यवधान) प्लीज, मिस्टर कालीचरण सराफ, सीनियर आदमी है। You cannot dictate me. आज मेरी इच्छा थी, इसलिए लाया हूं मैं कि हाउस के लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रिविलेज कैसे आता है? बहुत-से आदमियों को मालूम नहीं है। राजेन्द्र राठौड़ कहते हैं, वैसे प्रिविलेज नहीं आती है। प्रिविलेज नियम-कानून के अंतर्गत आती है। यह लोगों को सिखाना जरूरी है, इसलिए मैं सोच-समझकर हाउस में इस स्टेज पर लाया हूं। अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। जब डिस्कशन होगा तब, मान्यवर, मैं पूरा का पूरा टाइम, जितना समय आप लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, पूरा का पूरा टाइम दूंगा, परंतु अभी वह स्टेज नहीं है। अभी मैं नियम के अंतर्गत जो माननीय सदस्य लेकर आए हैं, उस नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहने का इसमें नियम है। मैं उस नियम के अंतर्गत उनको अलाउ कर रहा हूं। वह

(श्री अध्यक्ष)

क्या बोल रहे हैं, ये आपका एप्रिहेंशन है, वह भाषण देगा, मैं भाषण दूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है नियम के अंतर्गत माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसको बोलने के लिए मैं अलाउ करूं। अभी ये स्टेज आई है, नमस्कार, सुनिए आप। माननीय संयम लोढ़ा जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा के...

श्री अध्यक्ष: माननीय संयम जी, जब इतना डिस्कशन किया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि नियम के अंतर्गत, please be brief.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस्तीफों को लेकर के भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3)(ख) में बहुत साफ उल्लेख है, मैं उसको यहां पढ़कर के सदन का समय नहीं लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से विधान सभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम है उसमें भी 173(2) में भी बहुत साफ उल्लेख है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने उन इस्तीफ़ों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया। अध्यक्ष महोदय के वे विचाराधीन थे, लेकिन हमारे ही सदन के, हमारे ही परिवार के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य के आचरण से व्यथित होकर मैं आज आपके सामने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत यह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार के लिए या किसी भी तरह के अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है कि हर संवैधानिक संस्था की अपनी कार्यप्रणाली, अपना दायरा पूरी तरह से नियत है....(व्यवधान) और अनेकानेक बार न केवल विधान सभा अध्यक्षों ने बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के जरिये इस व्यवस्था को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह भाषण दे रहे हैं। मुझे भी अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष: Please be brief. (interruptions) माननीय कटारिया जी, प्लीज। I can't put my words in his mouth. संक्षिप्त बात करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा के अन्दर मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष पद से महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये, ...(व्यवधान) उसमें प्रथम खण्ड के पृष्ठ 878 पर 14/05/84...

श्री अध्यक्ष: संयम जी, please be brief.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रस्ताव में क्या लिखा है? मूल प्रस्ताव पढ़ना है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, आप कौन होते हैं? (व्यवधान) कटारिया जी, ये लिमिट है। ये बिलकुल लिमिट है। आप बैठिए, माननीय सदस्य, मदन जी, आप बैठिए प्लीज। नीचे बैठिए। मुझे गाइड करेंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तो फिर आप तो ये ही कर रहे हैं। Who are you to stop me? आपको प्रॉब्लम है कुछ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप हमारे भी अध्यक्ष हैं, आप उन्हीं के अध्यक्ष नहीं हैं। हमारे अध्यक्ष नहीं हैं क्या? मेरे भी अध्यक्ष हैं आप।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं आपका अध्यक्ष हूं। आपका अध्यक्ष बन रहा हूं मैं। धन्यवाद, बैठिए आप। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। नीचे बैठिए। आप मुझे अध्यक्ष मान रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय संयम जी, दो मिनट में अपनी बात खतम कीजिए। दो मिनट में प्लीज। आपका जो उद्देश्य था पूरा हो गया। जब आप बोल चुके हैं तो ब्रीफ कीजिए अपनी बात को।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे सिर्फ यही कहना है अध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन में बैठकर हम सब लोग अपने ही इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम करें? क्या यह सदन राजस्थान हाई कोर्ट का सबोर्डिनेट है कि राजस्थान हाई कोर्ट इस सदन को डिक्टेट करेगा। (व्यवधान) कोई प्रश्न का अगर विधान सभा में हमारा जवाब नहीं आएगा, किसी प्रस्ताव का जवाब नहीं आएगा तो क्या हम इसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ये क्या तरीका है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में किसी मामले का निर्णय नहीं हो तो क्या ये विधान सभा हाई कोर्ट को कह सकती है कि आप फैसला कीजिए। जब यह विधान सभा नहीं कह सकती तो हाई कोर्ट विधान सभा को कैसे डिक्टेट कर सकता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ सदस्य ने उनके आचरण ने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को अपमानित किया है, लांछित किया है। (व्यवधान) उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का ये सदन माध्यम है इसलिए इसको आप निर्देशित करें, इसकी जांच हो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे क्या बोल रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और इसका प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाए। मैं ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद। आप और हम सब जानते हैं कि कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के पावर डिफाइन हैं। माननीय सदस्य प्रश्न लेकर आए हैं, मैं इस पर सोचकर, निर्णय करने के बाद इस पर हम सदन में निर्णय करेंगे। धन्यवाद।

सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार छह वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेन्स एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2021-22)

(2) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2021-22;

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22;

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे (वर्ष 2021-22)

(4) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2021-22;

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(5) अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा-60 के अन्तर्गत अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं

अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(6) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप एक बार फिर देखो, 2019-20 का प्रतिवेदन आ रहा है। बार-बार कहने के बाद भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय, मैं कह चुका हूं। डा. महेश जोशी।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(1) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2021-22)

(2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2021-22.

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। प्रवर समिति प्रतिवेदन के उपस्थापन के सम्बन्ध में। श्री परसादी लाल जी मीना।

विधायी कार्य: प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। श्री संयम लोढ़ा।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आपकी कोई प्रोब्लम है? आज सुबह से कोई दस बार बोल चुके हो। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चार सालों में जिस रूप में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समाज के हर तबके के हित का चिन्तन करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ विकास की दृष्टि से नहीं, जिन मूल्यों के आधार पर आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई और जिन सिद्धान्तों के आधार पर समाज के निर्माण की कल्पना की गई, उनसे कैसे समाज को जोड़ा जाए, समाज में उनका कैसे प्रसार किया जाए। आज समाज में हिंसा का भाव बढ़ रह है। आप देखिए, किस ढंग से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अभी उड़ीसा में, परसों ही एक एएसआई ने किस ढंग से गुस्से में आकर एक मंत्री की हत्या कर दी। हमारे यहां समाज में छोटी-सी घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोगों में इतना गुस्सा है कि वे वाहन फूंक देते हैं, लोगों को जला देते हैं। अस्पताल में कोई घटना हो जाए तो हिंसा का एक अलग ताण्डव देखने का वातावरण मिलता है। इन परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समाज में शान्ति और अहिंसा का भाव कैसे बढ़े, इस विचार को लेकर राजस्थान में शान्ति व अहिंसा का एक नया विभाग बनाया और पांच विचारकों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए, यह सोचकर कि गांधी जी के सिद्धांतों पर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा-

(श्री संयम लोढ़ा)

"तुम तो प्राण दे चुके बापू स्वयं उन्हें साधारण जान,
कृपया कभी ना करना फिर अपने दिए हुए का दान,
उन्हें न्यास सा रखना आगे अब उन पर अधिकार उन्हीं का,
उनमें है जिनके भगवान और भाग्य है जिनके जागे।"

उस दिनकर की पीड़ा को समझते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने शान्ति और अहिंसा का विभाग स्थापित करके राजस्थान के नौजावानों को उन विचारों से जोड़ने के लिए जगह-जगह सम्मेलन किये, जगह -जगह प्रशिक्षण शिविर किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कल प्रतिपक्ष की ओर से पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें रखीं और उस किसान सम्मान निधि का हवाला दिया, इसका मतलब है एक किसान को दिन के 16 रुपये देना। महीने के 500 रुपये यानी दिन के 16 रुपये। अध्यक्ष महोदय, दिन के 16 रुपये में तो एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं आता है और उस सम्मान निधि के पैसे की वाहवाही लूटना चाहते हैं, जबकि उनका अकुशल वित्तीय प्रबंधन पूरे देश के सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार का वर्ष 2022-23 का ब्याज भुगतान है, वह रेवेन्यू रिसीट का 46 परसेंट है जबकि राजस्थान का ब्याज भुगतान रेवेन्यू रिसीट्स का मात्र 13.41 प्रतिशत है। यह अपने आप में जाहिर करता है कि क्या भारत सरकार का वित्तीय अनुशासन है और क्या राजस्थान सरकार का वित्तीय अनुशासन है। किस तरह गरीब और किसान विरोधी है नरेन्द्र मोदी की सरकार, उसकी बानगी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

(समय: 13.15 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें 2020-21 के अन्दर 01 लाख 11 हजार 170 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, 2022-23 के अन्दर मात्र 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो 34 परसेंट से भी ज्यादा कम है। किस आधार पर ग़रीबों का मसीहा बताने की चेष्टा की जाती है?

जो नरेगा योजना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्दर ग्रोथ का एक

(श्री संयम लोढ़ा)

बड़ा माध्यम बनी है, उसके अन्दर भी हजारों-करोड़ रुपये का प्रावधान नरेन्द्र मोदी जी ने किया, कम किया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत साहब हैं, जिन्होंने मज़दूरों के 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का फैसला किया। यह स्वायत्त शासन मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने उस मजदूर की पीड़ा को समझा और शहरी रोजगार गारंटी के माध्यम से 100 दिन शहर के लोगों को भी मजदूरी देने का प्रावधान किया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत सरकार के 2022-23 के अन्दर मात्र 9 हजार 652 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि 2020-21 के अन्दर 42 हजार 443 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। सामाजिक सहायता के अन्दर एक चौथाई से भी कम प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, कल पाली से आने वाले माननीय सदस्य यूरिया की बात कर रहे थे, आप थोड़ा यूरिया सब्सिडी पर भी नजर डाल देते। 2020-21 के अन्दर यूरिया सब्सिडी 90 हजार 549 प्रदान की गई, उसको 2021-22 में घटाकर 75 हजार 930 करोड़ पर ले आए। 2022-23 के अन्दर उसको घटाकर 63 हजार 222 करोड़ रुपये पर ले आए तो आप किस मुंह से किसानों की हिमायत और ग़रीबों की कल्याणकारी सरकार और पार्टी होने का दावा करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, 2014 के प्रधान मंत्री के दावेदार के रूप में नरेन्द्र मोदी जी का वह भाषण आपको याद होगा। तब कहा था, भाइयों-बहनों, नरेन्द्र मोदी की जब सरकार आ जाएगी तो यह किसानों का कर्जा आपका नहीं रहेगा, यह किसानों का कर्जा नरेन्द्र मोदी का हो जाएगा। इन दस सालों के अन्दर एक भी नेशनलाइज्ड बैंक ने एक रुपये का किसानों का कर्जा माफ करने का काम नहीं किया। उनके 2014 के भाषण हैं, उसका वीडियो भी, कोई भी मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकता है। दस साल में हिन्दुस्तान के किसानों को सिवाय धोखा देने के कोई काम नहीं किया। अरबों रुपये, इनके मित्र जो विदेशों में भाग गए माल्या, मोदी, वह लेकर निकल गए। लाखों-करोड़ रुपये एनपीए इन पूंजीपतियों का इन्होंने माफ किया लेकिन किसान

(श्री संयम लोढ़ा)

के बेटे का एक रुपये का कर्जा नरेन्द्र मोदी की सरकार ने माफ नहीं किया और कठघरे में अशोक गहलोत की सरकार को खड़ा करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि अशोक गहलोत की सरकार ने शासन में आने के बाद 20 लाख 77 हजार किसानों का 07 हजार 855 करोड़ रुपये का माफ किया अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन 160 करोड़ रुपये का माफ किया, दीर्घकालीन 200 करोड़ रुपये का माफ किया और यह तो सारे आंकड़े राजस्थान की जनता के बीच में हैं।

माननीय सभापति महोदय, भूमि विकास बैंकों में भी 58 हजार किसानों का रहन भूमि मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के कृषि मंत्रीजी को कि आज राजस्थान में 54 कृषि महाविद्यालय चल रहे हैं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन 54 में से 42 अशोक गहलोत की वर्तमान सरकार के द्वारा खोले गये हैं।

कृषि के लिए अलग से बजट लाया गया, अलग से मिशन तय किये गये। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के हक, किसानों की रहनुमाई करने वाली यदि कोई सरकार है तो वह अशोक गहलोत की सरकार है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, आप किसी भी गांव में जाकर खड़े हो जाइये और किसानों से यह पूछिये कि कितने लोगों का बिल जीरो आ रहा है तो आपको सैकड़ों हाथ खड़े हुए मिलेंगे। क्यों? जिनके पांच हार्स पावर की मशीन लगी हुई है उनका तो सेंट-परसेंट बिल जीरो हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 8 लाख 93 हजार किसानों के जीरो राशि के बिल वितरित किये गये हैं। 8 लाख 93 हजार। मई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 12 लाख 88 हजार किसानों को 1,726 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। 'भूतो न भविष्यति', ऐसी लोक कल्याणकारी सरकार और ऐसा शासन न तो पहले कभी आया है और न भविष्य में कोई ला सकेगा। 3 लाख 27 हजार किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये।

माननीय सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था की बुनियाद होता है रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट। आप भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के राजकोषीय घाटे की भी तुलना करिये तो राजस्थान का राजकोषीय घाटा है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, जब केन्द्र पूरी तरह से असहयोग कर रहा है, जो केन्द्र और राज्य की मिलीजुली योजना है, जिस पर नब्बे-दस का

(श्री संयम लोढ़ा)

रेशो होता था, सत्तर-तीस का रेशो होता था वह सब घटाकर आप पचास-पचास पर ले आये या साठ-चालीस पर ले आये, इसके बाद भी राजस्थान का राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 का है 4.03 परसेंट और भारत सरकार का क्या है? 6.71 परसेंट। मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों, अगर उनके पास इसके अलावा जानकारी हो तो जब वे बोलें तब आप इसका जवाब दे दें।

माननीय सभापति महोदय, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान देखिये। वर्ष 2022-23 में हमने अनुमानित किया 11.56 परसेंट और भारत सरकार ने क्या किया? मात्र 11.00 परसेंट और लोन और अदर जो लायबिलिटीज हैं उसमें जी.एस.डी.पी. का वर्ष 2021-22 के अन्दर हमारी स्थिति 39 परसेंट पर थी और भारत सरकार 59 परसेंट पर थी, तो आप इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जो वित्त मंत्री भी हैं, किस रूप में वित्तीय अनुशासन के साथ में राजस्थान की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ये पहले भी पांच साल मुख्य मंत्री थे, तब भी राजकोषीय घाटा हमेशा तीन परसेंट के नीचे रहा। कभी उन्होंने तीन परसेंट से ऊपर नहीं आने दिया और जैसे ही यहां वसुन्धरा की सरकार आयी 2014 से 2018 तक, पूरा वित्तीय अनुशासन गड़बड़ा गया और राजकोषीय घाटा छलांग मारकर 3 परसेंट से ऊपर चला गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि हमने कालेज तो बहुत से खोल दिये हैं और पढ़ाई की व्यवस्था भी हमने बहुत व्यापक रूप से की है। गांवों में बैठा हुआ किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वह कालेज में पढ़ाता भी है लेकिन लोक कल्याणकारी सरकार को यह सोचना चाहिए कि लाखों की तादाद में डिग्रियां लेकर निकल रहे इन बच्चों का आगे भविष्य क्या है और उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? उसका एक मात्र रास्ता है औद्योगिक विकास और राजस्थान की मौजूदा सरकार ने जो राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट किया 4,192 एम.ओ.यू. साइन किये गये 10 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के और यह पिछली सरकार की तरह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह विनती करना चाहूंगा कि 4,192 में से 2,035 धरातल पर आ चुके हैं और उनके काम शुरू होने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और जो one stop shop system हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लेकर आया, हमारे मुख्य मंत्री ने अनेक नियमों में

(श्री संयम लोढ़ा)

शिथिलता दी और यहां तक कह दिया कि जो राजस्थान के कानून हैं वे तीन साल तक प्रभावहीन किये जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके और one stop shop system की जो तीन मीटिंग्स अभी तक हुई हैं, 4 लाख 34 हजार 788 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान की मौजूदा सरकार लेकर आयी है। पांच हजार से ज्यादा 12वीं तक के स्कूल खोले हैं, 1,700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। पहले वह स्थिति थी कि सरकारी स्कूल को हेय दृष्टि से देखा जाता था और आज गरीब आदमी जो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई देना चाहता है, पैसे नहीं है पर पढ़ाना चाहता है, वह भी यह चाहता है कि उसके बच्चे अधिकारी बनें, आज उन स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लग रही है। माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा ढांचा बदलने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर जो क्रांतिकारी काम हुआ है, देश में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। मुझे याद आता है कि 2008 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन था। प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी भी बैठे हुए थे, उस वक्त राजस्थान की ओर से मुझे बात कहने का मौका दिया गया। वेलांगरी मेरे क्षेत्र का एक गांव है जहां कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत पर मैं शोक व्यक्त करने गया था। वहां पर जाने पर यह मालूम पड़ा कि उसने 12 लाख रुपये कर्जा लिया लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाया। उसका प्रभाव दिमाग पर ऐसा था कि उस ए.आई.सी.सी. के अधिवेशन में मैंने प्रधान मंत्रीजी से यह विनती की कि आप कैंसर और हार्ट जैसी जो बीमारियां हैं इनका सरकार के खर्चे पर इलाज मुफ्त करवाइये।

माननीय सभापति महोदय, तब तो वह हो नहीं सका पर आज राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री की बदौलत, चिरंजीवी योजना की बदौलत पन्द्रह साल पुराना हमारा वह सपना पूरा हो सका कि हम सरकार के खर्चे पर हार्ट, कैंसर, लीवर, किडनी का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा पा रहे हैं और मैं यह चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों का आंकड़ा भी

(श्री संयम लोढ़ा)

यहां पर लाकर रखिये, पूरे देश का भी आंकड़ा लाकर रखिये, कौनसा स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित हैं?

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में मात्र 41 परसेंट लोग इस बीमा से लाभान्वित हैं और राजस्थान की 88 परसेंट जनता चिरंजीवी योजना के माध्यम से लाभान्वित है और जब से यह योजना अनाउंस हुई है, बातें आप चाहे कुछ भी करिये पर गांव में जाकर आप पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस तरीके से इस सरकार को दुआएं दे रहे हैं, अशोक गहलोत को दुआएं दे रहे हैं। 31 लाख 58 हजार लोग इस चिरंजीवी योजना के माध्यम से जिन्होंने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है और 3,625 करोड़ रुपया चिरंजीवी योजना के माध्यम से अशोक गहलोत साहब ने खर्च किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को भी याद करना चाहूंगा कि जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किये थे और यह मेडिकल की सीट्स बढ़ाना, मेडिकल कालेज नये खोलने, नया स्वरूप लेकर आना, यह उनकी देन थी। पाली और बाड़मेर में मेडिकल कालेज खुले तो उस योजना के तहत खुले और उसके बाद अब उसी योजना के तहत मौजूदा सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी मिलकर नये मेडिकल कालेज खोल रही है। आज राजस्थान के 30 जिलों के अन्दर सरकारी मेडिकल कालेज की सुविधा है। इन चार सालों में एम.बी.बी.एस. की सीटें जो 2018 में 1,950 थीं, आज 3,330 हैं, सिर्फ इन चार साल में। आप अन्दाजा लगाइये। खाली इस साल में 400 सीटें बढ़ी हैं और वह क्यों बढ़ी हैं? सिरोही समेत चार मेडिकल कालेज, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, उन्होंने चार नये मेडिकल कालेज शुरू किये। सभापति महोदय, आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से कायाकल्प हुआ है। आप आंकड़े मंगवाकर देखिए। दिसम्बर के अन्दर सरकारी अस्पताल में जो डिलीवरी हुई थी, उनका आप आंकड़ा मंगवाइये। आपको फर्क मालूम पड़ जायेगा कि दोगुनी डिलीवरी सरकारी हास्पिटल्स में होने लग गयीं। वह क्यों? क्योंकि हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने तय किया कि जो आकांक्षी जिले हैं, जो पिछड़े जिले हैं, जहां चिकित्सकों का अभाव रहता है उन जिलों से मैं कार्मिकों को नहीं हटाऊंगा। उन कार्मिकों के रहने की वजह से उन आकांक्षी जिलों के अन्दर इतना उठाव आया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, चाइल्ड आई.सी.यू. 2020 में 665 थे और आज 2022 में 2,110 चाइल्ड आई.सी.यू. हैं। कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस कदर विकास हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को भी विनती करना चाहता हूं। यह सही है कि पेपर लीक में अनुचित साधनों के प्रयोग को लेकर आप सख्त कानून लाये हैं, दस साल की सज़ा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मैं विनती करूंगा कि हत्या के मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान है, उसके बावजूद भी हत्या रुकती नहीं है। कानून के जरिये इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। आप 10वीं की एग्जाम की डिग्री देते हो, आप 12वीं की डिग्री देते हो, आप ग्रेजुएशन की डिग्री देते हो। क्या उनका कोई महत्व नहीं? वह सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी हमारे बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ता है तो आपकी इन डिग्रियों का क्या महत्व है? आप क्यों नहीं सरकारी नौकरियों की भर्तियों के अन्दर उन डिग्रियों के आधार पर जो आपके बोर्ड के द्वारा दी गयी हैं, कोई ऐसा साइन्टिफिक मैकेनिज्म लेकर आते जिससे हमारे बच्चों के आसूं पोंछने का काम हमारी सरकार कर सके।

सभापति महोदय, खेल वास्तव में जादूगर का गेम है। पूरे राजस्थान के गांव-गांव के अन्दर ग्रामीण ओलम्पिक के माध्यम से क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या बहिन, क्या मां, क्या दादी सबको खेल के मैदान में उतार दिया। राजस्थान की हिस्ट्री में ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। हम पढ़ते ही रहते थे कि हरियाणा का खिलाड़ी सरकारी नौकरी में जा रहा है, पंजाब का खिलाड़ी सरकारी नौकरी में जा रहा है। हमारे बच्चे टुकुर-टुकुर देखते रहते। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी और खेल मंत्री अशोक चांदनाजी को जो खुद भी एक स्टार प्लेयर हैं पोलो के, उन्होंने नियमों में बदलाव किया। पहले उसी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिलती थी जिसकी टी-शर्ट के पीछे इण्डिया लिखा होता था, अब जिस खिलाड़ी की टी-शर्ट के पीछे राजस्थान लिखा हुआ है, उसको भी सरकारी नौकरी मिलती है। इन चार सालों में 400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां इस सरकार ने दी हैं।

सभापति महोदय, मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम हर ब्लाक में बना रहे हैं। जयपुर में इन्टरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का बन रहा है। जोधपुर में

(श्री संयम लोढ़ा)

इन्टरनेशनल मैच शुरू हो गये। स्टेडियम का लोकार्पण हो गया। उदयपुर में नया क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है तो खेलों के लिहाज से यह स्वर्णिम काल है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। सबसे कठिन बात मैं बजरी की कहना चाह रहा हूं। खान मंत्रीजी भी आज प्रकट हुए हैं। बजरी प्रति टन 480 रुपये से लेकर 650 रुपये के हिसाब से वसूल किये जा रहे हैं। राजस्थान में आप यह हालात क्यों बनने दे रहे हैं? क्या इसलिए कि वह ठेकेदार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नजदीक हैं? महाराष्ट्र के अन्दर 55 रुपये टन है बजरी। गुजरात के अन्दर 150 रुपये टन है तो राजस्थान में क्या बजरी की फसल खराब हो गयी या बजरी पर पाला पड़ गया या बजरी पर बर्फ गिर गयी कि जिससे बजरी की कमी हो गयी? क्या हाल कर रखे हैं। बिना नम्बर की गाड़ियां, गाड़ियों में बैठे हुए गुण्डे। वह गुण्डे ट्रैक्टर के चालक के साथ मारपीट करते हैं। बजरी छान कर देनी पड़ती है। ट्रैक्टर लेकर भी, रवन्ना लेकर भी अगर वह बजरी लेकर जा रहा है, वह छान कर दे रहा है तो वहां भी हमला। पुलिस संयम लोढ़ा के फोन से तो आये या नहीं आये लेकिन उस बजरी माफिया के कहने से सबसे पहले आती है। इसलिए, कल्ला साहब, मैं आज आपको चेता रहा हूं कि अगर आपने प्रति टन बजरी के दाम नहीं घटाये तो बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैं यह चेतावनी दे रहा हूं। आप देखिये। जितने भी सरकारी काम हैं ठेकेदारों ने काम करने बन्द कर दिये। ठेकेदार हड़ताल पर हैं। कलेक्टर के पास जाकर बीएसआर की रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर यहां चिट्ठी भेज रहा है। यहां से कोई जबाव नहीं जा रहा है। सब काम ग्रामीण क्षेत्र में ठप हैं। सरकारी काम के लिए भी यदि कोई बजरी लेकर जाए तो वह नहीं जा सकता। आपने जिस रेट पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए, बजरी नहीं है, कैसे प्रधानमंत्री आवास बनायेगा? कैसे आंगनबाड़ी केन्द्र बनायेगा? दो हजार रुपये टन में भी लाइसेंसी नहीं आये, तब वही ट्रैक्टर जो सात सौ रुपये में बजरी डालता था, वह अब ढाई हजार रुपये ले रहा एक ट्रैक्टर के। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि 2012 से जो दंगल चल रहा है, पहले तो आपने कलेक्टर को एम्पावर्ड किया था कि वह बजरी की रेट तय कर सकता था लेकिन अब बजरी को क्रेशर की तरह खुले बाजार में छोड़ दिया है। इसलिए इसको आप गम्भीरता से लें।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, आपने इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूं, इससे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो मुख्य मंत्रीजी के सलाहकार हैं, उनको जरूर बधाई देना चाहूंगा कि वह हैलीकोप्टर से लटकने की बात कहा करते थे ट्वीट करके, पर अब हैलीकोप्टर के अन्दर पहुंच गये। उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ किया, वह मुख्य मंत्रीजी की सलाह पर किया। मैं बड़ी गम्भीरता से भाषण सुन रहा था। आप केन्द्र सरकार के बजट की बात कर रहे थे, केन्द्र सरकार की वित्तीय हालत की बात कर रहे थे। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप आरबीआई की 2022 की रिपोर्ट को पढ़ लेते तो ठीक रहता। इस रिपोर्ट ने 10 राज्य जो आज आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुके हैं, उनको चेतावनी दी। उसमें राजस्थान भी एक है। चेतावनी इसलिए दी कि जीएसडीपी का 39.8 प्रतिशत कर्जा जिस राज्य पर हो और जिस राज्य में रेवेन्यू का कुल टैक्स 14.9 परसेंट ब्याज में चला जाए और आरबीआई यह कहे कि आपका कुल जितना राजस्व है, उसका 87 परसेंट आप रेवेन्यू अकाउन्ट में खर्च कर रहे हैं वेतन भत्तों में, पेंशन में, ब्याज में, प्रशासनिक खर्चों में और मात्र 13 परसेंट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि अगर उत्तर दें तो इस आरबीआई की रिपोर्ट 2022 जिसको नेट से मैं लेकर आया हूं, इसको देख लें। 2019 में 03 लाख 39 हजार करोड़ का कर्जा था, आज बढ़ कर 05 लाख करोड़ 59 हजार हो गया। इस पर चर्चा करते तो बड़ा अच्छा लगता।

सभापति महोदय, हम सबको मालूम है कि हम जिस अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, वह सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय से लेकर संवैधानिक परम्परा, मान्यता और कौल एण्ड शकधर ने इसको ऐसा दस्तावेज किया जो सरकार के नीति पत्र के रूप में उल्लेख किया गया।

सभापति महोदय, आपकी उपस्थिति में यहां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषणों के संकलन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का विमोचन हो रहा था तब कहा गया कि यह लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत सरकार के लिए लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ है तो राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान की हुकूमत के लिए महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी धर्म ग्रंथ है। मैंने इस अभिभाषण को जो 63 पृष्ठ और 281 पैराज में है, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले के चार अभिभाषणों को भी पढ़ा और मैं यह कह सकता हूं कि संवैधानिक दस्तावेज की पवित्रता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, आप कहने को कुछ भी कर दें, हम जनता के दरबार में जायेंगे। हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, घोषणा करो और भूल जाओ, यह इनकी आदत रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस अभिभाषण पर चर्चा उस समय कर रहे हैं जब पूरा मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और भारत का परचम इसलिए विश्व में फहरा रहा है कि आज विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की अध्यक्षता हिन्दुस्तान कर रहा है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें यह कहा गया कि भारत लोकतंत्र की जननी है और हमें गर्व है कि हिन्दुस्तान जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और यह बात भी आयी कि जिस ब्रितानिया हुकूमत ने 100 वर्ष से ज्यादा समय तक हमारे मुल्क पर शासन किया, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हिन्दुस्तान इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, नरेन्द्र मोदीजी की अगुवाई में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का एक अल अरेबिया टी.वी. में उनका इंटरव्यू सुना। वह बोल रहे थे कि हिन्दुस्तान से तीन बार युद्ध करके पाकिस्तान ने सबक ले लिया और अब पाकिस्तान अमन-चैन चाहता है। पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग जुलूस निकाल रहे हैं कि मुल्क का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं इसलिए हम हिन्दुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, मैं इसका जिक्र नहीं करता, पर क्या आम आदमी के लिए जो राजस्थान की सात करोड़ जनसंख्या में एक व्यक्ति है, वह हिन्दुस्तान का नागरिक भी है, उसे गौरवान्वित भी नहीं होना चाहिये कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हिन्दुस्तान जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। उसको गर्व नहीं होना चाहिये कि हमारा मुल्क इस दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है। आपसे ज्यादा संविधान का कोई ज्ञाता नहीं। हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल सिस्टम आफ कांस्टीट्यूशन, हम संघवाद पर आधारित हैं। मैं आपका ध्यान अभिभाषण के पृष्ठ 270 पर दिलाना चाहता हूं। इसमें आपने महामहिम के श्रीमुख से कहलवाया है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उसमें 800 राजस्थानी विद्यार्थियों की घर-वापसी में आवासीय आयुक्त की मेहरबानी रही। यह धीरज श्रीवास्तव बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, दुनिया ने नजारा देखा कि दो लड़ते हुए मुल्कों ने युद्ध-विराम इसलिये किया कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि मेरे मुल्क के बच्चे, जो आपके यहां पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 25,600 है, वह सुरक्षित वापस आने चाहिये। इसके लिए आपरेशन तिरंगा चला। अब इस बात का उल्लेख नहीं करके और एक RAS अधिकारी, मुझे कहना नहीं चाहिये, मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहता, इन RAS अधिकारी की पहुंच कहां से कहां है? आप क्या समझते हो, इससे कोई राजनीतिक हित हो जाएगा? युद्ध-विराम उन्होंने दो मुल्कों में करा दिया।

माननीय सभापति महोदय, यहां राजाखेड़ा से आने वाले विद्वान सदस्य बैठे हैं, आप सब लोग मिलकर अपनी इस पार्टी में इस सरकार के गठन के साथ जो युद्ध प्रारम्भ हुआ, उसका विराम कराकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, अंडमान-निकोबार में 21 द्वीप हैं। आप जानते हो शैतान सिंह को, पीरूसिंहजी को, आप शेखावाटी से ताल्लुक रखते हो, आप जानते हो कर्नल होशियार सिंहजी को, तीनों शेखावाटी के हैं। इन तीनों के नाम से द्वीप का नाम रखना, यह छोटी बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, निश्चित तौर पर यह पन्द्रहवीं विधान सभा इसलिए याद की जायेगी कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में पाइंट पांच फीसदी के अन्तर से, यानी सिर्फ 01 लाख 58 हजार मतों का अन्तर हुआ, 200 में से एक आदमी का मन बदला और सरकार चली गयी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहता, पर अभी भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में हम गये तो गांवों के अंदर लोगों ने हमारी शिकायत पट्टिका को भर दिया, इसलिए भर दिया कि सरकार के चलते कोई वर्ग नहीं जो संतुष्ट हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं यह जो फिल्म चली किस्सा कुर्सी का, एक नायक दूसरा खलनायक और इस वृत्त चित्र से कैसे-कैसे शब्द निकले। ''नाकारा'' भी निकला, ''निकम्मा'' भी निकला, ''गद्दार'' भी निकला, ''अनुभवहीन'' भी निकला और ''रगड़ाई'' भी निकली। माननीय सभापति महोदय, आप ''रगड़ाई'' को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सदन में बाकी कोई जाने, न जाने। भादरा से आने वाले कामरेड जरूर जानते हैं। यह ''रगड़ाई'' बड़ा घातक शब्द है। यह राजस्थान की जनता की आदत है कि पीसती है तो बड़ा बारीक पीसती है और इस बार बारीक पिसाई के बाद जब दुबारा सोलहवीं विधान सभा में आयेंगे तो मैं समझता हूं कि वह संख्या कितनी होगी?

माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोरोना आ गया। कोरोना में सबसे पहली बात है, डाक्टर कहता है कि इसको आइसोलेशन में ले जाओ, इसको कोरोना है, किसी से मुलाकात नहीं करनी है। यह अपने दम पर अकेला खड़ा है। यह आइसोलेशन के अंदर सरकार है। इस सरकार का संबंध राजस्थान के आम-अवाम से नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह जीभ वाली बात तो बड़ी खतरनाक बात कह डाली। यह 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। मैं आपको जानता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप जब एस.के. कालेज में थे तब आपने कई-कई बार कहा। ज्यादा बोलते थे न तो कहते थे कि तेरे 32 दांतों के बीच जीभ है न, इसको तू संभाल। अब जीभ के बारे में कह दिया, मैं तो डर गया। यह इशारा किसकी तरफ है? मैंने तो देखा कैसे-कैसे मंजर हैं। माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता गंगानगर में जाकर भाषण देते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य दोनों आये नहीं हैं, श्रम मंत्रीजी, हाथ से हाथ तोड़ो। यह अखबारों में सब चीजें हमने देखीं।

माननीय सभापति महोदय, अभी चिंतन शिविर हुआ। सरकार का चिंतन शिविर होना चाहिये। चिंतन शिविर के बाद मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैंने पढ़ा कि राजस्थान में साम्प्रदायिकता की आग भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है। यह सही है कि राजस्थान आज साम्प्रदायिकता की आग की भट्टी में झुलस रहा है। करौली की घटना हो, जोधपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, भीलवाड़ा की घटना हो। इस प्रकार का स्वभाव राजस्थान का नहीं, उसके स्वभाव के विपरीत इस प्रकार की बात हो रही है और हमारे पर क्या आरोप लगाया? उदयपुर में कन्हैयालाल का सिर कलम हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय कार्य समिति में हैदराबाद में थे, यह हमसे बड़ी गलती हो गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा था, मैं उस मंजर को देखकर आया हूं, भूंगरा की गैस त्रासदी को आंखों से देखा है। 32 लोग उस गैस त्रासदी में काल कवलित हो गये। उनकी चिताओं से जिस दिन धुआं उठ रहा था, माननीय सभापति महोदय, उस दिन अपने बड़े नेता की मिजाजपुर्सी के अंदर अल्बर्ट हॉल के सामने संगीत संध्या के अंदर वही हमारे सदन के नेता, जिनके जिले में यह घटना होती है, वह ताली बजा रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, चिंतन शिविर में उन्होंने कहा अंतिम बजट युवाओं, छात्रों और महिलाओं को समर्पित होगा। जिस दिन उन्होंने यह कहा, एक किस्सा कुर्सी के किरदार ने, अगर मैं कहूं कि फिल्म बड़ी अच्छी थी, पर हीरो फ्लाप हो गया, हो जाता है, माननीय सभापति महोदय, इस फ्लाप हीरो ने क्या-क्या कहा कि यह पेपर माफियाओं के सरगना को सरपरस्ती किसकी है? यह तिजोरी के अंदर से किस जादूगर ने पेपर बाहर निकाल दिया? मैं समझता हूं यह सारी बातें अपने आप में सार्थक हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां अभी सैनिक कल्याण राज्य मंत्री नहीं हैं। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री गणित के बड़े जानकार हैं। अगर मैं उनको प्रदेश का रामानुजन कहूं, रामानुजन वह थे जो गणित के अंदर इस मुल्क के सबसे बड़े विद्वान थे, उनको मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन्होंने क्या बात कही कि 200 में से 99.9 नंबर जो लेकर आये वह तो फेल और 200 नंबर में से 21 नंबर जो लेकर आये वह पास। अब 200 में से 156, यह शेखचिल्ली के हसीन सपने और, माननीय सभापति महोदय, आपको तो मालूम है, यह जो मंत्रिमण्डल है, यह आर्टिकल 164(2) के तहत ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी से बात करता है। कल्ला जी, एक मंत्री बोलता है तो पूरा मंत्रिमण्डल बोलता है। आपके मंत्रीजी ने क्या कहा, हमारे हालात क्या हैं, एक फोर्च्यूनर गाड़ी, उसमें इस बार इतने जीतेंगे कि चारों धाम की यात्रा करके फिर यहां विधान सभा में धोक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगाने आयेंगे। यह मैं नहीं कह रहा। यह वे लोग कह रहे हैं जो आपके मंत्रिमण्डल में बैठते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक प्रमुख समाचार-पत्र भास्कर ने एक सर्वे करवाया। क्योंकि बड़े-बड़े विज्ञापन, चार साल बेमिसाल, तो चार साल बेमिसाल पर भास्कर के सर्वे ने क्या कहा, 33 जिलों के सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान का अवाम, एक-दो नहीं, 57 प्रतिशत लोगों ने यह कहा कि चार साल पूरे के पूरे सरकार के मुखिया के झगड़े में और कुर्सी बचाने में निकले, यह हालात हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, वह कहते हैं न -

'जिक्र तुम्हारा ही होगा महफिल में,

बस तुम्हारा नाम न लूंगा।'

वह हालात राजस्थान में हो रहे हैं।

यह अभी हमारे रसद मंत्री जी चले गये। अधिकारियों की एसीआर लिखेंगे। मुख्य मंत्री जी क्यों लिखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब एसीआर लिखने का काम राजस्थान की जनता के पास आ रहा है। मण्डावा से आने वाली माननीय सदस्या, राजस्थान की जनता जो एसीआर लिखेगी तो मैं समझता हूं कि उसमें डबल जीरो आयेगा। यह एसीआर लिखना और कभी सैनिकों के आरक्षण की बात, कभी सारे आईएएस मिलकर के मंत्री की शिकायत सबसे बड़े अधिकारी के पास जाकर के करें। इस प्रकार का क्या काम है?

सभापति महोदय, अगर सरकार की आलोचना मैं खुद करूं तो आप मुझे कहोगे कि मेरा राजनीतिक स्वार्थ है। आज आपने देखा कि मैं आर्टिकल 226 के तहत मेरे अधिकारों का उपयोग करते हुए जनहित याचिका में चला गया। आज राजस्थान के अंदर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जिस दिन प्रिविलेज आयेगा उस दिन करूंगा। लेकिन कहा कि राजनीतिक स्वार्थ है।

उन नामचीन संस्थाओं ने, उन एजेंसियों ने जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिन्होंने आकलन किया है कि राजस्थान आज किस स्थिति में है। यह सबसे पहला आकलन जो नवम्बर, 2022 में आया। हालांकि मेरी बात न तो कल्ला जी नोट करेंगे, न स्वास्थ्य मंत्री जी नोट करेंगे, लेकिन मैं एक व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो उप मुख्य सचेतक हैं, मैं चाहता था कि सचेतक बने, वह उसी कारखाने से निकले हैं जिस कारखाने से मैं निकला हूं, वह जरूर मेरी बात को लिखेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर काम्पीटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, यह जारी किया आम आदमी से जुड़े हुए 89 मुद्दों पर। राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की क्या हालत है? बिजली की क्या हालत है? सड़क की क्या हालत है? मूलभूत आवश्यकताओं की क्या हालत है? 33 राज्यों में राजस्थान का तीसरा नंबर, 33 राज्यों में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। राजस्थान के माथे पर फिर बीमारू का कलंक लगाने वाले हैं।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कसीदा पढ़ रहे थे। यह सेंटर फोर मानिटरिंग इंडियन इकॉनोमी, सीएमआईई ने दिसम्बर, 2022 में बेरोजगारी की दर 28.5, पूरे मुल्क में हम दूसरे नंबर पर हैं। दिसम्बर, 2018 में जब इन्होंने शासन लिया था, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यही सीएमआईई की रिपोर्ट कह रही थी कि यहां बेरोजगारी दर 14.9 परसेंट थी।

सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में जब यह खबर आयी कि राजस्थान के अंदर ग्रेजुएट लोगों ने जितनों ने आत्महत्या की उसमें राजस्थान एक नंबर पर है। यह मैंने नहीं कहा, यह सामाजिक सूचकांक जारी करने वाली एजेंसी ने कहा।

स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक संस्था है। पहली बार हिन्दुस्तान में हैप्पीनेस इंडेक्स पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। प्रतिपक्ष के नेता, 33 राज्यों में, उसमें भी हम तीसरे नंबर पर हैं। अभी नीति आयोग ने, दिसम्बर, 2021 के मेरे पास आंकड़े हैं, हैल्थ इंडिकेटर में जो रिपोर्ट जारी की, यह बात करते हैं चिरंजीवी की, हैल्थ इंडिकेटर में राजस्थान देश में सोलहवें स्थान पर है।

यह सेंटर फोर सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टर आफ इकॉनोमी एंड स्ट्रेटेजी ने जो 55 इंडिकेटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट जारी की है। 13 इंडिकेटर्स, उसमें से 01 इंडिकेटर्स में भी महिला, बाल सुरक्षा से संबंधित, अपराध से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, एक जिला भी ग्रीन कैटेगरी में नहीं है। इसी प्रकार नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे में राजस्थान 05 वर्ष से हिन्दुस्तान में सबसे कुपोषित बच्चे 51.8 परसेंट यहां पर हैं।

सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार में जीरो टोलरेंस की बात करते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे। लेकिन, कल्ला जी, यह जो रिपोर्ट है ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इसको देखें आप। 2020-21 की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। यह दिसम्बर में जारी हुई। हिन्दुस्तान के अंदर राजस्थान सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। 67 परसेंट लोगों ने कहा कि यहां बिना रिश्वत काम नहीं होता है।

सभापति महोदय, एक और सर्वे हुआ। इंडियन करप्शन सर्वे, 2021, ट्रेप्स, रिश्वत जोखिम दिसम्बर, 2021 में हुई। राजस्थान के 78 परसेंट लोगों ने माना कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। यह भ्रष्टाचार का ताना-बाना है। मैं देख रहा था, आज एक सवाल आया था। हमने बड़े लोगों को रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन आज अभियोजन स्वीकृति के 489 मामले बाकी हैं, 60 कार्मिक विभाग के पास पड़े हैं, 429 विभागाध्यक्ष के पास पड़े हैं। यह कहानी है।

सभापति महोदय, रींगस के अंदर आपके पड़ौस में उस हंसराज बावलिया, एडवोकेट ने क्या गुनाह किया? उसने एसडीएम के भ्रष्टाचार की शिकायत की। सीआई ने कहा कि मुझे शिकायत लिखकर के दो। शिकायत लेकर के आया तो उसकी पिटाई हुई। उसने अपने जीवन को खतम कर लिया। आज अमराराम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बाड़मेर में आरटीआई में सूचना मांग ली। उसको ईसा मसीह बना दिया। दोनों हाथ, दोनों पैरों में कील ठोक दी। यह हालात हैं।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। दर्जनों सदस्यों ने शिक्षा में बदहाली की बात की। सभापति महोदय, असर की रिपोर्ट जारी हुई है। 2018 के बाद असर की रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं एनुअल स्टेट्स आफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें राजस्थान में 62 परसेंट पांचवीं कक्षा का बच्चा, उसका शिक्षा का स्तर दूसरी तक का नहीं है। आठवीं कक्षा तक के 29.5 परसेंट बच्चों का स्तर दूसरी कक्षा तक के बच्चे के बराबर है। 100 अंकों से ज्यादा पहचान करने वाले आठवीं कक्षा में 37.5 परसेंट बच्चे हैं।

शिक्षा मंत्री जी, आप ही के जिले से कहां डंडी पूगल से लोग चलकर मास्टर लगवाने के लिए 110 किलोमीटर चलकर के कलेक्टर के पास बच्चियां आईं। क्या हालात बना रखें हैं आपने? यह जो आधारभूत आवश्यकता थी, आठवीं कक्षा में लाइब्रेरी सिर्फ 36 परसेंट में है। पेयजल सिर्फ 75 परसेंट में है। 25 परसेंट में पानी उपलब्ध नहीं है। टॉयलेट सिर्फ 84 परसेंट में है।

एक बात जो मुख्य मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मीडिया दबाव में है। अब संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। अब मुख्य मंत्री जी का आचरण क्या है? इन्होंने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2020 में मीडिया को एक बात कही कि +++ पंडित हजारी लाल जी को आप जानते हो, दैनिक राष्ट्रदूत, जिन्होंने जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसके एडवर्टाइजमेंट बंद कर रखे थे।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य पर राष्ट्रदूत के एम.डी. राकेश शर्मा प्रेस कौंसिल आफ इंडिया में गये। यह प्रेस कौंसिल आफ इंडिया का 1978 का एक्ट बना हुआ है। प्रेस कौंसिल ने जांच समिति बनाई। जांच समिति के बाद जस्टिस रंजना देसाई ने जो अपना निर्णय दिया, वह मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि मालूम पड़ जाये कि मीडिया पर दबाव की बात कहने वाले मुख्य मंत्री जी का खुद का आचरण कैसा है? "The press Council on consideration of records of the report of the enquiry committee, accepts reason, findings and adopts the report of the committee and decides to express its extreme displeasure about the statement in question made by the chief Minister of Rajasthan Shri Ashok Gehlot and observes that in future such statements may be avoided as it may have adverse impact on the print media in general. The Council disposes of the matter accordingly with aforesaid observations." क्या हालत है? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें कोई एक नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात कानून-व्यवस्था पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने एक झुनझुना खूब बजाया, ओल्ड पेंशन स्कीम। 23 तारीख को राजस्थान के अंदर अब तक इन 4 सालों में सबसे बड़ा प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया। कल्ला जी, 2-3 मांगों को लेकर किया। एक तो जो आपने संविदा नियम, 2022 बनाये थे, उन्होंने कहा कि इनको निरस्त करो, अपने वादे के अनुसार हमें नियमित सेवाओं में लो। दूसरा, 5 लाख 22 हजार कर्मचारियों के धन से जो एनपीएस योजना के अंदर 2004 से, 18 साल हो गये, 2 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के हर एक साल में कटते हैं और इतना ही राज्य अंश, यह सारा पैसा न्यू पेंशन स्कीम में पीएफआरडीए ट्रस्ट में जमा होता है। यह राशि छोटी, मोटी नहीं है। यह 42 हजार करोड़ रुपये हैं। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि 01 अप्रैल, 2022 को हम जब इसको बंद करेंगे तो यह सारी राशि जीएफए अकाउंट में डालेंगे। लाओ, डालो इस अकाउंट में।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक वादा किया, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 2004 से पहले जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आये और जो ओपीएस से वंचित रह गये, ऐसे एक लाख कर्मचारियों को हम इस पेंशन के दायरे में लायेंगे। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी नहीं हूं, मेरी पार्टी भी विरोधी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार रेवड़ी बांटने के लिए, जिस प्रकार से आनन-फानन में फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन बिना देखे यह लेकर के आये हैं, आज इनके जी का जंजाल बन गया है।

सभापति महोदय, डिस्कॉम के 52 हजार, आरएसआरटीसी के 13 हजार, आरटीडीसी के 3,500 और 2,000 से पहले के सरकारी महकमों और विश्वविद्यालय के 35 हजार, यह कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमें भी आप लो। 2004 में जब ये योजना आई तो पूरे हिन्दुस्तान में सारे राज्यों ने तय किया था।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सनसनीखेज बात कहना चाहता हूं। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो पीएफआरडीए ट्रस्ट बना उसके एमओयू पर 2010 के अंदर हस्ताक्षर करने वाले अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत के हस्ताक्षर करने से न्यू पेंशन स्कीम में पीएफआरडीए ट्रस्ट में हमारे कर्मचारियों के पैसों का कंट्रीब्यूशन और राजस्थान सरकार का कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, यह एक्ट है पीएफआरडीए, इसके रूल्स बने हैं 2013 में, यह संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके अंदर जो कर्मचारी है उसका पैसा उसमें 60 प्रतिशत पैसा कर्मचारी सेवा में रहते हुए विथड्रा कर सकता है। एक साथ 25 परसेंट ले सकता है और आज किस बिहाफ पर इन्होंने कह दिया कि 42 हजार करोड़ रुपये हम जीपीएफ में जमा कराएंगे? कर्मचारियों का 01 अप्रैल, 2022 से जीपीएफ कटना चालू हो गया, जीपीएफ का अकाउंट उनको नहीं मिला, कर्मचारियों की आईडी से कट रहा है, आईडी से जमा हो रहा है। क्या सरकार अपने संसाधनों से उसको जमा कराएगी? 01 अप्रैल, को राजस्थान के वित्त सचिव लिखते हैं केन्द्रीय वित्त सचिव को कि हमने 01 अप्रैल, 2022 से न्यू पेंशन स्कीम बंद कर दी है, हमारा जो पैसा पीएफआरडीए फंड में है 39 हजार करोड़ रुपये था उस वक्त, यह कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराओ। 02 मई को केन्द्र सरकार जवाब देती है कि ये रूल्स बने हुए हैं 2015 के, एक्ट बना है 2013 का, ये रेवेन्यू रिसीट्स

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में जमा नहीं होगा। यह मामला लोक सभा में गया, लोक सभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कहा, पीएफआरडीए फंड की राशि राज्य सरकार को पीएफआरडीए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लौटाई नहीं जा सकती, क्योंकि 18 सितम्बर, 2013 को इस एक्ट को लोक सभा और राज्य सभा ने पारित किया।

माननीय सभापति महोदय, अब यक्ष प्रश्न यह है कि ये राशि कब और कहां जाएगी? कौन जिम्मेदार है इसका? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद कोढ़ में खाज देखो आप, 6 परिपत्र जारी कर दिए। पहला परिपत्र जारी किया 19 मई, 2022 को, एनपीएस बंद हो चुकी है, ओपीएस लागू हो चुकी है इसलिए 01 अप्रैल के बाद पीएफआरडीए फंड से जिन कर्मचारियों ने पैसा 25 परसेंट विथड्रा किया है, इस तरह के एक-दो नहीं, अस्सी हजार कर्मचारी हैं, वो पैसा 31 दिसम्बर तक चार किस्तों में चुकाओ। क्या परिपत्र जारी किया! 18 अगस्त को जारी कर दिया कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यू पेंशन स्कीम में देय सुविधा में पीएफआरडीए फंड से राशि वापस निकाल ली तो ओपीएस से बाहर हो जाएंगे। एक परिपत्र यह जारी कर दिया, 01 अप्रैल, 2022 से अगर कोई सेवानिवृत्त हो गया, ओपीएस का लाभ लेना चाहता है तो सारा पैसा मय ब्याज जमा करायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एफआरबीएम एक्ट 2022-23 के पृष्ठ 4 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि 2020-21 में 6 हजार 283 हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स थी जिसमें 22 हजार 439 पेंशन पर खर्च यानी 37.2 परसेंट, 2022 में 30.9 परसेंट, ये सारे बता रहे हैं कि पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। इस प्रकार की तर्ज पर राजस्थान की सरकार चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा के बाहर आज संविदाकर्मी धरने पर बैठे हैं। इन संविदाकर्मियों से आपने क्यों वादा किया था, वोट की फसल काटने के लिए जन-घोषणा पत्र के पृष्ठ 15 के पैरा 10 में और आपने 17 जनवरी, 2019 को महामहिम राज्यपाल महोदय के पहले अभिभाषण में यह कहा कि सरकारी महकमों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, सरकारी विश्वविद्यालयों और उपक्रमों में 03 लाख 60 हजार संविदाकर्मियों को नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वेतन-भत्ते, परिलब्धियां, पेंशन हम देंगे, दे दो, दे रहे हैं न?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कल्लाजी, आपके खिलाफ तो इस बार बड़ा षड्यंत्र हुआ। दो कमेटियों का चेयरमैन आपको बनाया। एक तो किसानों का कर्जा कामर्शियल बैंक और शिड्यूल्ड बैंक से माफ करवाने वाले मामले में, वहां आप मारे गए और कर्मचारियों वाले मामले में बनाया। कर्मचारियों वाली जो कमेटी थी, 01 जनवरी 2019 को आप अध्यक्ष नहीं बने संविदा वाली कमेटी के, आपने क्या किया, 3 साल बाद 11 जनवरी, 2022 को राजस्थान कोंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 निकाले, 3 लाख 60 हजार संविदाकर्मी सड़क पर उतर आए क्योंकि आपने संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के नाम पर पुन: संविदा में रखने का प्रावधान कर दिया और उनके सारे पुराने एक्सपियरेंस को जीरो कर दिया। उनके वेतन को बढ़ाने का काम मैं देख रहा था, शिक्षा कर्मी को प्रारम्भिक वेतन 10 हजार 400 और 9 साल बाद शिक्षा सहायक और वेतन 18 हजार, ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपने 05 साल तक तो रिपोर्ट ही नहीं दी। हमने कम से कम कुछ किया तो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमने आपकी तरह वोट की फसल काटने के लिए वादा नहीं किया ...(व्यवधान) कल्लाजी, आपको ध्यान होगा, आर्टिकल 21 में समानता का अधिकार दिया है। उमा देवी बनाम स्टेट आफ कर्नाटक का मामला आपके सामने है, आप समान काम लेंगे तो समान वेतन आपको देना पड़ेगा। आपने इन संविदाकर्मियों के साथ जो धोखा किया, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में न उनको दुर्घटना बीमा है, न आरजीएचएस का लाभ है, न ओल्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, वो चले गए, मुख्य मंत्रीजी के स्वयंभू सलाहकार, मुख्य मंत्रीजी सलाह नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों से छेड़छाड़ मत करो, मैं तो उड़ते हुए हेलिकॉप्टर के साथ लटका हुआ हूं। मैं समझता हूं कि उनकी बात तो आपको निश्चित तौर पर माननी चाहिए, इस प्रकार की बात भी मैं आपके सामने रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अब आपने किया क्या? वोट लेने हैं, क्या-क्या हथकंडे अपनाए! स्मार्ट फोन, सरकारी धन से चुनाव की वैतरणी पार करने की योजना, 2022-23 के बजट पैरा 114 में चिरंजीवी परिवार की 01 करोड़ 35 लाख मुखिया महिलाओं को हम स्मार्ट फोन देंगे।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहां दिए? कहां दिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं दिए न? ये है।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहां दिए? जबरदस्ती ठोक रहे हो यहां।

श्री सभापति: विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इसको कहते हैं जागरूक मंत्री। नहीं दिया न, बजट की घोषणा में था।

माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा था 12 हजार करोड़ रुपये इनका बजट मुझे कहीं नहीं दिखा। स्मार्ट फोन में जो डेटा बैकअप था, 18 बार मुख्य मंत्रीजी की फोटो, वो वजीर-ए-खजाना हैं, कुछ भी करें।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने और क्या किया, 17 हजार डिजिटल सखी बनाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा समय समाप्त नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, एक रिसर्च है, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस, लिख लो कल्ला जी। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसकी जून, 2021 में रिपोर्ट आई, राजस्थान में 77 परसेंट लोगों ने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना है वो उपयोगी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे, 82 हजार 295 लोगों को आपने नामजद कर लिया, नाम लिख लिया उनका, न उनको मानदेय दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए कार्यकर्ता तैयार करने के लिए राजस्थान की सरकार जो खेल खेल रही है, राजीव गांधी के नाम से इन्होंने बजट 2021-22 के पैरा 57 में घोषणा की कि सरकार की कथित कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचाने के लिए 2,500 'राजीव गांधी युवा मित्र' बनाएंगे और इनका मानदेय रखते हैं 32 हजार और 50 हजार राजीव गांधी वालेंटियर, मानदेय रख दिया 17 हजार 500 रुपये, यानी हिडन एजेंडा, सरकार का लूटो माल। इसी तरह से आपने पुलिस मित्र बनाए, राजस्थान के अंदर 42 हजार पुलिस मित्र बनाए हैं आपने, आइडेंटिटी कार्ड दे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिया, दलाल छोड़ दिए गांवों के अंदर, जो पुलिस की लाइजनिंग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार नगर मित्र बनाए आपने। आपने 10 लाख पट्टे देने की बात की, पर उसके बाद कृषि भूमि, मंदिर भूमि, सिवायचक में फार्म भरने के नाम पर इनको मोटी फीस देने का काम कर दिया और अभी स्कूली बच्चों के साथ क्या किया आपने?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अभी मेरा टाइम है।

माननीय सभापति महोदय, 64 हजार 906 विद्यालयों में पढ़ने वाले 90 लाख 52 हजार 404 मासूम बालकों को आपने 12 फ्लॉप हो चुकी फ्लैगशिप योजनाओं के कैलेंडर लेकर घर जाने के लिए कह दिया। 16 करोड़ रुपये लुटा दिए। 90 लाख विद्यार्थियों में से 67 लाख विद्यार्थी वो हैं पांचवीं से आठवीं कक्षा तक का, फरवरी, 2021 की घोषणा, नि:शुल्क 2 ड्रेस, नि:शुल्क पूरी पाठ्यपुस्तकें, आज यह सब हवा-हवाई हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं किसान के कर्जे को लेकर आपने जो बात कही, आपने वन टाइम सैटलमेंट की बात कही। मैं समझता हूं कि, कल्लाजी, वो कमेटी कहां अल्ला के पास चली गई। राजस्थान का किसान आपको माफ नहीं करेगा, 12 लाख किसानों के साथ आपने धोखा किया, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चालू होकर, उनके लिए एक तरफ तो खुद आप कहते हो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 26 में 5 एकड़ तक की भूमि कुर्की से मुक्त होगी। दूसरी तरफ इसी सदन में हमारे अध्यक्ष, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहते हो, 2019 से 2022 तक किसान की जमीन कर्ज के नाम पर कुर्क और नीलाम करने के 22 हजार 215 प्रकरण आए, 18 हजार 817 किसानों को नोटिस देकर भूमि नीलाम कर दी। मैं समझता हूं कि ये छुपने वाली बातें नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहूं क्योंकि आप मुझे टोक रहे हैं। बिजली को लेकर जिस प्रकार इन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार किया, बिजली में आत्मनिर्भर होने की बात आपने कही, बिजली के अंदर आपने कहा कि 16 जिलों में किसान को दो ब्लाक में बिजली दे रहे हैं बाकी 16 जिलों के लिए कहा कि हम 01 अप्रैल, 2023 से देंगे। मैं समझता हूं कि 9 बार आपने फ्यूल चार्ज बढ़ाया है। फ्यूल चार्ज, जो भारतीय जनता पार्टी के समय 18 पैसे प्रति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यूनिट था, आपका औसत निकालें तो वह 59 पैसे प्रति यूनिट है। आपकी कृषि वितरण विद्युत कम्पनी कहां खो गयी? वह एग्रीकॉम कहां चली गयी? किसानों के लिए बना रहे थे। टर्नकी प्रोजेक्ट के नाम पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, टर्नकी प्रोजेक्ट के नाम पर आपने सीधा 1,600 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। 2,300 करोड़ के टेंडर 3,900 करोड़ के हो गये।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने इसकी निविदा 6 बार बढ़ायी है। यह संस्थागत भ्रष्टाचार इस सरकार को लेकर बैठ जाएगा।

कहने को मेरे पास और भी बहुत कुछ था। कानून-व्यवस्था की दहशतगर्दी से आम आदमी त्रस्त है। आज गैंगस्टर पनप गये हैं। राजस्थान की राजधानी में धांय-धांय करके गोलियां चल रही हैं। सरकार न जाने कौन-से डर से कुछ बोल नहीं रही है।

इस मीरा की धरती पर, पन्नाधाय की धरती पर तीन बार लगातार, 2019, 2020, 2021 में दुष्कर्म में पहला नम्बर लाकर हमें कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपको धन्यवाद देते हुए इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अनिल कुमार शर्मा।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की पूरी जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिसने मुझे इस सदन में आने एवं आप सभी के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया।

हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री एवं जननायक माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में गत चार सालों में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। जनसेवा को समर्पित विगत चार वर्षों में हमारी लोकप्रिय सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, बुनियादी विकास, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है। इसके लिए मैं

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। विकास का यह क्रम निरन्तर जारी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ यह कहा जा सकता कि आने वाले समय में राजस्थान विकास के सभी पैमानों पर अव्वल होगा।

राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिन्ता हमारी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह निरन्तर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि महंगाई के इस जमाने में आम आदमी को बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च की चिन्ता से मुक्ति दे। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने गरीबों को मुफ्त दवा एवं जांच की सुविधा दी। हमारी लोकप्रिय सरकार ने इस बार एक क्रान्तिकारी पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के हर नागरिक को दस लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है। इस बीमा पालिसी के तहत करीब 1750 अस्पताल पंजीकृत हैं।

इसी क्रम में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सरदारशहर कस्बे में सौ बेड का अस्पताल चालू हो गया है। साथ ही सरदारशहर कस्बे के उप-जिला चिकित्सालय का नामकरण मेरे पूज्य पिताजी एवं दिवंगत विधायक पं. भंवरलाल जी शर्मा के नाम से किया गया है। इसके लिए मैं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही कस्बे के ताल मैदान स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा वितरण केन्द्र (डीडीसी) खोले जाने की मांग करता हूं। यहां पर रोजाना औसतन 1200-1500 के बीच की ओपीडी है। दवा वितरण केन्द्र खोले जाने से स्थानीय जनता को सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी लोकप्रिय सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच सुगम बनाने के लिए वर्ष 2022-23 में कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनमें 61 कन्या महाविद्यालय एवं 29 कृषि महाविद्यालय हैं। हमारी सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कुल 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनमें से 94 कन्या महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में सरदारशहर में भी नवीन कन्या राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की गयी है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहूंगा।

राजस्थान विषम भौगोलिक स्थितियों वाला प्रदेश है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहां किसान, पशुपालक एवं आमजन की चिन्ताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इन वर्गों के प्रति सदैव मानवीय दृष्टिकोण रखा है। ओलावृष्टि, बाढ़ और सूखे के कारण फसल खराबे से प्रभावित किसानों के लिए कृषि अनुदान हेतु वर्ष 2022-23 में 815 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आबंटित किया जा चुका है। गत दिनों सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में हुई बारिश, ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए मैं हमारी सरकार से मुआवजे की मांग करता हूं। साथ ही, क्षेत्र में गिरदावरी करवाकर किसानों को जल्द से जल्द सहायता प्राप्त हो, यह भी मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं।

हमारी लोकप्रिय सरकार ने सड़कों के विकास में भी नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, जिनमें नवीन सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, राज्य राजमार्ग का विकास, ग्रामीण सड़कों का विकास, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण इत्यादि शामिल है। इसी क्रम में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हुडेरा से बाडा की ढाणी तक 32.5 किलोमीटर की सड़क, जिसकी लागत लगभग 33 करोड़ रुपये है, का काम प्रगति पर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही, सरदारशहर क्षेत्र के लिए दस करोड़ रुपये मिसिंग लिंक की सड़कों के लिए स्वीकृत हुए हैं उनका भी निर्माण कार्य चालू है।

सरदारशहर से चूरू वाया उदासर सड़क की मांग काफी लम्बे समय से थी। इसकी लागत लगभग 52 करोड़ की है, इसका भी काम प्रगति पर है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

हमारी लोकप्रिय राज्य सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया और 01 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त राजकीय कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना के स्थान

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

पर पुरानी पेंशन योजना लागू की ताकि कर्मचारी अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन भविष्य की चिन्ताओं से दूर रहकर समर्पित भाव से कर सके। इसके लिए भी मैं समस्त राजकीय कर्मचारियों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

हमारी जनकल्याणकारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में नये-नये कीर्तिमान बनाये हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 25 हजार कृषि कनेक्शंस हैं, आगामी मार्च तक 4 हजार कृषि कनेक्शंस और दिये जाने हैं। कृषि कनेक्शंस की संख्या पूरे जिले में सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, इस कारण वहां स्थिति गम्भीर होने की सम्भावना है। इस समस्या के समाधान हेतु मैं क्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए ग्रिड सब-स्टेशंस के ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाये जाने की मांग करता हूं। पातलीसर 132 ग्रिड सब-स्टेशन को 220 केवी में क्रमोन्नत करने और 120 केवी ग्रिड दल्लूसर और घड़सीसर में बनाये जाने की मांग करता हूं।

साथ ही, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सरदारशहर तहसील के 58 गांवों में काटे गये रकबों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जोड़े जाने का निवेदन करना चाहता हूं। सरदारशहर में नवीन उपपरिवहन कार्यालय तथा सदर थाना स्वीकृत किये जाने की मैं सरकार से मांग करता हूं। सरदारशहर नगरपालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किये जाने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष की माननीय सदस्या को मैं सुन रहा था, अभिभाषण के शब्दों को वे शुगर कोटेड बता रही थीं। मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण के सिर्फ शब्द ही शुगर कोटेड नहीं थे बल्कि हमारी सरकार ने आमजन के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए आमजन के दिल और जीवन में मिठास घोलने का इन चार सालों में काम किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, 1993 से लगातार एक परम्परा चली आ रही है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): इस परम्परा की आशा को पाले हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं सुन रहा था। कोई कह रहा था, मैटाडोर में आ जाएं, उतने सदस्य आएंगे, कोई कह रहा था, फार्च्यूनर में आ जाएं, उतने सदस्य आएंगे, कोई ऑटो के लिए कह रहा था। निश्चित रूप से यह आशा आप रख सकते हैं। आज सरकार को चार साल हो गये। चार साल में जनता की भावनाएं धरातल पर आ जाती हैं कि सरकार के प्रति उसका क्या रुख है। माननीय सभापति जी, आप सबके, पूरे सदन के सामने है कि अभी सरदारशहर में विधान सभा उप चुनाव हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें आप। एक मिनट विराजिये आप।

माननीय सदस्य, आप इंटरवीन कर रहे हैं तो मैं आपके समय में कटौती करूंगा। कितने लोग बोलने वाले हैं और लास्ट में जो बैठे रहते हैं बोलने के लिए और वे बोल नहीं पाते हैं। आपने सदन को मजाक बना रखा है। आप अपने-अपने स्थान पर जाइए। सीमा से बाहर कर दिया सारा। (व्यवधान) विराजिये, आप। बैठिये-बैठिये। हर वक्त खड़े होकर बीच-बीच में इंटरवीन करते हो। यह समय मैं लिख रहा हूं और आपके माननीय सदस्यों के समय में मैं कटौती करूंगा।

माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें और इधर आसन की तरफ देखें।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अभी इस उप चुनाव में प्रतिपक्ष के माननीय नेतागण, माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब जिनका मेरे विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पैतृक निवास है, आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का शीर्ष पार्टी नेतृत्व और केन्द्र के मंत्री, सांसदगण तथा आरएलपी से माननीय नारायण जी बेनीवाल और तीनों माननीय सदस्य, सारे चुनाव में थे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अनिल कुमार शर्मा (सरदारशहर): इन्होंने जनता के सामने सारी बातें रखीं। मैं एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय, जनता इनकी बातों से गुमराह नहीं हुई और चार साल के सरकार के कार्यकाल में जनता की जो सेवा की, योजनाएं थीं उन पर अपनी मोहर लगाकर पिछले आम चुनाव में पण्डित जी 17 हजार वोटों से जीते थे और जनता ने 27 हजार वोटों से जिताकर मुझे इस सदन में भेजा इसलिए आप

(श्री अनिल कुमार शर्मा)

किसी मुगालते में नहीं रहें। जो आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो, सरदारशहर की जनता ने पूरे प्रदेश की भावना का आक्रोश आपमें व्यक्त किया है इसलिए आप किसी मुगालते में नहीं रहें। इन सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बल पर आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार दुबारा कांग्रेस की बनने वाली है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अनिल जी, वह तो श्रद्धांजलि थी। वह तो पण्डित भंवर लाल जी को श्रद्धांजलि थी, अबकी बार आना बताएंगे आपको।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के जितने लोगों ने इस अभिभाषण पर बोला है, किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो कुछ अभिभाषण में लिखा है, क्या धरातल पर वह हूबहू परिणीत हुआ है या नहीं हुआ है? हर वर्ष बजट सत्र से पहले माननीय महामहिम का अभिभाषण होता है।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं वर्ष 2019 का अभिभाषण पढ़ रही थी, 2020 का अभिभाषण पढ़ा, 2021 का पढ़ा, 2022 का पढ़ा और अब यह 2023 का पढ़ा। माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, हर अभिभाषण में महामहिम के द्वारा यह बात कहलवायी गई कि हम विद्युत के क्षेत्र में सरप्लस हो गये हैं, आत्मनिर्भर हो गये हैं और अब बिजली उत्पादन हमारा इतना अधिक हो गया है कि हमें अब किसी दूसरे से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे उप नेता महोदय ने कहा कि बिजली के लिए किस तरह से कोयले का कृत्रिम संकट उत्पन्न करके हम कैसे प्राइवेट कम्पनियों से अधिक मूल्य पर बिजली खरीदें ताकि कमीशन के रूप में जो राशि आये वह आधी मेरी जेब में भी आ जाए। उस वजह से इस भ्रष्टाचार के कारण से राजस्थान प्रदेश की सात करोड़ जनता, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता के ऊपर वह मार पड़ रही है और लगभग 7 रुपये पर यूनिट तक

(श्रीमती अनिता भदेल)

का बिजली का सरचार्ज इस जनता ने चुकाया है तो जब आप सरकार में आने वाले थे तब तो आपने वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरचार्ज के तौर पर इतने अधिक बिजली के दाम बढ़ाये हैं कि आज जनता को बिजली के तारों में करंट नहीं मिल रहा, बिजली के बिलों में करंट मिल रहा है और वह पूछ रही है कि कहां है इस सरकार के नुमाइंदे, जरा आकर के तो बताएं कि तार में करंट आ रहा है या बिजली के बिल में करंट आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कम और केन्द्र सरकार पर ज्यादा चर्चा कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस परम्परा से वे आते हैं, कांग्रेस परम्परा से वे आते हैं जिनके नेता नेशनल हैराल्ड केस में जमानत पर छूटे हैं। वे ईमानदारी की बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपनी संस्था को चूना लगा दिया, अपनी संस्था में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। उनकी जनता, उनके फालोअर उनसे क्या सीखेंगे, यह तो वह जानें लेकिन हम जिस परम्परा से आते हैं वह दीनदयाल उपाध्याय जी की परम्परा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी की परम्परा है और जहां से नरेन्द्र मोदी जी आते हैं, उन्होंने सीखा है उस परम्परा से कि कैसे जनता को जवाब देना है, कैसे सेवक बनकर काम करना है। यही कारण है कि आजादी के 70-75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जिस देश ने इस भारत पर शासन किया, उस देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। यही नरेन्द्र मोदी जी थे जिनकी वजह से 200 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लग पाया। यदि मोदी जी नहीं होते तो कल्पना कर सकते हैं कि आज तक भी मुंह पर पट्टी लगाकर घर से बाहर निकलना पड़ता जैसे चाइना जो इतनी बड़ी इकॉनोमी का देश है, आज भी वहां पर कोविड के कारण से परेशानी है और उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। यही कारण है कि कोविड पर हमने विजय प्राप्त की और इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी होकर आज बहुत गति से दौड़ रही है।

इस अभिभाषण के पेज नम्बर 10 के पैरा नम्बर 11 में बहुत साफगोई से लिखा हुआ है कि राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ दहाई में 11.04 प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की जीडीपी की ग्रोथ जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

आई है वह इसीलिए आई है क्योंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों के कारण से यह राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ इतनी अधिक है। इस कारण से है कि उन्होंने आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना पैसा दिया है, आज राजस्थान में जितने नेशनल हाईवेज देखते हैं, आज राजस्थान में जितने एयरपोर्ट्स देखते हैं, आज राजस्थान में जितनी रेल की कनेक्टिविटी देखते हैं, आज राजस्थान में हम जितने व्हीकल्स देखते हैं, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि जिस जर्मनी और जापान को टू-व्हीलर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता था कि टू-व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स यदि कहीं से लेना है तो जर्मनी और जापान की कम्पनी का लेना चाहिए और वे पूरी दुनिया में अपने को बूम करते थे, लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यही नरेन्द्र मोदी जी का शासन है और इन्हीं नरेन्द्र मोदी जी के कारण से आज आटोमोबाइल हब में हम जापान को पछाड़ कर आगे निकल गये हैं। यह है नरेन्द्र मोदी जी की ताकत, यह है देश की ताकत।

अभी हाल ही में हमने 26 जनवरी का पर्व मनाया है। नरेन्द्र मोदी जी की आत्मनिर्भर योजना के कारण से, आत्मनिर्भर भारत के कारण से आज हम इस देश के निर्यात को बढ़ा पाये हैं और आयात को हमने कम किया है और यही वजह है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जी ही कारण हैं कि आज देश की दुनिया में जो साख बनी है, जिसकी बात को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत गौर से सुना जाता है न केवल गौर से सुना जाता है बल्कि जी-20 जैसे महत्वपूर्ण देशों की अध्यक्षता यदि किसी को मिली है तो वह भारत को मिली है और यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी जी इसके कारण हैं। हमारे साथ एक देश और आजाद हुआ था और कांग्रेस की नीतियों के कारण से हमारे देश के टुकड़े हुए थे।

कांग्रेस के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने कश्मीर में जाकर के क्या स्टेटमेंट दिया है, हम यदि सत्ता में आयेंगे तो धारा 370 वापस हूबहू लागू करेंगे। आप कौनसे सपने देख रहे हो? धारा 370 लगाना अब आपके हाथ की बात नहीं है, राज्य सभा और लोक सभा में जब तक दो तिहाई बहुमत नहीं मिल जाता। अब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। जैसे नेहरू जी ने मनमर्जी करके थोपा था, भारत के टुकड़े करने की कोशिश की थी। कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की थी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अब भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। लाल चौक पर इतनी आसानी से जो तिरंगा फहराया है, यह नरेन्द्र मोदीजी के कारण ही सम्भव हो पाया है, नहीं तो नहीं होता सम्भव। आतंकवाद के कारण से वहां जाने से लोग डरते थे, लाल चौक पर कैसा वातावरण हुआ करता था। अब आप लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हो तो यह नरेन्द्र मोदी जी की वजह से फहरा रहे हो। इसलिए इस बात को मत भूलो। मैं इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूं, पर मैं इतना कहना चाहती हूं कि मोदीजी की वजह से आप ये सोचें कि हमारे देश को कितना बड़ा मान-सम्मान देश दुनिया में मिला है। इसीलिए मोदीजी के कारण से ही हमने अपने देश की पहचान बहुत अच्छे से बनाई है और उन्होंने हमारे देश को आगे ले जाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं राजस्थान की बात पर आ जाती हूं, क्योंकि उनकी बातों का जवाब देना बहुत जरूरी था। हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है? सबसे पहले हम कानून व्यवस्था की बात कर लें। कानून व्यवस्था में हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? प्रदेश में व्यापक जंगलराज है, कुशासन है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसकी जो मर्जी आए वह करे क्योंकि 200 में से जो कांग्रेस के सदस्य चुनकर आये हैं, वे कांग्रेस के सदस्य अपने आप में मुख्य मंत्री हैं। कौन-सा एस.पी. लगेगा, कौन-सा डीवाई.एस.पी. लगेगा, कौन-सा सी.आई. लगेगा, वह कितना भ्रष्ट है, काम करने में एफिशिएंट है या नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, पर मेरा हुक्म कितना बजाता है, उस पर उसकी मेरिट निश्चित होती है और उस हुक्म की वजह से राजस्थान में जंगलराज है।

अभी माननीय उप नेता चर्चा कर रहे थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीनों सालों से भ्रष्टाचार में राजस्थान देश में नम्बर एक है। आप ये जितनी भी योजनाएं लाये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम 10 लाख पट्टे देंगे। माननीय सभापति महोदय, वहां फील्ड में जाकर देखिये, बिना सेवा के फाइल खिसकती नहीं है। पट्टा देने में इतना करप्शन है कि जितनी भी सरकारी भूमियां हैं, जो खाली पड़ी हैं, माननीय मंत्री महोदय, उन खाली पड़ी भूमियों पर भी पट्टा देने का काम करोड़ों के खेल के द्वारा हुआ है लेकिन वास्तव में जो गरीब आदमी भूमि पर काबिज है, वह पट्टे के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसको पट्टा नहीं मिल रहा है। आप कुछ भी कर लें पर आपका यह 10 लाख का टारगेट पूरा होने वाला नहीं है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसी प्रकार से फर्टिलाइजर स्कैम है। माननीय सभापति महोदय, आप देखिये कि किस तरह से करप्शन के रास्ते कहां से निकाले जाएं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए कैसे फर्टिलाइजर की कमी, हमने जान-बूझकर केन्द्र सरकार को आर्डर नहीं दिया कि हमें कितना फर्टिलाइजर चाहिए। आपने समय पर पेपर नहीं भेजा और पेपर नहीं भेजने की वजह से ही आपको समय पर जितना फर्टिलाइजर चाहिए था, उतना आपको मिला और आपने किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दिया, किसान ब्लैक में दुगुनी रेट में फर्टिलाइजर लेने को मजबूर हुए।

माननीय सभापति महोदय, साम्प्रदायिक दंगों की यदि मैं बात करूं तो मुझे शर्म आती है। जब भी कोई सरकार चुनकर आती है तो वह सबकी सरकार होती है, किसी वर्ग विशेष की सरकार नहीं होती है। लेकिन हमारे मंत्री खुद यह आर्डर निकालें कि रमजान का महीना चल रहा है इसलिए उन अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बिजली की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए और नवरात्रा चल रहा है, लेकिन नवरात्राओं में हिन्दू बहुल क्षेत्रों में बिजली की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कभी सरकारों के ऐसे आर्डर निकलते देखे हैं? यह पहली बार है कि सरकार ने ऐसे आदेश निकाले हैं। उस वजह से जो बदमाश हैं, जो शातिर हैं, जो हमेशा ही साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं, जिनको साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं भाता है वे हमेशा इस प्रकार की घटना कारित करते हैं और समाज को नरक में धकेलने का काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर की घटना किसी से छिपी नहीं है। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस प्रकार की घटनाओं से आम आदमी बहुत दर्द महसूस करता है कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, क्या वे जाकर के इस प्रकार से जात-पात करेंगे क्या? हमने जिन लोगों को चुनकर के भेजा, क्या वे इस प्रकार से भेदभाव करेंगे क्या? इसलिए आज आमजन बहुत परेशान है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुझे 12 मिनट बोलने के लिए मेरे सचेतक महोदय ने कहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, दो-तीन मिनट और मुझे दे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं समाप्त कर रही हूं। आप चाहेंगे तो मैं समाप्त कर देती हूं, पर मैं निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्य को कहें कि वे निर्देश मानें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, आप विराजिए। आसन पैरों पर, आप विराजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंकित नहीं होगा। 45 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी के माननीय सदस्य रह जायेंगे। आपके पास आपकी लिस्ट है, यह मेरी लिस्ट नहीं है। कृपया, सभी माननीय सदस्य सहयोग करें। श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, 63 पृष्ठ एवं 281 बिन्दुओं का महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सत्य और तथ्यों पर आधारित है। यह दस्तावेज वह दस्तावेज है, राजस्थान सरकार ने 4 साल तक जो शानदार काम किये हैं, उनका वर्णन है, उनका चित्रण है। इस अभिभाषण के पक्ष में मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब पिछला बजट इस हाउस में पढ़ा था, जब पुरानी पेंशन योजना का बिन्दु उन्होंने पढ़ा तो वह चित्रण अब भी हम सबकी आंखों में है। उन्होंने जब वह पढ़ा तो मेरे जो विपक्ष के साथी हैं, उनके चेहरे पर ऐसा था जैसे कोई वज्रपात हो गया हो। ओल्ड पेंशन स्कीम, एक बहुत बड़ी ऐसी योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विजन ने दी। यहां का कर्मचारी वर्ग जो सोशल सिक्योरिटी के कारण से पीड़ित था, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अपने रिटायरमेंट के बाद नजर नहीं आ रही थी, वे सब के सब इससे प्रभावित हुए हैं और वे सब कांग्रेस के पक्ष में हैं। न केवल खुद पक्ष में हैं बल्कि जहां भी उनको मौका मिलता है अपने आचरण नियमों का पालन करते हुए, वे वहां इस सरकार के लिए सकारात्मक बात करते हैं।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

स्वास्थ्य की बात मेरे साथियों ने कह दी, इसलिए मैं बार-बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन देश के सभी राज्यों से आप तुलना कर लें राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो स्वास्थ्य योजना दी है वह अतुलनीय है।

सड़कों का जाल, शहरी रोजगार योजना, जगह-जगह कृषि महाविद्यालय और दूसरे सामान्य महाविद्यालय उन्होंने दिये हैं। वे ही तो प्रगति के सूचक हैं, वे ही विकास के इंडेक्स हैं। उनको झुठला नहीं सकते हैं। सत्य को झुठलाने से सत्य असत्य नहीं हो जाता।

अनुसूचित जाति, जनजाति, ई.डब्ल्यू.एस., दिव्यांगों के कल्याण के लिए इन चार सालों में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो कार्य किये हैं, मैं उन कार्यों का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं।

अभी अजमेर से आने वाली हमारी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि आटो इंडस्ट्री में माननीय मोदीजी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं यहां हाउस में निवेदन करना चाहता हूं कि ये आटो इंडस्ट्री ही है जिसने सबसे ज्यादा रिट्रेंचमेंट किया है और जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की लाइन में लगे हैं, ये वही लोग थे जो आटो इंडस्ट्रीज में काम करते थे।

माननीय सभापति महोदय, आप किसी भी चीज को समग्र रूप से नहीं देखें और इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हों तो माइक्रो रूप से आप उसको परख सकते हैं। विधान सभा क्षेत्र 200 हैं। मैं एक विधान सभा क्षेत्र का, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का वर्णन करता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइये कि 200 विधान सभा क्षेत्रों में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इन चार सालों में कितना भारी काम किया है।

10 साल से पिलानी विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, दो बार रिपीट हुए। वहां का नौजवान, वहां का आमजन तरस गया, एक अदद कालेज के लिए, नौजवान धरने पर बैठे, आन्दोलन करते रहे, लेकिन एक अदद कालेज उन्हें नहीं मिला। जब हमारी कांग्रेस की वर्तमान सरकार आई, पिलानी में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो एक की बजाय चार कालेज पिलानी विधान सभा क्षेत्र में आए। एक चिड़ावा में सामान्य कालेज, जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे-बच्चियां आज पढ़ रही हैं। एक लड़कियों के लिए अलग से कालेज मण्ड्रेला में। एक पॉलीटेक्निक

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

कालेज पिलानी में और सबसे बड़ी बात कहूं, किसानों का क्षेत्र है मेरा, वहां एग्रीकल्चर कालेज चालू भी हो गया है और उसमें सेंट-परसेंट एडमिशन भी हो गये हैं। इतना भारी काम, साथ में सड़कों का जाल और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पिलानी विधान सभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ हो। जब एक विधान सभा क्षेत्र में यह तो खाली गिनने को गिनाया है मैंने, इतना काम हो सकता है तो मैं समझता हूं कि हमारे दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं, राजस्थान बहुत बड़ा है, बहुत काम हुआ है।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम हुए हैं। जनता क्लिनिक की बात अभी कोई मेरे साथी कल कह रहे थे। पिलानी विधान सभा क्षेत्र एक विधान सभा क्षेत्र है वहां दो जनता क्लिनिक प्रारम्भ हो गये, एक पिलानी में और एक चिड़ावा में। आक्सीजन के लिए हमारे बहुत लोग गये हमको छोड़कर कोरोना के अन्दर। दो आक्सीजन प्लान्ट, एक आक्सीजन प्लान्ट पिलानी में लग गया, दूसरा आक्सीजन प्लान्ट हमारे चिड़ावा में लग गया। जगह-जगह जिधर आप नजर डालो उधर काम हुए हैं। काम तो बहुत हुए हैं लेकिन मुझे और भी बात करनी है, इसलिये मैं समरिली यह कहता हूं कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में पूरे राजस्थान में समग्र रूप से शानदार डवलपमेंट हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, 14 हजार करोड़ रुपये का जो लोन माफ करने की बात हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि वादे के अनुसार लोन माफ नहीं हुआ। सहकारी क्षेत्र राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कन्ट्रोल में है। सब्जैक्ट टू कन्ट्रोल आफ द स्टेट गवर्नमेंट होती है ये इंस्टिट्यूशंस वहां लोन माफ हो गये, लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक, सेन्ट्रल बैंक राजस्थान सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, वो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। यहां यह बात करने की बजाय कि ऋण माफ नहीं हुए, वो वहां जाकर कहें माननीय मोदी जी से और उनसे परमिशन दिलायें कि वो लोन माफ कर दें। नेशनलाइज्ड बैंक्स के लोन किसानों पर चढ़े हुए हैं, सेन्ट्रल बैंक के लोन किसानों पर चढ़े हुए हैं, वो लोन यहां से नहीं हो सकते। इसलिये मैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि वो वहां जाकर यह बात कहें।

पाला पड़ा, किसानों की अगेती की जो पहले फसल बोयी सरसों की हमारे यहां, तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों के पक्ष में आदेश जारी कर दिये। हमारा तो कलेक्टर भी किसान का बेटा है, उसने तुरन्त

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

आर्डर्स निकाल दिये और अभी गिरदावरी बहुत तेज गति से चल रही है। इसमें मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि जितना किसानों का नुकसान हुआ है वास्तव में जमीन पर उतना अंकन होना चाहिये, उतना आकलन होना चाहिये और किसानों को उतना मुआवजा मिलना चाहिये जितना वास्तव में उनका नुकसान हुआ है। किसान बहुत परेशान हैं इस पाला पड़ने के कारण से।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था और उसको रिपीट कर रहा हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र संकटग्रस्त है पानी के लिए। वहां के गांव के लोग करीब-करीब अपने खेतों में जा चुके हैं, वहां अपने मकान बना चुके हैं, प्रत्येक किसान को एक कुण्ड किसान कुण्ड के नाम से स्वीकृत होना चाहिये। जब सरकार पानी की योजना बनायेगी, पेयजल की योजना बनायेगी तो उस समय वो गांव के हिसाब से बनायेगी, खेतों के हिसाब से नहीं बनायेगी। अगर कुण्ड एक-एक मिल जाता है किसान को बड़ा तो यह मिट्टी इधर से उधर नरेगा में डालने की बजाय उचित यह होगा कि वह किसान को कुण्ड बनाने की स्वीकृति जारी करे। कुछ किसान की मेहनत होगी, कुछ मैटेरियल मैनेजमेंट नरेगा के माध्यम से होगा और किसानों के कुण्ड बन जायेंगे ताकि कम से कम बारह महीनों का पेयजल तो वह अपने लिए सुरक्षित रख सकेगा। यह निर्देश राज्य सरकार की तरफ से प्राथमिकता से जारी होने चाहिये ताकि सभी को...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): तो, सर, फिर दो मिनट हैं तो मैं तो सबसे पहले पानी की ही बात करूंगा। निवेदन यह करना चाहता हूं कि चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से हमारे क्षेत्र को पानी मिलना था, लेकिन योजना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बावजूद भी अभी तक पानी नहीं मिल पाया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में बहुत समय लग रहा है, फिर भी धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार को कि 156 एमएलडी पानी हमारे सीकर और झुन्झुनूं जिले के गांवों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उसी में मेरा विधान सभा क्षेत्र आता है। 103 आरडी हनुमानगढ़ से अब हमारा यह सोर्स तय किया गया है। रावतसर होते हुए तहसील तारानगर से पानी हमारा ट्रीट होगा और मलसीसर के पम्प हाउस के माध्यम

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

से 8,082.76 करोड़ की योजना नये सिरे से बनायी गयी है। यह योजना एसएलएसएससी स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग आथोरिटी के सामने जा रही है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस एसएलएसएससी की मीटिंग जब हो तो यह 8,082.76 करोड़ की योजना पानी की जो हमारे लिए है पिलानी के लिए है, नवलगढ़ के लिए है, सीकर के लिए है, धोद के लिए है, दांतारामगढ़ के लिए है, श्रीमाधोपुर के लिए है और नीमकाथाना के लिए भी है, वह मंजूर होनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहेगी। मैं आपकी झुआरी की माकूल व्यवस्था रखूंगा।

सभापति महोदय, 2018 के अन्दर कांग्रेस की सरकार जब चुनावी मैदान में थी तो बड़े-बड़े वादे और बड़ी-बड़ी घोषणाएं तत्कालीन समय के अन्दर कांग्रेस के नेताओं ने कीं। सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात की, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, दिन में बिजली देने की बात की, संविदाकर्मियों को नियमित करने की बात की, रोडवेज कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने की बात की, पत्रकारों को सुविधाएं मुहैया कराने की बात की और इसके साथ अनेकों ऐसे-ऐसे वादे तत्कालीन समय में किये गये कि आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बन गयी तो आम जन को राहत पहुंचाने का काम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, सभापति महोदय, सरकार की वह उद्घोषणाएं थोथी साबित होती गईं और, सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो सरकार की योजनाएं चल रही थीं इस सरकार ने आने के बाद उन योजनाओं को बन्द करने का काम किया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। निर्माण श्रमिक योजना चल रही

(श्री रामलाल शर्मा)

थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया। किसानों को बिजली के बिलों में सब्सिडी योजना चल रही थी, उस योजना को बन्द करने का काम किया और हमारी सरकार के समय टोल फ्री योजना चल रही थी, उस योजना को भी इस सरकार ने बन्द करने का काम किया।

अब समय नजदीक देखते हुए, चुनावी समय नजदीक आ रहा है तो इन योजनाओं का नाम परिवर्तित करके वापस शुरू करने का काम किया। अगर सरकार ने कोई बड़ा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बन्द करके और वर्तमान में नाम परिवर्तन करके और दो-ढाई साल तक उन योजनाओं के लाभ से जनता को वंचित रख कर और फिर शुरू करने का काम किया है। यह सरकार की उपलब्धि है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं ट्रेजरी बैंचेज में एक मंत्री नहीं है। हालत देखो इनकी।

श्री सभापति: आ जायेंगे, सब आ जायेंगे। मंत्री बैठे हैं। विराजिये। प्लीज विराजिये। अपनी बात चालू रखें आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, चार बजट आ चुके हैं सदन के अन्दर, चार बजटों की वास्तविक स्थिति भी देखें, सभापति महोदय, तो बीस परसेंट घोषणाएं भी आज धरातल के ऊपर नहीं है। राजस्थान में इन्होंने वादा इस बात का किया था कि राजस्थान में 12 हजार ग्राम पंचायतें हैं, उन तमाम ग्राम पंचायतों के अन्दर हम विकास पथ बनाने की बात करेंगे, लेकिन आज भी राजस्थान की सौ ऐसी ग्राम पंचायतें नहीं हैं जहां इन्होंने विकास पथ बनाने का काम किया हो। जनता क्लिनिक खोलने के बड़े-बड़े वादे इन्होंने किये थे, आज राजस्थान में एक भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां एक भी जनता क्लिनिक खोलने का काम किया हो। नन्दी शालाएं खोलने की घोषणा इन्होंने सदन में की थी, आज एक भी विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति के अन्दर नन्दी शालाएं नहीं खुलीं।

सभापति महोदय, आज भी भेदभावपूर्ण तरीके से सड़कें, इस विधान सभा में आसन से व्यवस्था दिये जाने के बावजूद भी भेदभावपूर्ण तरीके से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन यह करूंगा कि कालेज खोलने की वाहवाही जरूर इन्होंने ली, लेकिन धरातल पर यह है कि इनकी खोली हुई तमाम कालेजें एक-एक कमरे में

(श्री रामलाल शर्मा)

संचालित हैं, एक प्राध्यापक के द्वारा संचालित है। न कोई सुविधा है, न कोई स्टाफ है, न कोई काम करने वाले हैं। सिर्फ मेज थपथपाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज भी राजस्थान में सरकार यह कहती है कि हम कर्मचारियों के साथ फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और कर्मचारी सरकार से खुश हैं। अगर कर्मचारी आपकी सरकार से खुश हैं तो अभी कुछ दिनों पहले पचास हजार कर्मचारी जो अलग-अलग विभागों के थे, वो प्रदर्शन करने क्यों आते? उनकी मांग जायज है तो आप उनका समाधान करने का काम क्यों नहीं करते? सभापति महोदय, आज एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग इस सरकार से सन्तुष्ट हो। एनटीटी के विद्यार्थी सरकार के सामने हमेशा ज्ञापन, प्रदर्शन और धरने दे रहे हैं। बेरोजगार नौकरी पाने के लिए धरने दे रहे हैं। बेरोजगार युवा मेहनत और परिश्रम करता है, लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है तो पेपर लीक होते हैं। उनके अरमानों के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर पानी फेरने का काम भी यह सरकार कर रही है। सभापति महोदय, रोडवेज कर्मचारी आये दिन धरने पर बैठ रहे हैं, कम्प्यूटर अनुदेशक आज आये दिन धरना दे रहे हैं, सरकार को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और इस सरकार में बेरोजगार युवाओं ने राजस्थान की धरती पर ही नहीं, लखनऊ तक पैदल मार्च करते हुए सरकार को जगाने का काम किया। यहां राजस्थान से लेकर गुजरात तक पैदल गये फिर भी सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे। इस देश में मासूम बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी हुई है तो वह राजस्थान में हुई है। अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार हुए हैं तो राजस्थान में हुए हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, बानसूर से आने वाली विधायक महोदया और राजस्थान सरकार की मंत्री के इन्हीं के विभाग का विवरण आपके सामने रखना चाहूंगा। इन्हीं के विभाग में मेरी विधान सभा क्षेत्र में रीको इंडस्ट्रियल एरिया है जिस पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। एक बार नहीं, अनेकों बार इस सदन में मैंने बात रखी। पहले परसादी लाल जी मीणा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हां हमारी जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसके बावजूद भी अभी तक कब्जा

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं हटा। मंत्री जी ने खुद ने आश्वस्त किया कि हां, जमीन हमारी है, कब्जा हटाने का काम करेंगे। आज दिन तक वह कब्जा नहीं हटा। इनके शासन में कोई सुरक्षित नहीं है। मंदिरों की जमीनें सुरक्षित नहीं हैं। सभापति महोदय, सामोद की बंदोल में 1963 की पहले सैटलमेंट में सार्वजनिक प्याऊ के नाम से जमीन, उस 19 बीघा जमीन को भी इनकी सरकार के नुमाइंदों ने खुर्द-बुर्द कर दी, भू-माफियाओं ने कब्जा करने का काम किया।

सभापति महोदय, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, मंदिर की जमीनें सुरक्षित नहीं हैं, तो इस सरकार में आखिरकार सुरक्षित है कौन? सभापति महोदय, मुझे पता है आप भी कुंठा में जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार की कार्यशैली को लेकर आपके मन में भी दर्द और पीड़ा है लेकिन आप आसन से बंधे हुए हो, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस विधान सभा परिसर में आप जिस तरह से बात करते हैं, अपनी वेदना को प्रकट करते हैं, उससे महसूस किया जा सकता है कि आप भी कितने दुःखी हो।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में बीमारी के लिए वाहवाही करते हैं कि चिरंजीवी योजना में इतने पैकेज हमने शामिल किये हैं, इतने लोगों को राहत प्रदान करने का काम किया है। सभापति महोदय, मस्कुलर डिस्ट्रोफी यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति बीमार होता है लेकिन पूरा परिवार परेशान और पीड़ित रहता है। उस एक बच्चे को बचाने के लिए, उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगती है, लेकिन राजस्थान की सरकार अभी तक भी इस तरह के मरीजों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस तरह के मरीजों के परिवार को पेंशन शुरू की जाये, उनको यातायात का भत्ता दिया जाये, रोडवेज में उनका यातायात नि:शुल्क किया जाये और बीमारी के इलाज के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करे ताकि उस परिवार को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, उप सभापति महोदय ने जो बात कही थी वह हकीकत है। राजस्थान में पहली बार सुनने को मिल रहा है फिरौती के नाम पर उगाही करना, अपहरण के नाम पर पैसा वसूल करना, धमकी से पैसा वसूल करना। मंत्री महोदय, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कही गई बात को मैं इस सदन में कह रहा हूं, इज्जत

(श्री रामलाल शर्मा)

बचाने के लिए, जान बचाने के लिए लोग पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते, इन माफियाओं को पैसा देना ज्यादा पसंद करते हैं। सभापति महोदय, ईमानदारी से आप कहो कि किसी का नाम उजागर नहीं किया जायेगा। किसी से फोन के माध्यम से वसूली की गई है तो सरकार को बताएं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर अपनी जान बचाई है, सरकार के नुमाइंदों ने उनकी जान नहीं बचाई। सभापति महोदय, भय बिना प्रीत नहीं होती है। अपराधी जिस भाषा में समझना चाहे, उसे उसी भाषा में समझाना चाहिये। अगर आपकी सरकार में दम है, आपकी सरकार में इच्छा शक्ति है तो अपराधी को अपराधी की भाषा में समझाओ तभी अपराध कंट्रोल होगा। कानून के दायरे में अपराध कंट्रोल होने वाला नहीं है। आप कहो कि इज्जत के साथ बुलायेंगे और अपराध कंट्रोल हो जायेगा।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है पुलिस के कर्मचारी 24 घंटे काम करते हैं, आज भी वह 3,600 रुपये पे-ग्रेड की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कीजिए, आप सरकार को अपना रौद्र रूप दिखाइए, आपके सीधे-सादे रूप की वजह से सरकार गंभीर नहीं है। सभापति महोदय, आप अपने तीसरे नेत्र को खोलने का काम करें, सरकार को निर्देशित करें ताकि आने वाले समय में पुलिस के कर्मचारियों को 3600 रुपये की पे-ग्रेड मिल सके।

सभापति महोदय, जिस तरीके से अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या जिक्र कर रही थी तुष्टिकरण की राजनीति, सांप्रदायिक घटनाओं को जिस तरह से अंजाम देने का काम आपने किया है, समय पर आप चेत जाते, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते तो आज कन्हैया लाल हमारे बीच में जिंदा होता लेकिन आपकी तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है और उस हत्या का दोष सरकार को निश्चित रूप से लगेगा। करौली की घटना में जिस तरीके से आपने वक्तव्य दिये, जोधपुर की घटना में जिस तरीके से आपने वक्तव्य दिये, वह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। आपने करौली में तो कह दिया कि आपत्तिजनक नारे लगाने से घटना हुई, जोधपुर में तो कोई जुलूस भी नहीं था, आपत्तिजनक नारे भी नहीं थे, फिर क्या मजबूरी थी कि अपराध करने वाले व्यक्तियों को रात को 12 बजे आपको रिलीज करना पड़ा? क्या आपको

(श्री रामलाल शर्मा)

वोटों की इतनी चिंता है? अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। सभापति महोदय, अपराधी अपराधी होता है, इसलिए अपराधी को अपराधी के तरीके से ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में पहले शीतलहर की वजह से फसल चौपट हुई है, अब राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसल चौपट हुई है। गिरदावरी करने वाले तमाम पटवारी 25 से 30 परसेंट खराबा बता रहे हैं। मैं सरकार को चेता रहा हूं अपने अधिकारियों को निर्देशित करें, मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि 60 परसेंट नुकसान हुआ है, कम से कम ईमानदारी से गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दें।

सभापति महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा जिस जिले से आप आते हैं, मंत्री जी, पंजाब के व्यापारियों से मेरी बात हुई है, वह कहते हैं कि चारा 1300-1400 रुपये क्विंटल सिर्फ इसलिए है कि राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हुए हर थाने में 500 रुपये की एंट्री। हर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर की 500 रुपये की एंट्री। चौमूं-जयपुर आते-आते वही चारा 20-25 हजार रुपये की एंट्री की वजह से, आज ईमानदारी से पुलिस की और परिवहन विभाग की यह एंट्री बंद करा दो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चारा 800-900 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा।

सभापति महोदय, अंत में एक और निवेदन करना चाहूंगा। मेरी विधान सभा के पीएसीएल और सहारा दो ऐसे हैं जिनमें 200-250 करोड़ रुपये हैं, राजस्थान के अरबों रुपये हैं। सदन इस बात की भी चिंता करे। गरीब आदमी ने अपनी आजीविका में से कटौती करते हुए, अपने भविष्य के सपनों को साकार करते हुए कटौती करके सहारा और पीएसीएल में पैसे जमा कराये थे। आज भी 250-300 करोड़ रुपया एक विधान सभा का पैसा है, वह पैसा कैसे निकले, कैसे उन तक पहुंचे और कैसे उस पैसे से उनकी आजीविका चले, इस बात की भी चिंता करनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा अंतिम निवेदन इतना ही है कि रेवेन्यू के अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, मैं चेताना चाहता हूं चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो, चाहे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो रेवेन्यू का

(श्री रामलाल शर्मा)

काम देख रहे हैं, आप इन पर कंट्रोल करके विजिलेंस की एक टीम गठित कीजिए, इनके निर्णयों की समीक्षा कराइए, तभी जाकर इन पर अंकुश लग सकेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन है। आज राजस्थान में अपराध अपने चरम पर है, इनका एक ही इलाज है पुलिस को आप फ्री कीजिए। अपराधी जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का काम करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बिना टोके दिया, आपको धन्यवाद। आप अपनी तीसरी आंख खोलकर सरकार को चेताएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 15वीं सरकार है, इससे पहले 14 सरकारें रहीं, 14 में 5 बार भाजपा का, उसी में एक बार भाजपा और जनता दल का राज रहा और 9 बार कांग्रेस का राज रहा। यह 15वीं सरकार है, माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में चार वर्षों में पूरे राज्य में जो काम हुए उसका लेखा जोखा माननीय राज्यपाल महोदय ने बिन्दु संख्या 1 से 281 तक दिया। अभी तक की चर्चा में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अलग-अलग बताया, उससे ऐसे लग रहा था कि चार वर्षों में जो भी काम हुआ है वह हां पक्ष के लोगों ने कहा और उसी एरिये में हुआ है जबकि ऐसा

(समय: 15.00 बजे)

नहीं है। क्रोस करने के लिए विपक्ष के हर माननीय सदस्य ने कई बार, अनेकों बार मोदी जी का नाम लिया, जबकि राजस्थान राज्य में 20 वर्ष तक भाजपा का राज रहा। उसमें स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, माननीया वसुन्धरा जी राजे जो कि दो बार मुख्य मंत्री रहीं, भैरोंसिंह जी तीन बार रहे। विपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य से इन 20 वर्ष के कार्य की अवधि में क्या विशेष किया और हम लोग चार वर्षों में नहीं कर पाये, इसके बारे में एक शब्द भी शायद सुनने को नहीं मिला।

चार वर्षों में जो काम हुए, विशेषकर कोरोना के समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सभी विधायकों, दो सौ विधायकों, चाहे किसी भी

(श्री रूपाराम)

पार्टी के हों, 25 सांसदों, जो कि पूरे के पूरे भाजपा से थे, उसके अलावा विभिन्न धर्म गुरुओं, विभिन्न वर्ग के लोगों, वैज्ञानिकों, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी से चर्चा करके और समय-समय पर निर्णय लिए गये। सभी की राय को इन्कार्पोरेट किया गया।

इसी प्रकार चारों ही बजट में सभी से मोटे तौर पर चर्चा करके जितनी भी बजट की घोषणाएं हुईं मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि चार बजट में जो भी घोषणाएं हुईं इतना टाइम नहीं है कि एक-एक बताऊं, लेकिन लगभग 75 से 80 परसेंट की क्रियान्विति फील्ड पर हो चुकी है। राज्य में जो विपरीत परिस्थितियों में चार वर्षों में काम किया गया। भारत सरकार, अधिकतम टाइम 50 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय में कभी भी यह भेदभाव नहीं रखा गया कि कौनसे राज्य में किसका राज है। चाहे पहाड़ी एरिया हो, रेगिस्तानी एरिया हो, जहां पर तकलीफें अधिक हैं, वहां के लिए अधिक योजनाएं, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो स्वीकृत होती थीं। जैसे ही, जिनका बार-बार नाम लिया जा रहा है, मोदी जी साहब का, उन्होंने राज्य के लिए सबसे पहले 2014 में आते ही 2015 में बीआरजीएफ योजना, जिसमें राजस्थान के पिछड़े हुए 13 जिले थे, इससे उनके विकास के काम होते थे, प्रथम काम यह किया कि उसको बन्द किया। उसके बाद बीएडीपी योजना, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आते थे, इस योजना को भी 2021-22 में बन्द किया, और कई योजनाएं, जिनको लागू करने के लिए यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राजस्थान स्टेट के जो वित्तीय संसाधन हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

पहले कई योजनाओं में, पेयजल की अधिकतम योजनाओं में 90 परसेंट पैसा भारत सरकार देती थी और कई योजनाओं में 60, 70, 75, 80 परसेंट देती थी, सभी को एक साथ भारत सरकार ने बन्द करके करीब 50 परसेंट पर ले आये। इसमें मैं पेयजल का उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने घोषणा की कि 2024 तक घर-घर नल देंगे। राजस्थान में घर-घर नल देने के लिए लगभग दो लाख करोड़ की आवश्यकता है। तीन वर्ष की अवधि थी, तीन वर्ष के अन्दर 50 परसेंट अगर राजस्थान सरकार खर्च करती है तो उसको एक लाख करोड़ खर्च करने हैं और एक साल का मानो तो 33 हजार करोड़। जब जिस सरकार के पास विकास के काम करने के लिए पैसे उपलब्ध ही 70-80 हजार करोड़ हैं, कैसे सम्भव होगा तो भारत सरकार को स्टेट में किसका राज है, इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

(श्री रूपाराम)

इन विषम परिस्थितियों में कोरोना आया, 100 वर्ष में इतनी बड़ी महामारी आयी। आजादी के पहले इतनी बड़ी कोई महामारी नहीं आयी। संवत 1975 में भड़बड़ी आयी थी, वह करीब 100 वर्ष पहले थी। आजादी के बाद पहली बार कोरोना आया, ये भी बहुत विपरीत परिस्थितियां थीं।

माननीय मोदी साहब, जिनकी प्रशंसा की जा रही है। मारवाड़ी में कहते हैं, थूका हुआ कोई गिटता नहीं है। 13 जिलों के लिए जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, उनकी घोषणा की। विपक्ष का कोई भी सदस्य यह नहीं कह रहा है कि घोषणा नहीं की थी। करने के बाद नट गये, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस योजना को भी, राज्य के वित्तीय संसाधन लिमिटेड होने के बाद भी पिछले बजट में 9 हजार करोड़ की घोषणा की और कार्य भी शुरू कर दिये हैं। जिस दिन से विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा है, उससे सब इकतरफा हो रहा है।

मैं आपको कुछ एक योजनाएं बताता हूं, जिसके अन्दर न जाति है, न धर्म है, न पार्टी है और न क्षेत्रवाद है, सभी के लिए है। चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो। जिसमें मोटी-मोटी है, चिरंजीवी योजना, इन्दिरा रसोई योजना और तीन हजार से अधिक की आबादी वाले गांव हैं, उनमें अंग्रेजी स्कूल खुली है। शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा है, उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी है। राज्य में जितनी भी गोशालाएं चल रही हैं, उनमें छह की जगह नौ माह करना। राज्य में सभी बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करना।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): अब मैं अगले बजट के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। राज्य में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अभी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, सभी में इसी साल घोषित की जायें। जिन ग्राम पंचायतों में बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय नहीं है, पांचवीं के बाद बच्चियों को बच्चों के साथ नहीं पढ़ाते हैं, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां बालिका विद्यालय नहीं है, वहां खोले जाएं। एसडीआरएफ में अकाल के दौरान पशुधन बचाने के लिए संरक्षण के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें पशु ऊंट, भेड़, बकरी सम्मिलित नहीं है। भेड़, बकरी पर आज सभी पशुपालकों का जीवन निर्भर है, वह किया जाये।

(श्री रूपाराम)

राज्य में जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं, पशु स्वास्थ्य संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, इन सबकी कुछ न कुछ मैक्सिमम दूरी डिसाइड करें कि इससे दूर नहीं होने चाहिए। कई जिलों में पांच किलोमीटर पर है। जैसलमेर और बाड़मेर में कई जगह पर पांचवी तक की स्कूल भी 40 किलोमीटर के नजदीक नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ तय किया जाये, ताकि सबको इक्वल दूरी पर मिले। जो रोड्स नेटवर्क है, जैसलमेर जिले में एक हजार वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 130 किलोमीटर है और राज्य का एवरेज करीब 500 किलोमीटर है। इस प्रकार जो इन-इक्वल है, इसको पूरे एरिये के हिसाब से इक्वल किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): एक मिनट में। जैसलमेर जिले के लिए भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र में साढ़े चार लाख हैक्टेयर खेती होती है। पिछली बार 600 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी, इस बजट में 600 करोड़ की और घोषणा करें तो नहरी एरिया पूरा कवर हो जायेगा और वहां जो फसल एक साल में 12 सौ करोड़ की होती है, वह लगभग ढाई हजार करोड़ की हो जायेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभिभाषण में सरकार कहती है, अब हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। किन पैरामीटर्स पर उभर रहा है? सरकार एक बार एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लेती तो निश्चित तौर पर पता चल जाता कि हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट किस चीज पर बना है। गैंगस्टर अपराध के मामलों में, महिला अत्याचार के मामलों में, दुराचार के मामलों में, बलात्कार के मामलों में और ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान पहले पायदान पर है, मॉडल स्टेट है।

सिरोही से आने वाले सदस्य ने अवैध खनन की बात की, अवैध रायल्टी की, बात की। बजरी को लेकर चिन्ता व्यक्त की। पूरे प्रदेश में बजरी को लेकर त्राहि-त्राहि है। बीकानेर में जहां धरती से बजरी निकलती है, किसी नदी-नाले से खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो पूरा सरकारी तंत्र, सरकारी

(श्री बिहारीलाल)

ओहदेदार सब लोग लूट में लगे हुए हैं। ट्रक मालिकों से 10-10 गुना रायल्टी वसूली जा रही है, इसलिए बजरी महंगी हो गयी है। इस बात की चिन्ता सरकार को करनी चाहिए, लेकिन यह चिन्ता कहीं दिखायी नहीं देती।

अभिभाषण में सरकार ने राज्यपाल महोदय से कहलवा दिया, 'जन सेवा के समर्पित चार वर्ष'। माननीय सभापति जी, ऐसा लिखा जाता, 'येन-केन-प्रकारेण सरकार बचाने के चार वर्ष' तो यह सही प्रतीत होता। लिखते हैं कि विगत चार वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, ऊर्जा, उद्योग, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है। माननीय सभापति जी, थोड़े दिन बाद 30 मार्च आयेगा, राजस्थान दिवस होगा और राजस्थान बने 75 साल, हीरक जयन्ती होगी, ऐसे अवसर पर तो कम से कम सही बात अभिभाषण में आनी चाहिए थी। क्या स्थितियां हैं, इसका इसमें विश्लेषण करना चाहिए था।

शिक्षा की क्या स्थिति है? 21 जनवरी को मुख्य मंत्री डाबला, श्रीगंगानगर में पधारे और कहा कि चार वर्षों में 211 कालेज हम खोल चुके हैं और देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं है तो राजस्थान में हैं। माननीय सभापति जी, क्या फायदा ऐसी शिक्षा का जहां किराये के दो कमरों में कालेज चलता हो, जहां एक लेक्चरर के भरोसे कालेज चलता हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल सरकार सदन में लेकर आयी। आपके जिले से एक यूनिवर्सिटी, ऐसा बिल लेकर आई जिसकी एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी और उसका बिल यहां सदन में पास होने के लिए आ गया। यह स्थिति जब शिक्षा की हो तो ऐसी असत्य वाहवाही का क्या लेना-देना।

सिरोही से आने वाले सदस्य ने कहा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कालेज की बात भी की कि 41 कालेज तो खोल दिए, लेकिन एग्रीकल्चर एजुकेशन की गुणवत्ता, कहां प्रेक्टिकल संसाधन होंगे, क्या उनके फील्ड होंगे, क्या उनके फार्म होंगे, क्या उनका प्रशिक्षण होगा, उस बात की कोई चिंता नहीं है। इस तरह जब हम एक फौज तैयार कर देंगे जो अनस्किल्ड होगी, जो पूरी तरह से दीक्षित नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी तो क्या वह इस प्रतिस्पर्धा के दौर में टिक पायेगी? ऐसी फौज तैयार करने के लिए कुकुरमुत्तों की तरह बिना संसाधनों के कालेज खोले जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नजर नहीं आता।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति जी, स्कूल शिक्षा की स्थिति देखिए। नन्हे-मुन्ने बच्चे अभिभावकों संग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं, स्कूल वाले तालाबंदी करके हैडक्वार्टर पर आते हैं, डायरेक्टर के सामने आकर धरना देते हैं। ये एक गांव की नहीं, हर गांव की ये स्थिति है। तबादला उद्योग चलता है। गांव के गांव खाली हो जाते हैं। शहरों में अध्यापकों की पोस्टिंग हो जाती है और मुख्य मंत्री जी, जब सीएम साहब खुद मंत्री की उपस्थिति में पूछते हैं शिक्षकों से, क्या तबादलों में पैसे लिए जाते हैं तो कुर्सियों पर खड़े होकर हल्ला मचाते हैं कि हां, लिए जाते हैं। यह स्थिति जब शिक्षा की हो तो बड़ी चिंतनीय बात है। जब शिक्षा मंत्री, तब के शिक्षा मंत्री सीना ठोक कर कहते हैं कि हम तो सदन में, रोने वाले चाहे राजेन्द्र जी हो, चाहे कटारिया जी हो, सदन में रोने वाले रोते रहेंगे, हमने तो तीन साल इस तरह डोटे लगाए हैं और आगे भी दो साल इसी तरह लगाते रहेंगे। यह जनतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। इस पर सरकार को चिन्तन और मन्थन करना चाहिये।

सभापति जी, किसी सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। 21 जनवरी की बात करूं, बिश्नोई मंदिर, डाबला में माननीय मुख्य मंत्री जी गये तो एक 70 साल की दादी ने उनका हाथ पकड़कर मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्य मंत्री जी, आप कहते हैं कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', हम बेटी को पढ़ाते हैं, अपना उदाहरण देती है कि 6 बीघा का काश्तकार, 6 बीघा की जोत वाला परिवार अपनी पोतियों को पढ़ाता है और दादा उनको परीक्षा दिलाने ले जाता है, जब वापस घर लौटता है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गये। क्या बीतती है? कौन रोकेगा इसको? मुख्य मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होता। सदन में हमारे मंत्री जी कहते हैं, जब इस पेपर लीक पर बात होती है, हमारा स्थगन लगता है तो मंत्री जी कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं यहां नहीं हो रहा, उस प्रदेश में भी हो रहा है, फलां प्रदेश में भी हो रहा है। माननीय सभापति जी, यह कोई जवाब नहीं हुआ। हम आपसे कहना चाहते हैं कि -

'तू इधर'उधर की न बात कर,
ये बता कि पेपर का काफिला कैसे लुटा,
मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है।'

क्यों कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ी है? जब आप कालेज में शिक्षक लगा देंगे, जब आप स्कूलों में शिक्षक लगा देंगे, व्याख्याता लगा देंगे तो क्यों

(श्री बिहारीलाल)

कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ेगी। कोचिंग संस्थानों का नकल करवाने में, पेपर लीक करवाने में योगदान रहता है। इस परम्परा पर भी रोक लगनी चाहिये। सुरेश ढाका के किन-किन से संबंध थे? नेता, ओहदेदारों का, किन-किन का विश्वासपात्र था, इसका खुलासा होना चाहिये। सुरेश ढाका, भूपेन्द्र सारण तो मोहरे मात्र हैं। परदे के पीछे कौन लोग हैं? वे सामने आने चाहिये। इस बात की चिंता सरकार को होनी चाहिए क्योंकि ये 70 लाख बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मसला है। उनके परिजनों की गिनती करें तो 2 करोड़ राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ मसला है।

कृषि कल्याण की बातें, बिजली, ऊर्जा की बातें। बिजली मंत्री जी यहां बैठे हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है। 24 हजार मेगावाट का उत्पादन होता है। कंजम्पशन कितना होता है? 14 हजार मेगावाट, 10 हजार का फर्क पड़ा है, 2-3 हजार हम मान लें कि टी. एंड डी. लोसेस होता है, फिर भी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि गांव में किसान को 8 घंटे बिजली की बात करने वाले 2 घंटे भी बिजली नहीं दे पाते।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, दो मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): दो घंटे भी बिजली नहीं दे पाते। हजारों काश्तकारों की मोटरें जल जाती हैं। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सरचार्ज के नाम पर 8 रुपये के लगभग प्रति यूनिट चार्ज बढ़ा दिया। चार वर्षों में एक घरेलू कनेक्शन नहीं, जो पैसा घरेलू कनेक्शन के लिए केन्द्र से मिला वह भी आठ महीने इंतजार करते-करते, काम नहीं करेंगे, लैप्स हो गया। कौन चिंता करेगा इस बात की? टंकी के नाम पर क्या हो रहा है, अभी नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया। चार वर्षों में पांच 220 के जीएसएस बने हैं। मेरे नोखा में भी 500 का एक जीएसएस बना है। हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि उसकी लगातार पैरवी करेंगे। जीआईबी की वजह से जो अटका हुआ है, पास होगा और नोखा का यह काम होगा।

सभापति जी, अगर बिजली समय पर मिलती तो किसानों की खेतों में सिंचाई हो जाती और पाले की मार किसान पर नहीं पड़ती। उसका इतना असर नहीं होता। खेतों में पानी नहीं था, पाले की दोहरी मार पड़ी। स्पेशल गिरदावरी

(श्री बिहारीलाल)

के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। जो गिरदावरी आयी है, नोखा से, बीकानेर से, 33 परसेंट, 35 परसेंट और दोबारा उसके बाद फिर से किसानों को नुकसान हुआ है, 15 जिलों में ओलावृष्टि से, 15 जिलों में पाले से। इस बात को भी देखना कि दोबारा गिरदावरी जन-प्रतिनिधियों के साथ हो।

यूरिया खाद के नाम पर किस तरह लूट हुई? जब केन्द्र ने आपने जो एलोकेशन मांगा, उससे आपको ज्यादा दिया। तीन-तीन वर्षों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए रबी के, ख़रीफ़ के, फिर भी यूरिया वितरण में कहां धांधली हुई कि किसान को लाइन में लगना पड़ा और पुलिस के डंडे खाने पड़े?

चिकित्सा की स्थिति, मेरे नोखा में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की घोषणा, सीएचसी, पीएचसी, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं ईंट भी नहीं लगी, कहीं काम भी शुरू नहीं हुआ। संविदाकर्मियों की स्थिति जेजेएम की स्थिति, सबसे धीमी रफ्तार, नोखा में काम चल रहा है, वह बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। चिरंजीवी योजना, जिसमें कई विसंगतियां हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति जी, लम्पी के नाम पर, लम्पी की जो बीमारी आयी उसमें क्या स्थिति रही? बहुत संवेदनशील मंत्री हैं कटारिया जी, लेकिन विभाग के सचिव ने, विभाग के डाक्टरों ने एक गलत इंटरप्रिटेशन से वैक्सीनेशन के काम में महीनों लगा दिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए। श्री पुखराज गर्ग।

श्री बिहारीलाल (नोखा): आंकड़े आते हैं, 76 हजार गोवंश काल-कवलित हुआ है।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री पुखराज गर्ग। प्लीज सहयोग कीजिए, विराजिए आप।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने की कल्पना की गयी है। जो कल्पना की गई है, उसमें कोई मुख्य ठोस आधार नहीं दिया गया है। मैं शिक्षा की बात करूं तो पिछले 4 साल के अन्दर राज्य सरकार ने बहुत सारे नये कालेज खोले, स्कूलें खोलीं, स्कूलें क्रमोन्नत कीं, लेकिन उसके अन्दर स्टाफ नहीं है। शिक्षा की किसी तरह की गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो पद खाली पड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। प्रिंसिपल नहीं हैं, लेक्चरर नहीं हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, सरकार के इन चार साल के कार्यकाल के अन्दर 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसमें लगभग सभी विभागों के पेपर थे। पुलिस कांस्टेबल का हो, वनपाल का हो, जे ईएन का हो, ग्राम सेवक का हो, पटवारी का हो, इन सभी के पेपर लीक हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पेपर करवाने वाली संस्थाएं आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग आदि संस्थाएं बिलकुल फेल हो गयी हैं। इन संस्थाओं के अन्दर भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिससे प्रदेश के अन्दर बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं शिक्षा के बारे में बात करूं तो जो गांवों के अन्दर स्कूलें हैं, उनके अंदर न तो सब्जेक्ट के टीचर हैं। किसी स्कूल के अंदर जहां विज्ञान वर्ग है, वहां आर्ट्स के टीचर लगा रखे हैं और जहां आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, वहां विज्ञान के टीचर लगा रखे हैं।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य की बात करें तो पिछले बजट के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की कल्पना की थी, बात की थी, लेकिन प्रदेश के अन्दर और विशेषकर मेरी विधान सभा के अन्दर सीएचसी व पीएचसी के अन्दर कहीं भी स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, विभिन्न मेडिकल जांचों हेतु तकनीकी कर्मचारियों के पद भरे हुए नहीं हैं। बहुत सारी सीएचसी जिनके अन्दर सोनोग्राफी मशीनें हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए डाक्टर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ के अन्दर उप जिला हास्पिटल खोला और रतकूडिया के अन्दर नई सीएचसी खोली। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन जो स्वीकृत पद हैं, उसके अनुसार डाक्टर नहीं लगाये गये हैं,

(श्री पुखराज)

स्पेशलिस्ट डाक्टर्स नहीं लगाये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इनमें जो भी पद खाली हैं उनको भरा जाए।

सभापति महोदय, अभी बिजली की बात करते हैं, किसानों के कर्ज की बात करते हैं, जब सरकार बनी थी तब किसानों के दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी की बात की गयी थी, लेकिन सहकारी संस्थाओं से कर्ज माफ करके, बहुत सारा लोन किसानों पर है, किसानों की बुरी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अन्दर औसतन पर किसान परिवार पर 74 हजार 130 का कर्जा है। राजस्थान के अन्दर औसतन प्रत्येक किसान परिवार पर 01 लाख 13 हजार का कर्जा है। किसानों पर कर्ज के लिए देश के अन्दर राजस्थान का सातवां स्थान है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। न तो किसानों की कर्ज माफी हुई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली विधान सभा में कहा था कि विद्युत के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास विद्युत सरप्लस है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुःखी है तो प्रदेश का किसान है, उनको कृषि के लिए सप्लाई नहीं मिल रही है। कहीं तीन घंटे, चार घंटे सप्लाई मिल रही है, वह गुणवत्ता की नहीं मिल रही है। बार-बार ट्रिपिंग आ रही है। गांवों की सिंगल फेज, घरेलू सप्लाई है, इसके अन्दर 24 घंटे सप्लाई देने की बात कही गई थी, लेकिन 10-12 घंटे सप्लाई आ रही है, उसमें भी बार-बार ट्रिपिंग आ रही है। सरकार ने जो घोषणा की, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप कहीं भी सप्लाई नहीं हो रही है।

पिछले बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पिछले दस साल के किसानों के कृषि कनेक्शन, 2012 से जनवरी, 2022 तक के कनेक्शन इन दो साल में देंगे, लेकिन धरातल पर कहीं भी बिजली में काम नहीं हुआ है। किसी तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। न 33 केवी के जीएसएस बने हैं, न 132 केवी के बने हैं, न 220 केवी के जीएसएस बने हैं। मेरे भोपालगढ़ के अन्दर स्थिति यह है, 132 केवी का जीएसएस है, उस पर एक साल हो गया ट्रान्सफार्मर सैंक्शन है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): आज तक स्वीकृति होने के बावजूद ट्रान्सफार्मर नहीं रखा गया, जिससे किसानों को प्रोपर सप्लाई नहीं मिल रही

(श्री पुखराज)

है। मैं 33 केवी जीएसएस का उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार का, हमारे डिस्कॉम, जोधपुर का कार्यशैली का उदाहरण है। 33 केवी का जीएसएस चार साल पहले सैंक्शन हुआ, 2019 में उसको विभाग ने फेज प्रोग्राम में ले लिया था, लेकिन आज भी उस गांव का 33 केवी का जीएसएस अधूरा पड़ा है। डिस्कॉम की काम करने की मंशा नहीं है। गवर्नमेंट जो घोषणा कर रही है उसके अनुसार जोधपुर डिस्कॉम में काम नहीं हो रहा, मेरा यह आपसे निवेदन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की विद्युत की समस्या है। आसोप ग्राम पंचायत मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां विद्युत का उपखण्ड खोला जाए, नया आफिस खोला जाए। भोपालगढ़ कस्बा, जहां भोपालगढ़ विधान सभा का मुख्यालय है, वहां विद्युत का निगम कार्यालय खोला जाए। अभी निगम का कार्यालय है, डिविजन का कार्यालय है, एक्स ईएन आफिस का कार्यालय है। वह अभी बिलाड़ा के अन्दर है, टेल एंड पर जो उपभोक्ता बैठा है, उससे 120 किलोमीटर पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और सरकार से मांग करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ मुख्यालय पर एक्स ईएन विद्युत की पोस्ट की जाए, एक्स ईएन विद्युत को बैठाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सीएचसी बनाड़, जो चार नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके अन्दर ट्रोमा सेंटर नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): आये दिन नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल केस बनाड़ सीएचसी के अन्दर आ रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी व सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बनाड़ सीएचसी में ट्रोमा सेंटर बनाएं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट सत्र के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करती हूं।

राजस्थान सरकार ने बीते सालों में विपरीत परिस्थितियों का सामना

(श्रीमती मनीषा पंवार)

करते हुए राजस्थान के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये हैं। आज मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी इस संवेदनशील सरकार का नेतृत्व आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य है और मैं अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं कि ऐसे गांधीवादी नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत अपना हर एक-एक क्षण व हर पल, जरूरतमंद व्यक्ति को किस प्रकार से राहत मिले, उसके लिए वह किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सके, यही उनके मन और दिमाग में रहता है। माननीय मुख्य मंत्री जी के विगत कार्यकाल के साथ-साथ वर्तमान कार्यकाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके यही प्रयास राजस्थान सरकार को और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

हमारी सरकार ने सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, के नारे के साथ शुरुआत की। ऐसी योजनाओं की सौगात राजस्थान की जनता को प्रदान की, आज अगर हम बोलते-बोलते थक जाएं, चाहे 24 घंटे बीत जाएं, लेकिन योजनाएं खतम होने का नाम नहीं लेतीं। हर आम आदमी के लिए योजनाएं बनाईं, चाहे वह वृद्ध महिला हो, वृद्ध पुरुष हो, युवा हो, चाहे खिलाड़ी हो, माता हो या बहन हो, हर उस आदमी के लिए योजनाओं का अम्बार लगा दिया।

हम अगर सबसे महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो चिरंजीवी योजना। विगत काल में जिस तरीके से कोरोना काल रहा, किसी से छिपा नहीं है। कोरोना काल जिस महामारी के अन्तर्गत पूरे विश्व में एक साथ आया, दुनियां में कभी कोई ऐसा समय नहीं आया था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर भी बंद हो गए, सबने बाहर निकलना बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गईं, व्यापार बंद हो गए, घर बंद हो गए लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी मुख्य मंत्री जी ने हर अपने क्षण को, चाहे वह कोरोना पोजिटिव रहे हों, चाहे वह कितने भी बीमार रहे हों, हर क्षण राजस्थान की जनता के लिए जिया। 500 से ज्यादा वीसी के माध्यम से हर आम आदमी से सम्पर्क किया। सरपंच से सम्पर्क किया, धार्मिक गुरुओं से सम्पर्क किया। डाक्टर, इंजीनियर, पंचायत सरपंच, विधायकों से, एमपी महोदय से, सबसे बातचीत की कि किस तरह हम इस कोरोना काल से निपट सकते हैं, किस तरह कोरोना काल से उबर सकते हैं। अनेक सुविधाओं

(श्रीमती मनीषा पंवार)

के साथ, चाहे मुफ्त दवा योजना के माध्यम से, मुफ्त जांच योजना के माध्यम से, निरोगी राजस्थान को लेकर आए। कोरोना काल से निपटने के लिए लोगों से बातचीत करके, डाक्टर्स से बातचीत करके, हर एक क्षण उन्होंने लोगों के साथ बिताया, यह विपक्ष से भी छिपा हुआ नहीं है। विपक्ष के साथ भी उन्होंने हज़ारों वीसी के माध्यम से, जो-जो उन्होंने सुझाव दिए, उस पर मुख्य मंत्री जी ने अमल किया।

हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करें। अगर घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, हमारा पिता, हमारी माता, हमारी बहन, भाई और जब वह गम्भीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो परिवार भी साथ छोड देता है और हज़ारों-लाखों रुपये उस बीमारी के इलाज में लगते हैं, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान की परम्परा रही है कि हम अपने परिवार के आदमी का साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे घर भी बिक जाएं तो भी अन्त तक हम उसको स्वास्थ्य लाभ दिलाने का, अच्छी कामना करने की बात करते हैं। इस बात को राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने सोचा। किसी के भी दिमाग में यह बात नहीं आई होगी कि दस लाख रुपये का बीमा, इतनी बड़ी रकम, एक आम आदमी के लिए मुख्य मंत्री जी ने सोंची। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर आम नागरिकों को सौंपी। हज़ारों का इलाज इस मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना में होता है। आप स्वयं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप खुद यह जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में आई है। इसके साथ-साथ पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी इसमें जोड़ा गया।

ईश्वर न करे कि किसी घर में ऐसी दुर्घटना आएं, फिर भी कई दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना में, अगर इस बीमा से कोई आदमी जुड़ा हुआ है तो पांच लाख रुपये का सम्बल, हम उस आदमी को तो नहीं ला सकते लेकिन पीछे उसकी पत्नी, बेटे, बहन है, उसको पांच लाख रुपये का सम्बल मुख्य मंत्री जी ने प्रदान किया। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ मुख्य मंत्री जी ने निरोगी राजस्थान, जांच योजना, दवा योजना लाकर आम आदमियों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाया है, वह किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ-साथ आरजीएचएस, कर्मचारियों को भी इस योजना से जोड़ने में वह पीछे नहीं हट रहे हैं। कर्मचारियों के लिए भी आरजीएचएस योजना लागू करके उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाने का काम किया है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

मैं मेरे जोधपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। चाहे एमडीएम अस्पताल हो, चाहे एमजीएच अस्पताल हो, चाहे उम्मेद अस्पताल हो, उसमें करोड़ों रुपये की लागत से, चाहे आईसीयू बेड बनाना हो, चाहे ओपीडी का निर्माण करना हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाना हो, अलग-अलग माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को और ऊंचाईयों पर ले जाने का काम हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि शहर के भीतरी क्षेत्र में जो नवचौकिया हैं उसमें सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना करके आम नागरिकों को उन्होंने राहत प्रदान की है। इसके साथ-साथ रेजिडेंशियल अस्पताल में भी उन्होंने करोड़ों रुपये लगाकर आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

उन्होंने चिकित्सा के साथ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को क्रमोन्नत किया। जो स्कूल 8वीं तक थी उसको 10वीं तक करना, 10वीं तक थी उसको 12वीं तक करना, स्कूलों को क्रमोन्नत करके स्कूलों के विकास की बात की। बच्चों के विकास की बात की। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी समझा कि हर आम आदमी के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके का आज का परिवेश हो रहा है, हम बड़े-बड़े लोग जो लाखों रुपये कमाते हैं, वे तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज देते हैं, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, बाहर बच्चों को भेज देते हैं लेकिन आम आदमी क्या करें, असहाय व्यक्ति क्या करें? इसी बात को उन्होंने समझा, इस मर्म को समझा और इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल की स्थापना की। आज गरीब का बच्चा भी, असहाय का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़कर अपने आपको इंग्लिश मीडियम के समान जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें उनको सम्मान अपने आप में नजर आ रहा है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने इस तरीके की व्यवस्था लागू की और आम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करने में जो आपने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

चाहे वह काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हो, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना हो, इसके साथ-साथ उन्होंने इन स्कूलों में यूनिफार्म भी नि:शुल्क करके जो हरेक बच्चे को व्यवस्थित, सुंदर और स्वच्छ वातावरण

(श्रीमती मनीषा पंवार)

प्रदान करने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ बाल गोपाल योजना, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए सप्ताह में दो दिन जो दूध पिलाने का काम, हम सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले मां यह कोशिश करती है कि मेरे बच्चे को दूध पिलाया जाये, तो यह भावना भी हमारे मुख्य मंत्रीजी में नजर आयी और उन्होंने बाल गोपाल योजना के तहत हर बच्चे को सप्ताह में दो दिन दूध पिलाने का काम किया।

इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया। यहां तक कि बाहर अब्रॉड में भी बच्चों को भेजने की सरकार ने जो योजना बनाई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना नजर आती है। हमारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, फिजिकल कालेज, जोधपुर में 150 करोड़ रुपये की लागत से उसका विकास करना और इसके साथ-साथ खिलाड़ियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी अर्जित कर रहा है तो वह खेल में भी अपने आपको विकसित करे।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): उसके लिए खेल भी उतना ही आवश्यक है जितनी कि शिक्षा उसके लिए आवश्यक है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का विकास करना और इसके साथ-साथ हमारे जो भी सायरा किला मैदान है, उसमें करोड़ों रुपये लगाकर बजट का आबंटन करना। इंदिरा गांधी रसोई योजना, आप यह देखिये कि जहां पर दस रुपये में चाय मिलती है वहां पर आठ रुपये में शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन कराने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। सम्मानपूर्वक टेबल पर बैठाकर उसको खाना खिलाने का काम, जिस तरह कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोए की तर्ज पर मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना का निर्माण किया और आज वह योजना चरम पर है। बहुत ही अच्छे ढंग से यह योजना चल रही है, आम गरीब आदमी को आठ रुपये में भोजन मिल रहा है।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के साथ-साथ शहरी ओलम्पिक खेल की शुरुआत भी होने जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लाकर जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी आम लोगों को राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि जिस तरह लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना, हम सुनते थे कि एक श्रवण कुमार हुआ करता था और वह अपने माता-पिता को यात्रा करवाता था लेकिन आज मुख्य मंत्रीजी ने हर घर का श्रवण कुमार बनकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवायी है। मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

नई पेंशन योजना खतम करके जो उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि हर बुजुर्गों की लाठी बनने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। सम्मानपूर्वक बुजुर्ग अपनी जिंदगी जिएंगे तो उनका भी सम्मान होगा, वे आत्म-सम्मान से अपनी जिंदगी जी पाएंगे।

जब हमारी बहन महिलाओं की बात करती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात करती है लेकिन उनको यह नजर नहीं आया कि एफ.आई.आर. हमने अनिवार्य की है, इसीलिए आप लोगों को यह पता चल रहा है कि इतनी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं, आप महिलाओं की रसोई के ऊपर ध्यान दीजिए। कहां एक हजार रुपये से ज्यादा का आप सिलेंडर कर रहे हैं? दाल-आटे का भाव आप कहां तक बढ़ाये जा रहे हैं? आप अगर महिलाओं का वास्तव में सम्मान करते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनायें, ठोस योजनाएं बनायें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): इसके साथ-साथ, पूरे भारत में जिस तरीके से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सर, एक मिनट में। जिस तरीके से ग्रामीणों में मनरेगा योजना चल रही है तो शहरों में भी मनरेगा योजना की शुरुआत मुख्य मंत्रीजी ने की है और मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी आदरणीय प्रधान मंत्री मोदीजी को कि आप मनरेगा का पैसा बढ़ाइये ताकि आम गरीब आदमी को, घर में बैठे हर उस व्यक्ति को जो इस योजना से जुड़ा हुआ है वह अपनी कमाई को और बढ़ा सके। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात खतम करती हूं।

जो मांगा वह मिला, जुमला नहीं विश्वास मिला, हर डगर को विकास का एक सोपान मिला। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण पढ़वाया गया, सरकार की उपलब्धियां गिनायी गयीं लेकिन वास्तविक स्थिति देखें धरताल पर तो आपको क्या नजर आयेगा, क्या देखने को मिलेगा? यह अभिभाषण असत्य का पुलिंदा है, इसमें लिखी हुई सब बातें सत्य से बहुत परे हैं। सरकार अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी-बड़ी बातें अभिभाषण के माध्यम से कहलवा रही है लेकिन जनता से अगर मिलेंगे, धरातल पर देखेंगे तो वहां पर लगेगा कि जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। सरकार की जन विरोधी नीतियां, कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज से परेशान है जनता। आने वाले विधान सभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार तो जायेगी ही और आपके दस-बारह से ज्यादा लोग जीतने वाले नहीं हैं, यह आप इस सदन में याद रख लेना। हां, इतने ही आने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 7 में यह लिखा है कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन के मूलमंत्र को धरातल पर उतारा जा रहा है। मुझे यह कहीं नजर ही नहीं आता कि सरकार में कोई संवेदनशीलता है, न पारदर्शी है, न ही जवाबदेह है और न ही सुशासन है। प्रदेश में जंगलराज है, कानून व्यवस्था तहस-नहस हो गयी है। मैं कानून व्यवस्था का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी हालत क्यों हुई है? आप सुन लें और जान लें।

कांग्रेस सरकार में मुख्य मंत्री बनना, मुख्य मंत्री बने रहना, चार सालों में ब्यूरोक्रेसी दो भागों में बंट गयी आपसी स्वार्थ और लड़ाई के कारण, वह यह कहता है कि मैं मुख्य मंत्री बनना चाहता हूं और वह कहता है कि मैं मुख्य मंत्री रहना चाहता हूं। प्रदेश की सरकार कई महीनों तक होटलों में बंद रहती है, ऐसी परिस्थिति है और जितने भी ये सरकार के विधायक हैं, वे अपने आपको मिनी मुख्य मंत्री बनकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।

मैं इस अवसर पर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा बताऊंगा तो आप देखेंगे, दंग रह जायेंगे।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कांग्रेस के यह चार साल, राजस्थान बदहाल। कानून-व्यवस्था की जानकारी मैं आपको दूं। विगत चार वर्षों में 8 लाख 31 हजार मुकदमे दर्ज हुए हैं और 6550 निर्दोष लोगों की जानें गयीं, यह जिम्मेदारी कौन ले रहा है? चार वर्षों में महिलाओं के ऊपर 1 लाख 61 हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 27 हजार से ज्यादा बहन-बेटियों के ऊपर दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हुए यह दुष्कर्म की सरकार हो रही है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि गृह मंत्री कौन? खुद मुख्य मंत्रीजी के हाथ में यह है।

उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई, सर तन से जुदा के नारे लगे। आतंकवादी आ रहे हैं, लोगों को मारकर जा रहे हैं, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पुलिस के अन्दर शिकायत करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अलवर के अन्दर किसान चिरंजीलाल को समुदाय विशेष के लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भीलवाड़ा के अन्दर आदर्श तापड़िया की हत्या की गयी। चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या हुई। राजधानी में महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में रामनवमी की शोभा-यात्रा पर रोक लगाने का कोई पाप किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने कुख्यात संगठन पी.एफ.आई., पापुलर फ्रंट आफ इंडिया, उसको परमिशन देकर कोटा के अन्दर जुलूस निकालने की इजाजत देने का काम अगर किसी ने किया तो यह आपने ही किया।

भरतपुर के अन्दर कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली को खनन माफियाओं ने कब्जे में ले लिया। पूज्य संत श्री विजयदासजी ने आमरण अनशन किया, उनको आत्महत्या करनी पड़ी लेकिन सरकार ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की। सालासर दरबार में बुलडोजर से भगवान राम के परिवार को ढहाया गया। अलवर के राजगढ़ में ड्रिलिंग मशीन से शिव लिंग को हटाया गया। कठूमर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का पाप का काम आपने किया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आपका अध्यक्ष था बी.जे.पी. का, आप किसका नाम ले रहे हो? शिव लिंग हटाने का जो काम हुआ उसमें आपका अध्यक्ष था।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सरकार आपकी है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): इनके अध्यक्ष ने हटवाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात को चालू रखें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कम से कम दो दर्जन से ज्यादा साधु-संतों की हत्याएं की गयीं। प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक तनाव की आग लगाने का काम कभी होता है तो वह कांग्रेस के राज में ही होता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के पीपाड़ शहर में बारावफात के जुलूस के अन्दर बेखौफ रूप से सर तन से जुदा के नारे लगे, दंगाइयों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार ने नहीं की।

अलवर के थानागाजी में एक महिला के साथ उसके पति के सामने गैंग रेप हुआ, वीडियो वायरल हो गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं। महिला दुष्कर्म में राजस्थान नम्बर वन। दलितों पर अत्याचार के मामले में नम्बर वन। साइबर क्राइम में राजस्थान का नम्बर वन। बिजली की कीमतों में नम्बर वन। डीजल-पेट्रोल की कीमतों में नम्बर वन। परीक्षाओं में पेपर लीक करने का काम नम्बर वन। 16-16 बार परीक्षा होती है। बेरोजगार युवा आपको देख रहा है कि यह कांग्रेस की सरकार उनको रोजगार देगी। 17 बार परीक्षा होती है और 17 बार पेपर लीक होता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अभी तो दो मिनट हुए हैं, साहब।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): वरिष्ठ अध्यापक का पेपर 29 तारीख को वापस हो गया। इनको पता ही नहीं है। तथ्यात्मक बोलें। आज ही प्रिविलेज आया है। बिना तथ्यों के बोल रहे हैं। आंकड़े कहां से लाये आप?

श्री सभापति: आप रहने दो। बिना मतलब का समय बढ़ रहा है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, अभी तो चार मिनट हुए हैं। कृपा कीजिए मेरे ऊपर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की क्या व्यवस्था है? सम्पूर्ण कर्ज माफी के लिए आपने कहा था, उसका कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कि किसानों को दिन में आठ घंटे बिजली मिलेगी। उसका क्या हुआ? रात को बिजली मिल रही है। ऊर्जा मंत्रीजी, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि किसानों को बिजली रात को मत दो। किसानों की हाय लग जायेगी। वह अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है और वह अन्न पैदा नहीं करेगा तो हवा खानी पड़ेगी। याद रख लेना। सबको भूखे मरना पड़ेगा। हम शहर में जरूर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रहते हैं लेकिन वह अन्न पैदा करता है। किसान को आप रात को खड़ा कर रहे हो। मेरा एक निवेदन है कि आप और हम सब एक बिरादरी के लोग हैं, इस सदन में आते हैं, हम सबको किसान के साथ रात को खड़ा रहना चाहिए। हमारा सेक्रेटरी, एमडी, सीएमडी, चेयरमैन, विधायक और जन-प्रतिनिधि जितने भी हैं, वह सब, मंत्रिमण्डल है, उन सब को एक बार काश्तकारों के साथ रात को खड़ा होना चाहिए। किसान किस प्रकार से रात में कड़ाके की सर्दी में पिलाई करता है, उनको वहां खड़ा रखो, आप भी खड़े रहो और हम भी खड़े रहेंगे, तब जाकर किसान की पीड़ा को यहां पर कहा जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि बिजली के बिलों में करंट आता है। सात-सात बार आपने बिजली के बिल बढ़ा दिये। फर्जी वीसीआर भरे जा रहे हैं। दो-दो, तीन-तीन लाख रुपयों के वीसीआर भरे जा रहे हैं। जब आदमी खाना खाता है, किसान घर आता है, उस समय बिजली के तारों में लाइट नहीं है। मेरा निवेदन है कि चितौड़ जिले के अन्दर 400 केवी का बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण रात को बिजली दी जा रही है। आपने वह ट्रांसफार्मर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट में कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक बात और कहना चाहता हूं। सर, आठ मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके सचेतक की तरफ से आपको आठ मिनट ही दिये गये हैं। प्लीज सहयोग करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट, सर।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस अभिभाषण में 281 बिन्दुओं के माध्यम से राज्य सरकार की

(श्री मेवाराम जैन)

योजनाओं पर प्रकाश डाला। आप देख रहे हैं, उस पर आपके सामने अभी चर्चा भी हो रही थी। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने पिछले चार वर्षों में ऐसा कोई भी वर्ग पीछे नहीं छोड़ा, न कोई योजना ऐसी छोड़ी जो आम, गरीब, किसान, उद्योग, व्यापार से जुड़े हुए हरेक वर्ग के लिए शानदार साबित नहीं हुई हो। उन्होंने इन चार सालों में शानदार योजनाएं शुरू की हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन चार सालों में दो साल तो कोविड की महामारी से बचाव के उपायों में लग गये, दो साल बचे, उसमें आर्थिक मन्दी रही। उद्योग बन्द रहे, सारे कारखाने बन्द रहे। मजदूर वगैरह सभी दुःखी रहे, उसके बावजूद शानदार योजनाएं और शानदार बजट दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बजट के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं, कोई केन्द्र की बात कर रहा है, कोई कहां की बात कर रहा है। बजट की योजनाओं के बारे आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हो कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चिरंजीवी योजना का लाभ और मुफ्त दवा योजना का लाभ आपके लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? आपको पता ही नहीं है कि 15 साल पहले इलाज कराने के लिए क्या हालत होती थी। किस तरह से इलाज के लिए लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती थी, वह आप भूल गये। पता ही नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किस तरह से इस योजना को शुरू किया। राजस्थान प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत के अन्दर इस योजना को सराहा गया। आप अच्छे काम की प्रशंसा करना भी सीखो, कहना भी सीखो।

आज शिक्षा की बात करो। एक साथ पांच हजार सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में क्रमोन्नत किया गया। जिसमें से 3834 तो सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी...(व्यवधान) आपके विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुई क्या? उसमें कोई भेदभाव किया क्या? सभी के लिए नहीं किया गया? हम भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव आप कर रहे हो। आप उसके लिए बोल ही नहीं रहे हो। अंग्रेजी मीडियम की इतनी सारी स्कूल्स खोली गयीं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): खाली हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): खाली हैं तो भर भी जायेंगी। आप चिन्ता मत करो। सारे अध्यापक भी भर लेंगे। आपको चिन्ता करने की जरूरत ही नहीं है। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है।

श्री सभापति: बीच में इन्टरवीन नहीं करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): प्रशंसा आप करो भी कैसे? कर भी नहीं सकते। अच्छे कार्य और योजना के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप बातें कर रहे हो।

बिजली में कृषि कनेक्शन के लिए किसानों के एक हजार रुपये की छूट बिल में दी जा रही है। पचास यूनिट बिजली जो फ्री दी जा रही है, उसमें बहुत से परिवारों के बिल जीरो आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा। अभी तो जो बजट आ रहा है न, उसमें आप देखना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप अपने स्थान पर जाइये। Please go to your seat. I will not allow it. माननीय मंत्री महोदय, आप भी जाइये। प्लीज।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बिजली के मामले में माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या करेंगे बजट में, आप देखते रह जाओगे। उनकी जादूगरी ऐसी चलेगी कि आपका मुंह बन्द हो जायेगा। आप बोल नहीं पाओगे।

सभापति महोदय, इन्दिरा रसोई योजना बहुत बड़ी योजना है। गांव के लोग शहर में जाएं, अस्पताल में जाएं, कलेक्ट्रेट में जाएं, बस स्टैण्ड पर जाएं, सभी जगह आपको आठ रुपये में बहुत शानदार खाना मिलेगा। इतना शानदार खाना, इतनी शानदार योजना है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी की बात नहीं है। इस शानदार योजना की आपको प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन आप तो सीखे ही नहीं, आप तो आलोचना करना ही सीखे हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी शानदार योजना है। कर्मचारी कितने खुश हुए पूरे राजस्थान के। जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन आपके मुंह इतने हो गये थे, आप बोल नहीं पा रहे थे। बोल तो अब भी नहीं पा रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो, हम इतने आ जाएंगे, यह कर देंगे। भविष्य बतायेगा कि आपका होगा क्या।

प्रशासन गांवों के संग में शानदार काम हुआ। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर बताओ कि कितने लोगों को वहां पट्टे दिये गये, कितने लोगों के म्युटेशन हुए, कितने उसमें काम किये गये? यह आपको पता ही नहीं है। आप हर जगह गये होंगे, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना काम हुआ। प्रशासन शहरों की ओर अभियान में बहुत काम हुआ। कितने पट्टे दिये जा रहे हैं। पट्टे देने का काम आपने बन्द कर दिया था, आज घर बैठे पट्टे मिल रहे हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

शहरों के विकास के लिए सड़कें देना और शहर का विकास किस तरह से हो रहा है, यह आपको अन्दर से सब पता है। बोलना आपकी मजबूरी है।

सभापति महोदय, मैं पानी की योजनाओं की बात करूं तो हमारी शानदार योजना है परन्तु केन्द्र सरकार को 90 परसेंट पैसा देना था उसकी जगह 45-45 किया ताकि यह योजना आगे नहीं बढ़े। लोगों को पानी नहीं मिले। यह आपकी नीति है। आप भेदभाव कर रहे हो और जनता के साथ आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, जनता आपको कभी माफ करने वाली नहीं है।

मैं सड़क के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले गुजरात की बात करते थे कि गुजरात की शानदार सड़कें हैं, अब राजस्थान की तुलना गुजरात से करके देख लो। राजस्थान में शानदार सड़कें हैं। हर जगह अच्छी सड़कें बन गयी हैं। आप बाड़मेर आकर देख लेना, आपको एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। सारी शानदार सड़कें हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? क्यों इन्टरवीन कर रहे हो बीच में?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक और बात कह दूं कि जो यह बजट आयेगा न, आप हक्के-बक्के रह जाओगे कि जादूगर ने क्या जादूगरी कर दी। आपका मुंह बंद हो जायेगा, आप बोल नहीं पाओगे कि क्या हो गया? चाहे उद्योग में हो, रिफाइनरी, आप तो रिफाइनरी को बंद कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किस तरह से उस रिफाइनरी को शुरू किया और आज रिफाइनरी के क्या हालात हैं? आज रिफाइनरी का 60 प्रतिशत काम हो चुका है और उससे कितना रोजगार मिलेगा और राजस्थान की जनता का कितना भला होगा, यह आपको पता नहीं है। आप तो उसको बंद करने में थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह योजनाएं, चाहे पेंशन योजना हो, बुजुर्ग हो, 55 साल की महिला हो, 58 साल का पुरुष, विधवा, विकलांग, असहाय, इनको पेंशन कितनी लार्ज स्केल में सैंक्शन हुई है। सात करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा लोगों को यह पेंशन मिल रही है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य। दो मिनट में करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दो नहीं, पांच मिनट में कर दूंगा। मेरा निवेदन है कि आप बातें कर रहे हो, सिर्फ नारे मत लगाओ। गायों की बात करें, आप कह रहे थे कि गायों के लिए कुछ नहीं किया। आपने गायों का नाम लेकर सिर्फ वोट लेने का काम किया, गायों के लिए आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तीन महीने का अनुदान पहले हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी गहलोत साहब ने शुरू किया, फिर छह महीने का किया, फिर नौ महीने का किया। अभी थोड़े दिन पहले जिला मुख्यालय पर नन्दीशाला खोलने का काम किया है। पंचायत समिति पर नन्दीशाला खोलने का काम किया है। मैं आपको फिगर बताता हूं। आप इसमें खोलना नहीं चाहते हो, हमने टार्गेट दे रखा है कि इतनी नन्दीशालाएं खोलो, इतनी गौशालाएं पंचायत लेवल पर खोलो। पंचायतों के अंदर एक करोड़ रुपये का अनुदान दे रहे हैं। 9 महीने का दे रहे हैं। पंचायत समिति में 01 करोड़ 57 लाख रुपये दे रहे हैं और 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं। जिला स्तर पर दे रहे हैं। आप वहां पर आइये तो सही। आपने खोले हो तो बतायें। आप आवेदन करिये, रजिस्ट्रेशन में छूट दी है। पहले तीन साल का था, उसको हमने छूट दे दी। जमीन जो 20 बीघा थी, उसकी जगह 10 बीघा कर दी। पंचायत लेवल पर सिर्फ 5 बीघा कर दी। आप काम करिये न, आपके काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए आप एक ही बात कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे बाड़मेर की बात करूंगा। हमारे जो एस.टी. के लोग हैं, आप एस.टी. के लोगों की तुलना कर लो तो जोधपुर डिविजन में, उदयपुर डिविजन और इनकी तुलना कर लो, टाडा-माडा योजना का लाभ उदयपुर में मिल रहा है। हमारे वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। न नौकरियों में उनको कुछ फायदा मिल रहा है, और तो छोड़ो, बिजली कनेक्शन एस.सी. को दे रहे हैं, उसको बिजली कनेक्शन दो। एस.टी. के लोग हमारे वहां के आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि उनके लिए यह करना बहुत ही जरूरी है और उनकी मांग बहुत ही वाजिब है।

माननीय सभापति महोदय, मैं संविदा कर्मचारियों की बात करना चाहूंगा। हमारी सरकार इस ओर दृढ़ संकल्प है और कमेटी भी बनी है। आप देखेंगे कि संविदा कर्मचारी को ही हम राज़ी कर लेंगे, आप टेंशन मत करो।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में

(श्री मेवाराम जैन)

खतम कर रहा हूं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस बजट में जितनी भी योजनाएं हैं, शानदार योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी की हैं।

श्री सभापति: विराजिये। इनका अंकित नहीं होगा। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रखता हूं कि समय की सीमा है। ना पक्ष को 8 मिनट दिये गये हैं। यदि आप आपस में एक-दूसरे के समय व्यवधान डालेंगे तो आप अपनी बात नहीं कह पायेंगे। आप संयम बरतें, शालीनता बरतें। सदन आपसे अपेक्षा रखता है, आसन भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप गंभीरता बनाये रखें। माननीय दिलावर जी, अपने स्थान पर आइये। आप अपने स्थान पर आइये। Please go to your seat. मेहरबानी करके एक-दूसरे को व्यवधान नहीं डालें। शालीनता बनाये रखें, अनुशासन से यदि आप बोलेंगे तो आप अपनी अच्छी बात रख पायेंगे। एक-दूसरे को यदि आप इंटरवीन करेंगे तो इससे समय खराब होगा और मैं आपको निश्चित समय में बैठा दूंगा। आप समय का ध्यान रखें और जरूरी नहीं कि आप बैठे-बैठे बोलें। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, सभापति महोदय, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले जनता के साथ में धोखा किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। आधा प्रतिशत वोट फर्क से राजस्थान में आप लोग उधर की साइड में बैठे हुए हैं। किसानों के साथ में कर्जा माफी का वादा किया, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए गुमराह करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। इसके बाद में बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे, उद्योगों के अंदर हम इतना विकास कर देंगे। यदि मैं उद्योग की बात करूं तो किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत होती है तो वह मंत्री महोदया यहां बैठी हैं, उद्योग विभाग की है।

माननीय सभापति महोदय, अभी अक्टूबर, 2022 में सरकार का

(श्री अभिनेश महर्षि)

इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, बहुत प्रचार-प्रसार किया गया। माननीय सभापति महोदय, 100 करोड़ से ज्यादा इसके अंदर खर्च किया गया और ऐलान किया गया कि 11 लाख करोड़ रुपये के MOU हमने कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, जुलाई, 2022, केन्द्रीय मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की जो ताजा रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट यह कहती है कि 2020 में राजस्थान में 3,950 करोड़ रुपये निवेश किये गये और 2021 में 4,092 करोड़ रुपये निवेश आया। पिछले दो वर्षों में यदि इनका योग कर लिया जाये तो 8,050 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आपके राज्य में आया है। अब इसके बाद में 4,192 करोड़ रुपये के MOU किये गये और 647 ही मात्र धरातल पर उतरे। अब आपके पास में कौनसे जादू की छड़ी है जिसके कारण आप थोथी घोषणाएं करते जा रहे हैं और हम राजस्थान के अंदर इतना उद्योग लगा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैंने कई बार यह मांग की कि वहां पर औद्योगिक संवर्धन केन्द्र खोल दिया जाये जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज दिन तक उद्योग यह पूछ रहा है कि यह औद्योगिक संवर्धन केन्द्र होता क्या है? राजस्थान की सरकार को इस बात का पता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, वह जन आक्रोश यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति के लिए, पांच मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं- बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क। इनके राजस्थान में क्या हालात हैं, यह आप लोगों को जन आक्रोश यात्रा में जो लोग गये हैं, उनको वहां की जनता किस तरह से त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रही है, इस बात का ताजा उदाहरण गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ...(व्यवधान) क्या बोल रहे हैं, मंत्री महोदय?

श्री सभापति: कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात कहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप यह कह दीजिये कि यह बीच में बोलेंगे तो इनका समय जाया होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें, मैं समय काट लूंगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आसन को कर रहा हूं, लेकिन यह बीच

(श्री अभिनेश महर्षि)

में नहीं बोलेंगे। यह मैं आसन के माध्यम से निवेदन कर देता हूं। कोई बीच में नहीं बोलेगा और बोलेगा तो उसका समय काट लिया जायेगा।

श्री सभापति: सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें, बिजली मंत्रीजी अभी यहां बैठे थे, कड़ाके की ठंड में किसानों के हालात देखे नहीं जा सकते हैं। मेरे चूरू जिले के अंदर और मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर जब रात को किसान को बिजली दी जाती है तो वह पाइप के अंदर बर्फ के टुकड़े बाहर निकलते हैं और किसान वहां खड़ा रह नहीं सकता है। वहां पर अभी जो ओले पड़े हैं, पाले की स्थिति आयी है, इसके कारण किसान की फसल बरबाद हो गयी। आने वाले समय के अंदर किसान किस तरह से कर्जा लेकर अपनी फसल की बुवाई करता है, यह आप सब लोगों के सोचने की बात है। माननीय सभापति महोदय, फिर भी बिजली की कटौती ऐसे समय में की जाती है, अघोषित बिजली की कटौती की जाती है और राजस्थान की सरकार कहती है कि हम तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जायेंगे। अगर आत्मनिर्भर बन गये तो फिर यह बिजली की कटौती क्यों की जा रही है? अधिकारी हमेशा यह कहकर बहाना करते हैं, तीन-तीन साल से कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। किसान कर्जा लेकर लाखों रुपया जमा कराता है और उसके बाद में किसान को जब कनेक्शन नहीं मिलता है तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफार्मर गांवों के अंदर लगे हुए हैं, वह ट्रांसफार्मर नीचे हो गये और उनको जब बदलने की बात बिजली विभाग के अधिकारियों को करते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास में सामान नहीं है, हमारे पास में लेबर नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है, यह बिजली विभाग की बात बता रहा हूं। राजस्थान की इस नाकारा सरकार ने यह तय कर लिया है कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी नहीं होने देंगे।

(समय: 16.00 बजे)

जो भारत सरकार की स्कीम थी, जो राजस्थान की पूर्ववर्ती हमारी यशस्वी सरकार थी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने ढाणियों में कनेक्शन देने की योजना बनाई थी, गरीब के घर में रोशनी करने का काम किया था लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले यदि कोई कलम चलाई तो वह गरीब के घर में, ढाणियों की जो योजना थी, उसको बंद

(श्री अभिनेश महर्षि)

करने का काम किया। विद्युत दरें नहीं बढ़ाने वाली सरकार धोखे पर धोखा किये जा रही है। इन्होंने विद्युत दरों को इतना बढ़ा दिया कि अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उनमें करंट है। तारों में करंट नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणावीर सरकार घोषणा करने में तो अव्वल है, लेकिन घोषणाओं का 30 परसेंट भी धरातल पर नहीं उतार सकी है। 4 साल के अंदर थोथी घोषणाएं करके, होटलों में बंद रहकर के इस सरकार ने जो जनता के साथ में धोखा किया है, उसे जनता आने वाले समय में माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, पानी की बात करें। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमारी केन्द्र की सरकार थी। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल सपना नहीं देखा बल्कि यह कल्पना की कि मैं घर-घर में नल से पानी पहुंचा दूंगा। उसका उलटा करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। पहले रोना रोते रहे कि हमको 90 परसेंट सब्सिडी दे दो। हमको 90 परसेंट दे दो, 10 परसेंट हम देंगे। क्यों? जब 50-50 परसेंट का नियम है तो आप अलग से हैं क्या? ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इतनी देरी कर दी। 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर नल से पानी पहुंच रहा है, लेकिन राजस्थान इसमें फिसड्डी साबित हुआ है। राजस्थान की सरकार ने तय कर रखा है कि लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जायेगा। योजना बनाने के लिए कमेटियां बना दीं। पैसा जमा हो गया। गांव के लोग हमसे पूछते हैं कि पानी कब मिलेगा? मैंने कहा, पूछो राजस्थान सरकार से कि पानी कब देंगे। यह स्थिति बिजली के बाद में पानी की है।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता चिकित्सा विभाग की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। यह कह रहे थे, किस मुंह से बोल रहे हो, आयुष्मान भारत की योजना है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): यह लो, यह क्या हुआ? बिजली की बात करें। पानी की बात करें। शिक्षा के अंदर विद्यालय खोल दिये, विद्यालयों में टीचर्स नहीं हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों को खोलने की बात की, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं।

रतनगढ़ को जिला बनाने की बात करता हूं। यह बोलने नहीं देते हैं। क्या करें अब? रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग मैं कर रहा हूं। राजलदेसर को तहसील बनाओ। रीको इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रोथ सेंटर बनाओ।

(श्री अभिनेश महर्षि)

जो सीएचसी और पीएचसी की बातें हैं, मैं चिकित्सा की बात कर रहा था। अस्पताल खाली पड़े हैं। रतनगढ़ के अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन डाक्टर्स नहीं हैं। सीएचसी खाली पड़ी हैं, पीएचसी खाली पड़ी हैं। स्कूलें खाली पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सभी मामलों में राजस्थान की सरकार फेल हो गयी। उद्योग विभाग के हालात अभी मैंने बताये ही हैं।

ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार जनता के साथ में और अन्याय नहीं करे। अन्याय करना बंद कर दे। आने वाले समय में यह जो फोर्चूनर की बात कर रहे थे, अब तो टैंपो में आ गये हो। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का पांचवां अभिभाषण पिछले 4 साल में किये काम और भविष्य की सरकार की नीति का दस्तावेज है।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 4 साल में हमने 39 स्कूल क्रमोन्नत करवाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 30622 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 9 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सैकड़ों बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कालेज में 60 बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आईटीआई में अभी तक 35 बच्चों का एडमिशन हुआ है। आईटीआई कालेज शुरू हो चुका है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2021 के बजट में खाला निर्माण की जो घोषणा हुई थी, 84 करोड़ रुपये की लागत से अमरसिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर के खाला निर्माण हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार 2022 के बजट में जो भादरा से झांसल सड़क के निर्माण की घोषणा हुई थी, वह सड़क बनकर के तैयार हो गयी। मार्च में हम लोकार्पण कर देंगे।

सभापति महोदय, हजार उपलब्धियां हैं, कुछ कमियां भी हैं। मैं राजस्थान के नौजवान से और राजस्थान के किसान से कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जो डिबेट राजस्थान की विधान सभा में हो रही है, कुछ लोग जिस तरीके से मंत्रियों के कमरों में झांक-झांक करके देख रहे हैं कि थोड़े दिन बाद हम यहां बैठेंगे और इस कुर्सी को इस हिसाब से, इस वास्तु से

(श्री बलवान पूनियां)

लगायेंगे। मैं याद कराना चाहता हूं कि 5 साल पहले राजस्थान में क्या होता था। 18 हजार स्कूल बंद किये गये थे। राजस्थान में बिजली के दाम बढ़ाने की नाकाम कोशिश की गयी थी। राजस्थान में आनंदपाल के एनकाउंटर के साथ जिस प्रकार अपराध के नमूने पेश हुए थे, मैं वह सब बातें राजस्थान के नौजवानों को बताना चाहता हूं।

जिस तरीके से कर्मचारियों का अहित किया गया था। 2004 से लेकर के लगातार 2018 तक एनपीएस को वापस हमने ओपीएस में किया है। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि उस ओपीएस को और वृहद् करने की जरूरत है, राजस्थान रोडवेज और बिजली के कर्मचारियों तक लेकर जाने की जरूरत है।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना को लागू किया, आपने लोगों को जुड़ने के लिए जो समयावधि दी है, हम उसमें करेक्शन चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि उसमें आप नये आदमी को जोड़िये। प्रीमियम जमा कराने के 24 घंटे बाद वह मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से इलाज ले सके, ऐसी स्थिति हमें पैदा करने की जरूरत है।

मैं याद करना चाहता हूं राजस्थान के उस आखिरी आदमी को जो एसएमएस के चक्कर काटता था, जो किसी एमएलए से, एमपी से कहता था कि मेरा डाक्टर से इलाज करा दो। आज राजस्थान के अंदर यह स्थिति नहीं बची है। पिछले 2 साल में कोई एमपी या एमएलए के घर इलाज के लिए सिफारिश करने नहीं जाता है। यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की वजह से सम्भव हुआ है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का आदमी सांगानेर के पीयूष मेडिलाइट हास्पिटल में आया। वहां उस हास्पिटल की दूसरी ब्रांच और है। वह आदमी को एडमिट करने के बाद, भोला-भाला आदमी देखकर के बोला कि तेरा इलाज तो दूसरी जगह न्यूरो का होगा। उसका आपरेशन किया। वहां उससे पैसे ले लिए। मैं मौके पर गया। मैंने पूछा, मेरे बाद तो उसने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उस आदमी से 99 हजार रुपये पहले खोस लिए थे। इस तरीके की जो कमियां हैं, उनको दुरुस्त करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो फसलों में तबाही आयी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 4 साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम हुआ है। मेरे पूरे जिले में आप ताज्जुब करोगे, 3400 करोड़ रुपये फसल बीमा क्लेम मिला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1266 करोड़ रुपये का फसल बीमा का क्लेम मिला है। 2021 की खरीफ में बीमा कंपनी के पेट में गुड़गुड़ी होनी शुरू हो गयी। उसने बेईमानी की और सैटेलाइट का केन्द्र सरकार से अधिसूचना में नाम डलवा लिया। सैटेलाइट से बीमा हनुमानगढ़ और चूरू में दिया। मैं सदन से मांग करता हूं, आपसे मांग करता हूं कि यह सैटेलाइट की दुकान बंद करवाई जाये। बीमा का क्रोप कटिंग एक आधार है नुकसान तय करने में, क्रोप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम दिलवायें। मेरे पास 18 पटवार मंडलों के कागज हैं, जो को-विटनेस हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और एसीएस, कृषि को, सबको कागज उपलब्ध करा दिये। मेरी मांग है कि 2021 की खरीफ का मूंग, मोठ का फसल बीमा क्लेम सैटेलाइट की बजाय क्रोप कटिंग से दिया जाये। न सिर्फ हनुमानगढ़ का बल्कि चूरू जिले का भी दिया जाये।

सभापति महोदय, मेरी यह भी मांग रहेगी कि यहां कल जो चर्चा हुई थी सदन में और जो बात कर रहे थे टोल फ्री नंबरों की। मंत्री महोदय ने टोल फ्री नंबरों का ऐलान किया। टोल फ्री नंबर कोई नहीं उठाता। इसलिए सिर्फ राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए जो भारत सरकार ने अभी एक लैटर जारी किया है, यह लैटर की तारीख है मेरे पास 10 अक्टूबर, 2022, यह लैटर मैं राठौड़ साहब को समर्पित करता हूं कि आप भारत सरकार से संशोधन कराइये।

आप कह रहे थे कि एसडीआरएफ का पैसा 19 हजार करोड़ रुपया पड़ा है। इस लैटर में यह कहा है कि आप एसडीआरएफ का जो पैसा खर्च करो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा भी काट लेना। यह लैटर मैं आपको दे रहा हूं। आप भारत सरकार को कहिये कि एसडीआरएफ का पैसा एसडीआरएफ के हिसाब से ही दे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दे, क्षतिपूर्ति क्लेम के रूप में दे।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र समेत बात करना चाहूंगा

(श्री बलवान पूनियां)

कि राजस्थान का हिस्सा जो वाया हरियाणा हमें सीपी-4 और सीपी-5 पर पानी मिलता है, जो बीबीएमबी में पानी तय हो गया, वह हमारा पानी हरियाणा और पंजाब गटक जाते हैं। टेल के आदमी की मौत होती है। टेल पर यह दिक्कत आती है कि उसको उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाता है।

सभापति महोदय, हमारी पुरजोर मांग है, मैंने बार-बार सदन में मांग की है कि जो बीबीएमबी में हमारा हिस्सा तय हो जाये, वह हमारे खेतों तक पहुंचे, भादरा, नोहर की नहरों तक पहुंचे। पिछले दिनों 2 महीने लगातार बरसात हुई। हरियाणा में बरसात का एक्स्ट्रा पानी था, जो ओटू हैड से होते हुए घग्घर नदी में डाला गया। हम मांग करते हैं कि उसकी सरकार डीपीआर बनाये और उसको नोहर, भादरा और तारानगर के, चूरू के उन गांवों तक पानी लेकर के आये, जहां आज भी पानी की दिक्कत है।

मैं मांग करता हूं कि जो खाला निर्माण 2004 से 2008 तक इनके कार्यकाल में हुआ, राठौड़ साहब के कार्यकाल में घटिया खाला निर्माण हुआ, वह जो टूट गये, आज हमारा पानी वहां खेतों तक नहीं पहुंच पाता है, सरकार नया बजट दे और नये खाले बनाये। मैं मांग करता हूं कि हमारे इस बजट में राजस्थान की सरकार इस बात की घोषणा करेगी।

मैं मांग करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो अभी चुनाव होते हैं, ये चुनाव किसान के विरोधी हैं, इसलिए सरकार चुनाव बंद करके, मैट, चौकीदार, बेलदार की नियुक्ति करे। जे ईएन नहर की रखवाली करते हैं, सभापति महोदय, जे ईएन का काम तकनीकी काम है, उसका काम नहर की रखवाली करना नहीं है इसलिए जे ईएन से रखवाली करवाने की बजाय मैट, चौकीदार, बेलदार की नियुक्ति सरकार करेगी।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत करने की मैं मांग करता हूं। विकलांगों की पेंशन जो पिछले दिनों मिल रही है, इसको बढ़ाकर 5 हजार रुपये करे और मैं चाहता हूं कि जिनके कर्मचारी बेटे और बेटियां हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा में पेंशन नहीं मिलती है, सरकार इसको ठीक करे। इस पूंजीवादी युग में, इस भौतिकतावादी युग में सब बेटे-बेटियां एक से नहीं हैं जो मां-बाप की सेवा करते हैं, इसलिए सरकार सब वृद्धों को उसकी पेंशन हाथ में दे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मेरी थोड़ी-सी बात बची है। वर्ष 2021 में फसल बीमा में फ्रॉड हुआ, एसीडी में एफआईआर दर्ज हो गई। एसीडी ने कछुआ स्पीड से काम किया। यह बात तो सही है कि एसीडी ने उनको थका लिया, लेकिन हम चाहते हैं जिन लोगों ने फसल बीमा में फ्रॉड किया, मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो फ्रॉड हुआ, बोजरा में जो फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड को आइडेंटीफाई करें। जिन लोगों ने फ्रॉड किया वे जेल की सलाखों के भीतर हों, यह काम एसीडी को करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि जो नौजवान यह कहते हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों को आने से रोकिये, संवैधानिक मान्यता नहीं है इस बात की कि हम हिन्दुस्तान के भीतर किसी दूसरे राज्य के लड़के-लड़कियों को, युवाओं को फार्म भरने से रोक सकें, लेकिन हम राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस राज्य में जाते हैं तो वहां की भाषा हमारे राज्य के नौजवान को समझ में नहीं आती है या वह पकड़ नहीं पाता है, इसलिए राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का काम करें। इससे हमारे राज्य के युवाओं को अधिक मौका मिलेगा। हमारे हर सिलेबस में राजस्थानी को डालने का प्रयास करें, चाहे वह बिजली विभाग का सिलेबस हो, चाहे दूसरे विभागों का सिलेबस हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूरी करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके की बातें चल रही हैं और मेरे बीजेपी के साथी यह बार-बार गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और यह कह रहे हैं कि देखो इधर क्या हो रहा है, तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात सम्पन्न करना चाहता हूं। वह शेर है

अगर उल्फत इधर बड़ी है

तो सवेरा रोशन उधर भी नहीं है,

अगर गहलोत-सचिन की लड़ाई है

तो राजीनामा भाजपा में कोई ज्यादा नहीं है।

सुबह राठौड़ साहब जोर मार रहे थे और पूनियांजी अपनी जगह से उठे ही नहीं, इसलिए राजस्थान के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मजबूती से आगे बढ़ो और ज्यादा राठौड़ साहब के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आजकल ये पुराने बुड्ढे हो गये हैं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये हाथ छाप कामरेड की बोली है। कामरेड ने बिना मांगे वोट दिया, सरकार का समर्थन किया और मांग करनी पड़ रही है, मांग करो।

श्री सभापति: विराजो। श्री ललित कुमार ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका और मेरी पार्टी के नेताओं का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था तो सभी विधायक, लगभग सभी विधायक जैसे चुनाव में भाषण देते हैं ऐसे भाषण दे रहे थे, सदन में बोलने जैसा नहीं बोल रहे थे। मैं आपका ध्यान इस अख़बार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो 28 तारीख को भास्कर में छपा है, पोषाहार नहीं पशु आहार, बच्चे बीमार न हो जाएं इसलिए जानवरों को डाल रहे हैं। राजस्थान में पोषाहार जो आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाता है, स्कूल में छोटे-छोटे बच्चों को दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसका यह हाल है।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत जोर से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की गई। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जब धरातल पर जाएंगे तब देखेंगे कि जांच हो गई, जिसका आपरेशन होना है तो आपरेशन करने के लिए सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और उनका बीस-बीस दिन, पच्चीस-पच्चीस दिन तक आपरेशन नहीं होता है और उसके बाद आपरेशन होता है। आपरेशन होने के बाद वह जब घर पर जाएगा, उसके घर पर जो भी दवाई चलेगी वो उसको निजी पैसों से लानी पड़ेगी, चिरंजीवी योजना में वो अनुमत नहीं है, उसको जेब के पैसों से लानी पड़ती है। इसी तरह से आरजीएचएस है, जो हम पर भी लागू है, कर्मचारियों के साथ-साथ इसकी सुविधा का लाभ हमें भी मिलता है, लेकिन जब डाक्टर को बता दिया, चैक करा लिया, इलाज करा लिया, वह सब कुछ तो हो गया उसमें उसके बाद कई सारी दवाइयां जो लाइफ लोंग चलेगी, उम्र भर चलेगी, वह दवाई हमको जेब के पैसों से लानी पड़ती है और इसके बजाय अगर राजस्थान ने आयुष्मान भारत योजना लागू की होती तो कल जैसे हमारे गर्ग साहब ने बताया था कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं, उनको भी आयुष्मान

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

भारत योजना का लाभ मिलता और जो दूसरे राज्यों के नजदीक हैं, बोर्डर पर हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात के बोर्डर पर जो लोग हैं, उदयपुर, जयपुर के अस्पतालों में आना उनके दूर पड़ता है, जबकि दूसरे राज्यों के अस्पताल हैं, वहां जाना नजदीक पड़ता है लेकिन वहां पर चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू होने की वजह से उनको यह लाभ नहीं मिलता।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें तो बिजली में कई बार, इस साल कई जगह, कई लोगों ने ज्ञापन दिए, काश्तकारों ने ज्ञापन दिए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, बिजली की मांग की कि हमको दिन में बिजली दी जाए। अभी बिजली का एक सर्किट रात को दस बजे से सुबह तीन बजे तक चलता है। रात को दस बजे से तीन बजे तक और जो दिन में दो फेज में बिजली दी जाती है उनमें भी घंटा-दो घंटा यहां से बंद कर दी जाती हो तो उससे आगे खिसकता-खिसकता वह सर्किट भी रात में चला जाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा किसानों के हित में निवेदन है कि उनको दिन में बिजली दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की यदि बात करते हैं, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि राजस्थान की सड़कें ऐसी हैं, उनको मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आकर देखना चाहिए कि 25 लाख रुपये सिर्फ एक सब-डिविजन में पेचवर्क और रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है, इससे कुछ नहीं होता है। सड़कें सारी की सारी ही क्षतिग्रस्त हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री यदि यहां हों तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन चार वर्षों में रिकार्ड देख लें कि राज्य सरकार के पैसों से कौनसी नई सड़क बनी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी होगी, कुछ नवीनीकरण किया होगा। गत बजट घोषणा में एक सड़क है जो 75 परसेंट मेरी है, 25 परसेंट प्रतापगढ़ वालों की है, लेकिन वह भी अभी तक शुरू नहीं हुई है धरातल पर नहीं आई है। गत वर्ष बजट में एक-एक विधायक की अनुशंसा पर दस करोड़ रुपये देने की बात की थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उन दस करोड़ में से एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका बड़ी सादड़ी है। वहां की सडकें दस किलोमीटर उस साल करनी थी, पन्द्रह

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

किलोमीटर उस साल करनी थी, वो दस किलोमीटर तो हुई लेकिन उसके बाद की पन्द्रह किलोमीटर की सड़कें नहीं हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहां पर मजदूरी करने वाले लोग हैं। मजदूरी करने के लिए जाते हैं और शाम के समय आजकल लगभग हर थाने के बाहर पुलिस की जीप खड़ी रहती है। कोई मोटर साइकिल पर जा रहा है, वह मजदूरी करने के लिए जा रहा है, हो सकता है वे तीन सवारी हों, मजदूरी करने के लिए जाते हैं एक साथ मोटर साइकिल पर बैठकर जाते हैं, उनको भी रोका जाता है और उनका भी सौ रुपये या दो सौ रुपये चालान बनाया जाता है। कार वाले ने किसी ने सीट बैल्ट नहीं लगा रखी तो उसका हजार रुपये का चालान काटा जाता है। रोज ही ऐसी कौनसी नाकाबंदी है? नाकाबंदी अपराधियों को पकड़ने के लिए हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, खाद के लिए, किसान रात में तो पाणत करता है खेत में और दिन में खाद लेने के लिए लाइन में लगता है, यूरिया उसको समय पर मिलता नहीं है, लाइन में लगकर उसको यूरिया मिलता है।

अभिभाषण के बिन्दु संख्या 21 पर लिखा है, निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक-एक स्वास्थ्य मित्र की सेवाएं उपलब्ध कराकर कुल 82 हजार 956 स्वास्थ्य मित्र का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है, लेकिन मेरे यहां पर एक भी नहीं है। ग्राम पंचायत नई, पंचायत समितियां नई, उनके भवन के लिए जमीन आबंटन हो गया, लेकिन उनके लिए बजट आबंटन नहीं किया, वे दूसरे भवनों में चल रही है, उनका राजकीय भवन नहीं बना है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के बिन्दु संख्या 25 में आपने लिखा है कि 12 जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इन सभी कालेजों की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार वहन कर रही है। इसमें यह भी लिख देते कि बाकी की 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार दे रही है, आपने नहीं लिखा है।

बिन्दु संख्या 47 में आपने लिखा है कि प्रदेश को 16 जिलों में किसानों को दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है, 14 जिलों में अप्रैल, 2023 से दिन में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ मांग है। राजस्थान का बजट जो अभी पेश होना है, माननीय मंत्री महोदय, ध्यान दें थोड़ा-सा। बड़ी सादड़ी में 2004 से एडीजे कोर्ट का कैम्प चल रहा है, इसको स्थायी एडीजे कोर्ट के रूप में स्थापित किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगलवाड़-बानसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। डूंगला और बड़ी सादड़ी सीएचसी को क्रमोन्नत किया जाए। पाल और मांड कलां, दो पंचायतों के लगभग 7 हजार व्यक्ति सीतामाता अभयारण्य में निवास कर रहे हैं। यहां पर विद्यालय है, उप स्वास्थ्य केन्द्र है, लेकिन बिजली लाइन से एवं सड़कों से वंचित है। मेरा निवेदन है कि यहां पर डामर नहीं कर सकते तो कम से कम डब्ल्यूबीएम सड़कें बन जाएं।

जनता जल योजना पंचायती राज विभाग से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। इसमें बरसों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना में कार्यरत संविदा कम्प्यूटर आपरेटर्स को नियमित किया जाए। 28 हजार सीएचए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कोविड में लोगों की सेवा की थी, उन्हें वापस किसी न किसी पद पर लिया जाए। बड़ी सादड़ी में एक कालेज है, वहां पर एक भी स्थायी कर्मचारी नहीं है, विद्या सम्बल योजना में जो हैं, वे ही पढ़ा रहे हैं। फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, जो पाले से नुकसान होता है, उसकी भरपाई नहीं होती, उसकी भी भरपाई की जाए। पोषाहार योजना में पूर्व में जो सप्लायर्स थे, उनका भुगतान बकाया है, वह भुगतान किया जाए।

बिजली कम्पनियों में संविदा कर्मियों का मानदेय बहुत कम है, उन्हें परमानेंट किया जाए। नन्दीशाला एक भी नहीं खुली। जनता क्लीनिक नहीं खुला। डोडा चूरा चार वर्ष से सरकार ने नष्ट नहीं कराया। अभी राजस्थान सरकार ने एक आर्डर निकाल दिया कि चार साल का एक साथ नष्ट किया जाए। वह टिकता नहीं है। वह पहले से नष्ट हो चुका है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): 2018 में स्वीकृत मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पांच सड़कें अधूरी हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती गायत्री त्रिवेदी। अंकित नहीं होगा।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): 000

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): 000

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपका एवं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि पहली बार जीतकर आयी विधायक को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अनुमोदन करने एवं बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चार वर्ष के कार्यकाल में जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलायी हैं, वे आमजन के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

मैं आज गर्व से कहती हूं कि मैं एक ऐसे सदन का हिस्सा हूं जिसके मुखिया गरीबों के मसीहा माननीय अशोक जी गहलोत हैं। माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये प्रति परिवार निःशुल्क इलाज तथा 5 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के माध्यम से 37 प्रकार की जांचें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 15 प्रकार की जांचें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एवं 14 प्रकार की जांचें उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क की जा रही हैं।

मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की दवाइयां निःशुल्क इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के माध्यम से सभी चिकित्सालयों में आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं, जिनके माध्यम से बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकेगा तथा गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करवा सकेंगे।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से 55 वर्ष की महिला तथा 58 वर्ष के पुरुष को 75 वर्ष तक 750 रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों के पालन-पोषण,

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

शिक्षा के लिए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1500 रुपये तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

सभापति महोदय, राजस्थान को स्वस्थ राजस्थान बनाने की दिशा में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक योजना प्रारम्भ की गयी, जिसमें दादा ने पोते के साथ, बहू ने सास के साथ, देवरानी ने जेठानी के साथ खेल खेले। इन खेलों में एक साथ तीन-तीन पीढ़ियों ने खेल खेलकर आपसी सद्भाव, सौहार्द, प्रेम का परिचय दिया। उसी तर्ज पर अब शहरों में भी ओलम्पिक योजना प्रारम्भ की जाएगी, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोग खेल खेलकर स्वस्थ राजस्थान की कल्पना को साकार कर सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के लाखों कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) शुरू की गयी है। गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पुराने और नये कार्मिकों में पेंशन के भेदभाव को समाप्त किया है, जिससे राज्य सरकार कर्मचारियों के परिवारों का बुढ़ापे का सहारा बनी है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की सराहना देशभर में हो रही है, जिसे अब अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जा रहा है।

आज केन्द्र सरकार से युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, व्यापारी जीएसटी को हटाने की मांग कर रहे हैं, महिलाएं सिलेंडर, आटा, दाल, चावल, दूध और दही जैसी घरेलू जरूरी चीजों की महंगाई को कम करने की मांग कर रही हैं, जबकि माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से गरीब तबके के परिवार को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर दिये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्रदेश की सुरक्षा करने वाले पुलिस कान्स्टेबलों की ग्रेड-पे 3600 करने, हार्ड ड्यूटी अलाउंस को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, जोखिम भत्ता 5000 रुपये करने जैसी मांगों को बजट में शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि विगत 6 अक्टूबर, 2022 को रायपुर में पूर्व विधायक स्व. श्री कैलाश चन्द्र जी त्रिवेदी के मूर्ति अनावरण समारोह में

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत एवं आपके द्वारा 220 केवी जीएसएस, रायपुर का शिलान्यास किया गया था, उक्त जीएसएस का कार्य स्टाफ की कमी के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहती हूं। रायपुर एवं मोखुन्दा में पुलिस चौकी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है। गाडरमाला में नवीन पुलिस चौकी खोली जाए। कारोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाएं, ताकि कारोई सहित आस-पास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। गंगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला चिकित्सालय तथा रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए।

भीलवाड़ा जिले के एकमात्र हमीरगढ़ ईको पार्क को पर्यावरण एवं वन्य सुरक्षा की दृष्टि से आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाए। सहाड़ा क्षेत्र के भरका माता मन्दिर पर उड़न खटोला लगवाया जाए, ताकि वृद्ध लोगों को देवस्थान पर जाने में सहूलियत हो सके। हमीरगढ़ में नवीन पंचायत समिति एवं रायपुर में नगरपालिका खोली जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमीरगढ़ सहित आस-पास के क्षेत्र में युवाओं की संस्कृत विषय के प्रति विशेष रुचि है। हमीरगढ़ में संचालित संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात् युवाओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र नहीं जाना पड़े इसलिए हमीरगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय स्व. कैलाश चन्द्र त्रिवेदी पूर्व विधायक के नाम पर खोला जाए।

किसानों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति हेतु गंगापुर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, कोशीथल में सहायक अभियन्ता कार्यालय तथा मण्डी, भटेवर, डेलाना और सांगवा में नये जीएसएस खोले जाएं। ग्रामीणों को राजस्व सम्बन्धी कार्य की सहूलियत हेतु मोखुन्दा में उप तहसील कार्यालय खोला जाए तथा कारोई उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाए। गंगापुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जाए। पोटला उप तहसील का भवन निर्माण करवाने की स्वीकृति जारी करवाएं। गंगापुर कालेज को पी.जी. में क्रमोन्नति, गंगापुर एवं रायपुर कालेज में कृषि संकाय तथा सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित तीनों पी.जी. कालेजों में प्राचार्य सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त चल रहे पद शीघ्र भरे जाएं।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

रायपुर उप खण्ड यातायात की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है इसे भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, फालना, उदयपुर से जुडवाएं, ताकि आमजन को आवागमन की दृष्टि से राहत मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में चिकित्सा संस्थानों में काफी रिक्त पद चल रहे हैं, जिसके कारण आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरवाएं, जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। बिलिया कलां ग्राम पंचायत में बनास नदी पर एनिकट निर्माण कराया जाए, जिससे लगभग 40-50 गांवों को लाभ मिलेगा।

भीलवाड़ा जिले की कारोई से टहुका चौराहा तक शेष साढ़े नौ किलोमीटर की सड़क, मेवाड़ पेट्रोल पम्प से काला बावजी रोड, देवरिया-हरिपुरा सड़क, मैन रोड से वाया सूरजपुरा-सगरेव सड़क, पनोतिया से चांदरास, मैन रोड से खरडाया (कैलाशनगर) खेमाणा सड़क, तिलोली से महावीर चौराहा तक सड़क, एप्रोच रोड थला, कोट से सिरोडी सड़क, जूणदा से सांगास सड़क, दूडिया से दौलपुरा सड़क, हरिपुरा से कांगणी सड़क, उल्लाई से झडोल एप्रोच रोड सहित अन्य सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी करायी जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन की दृष्टि से सहूलियत हो सके।

माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान में बहुत सारे काम मंजूर किये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की हैं, अनगिनत घोषणाएं की हैं जो निरन्तर जारी हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो उड़न खटोले की मांग की है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आसन व्यवस्था दे दे और उड़न खटोला तो इनके निर्वाचन क्षेत्र में जरूर उड़ाया जाए।

श्री सभापति: आसन आपके लिए उड़न खटोले की व्यवस्था करेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह उड़न खटोला है, सभापति महोदय, भगवान राम भी उसमें चले थे।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): वे मोहर लगा रही हैं कि 30 परसेंट भी धरातल पर नहीं उतरीं। कैलाश जी की शहादत के समय में कही, वे भी पूरी नहीं हुईं।

श्री सभापति: आसन आपके लिए उड़न खटोले की व्यवस्था जरूर करवायेगा। प्लीज, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आभार, सभापति महोदय। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य का हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीने के लिए राज्य सरकार से कुछ मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा रखता है, जिसमें अच्छी हवा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, चलने के लिए गड्ढे मुक्त सड़कें, भय और भ्रष्टाचार मुक्त माहौल और बेहतर शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं हैं। अगर आज के हालात की बात करें तो पूरे राज्य में और अगर विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की बात करूं तो वहां पर गरीब किसान और गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन सुविधाओं की राह जोत रहा है। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सुविधाएं देने में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है जिसका खामियाजा उसे आने वाले समय में जो 2023 में चुनाव होंगे उनमें भुगतना होगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार सबसे ज्यादा गरीब किसान की बात करती है, गांव में रहने वाले लोगों की बात करती है और जब बजट का समय आता है तो उन्हीं को ध्यान में रखकर वह बजट भी अपना उसी हिसाब से तैयार करती है। इस अभिभाषण में भी उन्होंने समृद्ध किसान और खुशहाल किसान की बात कही है। आज मैं बात मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की करूं तो वहां पर न समय पर बिजली मिल रही है, न समय पर पानी मिल रहा है और न समय पर डीएपी मिल रहा है। अगर डीएपी मिल भी रहा है तो वह अधिक रेट में मिल रहा है और उसके साथ किसान को कुछ न कुछ और भी खरीदना पड़ता है। जो हालात प्रदेश और गांवों में इस सरकार की वजह से बने हुए हैं, उसमें मेरा मानना है कि यह वाक्य जो इन्होंने इस अभिभाषण में लिखा कि समृद्ध किसान और खुशहाल किसान, यह बिलकुल गलत साबित होता दिख रहा है।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, सरकार पूरे राज्य में 6 घंटे थ्री फेज और 18 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की बात करती है पर आज मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की बात करूं तो कई गांवों के अन्दर तो 24-24 घंटे बिजली नहीं आती है। मेरे से पहले कई लोगों ने कहा कि जब शाम के समय गांव का व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो सरकार को पता नहीं कहां से पता चलता है और उसी समय वहां की बिजली काट दी जाती है। गांव का व्यक्ति इस कटौती से इतना अधिक परेशान है कि उसको हर आधे घंटे में अपने खेत की तरफ भागना पड़ता है। 6 घंटे की ये बात करते हैं पर थ्री फेज की बिजली मुश्किल से 3 से 4 घंटे आती है और वह भी कट-कट कर आती है तो जैसे ही वह कटती है तो रात के समय में, दिन के समय में वापस अपने खेत में भागना पड़ता है और दुबारा अपनी मोटर चालू करनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि आप चाहे तीन से चार घंटे ही बिजली दें, पर उसको एक साथ, एक समय पर वह तीन से चार घंटे की पूर्ति की जाए, काट-काट कर पूर्ति नहीं की जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार बिजली के क्षेत्र के अन्दर अपने आपको आत्मनिर्भर बताती है पर जो हालात आज के समय में प्रदेश के अन्दर बने हुए हैं उनसे तो बिलकुल भी नहीं लगता कि सरकार के पास बिजली है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर सरकार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तो पूर्ति इनको करनी चाहिए और आप इनको आदेशित करें कि आने वाले समय में उसकी पूर्ति जरूर करें। माननीय सभापति महोदय, यह तो रही बिजली की बात। और तो और जले हुए ट्रांसफार्मर्स 72 घंटे में बदलने की सरकार बात करती है, पर मेरे यहां तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनके 72 दिन हो गये। आज ही मैंने माननीय मंत्री जी से बात की कि 72-72 दिन होने के बाद भी उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिये जा रहे हैं। सर्दी के अन्दर भी उनको समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, जबकि एक तरफ तो पाले की मार सरसो, गेहूं पर पड़ रही है और ऊपर से बिजली समय पर नहीं मिलने के कारण, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिलने के कारण पानी की कमी से भी उनकी फसल खराब हो रही है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जो फसल पाले की वजह से खराब हुई उसका एक बार सर्वे करवाकर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए।

((श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, युवा होने के नाते मैं अगर युवाओं की बात करूं तो सरकार राज्य के अन्दर भर्तियां तो जरूर निकालती है पर पेपर आउट होने की वजह से, उसके अनेकों कारण हैं, भर्तियां नहीं होती हैं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पिताजी के बहुत नजदीकी साथी रहे हैं। माननीय सदस्य ने भी समय-समय पर इस बात को यहां सदन के अन्दर रखा, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि पेपर आउट होने की वजह से और भर्तियां कोर्ट में अटकने की वजह से आज युवा प्रदेश में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए लाचार है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि समय-समय पर जो पेपर आउट हो रहे हैं, उनके कोई कड़े नियम बनाकर आप इन हालातों को ठीक करें और जो भर्तियां कोर्ट के अन्दर अटकी हुई हैं, आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा वकील कर उनको धरातल पर लाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले बोले वक्ताओं ने 75 परसेंट युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार देने की बात कही है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर राजस्थान के बड़े उद्योग स्थापित हैं। सभापति महोदय, राजस्थान से लगते हुए राज्य हरियाणा और गुजरात हैं जहां पर दोनों ही सरकारों ने वहां के स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाया हुआ है, तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि कम से कम दोनों पड़ोसी राज्यों को देखते हुए इस कानून को अपने यहां पर लागू करें, जिससे गांवों में जो गरीब किसान का बेटा रहता है, उसको आने वाले समय में वहां पर नौकरी मिलेगी, जिससे वह अपना परिवार ढंग से चला पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी नीतियों और नवाचारों के कारण राज्य में सुचारु कानून व्यवस्था की बात करती है। मेरे अलवर जिले में सरकार ने दो पुलिस अधीक्षक बिठाये हुए हैं पर दो पुलिस अधीक्षक होने के बाद भी मेरे हिसाब से कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान में अगर नाजुक हालत में है तो अलवर के अन्दर है। अगर हाल ही की बात करूं तो 5 दिन पहले बासनी में रहने वाले सचिन सेठ पर कुछ गुंडों ने गोली चलायी और वहां एक पर्ची फेंककर गये कि आपने हमें दस लाख रुपये नहीं दिये तो आने वाले दिनों में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं भी इस व्यथा से निकला हूं पर मुझे तो सरकार ने सुरक्षा मुहैया करायी इसलिए हर व्यक्ति को सरकार सुरक्षा मुहैया कराये, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश के हालात बहुत अधिक दयनीय हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि

((श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

उसी के नजदीक हरियाणा बोर्डर लगता है इसलिए बासनी के अन्दर एक चौकी बनाई जाए, जिससे आने वाले समय में अपराध पर अंकुश लग सके।

माननीय सभापति महोदय, सरकार पैरा नम्बर 162 और 23 में पेयजल के दीर्घकालीन समाधान और पेयजल कार्यों की बात करती है। पूर्व में मुख्य मंत्री जी ने ईसरदा बांध और चम्बल के माध्यम से अलवर के लिए पानी की घोषणा की थी पर मुझे कहते हुए दुख होता है कि इन दोनों योजनाओं में धरातल पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ईसरदा योजना तो कागजों में ही गुम हो गई और चम्बल के पानी को लाने की बात कभी भी सरकार से की जाए तो वह केन्द्र सरकार पर डाल देती है। हमारे जिले से दो-दो कैबिनेट मंत्री और अनेकों राज्य मंत्री आते हैं उसके बाद भी हमारे जिले के इतने बुरे हालात हैं तो यह सोचने वाली बात है।

आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करूं तो उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं मेरे एक गांव में जल जीवन मिशन के चल रहे कार्यों को देखने, निरीक्षण करने गया तो देखा कि वहां पर जिस कम्पनी के पाइप डाले जा रहे थे, वह कम्पनी सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, पर उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा उस कम्पनी के पाइप वहां पर डाले जा रहे थे। अधिकारियों से पूछने पर पता चला तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिये और कहा कि हमें नहीं पता कि ये पाइप कब और कहां से आये। उनके सामने ही जब ऑनलाइन चैक किया तो उन्होंने भी बताया कि हां, साहब, ये पाइप गलत हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इनको आदेशित करें कि आने वाले समय के अन्दर खराब पाइप पानी की व्यवस्था के लिए नहीं डाले जाएं क्योंकि यह योजना लम्बी चलने वाली है और अगर खराब पाइप अभी डाल दिये जाएंगे तो कुछ दिन बाद वे पाइप खराब हो जाएंगे जिससे जो सड़कें बनने जा रही हैं, वे टूट जाएंगे और आने वाले समय में अगर ये खराब पाइप डाले जाएंगे तो गांव में रहने वाले किसान की सेहत के ऊपर आने वाले समय में कहीं न कहीं इसका फर्क जरूर पड़ेगा।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत सारे स्कूल क्रमोन्नत किये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि स्कूल तो आपने क्रमोन्नत कर दिये, पर वहां पर शिक्षकों का क्या? वहां पर कक्षाओं का क्या? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पहले आप कम से कम मूलभूत सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध करायें, उसके बाद आप स्कूल क्रमोन्नत करें जिससे वहां पर रहने वाले गरीब किसान का बच्चा आराम से पढ़ सकेगा और आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा वहां पर ले पायेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सिर्फ एक मिनट। 194 नम्बर पैरा में सरकार उच्च शिक्षा की बात करती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की आबादी करीब चार लाख के आस-पास है और 2018 के अन्दर मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मपाल जी के द्वारा वहां पर एक राजकीय महाविद्यालय खुलवाया गया था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 5 साल पूरे होने के बाद भी उस महाविद्यालय की बिल्डिंग का काम चालू नहीं हुआ है। आज भी वह महाविद्यालय स्कूल के भवन में चल रहा है।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसके निर्माण का कार्य जल्द से जल्द चालू करवाया जाए जिससे आने वाले समय में वहां पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सुविधा मिल सके। आपके माध्यम से बचा हुआ टेबल करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से टेबल करना चाहूंगा।

(माननीय सदस्य श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी द्वारा सदन पटल पर रखे गये अपने शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमारी सरकार को चार साल हो गये हैं और चार साल में जो बेहतरीन काम किये हैं, अभी बिजली की बात चल रही थी, जब बिजली का बिल आता था तो बिल में करंट दौड़ता था, लेकिन जब से बिजली की सब्सिडी चालू हुई है गांवों में ज्यादातर लोगों के बिल जीरो आ रहे हैं।

सभापति महोदय, एक जमाना था जब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना देखते थे। गांव का आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना नहीं देखते थे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये देखिए परम्पराओं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। आप खाएं तो अकेले नहीं खाएं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सर, वास्तव में इनकी जांच करनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप देख लें, कुछ नहीं है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सर, मुंह के अन्दर कुछ न कुछ दिखा है। यहां से दिख रहा है।

श्री सभापति: शिकायत यह नहीं है कि आप क्यों खा रहे हो, शिकायत यह है कि आप इनके साथ साझा करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का एक सपना हुआ करता था। हमारी सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांवगांव में जहां जितनी डिमांड की, उन सभी गांवों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है। यह बात सही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी शिक्षकों की थोड़ी कमी है, लेकिन जब घर बनाते हैं तो उसको भी पूरा करने में पांच साल का समय लगता है, आप समय का इन्तजार करिये, शिक्षक भी आयेंगे, अच्छी बेहतरीन व्यवस्थाएं भी होंगी और आने वाले समय में गांव में, ढाणी में, गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा-बेटी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे।

मैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है। सभापति महोदय, मेरे अजीज दोस्त मुण्डावर से आने वाले सदस्य पानी की बात कह रहे थे। मैंने उनको इशारा भी किया था कि जब आप पानी की बात कर रहे हो, यमुना के पानी की बात कर रहे हो तो कम से कम ईस्टर्न कैनाल की बात भी करनी चाहिए। पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का इतना बड़ा मुद्दा ईस्टर्न कैनाल, आज पूर्वी जिले के 13 जिले इससे प्रभावित हैं। आज पानी की समस्या हो गई है। हर 6 महीने में बोरिंग ड्राई होने लग गये हैं। प्रधान मंत्रीजी ने अजमेर और जयपुर में आकर के घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे।

हमारे जलदाय मंत्री महोदय बैठे हैं। केन्द्रीय जलदाय मंत्री हमारे राजस्थान से आने वाले हैं। जब उनकी डिबेट हुई, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अगर प्रधान मंत्रीजी ने अजमेर की मीटिंग में एक शब्द बोला हो तो या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं कि उनको अपना वादा निभाना चाहिए और राजनीति छोड़नी चाहिए। जब हम डेमोक्रेसी में पब्लिकली कोई बात कहते हैं तो उसका एक वज़न होता है। केन्द्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री अगर इतनी बड़ी बात दावे के साथ बोलते हैं तो मैं तो कहता हूं कि उनको अपना दावा निभाना चाहिए। दुनिया में जुबान की कीमत है। अगर हमारी अपनी जुबान पर लगाम नहीं है तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, पिछली बार हमारी सरकार ने एक अच्छा महत्वपूर्ण काम किया। मैंने मुद्दा उठाया भी था कि पालनहार योजना, जिसमें

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

वह गरीब बच्चा, जो अनाथ हो जाता है, जिसके पिता या माता की मृत्यु हो जाती है, उसको सम्भालने वाला कोई नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होती है। अनाथ बच्चों के लिए ढाई हजार रुपये की घोषणा की गई। मैं इस बात में थोड़ा संशोधन चाहते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि हमने अनाथ बच्चों के लिए ढाई हजार रुपये की घोषणा की है, उस अनाथ शब्द के साथ, जिसके मां या बाप दोनों में से जो जीवित हैं, अगर वह गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, वह विकलांग हैं, उसको भी अगर इस श्रेणी में शामिल किया जाए तो इससे हजारों बच्चों का भला होगा। सभापति महोदय, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, मां विकलांग हैं, पिताजी की डैथ हो गई है, लेकिन वे उस श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से उन बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, यदि कुदरत का कहर सबसे ज्यादा कहीं बरसता है तो हमारे किसान भाइयों पर बरसता है। मैं किसान का बेटा हूं, उस दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं अभी पांच-सात दिन पहले गांव गया था। जब खेत की तरफ गया तो हमारे ताऊजी वगैरह सब कह रहे थे कि अब की बार तो सरसों पूरी तरह चौपट हो गई है, 20 परसेंट भी नहीं बची। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान सब्जियों और फसलों में हुआ है। बीमा कम्पनियां कह रही हैं कि जो सर्दियां पड़ती हैं, उसको इसमें कवर नहीं करते हैं। एसडीआरएफ से जो पैसा मिलता है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। सभापति महोदय, सरकार को ऐसा कोई संशोधन लाना चाहिए कि या तो एसडीआरएफ में पैसा बढ़ाये या फिर बीमा कम्पनियों को इसमें पाबन्द किया जाए कि जब भी पाला पड़े और यदि पाले से फसल खराब हो तो उसमें भी उनको मुआवजा दिया जाए।

सभापति महोदय, एक निवेदन है, यह ज्वलन्त मुद्दा है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि हम गांवों में रोज जाते हैं शाम को पांच बजे से लेकर रात के नौ बजे तक और सुबह पांच बजे से लेकर आठ बजे तक बिजली कटौती हो रही है। विद्यार्थियों की स्कूलें चल रही हैं और परीक्षाएं चल रही हैं। जब भी गांवों में जाते हैं, हर व्यक्ति यह बात बोलता है कि इस समय कम से कम बिजली कटौती बन्द करवाओ। परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चों को तैयारी में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की इतनी बड़ी स्कीम है कि पूरे देश में मॉडल मानी जाती है। यह अच्छी स्कीम है, इसमें एक सुधार की गुंजाइश है। जो व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ नहीं है उसका अचानक आपरेशन होना है, अगर उसे जोड़ते ही 24 घन्टे में वह चालू हो जाए तो उन काफी लोगों को फायदा मिलेगा, जो इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने शहरी नरेगा स्कीम लागू की है। पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने शहरी नरेगा स्कीम लागू की है, लेकिन थोड़ी-सी समस्या है। ग्रामीण नरेगा, शहरी नरेगा, इनकी न्यूनतम मजदूरी दर तय होनी चाहिए। कभी-कभार कोई जेटीए, जे.ईएन बदमाशी करते हैं। किसी के खाते में 80 रुपये आते हैं, किसी के खाते में 100 रुपये आते हैं, किसी के खाते में सवा सौ रुपये आते हैं। नरेगा में न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए, क्योंकि गांवों में नरेगा में वही व्यक्ति जाता है, वे ही महिलाएं जाती हैं, जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है। जिसको पीड़ा होती है, वही व्यक्ति नरेगा में जाता है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका, जो सर्वे करने के लिए घर-घर जाती हैं, गांवों में भी घर-घर जाती हैं, मैं उनका मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं, ताकि उन लोगों को भी राहत मिले।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगा। ऐसा नहीं है, मांगें पूरी हुई हैं, पहले भी हुई हैं और मांग करेंगे तो अभी भी होंगी। हमारे यहां प्रसिद्ध नारायणदास जी महाराज का त्रिवेणी धाम मन्दिर है, वहां पर पीएचसी है, चार-पांच पंचायतें हैं, मन्दिर में हमेशा कम से कम 500-700 साधु रहते हैं। मैं सदन में मांग करता हूं कि हमारी सायवाड़ पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, इससे चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी। वहां से 15 किलोमीटर पहले कोई भी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। रात में अचानक दिक्कत आती है तो या तो शाहपुरा जाना पड़ता है या फिर जयपुर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि हमारी सायवाड़ पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। हमारी ग्राम पंचायत भाकरी, मण्डा, पालड़ी, बडोदिया में पीएचसी खोली जाए।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, हमारी पावटा पंचायत समिति पिछली सरकार के समय में बनी। इसके बाद जितनी भी पंचायत समितियां खुली हैं, वहां ब्लाक स्तर पर ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठा दिया गया है। पद स्वीकृत किये गये, लेकिन पहले की जो पंचायत समितियां हैं वहां पर ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद अभी तक सृजित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वे पद भी सृजित किये जाएं।

सभापति महोदय, अगर सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। जिस क्षेत्र की सड़कें अच्छी हैं, निश्चित रूप से वह क्षेत्र बहुत ही अग्रणी है। मैं खुशनसीब भी हूं कि इस कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी सड़कें बनी हैं लेकिन फिर भी हमारे पावटा से विराटनगर को जोड़ने वाली सड़क एमडीआर 175 बावड़ी से विराटनगर की मैं मांग करता हूं कि उस सड़क को एमडीआर को दुबारा बनाया जाये निश्चित रूप से 7 मीटर चौड़ाई में, ताकि हमारे दो उप खण्ड आपस में जुड़ सकें, पूरा विधान सभा क्षेत्र जुड़ सके।

सभापति महोदय, हमारे एक एमडीआर रोड है 228 नम्बर, उसमें अलवर और जयपुर जिले जुड़ते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सिर्फ उसमें चार किलोमीटर बीच में टुकड़ा बचा हुआ है राजनूता से लेकर कराना तक, उस सड़क को बनाया जाये और एक सड़क एमडीआर 188 बीलवाड़ी से खोरा को भी बनाने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, विज्ञान का जमाना है। विज्ञान के जमाने में अगर स्कूलों में हम विज्ञान संकाय नहीं खोलेंगे तो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे-बच्चियां विज्ञान कहां से पढ़ेंगे? कालेजों में और स्कूलों में विज्ञान संकाय अधिक से अधिक खोले जायें। मैं मांग करता हूं कि हमारे गवर्नमेंट कालेज पावटा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जायें एवं हमारे सीनियर स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागावास अहीरान, बाड़ीजोहड़ी, पालड़ी व राजनूता में विज्ञान संकाय खोले जायें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करने का मौका मिल सके।

सभापति महोदय, हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

विद्यालय, खेड़ा जो काफी पुराना स्कूल है, मैं मांग करता हूं कि उस विद्यालय को प्रवेशिका में क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आने वाले समय में मिसिंग लिंक की सड़कों की हमारे यहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पिछली सरकार में हमारे जो भाजपा से विधायक थे, शायद मुझे लगता है कि उनकी सरकार में पटरी बैठी नहीं, तो बिलकुल भी हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनीं। भिण्डा जी की और युनूस खान की शायद बिलकुल ही पटरी पांच साल तक नहीं बैठी और उसका खामियाजा हमारे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र को उठाना पड़ा। पूरे पांच साल में सड़कों के नाम पर हमारा क्षेत्र जीरो रहा।

मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि इस चार साल में अच्छी सड़कों का हमने जाल बिछाया, लेकिन चूंकि पिछले पन्द्रह साल से वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इस वजह से सड़कों का जाल नहीं बिछ पाया। मिसिंग लिंक की सड़कें इस बार बहुतायत संख्या में दी जायें ताकि आने वाले समय में अच्छी सड़कें बन सकें क्योंकि जिस क्षेत्र की सड़कें अच्छी होंगी वह क्षेत्र अच्छा डवलपमेंट करता है, रोजगार भी आता है। हमारा क्षेत्र जयपुर के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक है इसलिये उसमें बनाया जाये।

सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं युवा हूं तो युवाओं की बात जरूर करूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारे पेपर लीक की घटनाएं आयी हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिये। आने वाले दस महीने बाद चुनाव है, जनता के बीच में हम लोगों को जाना है। युवा हमसे जवाब भी मांगेगा तो तह में जायें कि आरपीएससी के अन्दर कौन व्यक्ति उसमें शामिल है, जो पेपर चोर करके बाहर देता है। जब तक उस तह तक हम लोग नहीं जायेंगे, तब तक ये पेपर चोरी का सिलसिला रुकेगा नहीं और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने का काम किया जाये। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का प्रतिबिम्ब होता है। सरकार ने जो-जो काम किये उसमें उसका वर्णन होता है, परन्तु मुझे ऐसा

(श्री धर्मनारायण जोशी)

लगता है कि रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में जैसे रेत का एक समुद्र-सा दिखता है वैसे ही इस राज्य सरकार की घोषणाएं हैं। अनेक घोषणाएं राज्य सरकार की पिछले चार साल में ऐसी हैं जो धरातल पर बिलकुल नहीं हैं। अगर एक-एक घोषणा का नाम लिया जाये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यह असत्य का पुलिन्दा है केवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र मावली में राज्य सरकार ने 2019 के बजट में घोषणा की कि मावली के कालेज का भवन बनेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देने गया। साल भर कुछ नहीं हुआ। 2020 आ गया, 2020 में फिर घोषणा की, मावली भूल गये। घोषणा यह की कि राजस्थान में विभिन्न कालेजों में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ, वह घोषणा भी धरी की धरी रह गयी। फिर 2021 आ गया। 2021 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि राजस्थान के विभिन्न कालेजों में डीएमएफटी के पैसे से, डीएमएफटी का पैसा तो भारत सरकार का है, 21 अक्तूबर, 2021 को डीएमएफटी की बैठक हुई और डीएमएफटी में 6 करोड़ रुपये पास हुए, अभी उस कालेज का काम बिना उद्घाटन के है, क्योंकि भाजपा का विधायक है।

माननीय सभापति महोदय, इतना जबरदस्त भेदभाव। पानी का भयंकर संकट। मावली क्षेत्र में पीने के पानी का भारी संकट है और संकट के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की कि बीसलपुर पानी ले जायेंगे उदयपुर का। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पीने का पानी वे बीसलपुर ले जायें परन्तु उदयपुर में पीने के पानी का भयंकर संकट है। हमारी मानसी वाकल योजना के दो फेज बाकी हैं और उदयपुर का पानी बीसलपुर ले जायेंगे, यह सपने में भी नहीं है और 1800 करोड़ रुपये की घोषणा, परन्तु केवल घोषणा ही बची है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री के बजट की घोषणा है कि पंचायत समिति स्तर पर गोमाता के लिए आश्रय स्थल बनायेंगे। मैं उन गोभक्तों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लम्पी के समय में उन गोमाताओं को बचाया। सरकार सो रही थी, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने कहा था कि पंचायत समिति स्तर पर गोशालाएं खोलेंगे, नन्दीशालाएं खोलेंगे। कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने घोषणा की थी यह सरकार की घोषणा है। उन्होंने कहा था कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

पंचायत समिति स्तर पर खेल स्टेडियम बनेंगे, कोई खेल स्टेडियम का अता-पता नहीं है।

मेरा तो निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में, वल्लभनगर की माननीया विधायक बैठी हुई हैं यहां पर, हमारे यहां पानी की कमी है। एक योजना बनी हुई है जाखम से पीने का पानी लाने की, मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार को प्रपोजल भेजें और भारत सरकार पैसा दे, कुछ पैसा आप भी दें। अगर जाखम का पानी आता है तो वह पानी राजसमन्द की, मावली, वल्लभनगर की पूर्ति के साथ-साथ राजसमन्द में भी पानी की पूर्ति करेगा। ऐसा मेरा मानना है।

अनेक योजनाएं, कलेक्टर साहब को डीएमएफटी के लिए पूछते हैं तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को पहले डीएमएफटी से पूरा करेंगे और आपको आश्चर्य होगा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में डीएमएफटी का पैसा लग रहा है, भाजपा के विधायक के क्षेत्र में अभी पन्द्रह दिन पहले, जब बजट का यह सत्र आ रहा था तो देखा कि सत्र में खिंचाई होगी प्रशासन की तो उन्होंने घोषणा की है।

दवा की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना से चुनाव जीत जायेगी। चिरंजीवी योजना धरातल पर नहीं है। अनेक लोग प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं, उनकी हालत ऐसी है वो भर्ती नहीं करते हैं, बेड नहीं हैं हमारे पास और कुछ नहीं है, पैसा जमा करवाओ तो बेड मिल जाएगा। आपकी नि:शुल्क दवा योजना में एक हजार दवाइयां ऐसी हैं जो आपने सोचा था कि नि:शुल्क वितरण करेंगे परन्तु आपके पास उपलब्ध केवल 250 दवाइयां हैं, इसके अलावा कोई आपके पास दवा उपलब्ध नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एक यहां के सिरोही वाले विधायक भारत सरकार को कह रहे थे कि किसानों के कर्जे की मोदी जी ने घोषणा की। मोदी जी ने घोषणा तो नहीं की, आपके नेता ने घोषणा की और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपकी बात धरी की धरी रह गयी, परन्तु जिन किसानों की भूमि नीलाम हो गयी, मुझे लगता है उस पर रोक लगानी चाहिये आपको।

भारत सरकार ने जो काम किये, वो कोई सोच भी नहीं सकता। आज अस्सी करोड़ लोगों को प्रति माह पांच किलो अनाज फ्री में मिल रहा है, यह

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कोई सोच सकता है क्या कि ऐसा हो सकता है। भारत सरकार ने, आप तो आपके पचास साल के शासन में सेना की वर्दी आयात करते थे, सेना के जूते आयात करते थे, वे जूते भी आज भारत सरकार बना रही है और भारत सरकार तो जो शस्त्र हैं, वे निर्यात कर रही है। आपकी ऐसी स्थिति थी कि पचास साल में कुछ नहीं कर पाये। इसके अलावा भी अनेक बातें ऐसी हैं देश में साठ-पैंसठ हवाई अड्डे थे, पिछले सात साल में 72 हवाई अड्डे नये बने हैं। क्या यह उपलब्धि नहीं है केन्द्र सरकार की?

थोड़ा-सा आपसे मेरा निवेदन है। आपने मेडिकल में जैसे कहा कि जनता क्लिनिक खोलेंगे। जयपुर में बारह क्लिनिक खोले हैं, जोधपुर में दो क्लिनिक खोले हैं और हमारे एक विधायक महोदय कह रहे थे कि मेरे पिलानी में दो जनता क्लिनिक खोले हैं। जनता क्लिनिक की आपकी घोषणा थी कि गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में खोलेंगे। राजस्थान में बीस-पच्चीस हजार जनता क्लिनिक खोलने की योजना थी। वह योजना पता नहीं।

लॉ एंड आर्डर की बड़ी विचित्र स्थिति है। अनेक वक्ताओं ने अनेक बातें बताई हैं। लॉ एंड आर्डर की ऐसी स्थिति है कि भीलवाड़ा में दो भाई जा रहे थे और एक भाई को गोली से मार दिया। दूसरा भाई उसके साथ था। दूसरे भाई ने नाम बताया कि इन्होंने गोली मारी है। दूसरे दिन अख़बार में नाम दूसरे थे। पुलिस ने दूसरे नाम लिख लिए।

और तो और, माननीय सभापति महादेय, डूंगरपुर में जो अवैध शराब पकड़ी थानों में, मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लॉ एंड आर्डर का। थानों में शराब पकड़ी वह शराब वहां के सीआई ने, वहां के डीवाई एस पी ने बेच दी, यानी जब्त शराब थाने से बेच दी। यह सारा समाचार पत्रों में आया है। लॉ एण्ड आर्डर की आपकी ऐसी स्थिति है। मुझे लगता है कि राजस्थान में किसी

(समय: 17.00 बजे)

अधिकारी के खिलाफ कोई भी केस राज्य सरकार की परमिशन के बिना कोर्ट में नहीं लग सकता। राजस्थान में एक हजार से ऊपर केस ऐसे हैं जो राज्य सरकार की परमिशन के लिए अटके हुए हैं। चार महीने में राज्य सरकार को परमिशन देनी पड़ती है परंतु 2013-14 से लेकर अभी तक वह सारे केस अटके हुए हैं।

मेडिकल कालेज के लिए आपने कहा कि हर जिले पर मेडिकल कालेज खुल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परंतु केन्द्र सरकार को भी धन्यवाद दे देते

(श्री धर्मनारायण जोशी)

क्योंकि 60 परसेंट पैसा भारत सरकार का आ रहा है और तब मेडिकल कालेज खुल रहे हैं परंतु उसके बाद भी कोई धन्यवाद नहीं। आपने कहा कि राजस्थान में अतिरिक्त लाइट हो रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मैंने एक एसई को फोन किया कि श्रीमान जी, चार बजे आप लाइट दे रहे हो, किसान खेत में पाड़त कैसे करेगा? उसको मैंने कहा कि आपको सुबह उठाऊंगा, तब उसने पांच बजे की।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी आठ मिनट भी नहीं हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे दो मिनट का समय और देवें तो मैं अपनी बात को पूरा कर सकूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मावली में पानी की व्यवस्था चाहिये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको और कुछ नहीं चाहिये, बजट में प्रावधान करके मावली क्षेत्र में पानी की योजना स्वीकृत करावें। मावली में 74 गांव ऐसे हैं जहां पानी न जमीन में है और न ही ऊपर से पानी आ सकता है। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरी योजना को पूरा करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

राजस्थान के कण-कण में वीरता, त्याग, तपस्या और बलिदान का समावेश है। राजस्थान महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी लोगों के व्यक्तित्व का प्रदेश है। सभापति महोदय, राजस्थान का कोई भी राजस्थानी जब राजस्थान से बाहर गया है, चाहे वह देश में गया हो, चाहे विदेश में गया हो, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। सही मायने में राजस्थान सरकार की परीक्षा जब सफल होती है, जैसे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके राजस्थान की आर्थिक विकास की दर को 11.4 प्रतिशत पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए मैं पूरी सरकार, मंत्रीमंडल के तमाम साथी और

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के चहुंमुखी विकास की चिंता करते हुए आर्थिक विकास की दर को आगे पहुंचाया है।

आज चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करना, यह कोई मामूली काम नहीं है। उस गरीब आदमी से जाकर पूछिए जिसके घर में कोई आदमी बीमार होता है और वह ब्याज पर पैसे देने वाले लोगों के पास जाकर नाक रगड़ता था, जब भी उसके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था। उस कुप्रथा को मिटाने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। आज उस गरीब को किसी धनवान व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, केवल चिरंजीवी योजना के कार्ड को लेकर जायेगा और निजी अस्पताल में भी उसका फ्री में इलाज होता है, मैं समझता हूं कि अगर इसको भगवान की संज्ञा दी जाये तो वह भी कम नहीं होगी।

(समय: 17.04 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

ऐसे ही अगर किसी आदमी की सड़क पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके छोटे-छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें, इसके लिए भी 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना लागू की। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलना और खास बात यह रही कि जब पूरे विश्व में कोरोना से त्राहि-त्राहि मची हुई थी, उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री और पूरे प्रशासन के लोगों का, भीलवाड़ा मॉडल को देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी सराहा। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, अच्छे काम को अच्छा बताना पड़ेगा और बुरे काम को बुरा बताना पड़ेगा। सरकारें आती और जाती हैं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कोरोना काल में जो काम किया है वह तारीफ-ए-काबिल है। सभी जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं और समाजसेवियों ने मिलकर हमारे राजस्थान की आठ करोड़ जनता को बचाने का काम किया है, वह तारीफ-ए-काबिल है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): साहब, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक मिनट भी नहीं हुआ।

श्री सभापति: ठीक है, बोलिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाले लोगों के दो ही काम हैं, एक खेती करना और दूसरा पशुपालन। इन दोनों कामों को करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है किसान। इस लोकतंत्र में दो लोगों का बहुत बड़ा महत्व है, एक अन्नदाता का और दूसरा मतदाता का, लेकिन मतदाता से भी अगर कोई बड़ा है तो वह है अन्नदाता। उस किसान के दर्द को मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे कोई भी हों, पूर्वी राजस्थान में जहां 40-42 परसेंट आबादी निवास करती है, उन्होंने दोनों सरकारों को बनाकर दिया है। बारां से लेकर भरतपुर और भरतपुर से लेकर अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और अलवर, इन सारी सीटों पर 11 एमपी भारतीय जनता पार्टी के जिता कर भेजे, उन्होंने भारत सरकार को बनाने का काम किया और 48 सीटें जो विधान सभा की आती हैं, उनमें से 45 सीट जिता कर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। उन अन्नदाताओं की कहां कमी रह गई? लोग कहते हैं कि दोनों पहिये एक साथ चलें, एक सरकार हो। उस किसान ने तो कभी कांग्रेस को भी वोट दिया है और कभी भाजपा को भी वोट दिया है। उसने उसका काम कर दिया, अब हमारी बारी बनती है कि हम किस तरह से उनका भला कर सकते हैं।

पूर्वी राजस्थान का प्रमुख मुद्दा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। खास तौर से जो बांध इससे जुड़े हुए नहीं हैं, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और आस पास के उन सभी बांधों को जोड़ने की आवश्यकता है। सही मायने में ईआरसीपी का मुद्दा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फुटबाल की तरह बना हुआ है। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार बनायेगी और राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार बनायेगी। आखिर उस किसान का दुखड़ा कौन सुनेगा?

उस किसान के दर्द को मैं एक कविता के माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहूंगा-

"दिन का चूल्हा जल भी जाये खबर नहीं है शाम की,
ऐसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की,
कागज लेकर लिखूं नई कहानी गांव की,
कैसी हालत हो गई मेरे पूर्वी राजस्थान की।
कभी नहीं है चिंता तुमको खेती और खलिहान की,
जिनकी आंखों में आंसू हैं फिर भी चिंता है हिन्दुस्तान की।"

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

जिस किसान की आंखों में आंसू है फिर भी हिन्दुस्तान की चिंता करता है और सरकार में बैठे हुए लोग उनकी चिंता नहीं करते, यह दुर्भाग्य है इस देश का।

"नदियों से नदियों को जोड़ो सागर तक मत जाने दो,
मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो।"

कल-कल करके जो चंबल बह रही है, जिस पर राजस्थान का सर्वाधिक अधिकार है, वह चंबल क्या कहती है-

"चंबल बोली किसान से मैं सारे सपने सज़ा दूंगी,
पूर्वी राजस्थान धरा को पंजाब बना दूंगी।"

अब चंबल सरकार से अर्जी लगा रही है-

"मेरी अर्जी सरकारों से आगे मुझे बढ़ा दो तुम,
दौसा, अलवर तरस रहे हैं जयपुर तक पहुंचा दो तुम।
जिला करौली, दौसा, भरतपुर आस लगाकर बैठे हैं,
सब खेतों की तरफ देखते जिनके आंसू बहते हैं।
जो अमृत बादल से आता उस पर कोई ध्यान नहीं,
जिसका सदा पसीना बहता उसका क्यों सम्मान नहीं।"

जो खेत में रहकर किसान अपना पसीना बहाता है, उसका सम्मान क्यों नहीं। उसको सम्मान तब मिलेगा जब उसके खेत तक चंबल का पानी पहुंचेगा।

सबसे पहले समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया ने 1963 में लोक सभा में मांग उठाई थी कि नदियों को नदियों से जोड़ने की आवश्यकता है। 2002 में देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी ने इस बात पर गौर किया और 2012 में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यह आदेश दिया कि नदियों को जोड़ना चाहिये। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं-

"नदियों को नदियों से जोड़ो सागर तक मत जाने दो,
मीठा अमृत इनमें बहता खेतों तक मुड़ जाने दो।
आंसू पीकर भी रोती आंखें एक गरीब किसान की,
कैसी हालत कर दी तुमने खेती के भगवान की।"

अब मैं किसान की तरफ से सरकारों के लिए भी कहना चाहता हूं-

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

"जिस दिन गुस्से में किसान अपना अधिकार समझ जायेंगे,

महलों वालों कान खोलकर सुन लो सबके सिंहासन हिल जायेंगे।"

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, देश के प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप दौसा में आये थे तो आपने घोषणा की थी कि आप चंबल का पानी लाकर दोगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार करे या न करे लेकिन राजस्थान सरकार के मुखिया को 40 हजार करोड़ रुपये की ईआरसीपी की घोषणा इस बजट में करनी चाहिये, मैं इसकी पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिलना चाहिए।

अब मैं दो मिनट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगों को कहना चाहता हूं कि महवा में जो उप जिला अस्पताल है, उसे जिला अस्पताल बनाया जाये। सीएचसी, मण्डावर को उप जिला अस्पताल बनाया जाये। गहनौली, उकरूंद, खौंचपुरी, महुखुर्द, पाखर, सलेमपुर, धौलखेड़ा, उप केन्द्र हैं, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। पीएचसी हुडला को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। महवा को जिला बनाने की भी मैं मांग करता हूं। महवा शहर में एक अतिरिक्त पुलिस थाना और चौकी खोलने की मांग करता हूं। बालेड़ी में उप तहसील की मांग करता हूं। लोटवाड़ा से हुडला तक एक सड़क बनाने की मांग करता हूं। बैजूपाड़ा, पालेड़ी और तालचिड़ी में कालेज खोलने की मांग करता हूं। मण्डावर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। मण्डावर और पावटा में खेल स्टेडियम और देवनारायण योजना में पीपलखेड़ा में एक कालेज खोलने की मांग करता हूं। साथ ही, पावटा, समलेटी और गढ़हिम्मतसिंह में 33 बाई 11 केवी जीएसएस की मांग करता हूं और इसके साथ ही गढ़हिम्मतसिंह, गहनौली, तालचिड़ी, समलेटी, सांथा, सलेमपुर और खौंचपुरी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): इसके साथ ही हमारा एक ही उद्देश्य है। अन्त में यही कहना चाहता हूं कि सेवा ही हमारा धर्म है और सेवा ही हमारा कर्म है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल में कालेज खोलकर, बस स्टैण्ड बनाकर, एसडीएम आफिस बनाकर हमें बहुत सारी सौगातें मिली हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह निरन्तर विकास का प्रयास है। अन्त में यही कहना चाहूंगा-

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

'आंसू न होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत न होतीं,
अगर मिल जाता एक ही बजट में तो अगले बजट की इन्तजार न होती'

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। 15वीं विधान सभा के इस आठवें सत्र का शुभारम्भ माननीय महामहिम के उद्बोधन से प्रारम्भ हुआ और माननीय महामहिम ने हम सबको और हमारे साथ-साथ समस्त प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की ओर समृद्धता की कामना की, उनका आभार।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जिस प्रकार का सफेद असत्य इस अभिभाषण में प्रस्तुत करवाया, उससे मैं तो क्या सम्पूर्ण प्रदेशवासी असहमत होंगे, क्योंकि सरकार द्वारा यह वाचन खुद की प्रशंसा में कहलाया गया अभिभाषण था, जिसमें सत्यता बहुत कम और डींगें ज्यादा लगती हैं। काश आप राजस्थान की जनता को, उनके दु:ख को, तकलीफ को, उनकी पीड़ा को समझ पाते और जनता ने आपको राजस्थान में जो सत्ता सौंपी थी, उसके महत्व को समझ पाते और जवाबदेही से शासन करते तो मैं समझता हूं कि जमीनी स्तर की समस्याओं में कुछ प्रतिशत कमी आप ला सकते थे, परन्तु जिस लापरवाही के साथ इस प्रदेश को विकास के अन्तिम पायदान पर आप लेकर आये और साथ ही, जिस तरीके से आपने इस प्रदेश के प्रदेशवासियों को लॉ एंड आर्डर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इनके चार आदमी बैठे हैं। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने दल के लोगों को उपस्थित रखें?

श्री सभापति: कहलवाइये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, इन चार सालों में लॉ एंड आर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। आठ लाख से भी ज्यादा मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए। मैं समझता हूं कि पूरे देश में पहला राज्य होगा, जहां आठ लाख से ज्यादा रिकार्डेड मुकदमे दर्ज किये गये। आज के अखबारों में प्रमुख खबर है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में खुलेआम

(श्री संदीप शर्मा)

बदमाशों ने फायरिंग की और पांच करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के लिए जो आतंक मचाया है, उसका पूरा जयपुर गवाह है। यह राजस्थान की सरकार को खुली चुनौती है। आपके मंत्रियों को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सुबह जब मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल क्वालीफाइड लोग नहीं लगाये, जिससे अधिकांश साइबर और ठगी के मामलों में आज तक सब में आपने एफआर प्रस्तुत की या फिर मुकदमे को आपने फाइल बन्द करके रख दिया। कल मेरा प्रश्न लगा, उसके उपरान्त कोटा शहर में थाना भी कल खुला है। सरकार के द्वारा साइबर ठगी को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके से साइबर के निर्दोष लोगों को पकड़कर, जो कोई टिप्पणी कर देते हैं, किसी प्रकार से सरकार की आलोचना कर दी या कोई धार्मिक बात कह दी तो ऐसे निर्दोष लोगों को सींखचों के पीछे डाल दिया जाता है। यह सरकार उन अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रही है, जो वास्तव में अपराधी हैं, वे पुलिस के साथ बैठकर चाय पीकर निकल जाते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, जो पुलिस की लापरवाही से हुई। सिर्फ तुष्टिकरण की नीति से राजस्थान की सरकार ने इस राजस्थान की भोलीभाली जनता को साम्प्रदायिकता की आग में धकेल रखा है।

महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, शोषण के मामले दर्ज हुए, लगभग 1 लाख 65 हजार मुकदमे अभी तक दर्ज हुए जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। 27 हजार बच्चियों के साथ दुष्कर्म और शोषण के मुकदमे दर्ज हुए और माननीय मुख्य मंत्री जी का उसके ऊपर बयान कि उनमें से 56 प्रतिशत मुकदमे बच्चियों ने असत्य दर्ज कराये हैं, और 48 परसेंट मुकदमों में एफआर लगा दी गयी। बड़ा आश्चर्य होता है। यह होता है, अंधेर नगरी चौपट राज। इस तरीके से जहां महिलाओं और बच्चियों को सम्मान न मिल सके, उस जननी स्वरूप मां का जहां सम्मान न हो सके तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि महिलाओं और बच्चियों को सम्मान देने के लिए, उनके मुकदमों में आपने एफआर लगा दी, उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से आपको इसको पुन: दिखवाना चाहिए।

आपने युवाओं के सुनहरे भविष्य के साथ छलावा किया। आपने राजस्थान को नकल का और पेपर लीक का सबसे बड़ा राज्य बना दिया। आप

(श्री संदीप शर्मा)

नकल तो नहीं रोक पाये, क्योंकि आपके लोग इसमें शामिल थे। आपने छोटे-मोटे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और उनको सींखचों के पीछे पहुंचा दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जी की नकल करते हुए बुलडोजर चला रहे हो। उन किराये की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला रहे हो, जिनका कोई लेना-देना नहीं है। आप चाहते तो उस सीबीआई की जांच के द्वारा वास्तविक अपराधियों को सामने लेकर आते और उन्हें पुन: जेल पहुंचाते, तब जाकर राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ आप न्याय कर पाते।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपने संविदाकर्मियों को भर्ती के नाम पर धोखा दिया। पूर्व उप मुख्य मंत्री जी ने भी यह बात स्वीकार की कि यह भ्रष्टाचार उच्च स्तरीय मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जो पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुए हैं, वे उच्च स्तर के राजनीतिक दबाव और मिलीभगत के कारण हुए हैं और यह बात जगजाहिर है।

माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने कोरोना के काल में जनता की सेवा की, उन सीएचए कर्मियों को आपने सेवा से मुक्त कर दिया। आपने किसानों को ऋण माफी के नाम पर छला। आपने किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति के नाम पर छला। क्या आपको नजर आता है कि इस कड़कती ठंड में सुबह तीन बजे जब एक किसान, एक धरती पुत्र अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी देने जाता है तो उनमें से अधिकांश किसान मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं? सभापति महोदय, सैकड़ों किसान मृत्यु के ग्रास में चले गये।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशीलता से काम करे और राजस्थान की जनता आज उससे न्याय मांग रही है। असत्य बजट घोषणाएं, असत्य वादे, इनको करना बन्द करें। आप पुन: बजट देने वाले हैं, उसी बजट पर बात करें, आपके द्वारा कोई खोखली घोषणा न हो, ऐसा सरकार को प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आने वाले चुनाव में वास्तव में हम जो स्थिति देख रहे हैं, इस विधान सभा में उससे भी कम स्थिति हो जायेगी। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अमीन खां (अनुपस्थित), श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री शंकर सिंह रावत)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो बनाई, उस योजना में दस लाख की जो घोषणा की है प्रत्येक मरीज के लिए, वह तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है, क्षेत्र से पता लगाना चाहिये। मरीज जहां जाते हैं, उस अस्पताल में उसको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसको पैसे भी देने पड़ते हैं तो फिर ये सरकार के लाभ का क्या औचित्य है? इसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए।

साथ ही खाने-पीने की चीजों में इस प्रकार की मिलावट हो रही है, पहले जो खाने का तेल है वह टैंकरों में आता था, अब खाने का डम्पर के अन्दर, ट्रैक्टरों के अन्दर जिस प्रकार से गुड़ की भेलियां जो होती हैं, उस रूप में आता है और बॉयलरों के अन्दर गर्म होकर वह तेल छोटी पैकिंग में और बड़ी पैकिंग में होकर बाजार में बिकता है। आप और हम खाते हैं। इसके ऊपर कानून बनना चाहिये। जांच अधिकारी भी उसको जांच में पकड़ते हैं, लेकिन आपस में जांच अधिकारी भी वही होते हैं, उसका क्या नतीजा होता है? ढाक के तीन पात रूप में, पैसों का लेनदेन होकर के एक भी ऐसे अपराधी के ऊपर सज़ा नहीं होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर राजस्थान की जनता को बचाना है तो चिरंजीवी योजना से नहीं बचेगी, उसके ऊपर कानून बनना चाहिये, खाद्य सामग्री के अन्दर। चाहे मिलावटी मसाले हों, चाहे तेल हों। जिस प्रकार की नकली शराब बन रही है, फैक्टरियां पकड़ी जा रही हैं, विदेशी मार्का की शराब यहां बनाकर बेच रहे हैं। आपके अधिकारी पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है?

सभापति महोदय, इसके ऊपर कानून बनना चाहिये। मेरी मांग है कि ऐसा कानून बने खाद्य सामग्री के ऊपर, जो भी इस प्रकार मिलावट करके बेच रहा है, उसके ऊपर फांसी की सज़ा का कानून बनना चाहिये। अब हम किसी मंत्री जी से पूछेंगे कि आपके टाइम में कितने केस हुए, तो मंत्री जी के जवाब देने से पहले मैं बताता हूं, वह मंत्री यही जवाब देगा कि आप ज्यादा बोलते हैं, आपकी सरकार के टाइम में कितने हुए थे? यही बात बोलकर के वह हमें और

(श्री शंकर सिंह रावत)

सदन को संतुष्ट करता है। मेरी मांग है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिये। अपराधी कोई भी हो, इस प्रकार का यदि काम करे तो उसके ऊपर फांसी की सज़ा का कानून बनना चाहिये ताकि अधिकारी उस अपराधी को पकड़े तो वह बच न सके। खाली चिरंजीवी योजना से हम इस जनता को बचा लेंगे, ऐसा सम्भव नहीं है। कुछ उसके साथ में आप कानून भी सख्त लाएं।

साथ ही आज जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों में चाहे वह गैंगरेप का हो, चाहे किसी प्रकार के भ्रष्टाचारी का हो, एसीबी इतने अपराधियों को पकड़ती है, आप बताएं कि राजस्थान में कौन से आदमी को, एक भी बताएं, जिसको फांसी की सज़ा हुई है। नाबालिगों के साथ में बलात्कारी पकड़े जाते हैं। इसके लिए कानून बनना चाहिये। आप और हम आंकड़ा बता देते हैं, आपकी सरकार में इतने कैसे हुए, आप कैसे सहन कर रहे हैं? हां, हमारे थोड़े कम हुए हैं, हमने प्रयास किया है। यह प्रयास नहीं, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए ताकि किसी भी नाबालिग के साथ में इस प्रकार की घटना नहीं हो। आप यह सोचें कि आपकी बेटी के ऊपर यदि हुआ होगा तो आपके मन में क्या गुजरेगी? तलवार हाथ में नहीं होगी, नहीं तो सामने वाले की गर्दन उड़ा दें। ऐसा आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपके परिवार की सदस्य हैं। राजस्थान की जनता ने आपको चुनकर यहां भेजा है। आपको मंत्री बनाया है तो उनकी रक्षा के लिए बनाया है। आपको कानून बनाना चाहिये। राजस्थान में कोई भी नाबालिग के साथ में या और किसी प्रकार से रेप होते हैं तो उसके ऊपर फांसी का कानून बनना चाहिए तब जाकर इस हाउस में हमारा आना सार्थक होता है। अन्यथा हम एक-दूसरे को, पक्ष-विपक्ष को आंकड़ा बताकर हम इस सदन को संतुष्ट करते हैं, यह गलत है। मेरा निवेदन है सरकार से कि इस प्रकार का सख्त कानून बनना चाहिए, तभी जाकर जनता के अन्दर वाहवाही होगी।

आप खाली किसी प्रकार का, कर्मचारियों को इतना फायदा दे दिया, दूसरा दे दिया, आप इसके ऊपर संगीन करिए। आज जिस प्रकार से मेरे से पहले के वक्ताओं ने काफी ऐसे केस बताए हैं। भ्रष्टाचारियों को देख लीजिए, कानून के अन्दर नहीं होने की वजह से, एक मैं अजमेर जिले का केस बताता हूं, पुलिस ने अपनी जीप में उस अपराधी को पकड़ने के लिए, 60 केस हैं और 1 लाख 48 हजार रुपये का उसके ऊपर डीजल खर्च हुआ है, सिर्फ डीजल खर्च। उसमें स्टाफ कितना लगा होगा? सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ होगा? उस

(श्री शंकर सिंह रावत)

अपराधी को 6 महीने के बाद में सरकार पकड़ती है और पुलिस पकड़कर लाती है। कोर्ट में पेश करती है और 15 मिनट के अन्दर उसकी बेल हो जाती है। वहां के पुलिस अधिकारी मेरे से भी मिले। उन्होंने कहा, एमएलए साहब, कौनसा कानून है? कानून आपकी सरकार बनाती है, आप भी उस सदन के सदस्य हैं। कानून वह होना चाहिए कि इस सरकार के इतने पैसे जो खराब हुए हैं एक अपराधी को पकड़ने के लिए और ऐसी सैटिंग होती है कोर्ट के अन्दर भी कि 15 मिनट के अन्दर उसकी बेल हो जाती है। आपको कानून बनाना पड़ेगा। आप सख्त कानून बनाएंगे। जिसके ऊपर अपराध के 60 केस दर्ज हैं, इतने पैसे सरकार के खर्च हुए..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, अभी दो मिनट में बात कहने वाला हूं। मेरे चारपांच और मुद्दे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए ताकि अपराधी किसी अपराध को करने से थोड़ा हिचकिचाए।

साथ ही आज पेपर देखा है, ये गैंग्स पनप रही हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस की मिलीभगत के बगैर कोई गैंग पनप नहीं सकती है। पुलिस के सामने ऐसे गैंग के लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी रैलियां करते हैं और सरकार उनको परमिशन देती है। सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि क्षेत्र कोई भी हो, उसके अन्दर ऐसे परमिशन देने वाले अधिकारी के ऊपर भी आपको प्रश्न चिह्न लगाना चाहिए कि आपने किस हैसियत से परमिशन दी है। उसकी जांच करनी चाहिए कि शंकर सिंह परमिशन ले रहा है तो ये किस प्रवृत्ति का आदमी है? ये किसी गैंग से मिला हुआ है क्या? इस प्रकार से अधिकारियों को भी पाबन्द करना चाहिये।

साथ ही कानून-व्यवस्था पर बहुत कुछ बोलना था। एक आज के पेपर में जिस प्रकार की पाकिस्तान में घटना घटी है, पेशावर के अन्दर 59 लोग मर गये और 157 जख्मी हैं। ये पाकिस्तान ने ही पाले थे। वो का वो हाल अगर राजस्थान की सरकार ऐसे माफियाओं को पनपा रही है, ये आपके ऊपर डसने वाले हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कानून सख्त बनाएं। सभापति महोदय, बहुत कुछ मुझे बोलना था लेकिन सारे पाइंट्स को टच नहीं कर पा रहा हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरा आपसे निवेदन है, मेरी मांग है कि सरकार सख्त कानून बनाए और राजस्थान की जनता को सुखी करे।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राजकुमार जी गौड़।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साथ में एक ब्यावर जिला, जिस प्रकार की घोषणा हो रही है, राजस्थान का तेरहवां नंबर का बड़ा शहर है। वहां की जनसंख्या का आंकड़ा देख लीजिए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राजकुमार जी गौड़।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अगर कोई भी राजस्थान में जिला बनता है तो एक नंबर के अन्दर, पहले वाली रिपोर्ट भी मेरे पास में है, परमेश चंद्र कमेटी का गठन भी इस सरकार ने किया था, उनके आंकड़े भी मेरे पास में हैं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार जी गौड़, बोलिए आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अगर कहीं गलत घोषणा से ब्यावर का नाम वंचित किया गया तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पहली रिपोर्ट के आधार पर उस नये पर स्टे लेना पड़ेगा। इसलिए ब्यावर का नाम उसमें आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अशोक गहलोत सरकार के चार साल बेमिसाल। चार साल में जो काम हुए, वह पूरी जनता को नजर आ रहे हैं। राजस्थान की आम जनता को नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो कहा वह किया, शानदार चार बजट पेश किये गये और अधिकतर वादे पूरे हुए।

मेरे साथी माने या न माने परंतु जब मैं समाचार पत्रों में देखता हूं, मीडिया में देखता हूं कि प्रतिपक्ष के साथी विकास के कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं तो काम तो सब जगह हो रहे हैं, बोलने को चाहे वे न बोलें। प्रदेश में विकास के आयाम स्थापित किये गये। राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में जीडीपी ग्रोथ रेट में दूसरा स्थान हासिल किया है, इसके लिए मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत को, उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा।

(श्री राजकुमार गौड़)

प्रदेश में इतने विकास होने के बावजूद प्रतिपक्ष के साथी विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं। पर कैसे? जब यह अपनी पब्लिक में जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे तो यहां आज बोल रहे हैं कि वहां काम नहीं हुए, पूरे प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ, तो अवश्य ही इनके वोटर पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे कि काम नहीं हुए, तो इसमें नाकामी किसकी है।

सभापति महोदय, राजस्थान में चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों का जाल बिछाना, आम आदमी को 50 यूनिट बिजली फ्री देना, 200-300 यूनिट पर अनुदान देना, उस अनुदान का फायदा हम सब लोग भी उठा रहे हैं, जो बैठे हैं। सब लोगों को फायदा मिल रहा है। किसान को हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान मिल रहा है। आम आदमी को 50 यूनिट फ्री हैं। 28 लाख से ज्यादा लोगों को बिल नहीं आ रहा। अगर यह काम नहीं है तो काम किसको कहते हैं, मैं यह समझ नहीं पा रहा।

राजस्थान देश का प्रथम राज्य है, जहां प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज खोले जा रहे हैं। आज चार मेडिकल कालेज राजस्थान में शुरू हुए। मेरा भी सौभाग्य है कि गंगानगर में भी मेडिकल कालेज शुरू हुआ। चारों मेडिकल कालेज 2021 में बनने शुरू हुए थे और 2022 में प्रत्येक मेडिकल कालेज 100 सीटों के साथ शुरू हो गया। मेरा मानना है कि एक वर्ष में तीन कमरों का मकान नहीं बनता, पर इस सरकार की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत रही कि न केवल एक साल में बिल्डिंग बना दी, बल्कि एम.बी.बी.एस. की क्लासेज भी शुरू हो गई। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

गंगानगर में तीन साल में तीन कालेज। 2019 में मेडिकल कालेज स्वीकृत हुआ, जो शुरू हो गया। 2020 में कृषि महाविद्यालय की बजट में घोषणा हुई, 2020 में ही कृषि महाविद्यालय शुरू हो गया। तीसरे साल में नर्सिंग कालेज की घोषणा हुई, नर्सिंग कालेज की बिल्डिंग बन रही है, जैसे ही राज्य सरकार की परमिशन आएगी, बच्चों के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। जो कहा वह सरकार ने किया। जहां-जहां कालेज की घोषणा हुई, वहां कालेज शुरू हुए। नर्सिंग कालेज हर ज़िले में शुरू हुए। लवकुश वाटिका की घोषणा की, लवकुश वाटिका शुरू हो गई। किसानों के अनुदान की बात आई, अनुदान मिला। किसानों के ऋण माफ

(श्री राजकुमार गौड़)

की बात आई, ऋण माफ हुआ। मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि डेढ़ लाख से नीचे ऋण माफ हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं मेरे ज़िले में हैं, जिनके डेढ़ से दो लाख रुपये से ज्यादा ऋण माफ हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य मंत्री जी ने जो कहा वह किया।

मैं किसानों के लिए बधाई देना चाहूंगा कि राज्य में 9845 डिग्गियों का निर्माण हुआ। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, गंगानगर कृषि प्रधान जिला है, डिग्गियों की ज्यादा आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से मांग कर रहा हूं कि गंगानगर में कम से कम 5 हजार डिग्गियां और बनाने की स्वीकृति प्रदान करे जिससे किसानों को फायदा हो सके।

राज्य सरकार द्वारा खालें निर्माण की जरूरत ज्यादा है। पूरे गंगानगर की तरफ से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राज्य में फव्वारा एवं बूंदबूंद सिंचाई योजना को बढ़ावा दे रहे हैं, 20 से 30 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है, इस अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम राजस्थान में चारों तरफ जाते हैं। मैं अक्सर जिस रास्ते से आता हूं, सीकर, रतनगढ़, सरदारशहर से, तो मैं देखता हूं कि जहां टीले हैं वहां बूंद-बूंद सिंचाई से, फव्वारा सिंचाई से बड़ी हरियाली है। मेरे और भी साथी उस रास्ते से आते हैं, पूरी सरसों ही सरसों नजर आ रही है, तारा-मीरा नजर आ रहा है। हम अगर इसमें और अनुदान देंगे तो निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा और राजस्थान प्रदेश को भी फायदा होगा।

गोशालाओं के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार ने 6 माह से बढ़ाकर 9 माह भरण-पोषण का काम किया है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। बड़े पशुओं के लिए 40 रुपये, छोटे पशुओं के लिए 20 रुपये, निश्चित रूप से अच्छा कदम है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सड़कों पर जो पशु घूम रहे हैं बेजुबान पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उन पशुओं के लिए भी हमको जरूर सोचना चाहिए। मैंने पूर्व में भी विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया है। आज किसी भी सड़क पर चले जाइये, बेजुबान पशु वहां बैठे हैं, न केवल उससे एक्सीडेंट होता है, पशुओं के प्राण भी जाते हैं। लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है, न जाने कितनी ही घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इस तरफ सरकार को सोचने

(श्री राजकुमार गौड़)

की बहुत आवश्यकता है। सरकार को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नंदीशाला खुले, ज्यादा से ज्यादा गोशाला खुले, जिससे लोगों की जान व माल की रक्षा हो सके। उन गायों की व नंदी की भी हम सही सेवा कर सकें। गौ को जब हम माता कहते हैं, तो उसके लिए भी जन कल्याणकारी योजना में शामिल किया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे राहत मिले।

सभापति महोदय, अभी कोटा को कैटल फ्री बनाने की बात कही गई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि न केवल कोटा बल्कि जितने भी हमारे राजस्थान में शहर है, उन सबको कैटल फ्री बनाए, तो यह भी एक बहुत अच्छा कदम रहेगा।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत एक करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है। मेरा इसमें एक सुझाव है, डेफिनेटली राजस्थान एक मॉडल स्टेट का उदाहरण पेश कर रहा है, परन्तु अब भी बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, एज वाइज पेंशन है 500, 750, 1000 रुपये, यह काफी कम है। आज इस महंगाई में इतने रुपये में पालन-पोषण होना बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग कहां जाएगा? बुजुर्ग को बच्चे सम्भालते नहीं हैं, उनको केवल आस है तो आपकी तरफ है, सरकार से आस है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कई प्रदेशों में इस तरह का है कि अच्छी खासी रकम बुजुर्गों को पेंशन के रूप में दी जाती है, विधवाओं को पेंशन के रूप में दी जाती है, तो इसके लिए भी राज्य सरकार कदम उठाये।

राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, बहुत अच्छी स्कीम है, राजस्थान में लागू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैंने टीवी पर देखा था, उन्होंने कहा कि यह रेवड़ियां बांट रहे हैं। यह रेवड़ियां नहीं बांट रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो आदमी सेवा करता है, सरकारी कर्मचारी है, उसका भविष्य कैसे उज्ज्वल बने, उसकी सुरक्षा कैसे हो, यह राज्य सरकार ने किया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

सर, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। राज्य सरकार शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, परन्तु अभी भी गंगानगर में पंजाब से जो नहरें आ रही हैं उनमें गंदा पानी, जहरीला पानी आ रहा है। उसके लिए पूर्व में

(श्री राजकुमार गौड़)

भी कोशिश की गई, सरकार को चाहिए कि पंजाब सरकार से बात करके राजस्थान की नहरों में जो जहरीला पानी पंजाब से आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, कीटनाशक दवाओं का पानी आ रहा है, उस पानी को बंद कराये और लोगों के जीवन को बचाये।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): शुद्ध जल मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सीमित शब्दों में अपनी बात रखूंगा। इस बात के साथ शुरू करूंगा कि मेरे सत्य बोलने से अगर आपकी भावना आहत होती है तो अपनी भावना बदल लो, मैं तो सत्य को जैसा है वैसा ही कहूंगा।

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हम सबने पढ़ा, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि "मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगता है वह सामने से हट जाए।"

माननीय सभापति महोदय, अभी बहुत लम्बी-चौड़ी बातें की जा रही थीं। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति नकल भी करता है, प्रकृति कितना साथ देती है, उस बात को निवेदन करूंगा। कोई दाढ़ी बढ़ाकर रविन्द्र नाथ टैगोर सा महर्षि बन जाता है, कोई दाढ़ी बढ़ाकर महर्षि रविन्द्र नाथ टेगोर जैसा नजर आता है, दूसरी तरफ कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है तो तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा नजर आता है। अक्ल और नकल दोनों में प्रकृति कितना साथ देती है, यह हमारे सामने है।

एक बात और कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, पैदल यात्रा करने के बाद भी 2024 में सत्ता नहीं मिली, प्रधान मंत्री नहीं बन पाए, तो तय कर लेना कि 2024 में लेट कर आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वातावरण बना है राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार के समय में, उससे क्या हालत हो गयी राजस्थान की आठ करोड़ जनता की।

यह चार साल का बजट और पांचवां बजट इस समय आने वाला है और मैं यह कहूंगा कि इसी सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष

(श्री अविनाश)

2019 से लेकर वर्ष 2023 तक जो-जो बजट में घोषणा की, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे वहां पर आपने उप तहसील कार्यालय आनन्दपुर कालू में नया खोला, लेकिन आज भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। एक पुराने पंचायत भवन के अंदर उप तहसील का कार्यालय चल रहा है।

आपने उप परिवहन कार्यालय जैतारण में खोला, वित्तीय स्वीकृति चार साल बाद भी नहीं मिली। एक किराये की दुकान के अंदर वह परिवहन कार्यालय खुला हुआ है।

आपने राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, जैतारण के अंदर साइंस फैकल्टी नई खोली लेकिन आज भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कम से कम साइंस के जो बच्चे हैं, एक कम्प्यूटर लैब को खाली करवाकर उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के जो विद्यार्थी हैं वे एक ही रूम के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं। न तो लैबोरेटरी है, न भवन है, न कक्षा कक्ष है और ईवन बालकनी के अंदर बैठकर भी पढ़ाई करते हैं। ये घोषणाएं तो करते हैं पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है।

गिरी सुमेल की रणस्थली के अंदर पचास लाख के पैनोरमा की घोषणा इसी सरकार में हुई लेकिन आज वस्तुस्थिति देखिये कि उस पचास लाख रुपये का क्या हुआ, कितना पैसा लगा, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है।

आपने बर पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कर दिया लेकिन आज भी उसी पी.एच.सी. के अंदर सी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने का नाम करके उसको चलाया जा रहा है। आपने बर के अंदर पुलिस चौकी को पुलिस थाना में कन्वर्ट कर दिया, क्रमोन्नत कर दिया, उसी पुलिस थाने के भवन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बना, उसी के अंदर पुलिस चौकी पुलिस थाने के रूप में चल रही है।

आपने अल्ट्राटेक प्लांट लगने के कारण टूकड़ा में फैक्टरी प्रबंधकों के कारण एक नई पुलिस चौकी खोली लेकिन उस पुलिस चौकी का भी अभी तक कोई नामोनिशान ही नहीं है। एक साल बीतने को आया लेकिन धरातल पर वह टूकडा चौकी अभी तक नहीं खुली है।

आपने इन चार साल के अंदर गौरव पथ अगर दिया है तो चार साल के अंदर एक मात्र दिया है बलून्दा के अंदर, उसके बाद चार सालों में आपने

(श्री अविनाश)

एक भी गौरव पथ नहीं दिया है। आपने पिछले बजट में एक सड़क जरूर दी थी जैतारण से निम्बोल तक की, लगभग उसका काम पूरा हो गया है और एक आपने सी.एच.सी. जैतारण में पचास से सौ बेड करने की घोषणा की थी लेकिन आपने बाद में बताया कि हम 75 बेड का करेंगे, लेकिन आज दिन तक भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। अभी भी बहुत अधिक नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट्स खाली हैं, आपके डाक्टर्स के पद खाली हैं तो यह घोषणाएं जो करके आप लोगों ने यह काम किया है, जैतारण की जनता आपको समझ रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके भ्रष्टाचार के कारण जैतारण में ए.सी.बी. के अंदर, कई विभाग के अन्दर अधिकारी-कर्मचारी ट्रैप हुए हैं। एक्स.ईएन. डिस्कॉम का ट्रैप हुआ, ई.ओ. नगरपालिका का ट्रैप हुआ। ए.एस.आई. पुलिस चौकी, बाबरा का ट्रैप हुआ है। तहसील कार्यालय का रीडर ट्रैप हुआ है। पुलिस थाना जैतारण का रीडर और कांस्टेबल ट्रैप हुआ। यह भ्रष्टाचार अगर कहीं मिला है राजस्थान में तो वह आपकी सरकार के अंदर मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार जब बजट पेश करे, घोषणा करने में क्या जाता है, मैं चाहूंगा कि जब यह नया बजट आये तो उसमें मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जो पूर्व में बहुत ही प्रतीक्षित है, लम्बे समय से रास को उप तहसील घोषित करें और सेन्दडा उप तहसील जो है, लम्बे समय से उप तहसील के रूप में है उसको तहसील कार्यालय के अन्दर क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

मैं बहुत लम्बे समय से यह प्रयास कर रहा हूं कि जैतारण मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना हो जिसकी लागत लगभग आठ करोड़ रुपये की है और मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को, राज्य सरकार को लगातार यह प्रयास किया, यह प्रस्ताव दिया हुआ है कि जिला खेल अधिकारी से लेकर यहां क्रीड़ा परिषद् तक मेरा प्रस्ताव दिया हुआ है, उसको भी स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

साथ में, अभी जो जैतारण के अंदर बर के वकील साथियों ने एक हड़ताल कर रखी है, उनकी यह मांग है कि ए.डी.जे. कोर्ट बर के अंदर खोला जाये। मैं भी उसकी मांग करता हूं और साथ में एससी., एस.टी. कोर्ट का जो कोर्ट कैम्प है, कम से कम महीने में एक सप्ताह या दस दिन के लिए

(श्री अविनाश)

जैतारण के अन्दर खोला जाये, क्योंकि पाली जिला मुख्यालय पर कोर्ट होने के कारण लगभग सौ, सवा सौ, डेढ़ सौ किलोमीटर तक परिवादी को, पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को जाना पड़ता है इसलिए यह कोर्ट कैम्प के लिए निवेदन करता हूं जैतारण में।

विज्ञान संकाय, चाहे वह रास का माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे लाम्बिया का माध्यमिक विद्यालय हो, वहां पर इन विद्यालयों के अंदर साइंस फैकल्टी नहीं होने के कारण साइंस के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको दूर जाना पड़ता है, तो वहां पर भी इस विषय को खोलने की स्वीकृति प्रदान करायें।

लाम्बिया से पुष्कर तक वाया कुड़की होते हुए डबल लेन सड़क निर्माण का लम्बे समय से मैं प्रयास कर रहा हूं और मेरा यह निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बार जब बजट पेश करें तो मेरी यह जो लम्बित मांग है लाम्बिया से पुष्कर वाया कुड़की, उसकी डबल लेन की स्वीकृति प्रदान करायें।

इसके साथ में, पुष्कर से लेकर कुड़की लाम्बिया होते हुए पीपाड़ा, डिगरना, बरूंदा तक यह डबल रोड की मांग भी है हमारे क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से और हमारे माननीय सांसद महोदय भी इसके लिए प्रयासरत हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि यह दो रोड हमारी मिले। इसके साथ में झाला की चौकी से लेकर कोट किराणा तक, यह लगभग तीस से पैंतीस किलोमीटर है वाया काणूजा और बगड़ी कलालिया होते हुए, इस सड़क की हालत इतनी खराब हो गयी है कि वहां पर चलना भी मुश्किल है, इसको भी अपग्रेड करके नयी बनाने का प्रयास करें।

साथ में, माननीय सभापति महोदय, आप जिस चेयर पर विराजे हुए हैं, इसी चेयर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय श्री हीरासिंहजी चौहान साहब थे। मैंने यह बहुत बार निवेदन किया कि उनके नामकरण से उनका जो पैतृक गांव है काणूजा, उसमें राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय जो है, उसका नामकरण स्वर्गीय श्री हीरासिंहजी चौहान साहब के नाम पर करके रावत समाज को बहुत बड़ा आशीर्वाद यह सरकार अगर प्रदान करे तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री हीरासिंहजी चौहान साहब को नहीं होगी, तो यह घोषणा भी करें कि काणूजा की जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल है उसका नामकरण स्वर्गीय श्री हीरासिंहजी चौहान साहब के नाम पर होगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र का मगरा इलाका है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें सैनिक नहीं होगा और शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, अधिकतर परिवारों में सैनिक शहीद हुए हैं। मैं यह चाहूंगा कि सैनिक परिवार में जो शहीद हुए हैं उनकी मूर्ति लगाने का प्रयास करें ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं दो मिनट में अपनी बात को खतम करूंगा। सेन्दड़ा हुआ, देवरिया हुआ, सेलपुरा, यह जो सब सेंटर्स हैं, उनको पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करायें और साथ ही आनन्दपुर कालू जो बहुत बड़ा कस्बा है, वह पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराने की कृपा करायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब आज सुबह अख़बार पढ़ रहा था तो मैंने यह पढ़ा कि आज आप जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान सरकार ने इसी हाउस में यह घोषणा की थी कि जो-जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनको डिबार कर दिया गया।

श्री सभापति: थैंक यू। थैंक यू।

श्री अविनाश (जैतारण): उनको डिबार कर दिया गया। यह 31.01.2023 की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इसमें यह कहा है कि चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण आजीवन डिबार किये गये अभ्यर्थियों को सी.ई.टी. के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिये गये हैं।

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री अविनाश (जैतारण): यह ऐसी लापरवाही इस राजस्थान सरकार की है। यह आज का अख़बार है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं दो ही मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: टाइम हो गया। टाइम हो गया।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया (अनुपस्थित)।

श्री अविनाश (जैतारण): यह जो चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण

(श्री अविनाश)

हुआ है। एक आपने जो चिरंजीवी की बात की है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह कहूंगा कि इसी सरकार ने चिरंजीवी की बहुत बड़ीबड़ी बातें की हैं लेकिन 11 लाख कर्मचारी पेंशन की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री पब्बाराम विश्नोई। कृपया, आप समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): लगभग 30 से ज्यादा जरूरी दवाइयां बंद कर दीं इसी राजस्थान सरकार ने और इस सरकार के द्वारा यह देखें, मैं बताऊं कि बी.पी., हार्ट, विटामिन-डी, कफ सिरप, ईसबग़ोल, टूथपेस्ट, डायजेस्ट सिरप, डैंड्रफ सोल्यूशन, स्लीपिंग पिल्स, विटामिन डी-3, विटामिन ए, हीमोग्लोबिन, बी-12 यह जरूरत की 30 दवाइयां बंद कर दी हैं और इसके आपके जो पी.डी. है आर.जी.एच.एस. के उन्होंने यह कहा है कि सिविल सर्विस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत यह दवाइयां बंद कर दी गयी हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री अविनाश (जैतारण): यह दवाइयां लाभार्थियों को पहले गलती से दे रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री पब्बारामजी, बोलिये आप।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो राजस्थान सरकार ने अभिभाषण पेश किया है, यह किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है और आने वाले समय में ये घोषणा करें तो कम से कम जो यह घोषणाएं हैं, वे धरातल पर उतारें।

एक प्रमुख बात, यह जो डायलिसिस का आपने कहा था पिछली बार, सी.एच.सी. पर डायलिसिस शुरू करेंगे तो आप यह बताइये कि कितनी सी.एच.सी. पर डायलिसिस शुरू हुआ है? मैंने पावन धाम समाज सेवी संस्था से दिया है पर आज दिन तक दो साल बाद भी, पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी के हाथों से उद्घाटन करवाया है, लेकिन आज दिन तक चिकित्सा मंत्री के उद्घाटन करने के बाद भी वह डायलिसिस मशीन शुरू नहीं हो पायी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा यह जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए बार-बार शिक्षक संघों द्वारा निवेदन किया जा रहा है, उसके बाद में भी यह नहीं किया जा रहा है। मेरे पाली जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 2012 के नोशनल तिथि से ए.सी.पी. देने के सम्बन्ध में बार-बार जिला शिक्षा अधिकारियों को निवेदन किया गया लेकिन आज दिन तक वह काम नहीं हुआ और इससे शिक्षकों के अंदर हताशा है।

श्री सभापति: आप बोलिये। थैंक यू, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): अपराध के मामले में, माननीय सभापति महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। एफ.आई.आर. के बाद में आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री सभापति: पब्बारामजी, आप बोलिये। इनका रिकार्ड नहीं होगा। आप बोलिए। आप शुरू करिये। प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

चार साल का कुशासन, संवेदनहीन सरकार, जंगल राज, जवाबदेहहीनता यह चारों तरफ जिस प्रकार का आलम है, यह प्रदेश की जनता उसे भुगत रही है। मैं यह समझता हूं कि हमारे पक्ष के लोग जिस प्रकार से सावन का अंधा, उसको हरा ही हरा दिखाई देता है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमने कर दिया और जब जनता के बीच में ये जाएंगे तो हमारी वाहवाही होगी परंतु जब आप अपने-अपने क्षेत्र में मिनी सी.एम. हैं, कौन आपके गले में घंटी बांधेगा और जनता उस समय का इंतजार कर रही है जब इलेक्शन का शंखनाद हो जायेगा, उस समय जाने पर आपको पता चलेगा कि क्या-क्या आपने किया है और किस तरह का आपने विकास किया है, वे सारी बातें यहां सामने आ जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं के बारे में आपको बानगी बता देता हूं। आपने जेजेवाई के सारे ट्यूबवैल जलदाय विभाग को दे दिये, उनको न तो जलदाय विभाग ठीक कर पा रहा है और न ही उनके पास बजट है। दुर्भाग्य है मेरे फलौदी का, वहां सौ ट्यूबवैल आज भी बन्द पड़े हैं। एक कांस्टीट्यूएंसी में जब सौ ट्यूबवैल बन्द पड़े हों तो आप मान सकते हैं कि जल प्रदाय की स्थिति क्या होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम हमने जब आपको सुपुर्द किया था, एक भी ट्यूबवैल बन्द नहीं था और आज यह स्थिति है कि सौ ट्यूबवैल एक कांस्टीट्यूएंसी में बन्द हैं तो आप अन्दाजा लगा लीजिए कि राजस्थान में जल प्रदाय की स्थिति क्या है।

सभापति महोदय, मैं अपनी प्रमुख मांग को भूल जाऊंगा, बाद में आप बैठने के लिए कह देंगे। फलौदी की जनता लम्बे समय से लगभग 1977 से

(श्री पब्बाराम)

फलौदी को जिला बनाने की मांग कर रही है। सभी दलों के लोगों ने एक साथ मिलकर फलौदी को जिला बनाने के लिए आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी जो हमारे गृह जिले के ही रहने वाले हैं, सहानुभूतिपर्वक विचार करते हुए हमारे फलौदी को जिला बनाने की घोषणा करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन प्रधान मंत्रीजी की महत्वाकांक्षी योजना है परन्तु ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्य मंत्रीजी किसी तरह से इस योजना को लागू नहीं करना चाहते। यदि लागू करना भी चाहते हैं परन्तु वह मजबूर हैं क्योंकि उनके पास अपने हिस्से की राशि नहीं होगी। तीन बार टेंडर होने के बाद तीनों बार ही टेंडर को कैंसिल करवा दिया गया। आप अन्दाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से कछुआ चाल यह जल जीवन मिशन चल रहा है। प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि हम 2024 तक हर घर में नल से जल सप्लाई करेंगे, परन्तु जैसे कि आपने संकल्प ले लिया है कि प्रधान मंत्रीजी के कथन को असत्य साबित करना हमारा फर्ज है और इसीलिए आप बार-बार उस टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।

सभापति महोदय, शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। 10वीं से सीनियर सैकण्डरी करने की बात करते हो। नयी शिक्षा नीति के अन्दर 10वीं का स्तर है ही नहीं। आप कह रहे हो कि 3500 स्कूल्स को हमने सीनियर सैकण्डरी बना दिया। 10वीं की कक्षाएं पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं रही। सीधे 8वीं से 12वीं में क्रमोन्नत होती है। आपने क्या किया? यह तो केन्द्र की बात है। नयी शिक्षा नीति के अन्दर 10वीं का स्तर ही नहीं है। आपको तो वह करना ही था। आपकी मजबूरी थी इसलिए आपने कर दिया। आप उनके अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाये, आप शिक्षक नहीं दे पाये। आप शिक्षक नहीं दोगे तो ग्रामीण लोगों की स्थिति क्या होगी? आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्षेत्र के शिक्षक सभी शहरों के आसपास लगा दिये गये। हमारे वहां पर 35 परसेंट शिक्षक हैं और 65 परसेंट पद खाली हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हो कि ग्रामीण लोगों की शिक्षा की स्थिति क्या है।

सभापति महोदय, अंग्रेजी स्कूल्स की बात करते हैं। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं, मुझे पता है। वही शिक्षक जो हिन्दी स्कूलों में लगे हुए हैं उन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफर करके उसका इन्टरव्यू लिया जाता है। थोड़े बहुत ठीक होते

(श्री पब्बाराम)

हैं, उधर लगा दिये जाते हैं। पिछले ही दिनों जब एक आईएएस उनकी जांच करने गया तो पता लगा।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी तो दो मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति: आपको छह मिनट हो गये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। मैं 5.52 बजे शुरू हुआ हूं और आपने टोक दिया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बाद में बोलने नहीं देंगे।

महोदय, जिस प्रकार से पेपर आउट का ताण्डव हुआ, 16 पेपर आउट नहीं हुए, पूरे के पूरे, जितनी भी परीक्षाएं आपके समय में हुई हैं, उसमें सारे के सारे पेपर आउट हुए हैं। आपने युवाओं को इस प्रकार से अंधेरे के गर्त में झोंक रखा है। आपको तब पता चलेगा जब युवा आक्रोशित होगा। आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। युवाओं के साथ में कैसा धोखा किया है। बहुत सारी बातें की हैं।

तीन से चार घंटे बिजली मिलती है। आपने कहा कि बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। सात-सात रुपये तक आपने टैरिफ लगा रखा है। महोदय, यह फलौदी का दुर्भाग्य ही होगा। फलौदी में एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब है भड़ला, वहां से लगभग पूरे राज्य को बिजली सप्लाई होती है, वह क्षेत्र ही बिजली के लिए तरस रहा है। बिजली वहां पर पूरी नहीं मिल रही है। तीन से चार घंटे बड़ी मुश्किल से सप्लाई हो रही है। घरेलू बिजली जो 22 से 24 घंटे मिलती थी वह आज के दिन सिर्फ कृषि की बिजली के साथ में ही मिलती है।

डिस्काम की स्थिति यह है कि वहां पर जो ट्रांसफार्मर आते हैं वह डिफेक्टिव हैं। टेपू गांव की घटना आपको बता देता हूं, आपका दिल दहल जायेगा। सेना का एक जवान घर पर छुट्टी आया था। पाबूदान सिंहजी का बेटा हेमसिंह। डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण उसके अन्दर करंट आया, चार गायें खतम हो गयीं और वह जवान भी खतम हो गया। जब मैं उनके पास में दु:ख बांटने गया तब उस शूरवीर बाप ने यह कहा कि मेरा बेटा अगर सरहद के ऊपर दुश्मन से लोहा लेते समय शहीद हो जाता मुझे गम नहीं होता परन्तु डिस्काम की इस गलती के कारण, इस डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के कारण मेरे बेटे ने जान दी है, यह मुझे दर्द है। आप अन्दाजा लगा लीजिए कि डिस्काम किस स्थिति में है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्री पब्बाराम (फलौदी): चार मिनट ही दिये हैं, माननीय। सात मिनट का समय तो पूरा दीजिए। तीन मिनट मेरे बचे हुए हैं।

आप देखिए कैसे जादूगर हैं। पिछली सरकार ने सब्सिडी के दस हजार रुपये दिये थे, वह बन्द कर दिये। यानी कि 36 हजार आपने खा लिए। उसके बाद में दो-दो हजार और बढ़ाकर 24 हजार दे दिये दो साल के लिए। आपने हमारे कितने रुपये खा लिए। आपने 30 से 35 हजार रुपये खा लिए और हमसे ताली भी पिटवा ली। हम वाहवाही कर रहे हैं लेकिन आपने यह क्या किया? आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की जादूगरी नहीं करें।

आपने फलौदी को जिला अस्पताल घोषित किया। हमारा अस्पताल बीमार है। पिछले दिनों लोड़िया का एक जवान, हमारे वहां का हीरो, वहां का खिलाड़ी, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया तो एनेस्थीसियन नहीं था। पिछले एक साल से एनेस्थीसियन नहीं है। सारे के सारे आपरेशन वहां पर बन्द हैं। वहां पर एक तिहाई डाक्टर्स भी मौजूद नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है। ब्लड बैंक भी काम नहीं कर रहा है। ब्लड की कमी के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। राहुल गूचिया नाम का लड़का है। इस प्रदेश के अन्दर आपकी मेडिकल की क्या स्थिति है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। प्लीज हो गया।

श्री पब्बाराम (फलौदी): जिला अस्पताल आपने खोल रखा है। ऐसी ही स्थिति सभी जगह है। एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से पंजाब उड़ता पंजाब था, राजस्थान आज उड़ता राजस्थान बनता जा रहा है। हमारे वहां पर नशे की गोलियां हर किराने की दुकान पर मिल जाती हैं।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री पब्बाराम (फलौदी): वहां का युवा तिल-तिल के लिए मर रहा है। हालत खराब है। घरों के अन्दर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मां-बाप किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर देखते हैं। यह परिस्थिति है। आप उसको रोक नहीं पा रहे हो।

श्री सभापति: हो गया। प्लीज। बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिए। एक मिनट।

श्री पब्बाराम (फलौदी): कोई न कोई राजनीतिक शक्ति उनके पीछे

(श्री पब्बाराम)

लगी हुई है और उसके सपोर्ट के कारण वह सारा हो रहा है। इसको रोकने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: अब देखिए बोलने वाले ज्यादा हैं। आठ मिनट इनको दिये जा रहे हैं। आपका पहले दस मिनट था, आठ मिनट ही आपका किया जाता है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। बहुत लम्बे समय से इस अभिभाषण पर सभी के विचार जान रहे थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत साहब ने इस राज्य की सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद लम्बा समय कोरोना में निकला, उसको भी चार साल में ही काउंट कर रहे हैं। राज्य सरकार को कितना समय काम करने के लिए मिला। मैं आप सबका, माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो काम करने का समय मिला, उसमें चाहे सड़कों का काम हो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, चाहे कालेज खोलने हों, चाहे हमारे विद्यालय क्रमोन्नत हुए, सब्जेक्ट खुले, हेल्थ के क्षेत्र में, उप जिला चिकित्सालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में बना, दो CHC खुली। ऐसे अनेकों काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज संचालित हैं और कार्यरत हैं। जो महाविद्यालय खुला, उसके भवन का निर्माण लगभग अप्रैल में पूरा होकर उसका लोकार्पण होने की स्थिति में आ जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है?

(समय: 18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, यहां माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि यह जो विकास है, इसके बगैर कोई भी चीज सम्भव नहीं है। कोई भी सरकार आती है, चली जाती है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस कार्यकाल में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में ढाणियों की सड़कों का निर्माण कार्य था, वह लगभग 15 साल के कार्यकाल में जितनी नहीं बनी उतनी इस 5 साल के कार्यकाल में ढाणियों की नई सड़कें बनी हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। 5 करोड़ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले दिये। पिछले बजट में 10 करोड़ और दे दिये। आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर पूछ आइये, वहां पर ऐसे-ऐसे रास्ते थे जिसके अंदर बरसात के टाइम में पैदल जाना सम्भव नहीं था, आज उसके ऊपर ट्रक चलकर जाता है। चारे का ट्रक

(श्री आलोक बेनीवाल)

ठेठ गांव के खेत और किसान के घर जाकर खड़ा होता है। यह एक जगह का उदाहरण नहीं है, कई जगहों के उदाहरण हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये-सुनिये, आपस में बात नहीं करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं इसलिये कह रहा हूं, आपने भी अपने कार्यकाल में जब बीजेपी का शासन था, लोगों का खूब काम कराया। मैं आपको इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी क्षेत्रों में काम किया। चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, चाहे और अन्य क्षेत्र जो भी हैं, किसी भी क्षेत्र को उन्होंने प्रगति की रफ्तार से पीछे नहीं छोड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, आज इंडस्ट्री की बात करते हैं। आज जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो महंगाई की स्थिति है, महंगाई की स्थिति क्या हो गयी है? आपकी बीजेपी का राज जब दिल्ली में आया, उस समय आटे की क्या रेट थी और आज क्या हो गयी है? आपने खाने-पीने की चीजों पर भी GST लगा दिया है, वह आपको नहीं दिखेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या गांवों में है वह है पीने के पानी की। आज पानी की हालत बड़ी खराब है और खास तौर से पूर्वी राजस्थान, जहां से हम आते हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं है। आज सारी निर्भरता बरसात के ऊपर हो गयी है। पानी नीचे किस स्तर पर है, वह हम सबको अच्छी तरह पता है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि जब पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बात चली और यह उम्मीद जगी कि प्रदेश के ही मंत्री केन्द्र में मंत्री हैं। इसलिये उम्मीद जगी कि जो भी कोई मंत्री बनता है तो वह कहीं न कहीं अपने विभाग का और अपने प्रदेश का विकास करने में चार चीजें एक्स्ट्रा ही देता है। मैं यह इसलिए कह सकता हूं कि आदरणीय कमला जी जब मंत्री रहीं तो उसका लाभ हमारे क्षेत्र को विशेष रूप से मिला। आज जो भी मंत्री बने हैं या पहले बने हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ अपने क्षेत्र को मिलता ही मिलता है। लेकिन हमें बड़ी निराशा हाथ लगी कि इस योजना के संबंध में जो उनका दृष्टिकोण होना चाहिये था, वह हमें नजर नहीं आया। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सदन में ही

(श्री आलोक बेनीवाल)

विपक्ष के लोगों को कह चुके कि आप आगे चलिये, हम आपके पीछे चलते हैं और प्रधान मंत्रीजी के पास में जाकर इसको राष्ट्रीय योजना घोषित कराने के लिए, कोई तैयार नहीं हो रहा। सांसद बने हुए हैं, लेकिन इस संबंध में एक शब्द भी कहीं पब्लिक के बीच में नहीं बोलकर आते कि इस योजना को हम लागू कराने में प्रधान मंत्रीजी से बात करेंगे। मैं आपको इसलिये कह रहा हूं कि आज पानी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं दो ही मिनट लूंगा, माननीय सभापति महोदय। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं आज जनता कोई समझती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जनता सब चीजों को समझती है। पब्लिक सब जानती है कि कौन कहां काम कर रहा है, कौनसे काम नहीं किये, यह सब फैसला जनता करती है। यह आने वाले समय में भी करेगी, आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिये कहता हूं कि हम गांव में जाते हैं यह कह रहे हैं गांव में जाओगे तो, हम रोज ही गांव में जाते हैं। हमारे तो ऐसी स्थिति हो गयी है कि हमने जो काम किया, हमारे पास मांग ज्यादा आने लग गयी है। पहले मांग ही नहीं थी। मांग इसलिये नहीं कि कोई काम ही नहीं करता था, तो जनता भी यह सोचती थी कि यह काम तो होगा नहीं। जनता अब यह समझने लग गयी कि काम होता है तो ज्यादा मांग करने लग गयी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। इन्होंने अपने विभाग में बहुत नवाचार किया। जो सरप्लस लोग थे, उनको उस जगह भेजा है जहां पर लोग नहीं थे, चाहे जोधपुर हो, पाली हो, जालौर हो। इन जगहों पर काफी ANM, GNM को वहां पर पदस्थापित किया है जिससे उस क्षेत्र के अंदर जो कमी थी, उसकी पूर्ति कर सकें। इन्होंने वहां पर डाक्टर्स को भी भेजा है। यह जानते हैं कि कहां पर कमी-बेशी है। यह कमी-बेशी कोई एक दिन की नहीं है।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो ERCP की मांग है, उसके अंदर आप लोग भी सकारात्मक रूप से अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखें, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको भी पूछेगी कि आपने इसमें क्या किया?

श्री सभापति: समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): एक सैकण्ड। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र 1981 से लेकर आज तक जिले की मांग के लिए लड़ता रहा है और मैं भी पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि मेरे शाहपुरा को जिला बनाया जाये। इसकी मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करता हूं, हाउस को भी निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: दोनों ही पक्ष के सचेतक महोदयों से बात करने के बाद और चूंकि संख्या बोलने वालों की ज्यादा है, इसलिये सात मिनट इधर के और सात मिनट इधर के। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, दस मिनट तो दीजियेगा कम से कम। मुझे अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पांचवां अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा राजस्थान की विधान सभा में रखा गया। जिस तरह से महामहिम महोदय द्वारा उनके मुखारविंद से इस राजस्थान के सर्वांगीण विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने की बात कही गयी, निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ना चाहिये, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किस तरह से राजस्थान की जनता के लिए विकास के सभी द्वार हमें खोलने चाहिये, इस बात पर भी हमें मनन करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, इसे हम केवल आत्म-परिवेदना कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और जिस तरह से उन्होंने इस बात को भी कहा कि अब हमारा प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है, मॉडल स्टेट के रूप में उभरे, लेकिन क्या मात्र इस अभिभाषण का हम लोग उनके मुखारविंद से कहलवा दें, पढ़वा दें, इससे यह सम्भव नहीं होगा। मैं कहूंगी कि अगर इसमें इस बात को भी हम रखते, जैसा आपने कहा कि डबल डिजिट की GDP ग्रोथ रेट के साथ देश में दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है, लेकिन एक बात और इसमें जोड़ दी जाती कि मोदीजी के नेतृत्व में जी-20 और प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय हमारे जो संगठन हैं, उसकी अध्यक्षता करने के बाद, लम्बे समय के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर वह भी राजस्थान का एक गौरव है। यह भी अगर हम इसमें लिखवाते तो निश्चित तौर पर राजस्थान के सभी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

विधायक सम्माननीय राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देते और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देते।

मैं आज के दिन इतना ही कहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विगत 4 वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जो स्थिति बिगड़ी है, यह हम सभी को मालूम है। मैं इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। कई बार पेपर लीक हुए। सरेआम हत्याएं हुईं। महिलाओं पर अत्याचार हुए। बिजली और पेट्रोल की कीमतें प्रदेश में अन्य राज्यों से अधिक हैं। युवा वर्ग जो बेरोजगार है, किसान और कर्मचारी वर्ग सभी अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर यह विचार करने की बात है।

सभापति महोदय, मैं आज के दिन यह भी कहूंगी कि सम्माननीय हमारे सारे मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, चिरंजीवी योजना की हम सभी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप और हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो जो बातें हम लोगों के सामने आती हैं और जैसा कि हमने देखा है कि किस तरह से इस कार्ड को लेकर हमारे बंधु निजी हास्पिटल्स में घूमते रहते हैं। कभी वहां से भगा दिया जाता है, फिर दूसरे हास्पिटल में जाते हैं। मैं जहां रहती हूं, मेरे आसपास सारे प्राइवेट हास्पिटल हैं। वहां कई बार ऐसा मंजर देखने को मिलता है और उस बात से मन में पीड़ा होती है। निश्चित रूप से हम सभी हास्पिटल्स को पाबंद करें कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से बंधु इस योजना के लाभ के लिए आएं, उसे इधर-उधर गुमराह न किया जाये। इससे इस योजना को लाना सार्थक होगा।

लंपी वायरस की वजह से हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में 10 लाख गोवंश हमारा खतम हो चुका है। इस बात पर भी हमें आने वाले समय में क्या करना है और किस तरह से राजस्थान के गोवंश को बचाना है, इसकी रूपरेखा भी अगर हम तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में हमारे गोवंश के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, साथ ही मैंने कितनी बार सुना, सम्माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा, सीएम साहब ने भी पिछले सत्र में अपने भाषण में कहा और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भी कहलवाया गया कि बिजली में हम सरप्लस हैं, हमारी कई इकाइयां बिजली उत्पादन कर रही हैं। फिर आखिर यह स्थिति क्यों बनी हुई है कि गांव की जनता, हमारी बहनें जब नरेगा की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मजदूरी से आती हैं, खेत में से आती हैं, खाना बनाने के लिए चौक पर बैठती हैं तो बिजली गुल हो जाती है? सवेरे बिजली गुल हो जाती है। मेरी विधान सभा की यह हालत है कि बिजली जाने की वजह से पानी की टंकियां खाली रहती हैं, पानी के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसी स्थिति वहां की जनता की बनी हुई है।

मैं आज के दिन यही कहूंगी कि आने वाले समय में अगर हम राजस्थान को एक मॉडल बनाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। 18 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम होना और 200 किसानों का आत्महत्या करना, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे किसान को मजबूत करें जिससे किसानों की यह सारी बातें रुकें।

क्रोप कटिंग के माध्यम से हम उन्हें मुआवजा देने का काम करें। 2021 में अतिवृष्टि आई थी।

श्री सभापति: कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, समय देख लीजिये। मुझे आप 8 मिनट तो दीजिये।

श्री सभापति: 7 मिनट दे दी सबको।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 2021 का जो मुआवजा था, वह भी मेरी विधान सभा का आज तक नहीं मिल पाया है, मेरा निवेदन है कि उसे भी दिया जाये।

साथ ही मैं यह भी मांग करूंगी कि जो खनन की आपने बात की है, महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवायी गयी है कि हमने 7279 करोड़ रुपये हमारे खनन दाताओं से अंशदान के रूप में संग्रहित किये थे। आपने 3164 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं जिस विधान सभा से आती हूं, वहां की कितनी राशि बनती है, मेरी विधान सभा की, उस जिले की, उस राशि को वहां पर क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

हमारे सम्माननीय यूडीएच मिनिस्टर साहब यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे भी कहूंगी, आपने कहा कि ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने का आपने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जो प्रयास किया है कोटा के लिए, यह एक अच्छा प्रयास है। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। आपने 460 करोड़ रुपये के जो 3 अंडरपास बनाये और 5 फ्लाईओवर बनाये, वह ठीक हैं। मेरा निवेदन है कि जब मैं पाटन से आती हूं, जब भी मैं बालिथा रोड पर, फ्लाईओवर पर चढ़ती हूं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें टेक्निकल फाल्ट रहा है, ऊपर चढ़ना और वहीं पर उतरना, वह ऐसा लगता है जैसे कि वहां की जनता को गुमराह कर रहा है। उसमें भी अगर कोई टेक्निकल फाल्ट रहा हो तो उसे हम सुधारने का काम करें।

सभापति महोदय, साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि मेरी विधान सभा में बहुत सारी ऐसी पुलिया हैं जो जन-जीवन को रोक देती हैं। हम लोग 8-8 दिन दूसरे गांवों में नहीं जा पाते, गांव के लोग बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी पुलियाएं मैंने लिखित में भी सम्माननीय सीएम साहब को भेजी हैं कि बजट में उनकी घोषणाएं की जायें। जैसे कि मेरे यहां कुरेल नदी पर एक पुलिया का निर्माण है, उसे भी मुझे दिया जाये। एक और कोड़किया बालाजी से जगन्नाथ पुरा सड़क है, उस पर मेज नदी पर एक पुलिया बनेगी, उसका भी मैंने प्रस्ताव बनाकर के भिजवाया है। डांगाहेड़ी से रैबारपुरा जो हमारा गांव है, वहां पर भी पुलिया हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अलावा कुछ भी नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसकी भी अगर घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का फायदा होगा। स्टेट हाईवे 70 पर इंद्रगढ़-चांनदा-डीपरी-राजोपा सड़क पर भी अगर हम पुलिया निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी जनता को एक बहुत बड़ा बेनेफिट उससे होने वाला है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): कोटा और बूंदी जिले को वह पुलियाएं जोड़ती हैं। लास्ट में एक बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी।

मैं मान सकती हूं कि राजस्थान को निश्चित रूप से आपने विकास

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

की श्रेणी में आगे बढ़ाया है। अपराध को रोकने का प्रयास किया होगा, लेकिन अपराध के क्या आंकड़े हैं? यह हम सभी ने देखे हैं। साढ़े 8 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना और साथ ही साथ 27 हजार बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले जो आये हैं, निश्चित तौर पर इस राजस्थान के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है।

सभापति महोदय, एक ही बात को कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। राजस्थान प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में जो हार्डकोर अपराधियों के द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे कि परेशान होकर आये दिन जेल में बंद अपराधियों द्वारा भूख हड़ताल पर बैठना, यह हम सबके सामने है। कहीं न कहीं हम इसको रोकने का प्रयास करें।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साथ ही जो उदयपुर कांड में अपराधी थे, जो वहां पर बैठे हुए हैं, वहां लगातार मोबाइलों के माध्यम से पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉलिंग करना, इसकी जांच करवायी जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): इसकी छापेमारी होगी तो निश्चित तौर पर हम लोगों के सामने यह सारे आंकड़े आयेंगे।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद, जोहार।

आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पक्ष-विपक्ष दोनों के द्वारा चर्चा की जा रही है। पिछले 4 अभिभाषणों को हमने देखा। पक्ष और विपक्ष में एक तरफ तारीफों के पुल बांधना ही कर्म और धर्म है और दूसरी तरफ बुराई करना ही कर्म है और यही धर्म है, यह मुझे चारों और इस पांचवें अभिभाषण में देखने को मिला है।

सभापति महोदय, मैं बता दूं कि हमारी पार्टी को 10 मिनट मिले हैं, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति: आपकी पार्टी के बाकी सदस्य कल बोलेंगे न। आपको 7 मिनट मिली है, आप बोलिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, हमें इस चेयर से ही, अध्यक्ष महोदय द्वारा 10 मिनट दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि आपका संरक्षण मिले, मुझे 10 मिनट बोलने का अवसर मिले।

श्री सभापति: बोलिए, आप बोलिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, पिछले 4 सालों में हमारी राजस्थान सरकार ने हमारे विधायक कोटे की जो राशि थी, उसको बढ़ाया। मिसिंग लिंक्स सड़क दीं। हमारी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के लिए कडाणा प्रोजेक्ट जो स्वीकृत किया, इन सभी कार्यों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण में 15 नंबर पर लिखा गया है कि राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी में आगे बढ़ते हैं तो चिरंजीवी योजना का काफी बखान हुआ। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना एक शानदार योजना है, लेकिन धरातल पर जा पा रही है कि नहीं जा पा रही है? क्या यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो रही है?

आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए मैंने पिछली बार क्वेश्चन लगाकर के आंकड़ा निकलवाया कि आदिवासी क्षेत्र में जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया का क्या आंकड़ा है? उसमें 70 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं। एक जो आंकड़ा आया, उसमें 2 लाख 15 हजार 712 महिलाओं का टेस्ट हुआ और उसमें से 1 लाख 39 हजार महिलाएं एनीमिक पायी गयीं। इसमें से 11 हजार जो महिलाएं हैं, वह भयंकर एनीमिक पायी गयीं। इससे यह साबित होता है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो योजनाएं हैं वह कहीं न कहीं कागजों में ही सिमटती जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क जांच की बात होती है। नि:शुल्क जांच अच्छी बात है, हो भी रही है। जो सरकारी हास्पिटल्स हैं, हमारे पीएचसी, सीएचसी हैं, उनमें मशीनें खराब होने की वजह से जांच नहीं हो पाती हैं। वह लोग प्राइवेट जगहों पर जाते हैं और वहां उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। राज्य सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो प्राइवेट क्लिनिक हैं,

(श्री राजकुमार रोत)

जो मरीज आ रहा है उससे कितनी-कितनी राशि ली जाये। अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बहुल क्षेत्र में सिकल सेल नाम की एक भयंकर बीमारी होती है। उस बीमारी के बारे में अभी तक राज्य सरकार चिंतित नहीं है। कई डाक्टरों को भी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन यह अनुवांशिक बीमारी है। उस बीमारी को लेकर गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, केरल की सरकार काफी चिंतित है। सिकल सेल बीमारी है, सिकल सेल एक अनुवांशिक बीमारी है और अधिकतर यह ट्राइबल इलाकों में पाई जाती है। गुजरात में जो ट्राइबल इलाका है उसमें 14 परसेंट यह सिकल सेल बीमारी अब तक पाई गई है लेकिन राजस्थान के अंदर हम इसकी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि इसकी स्क्रीनिंग की जाए और इन लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में हमारे आदिवासी विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बजट का अब तक कहां-कहां उपयोग किया गया है, वास्तविक रूप से यह बजट धरातल पर नहीं उतारा गया।

अभी इस अभिभाषण में 93 नम्बर बिन्दु पर लिखा हुआ है कि आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, इनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस संस्कृति के आधार पर हमारे लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग चुनाव जीतकर यहां पर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज मैं विधायक बना हूं तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे मत दिया और जब मैंने आवेदन किया तो सर्टिफिकेट लगाया आदिवासी होने का, उस क्षेत्र का नागरिक होने का सर्टिफिकेट लगाया तो वहां पर मेरा नामांकन पास हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई पार्टियों में रहने वाले लोग जो सर्टिफिकेट को कम महत्व देकर पार्टियों की टिकट को महत्व देते हैं और उसी आधार पर इसी कारण से इस क्षेत्र की बात होती है, आदिवासी समाज की बात होती है, हक और अधिकार की बात होती है तो वो यहां पर आकर नहीं बोल पाते हैं लेकिन जनता समझ चुकी है, आने

(श्री राजकुमार रोत)

वाले समय में अहसास कराएगी कि टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी का सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई। कहने को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हमने स्कूलें खोल दीं, सब कुछ किया, हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पता नहीं ऊपर के जो आईएएस लोग हैं, किस तरह के लोग बैठते हैं, सुबह 11 बजे से सूचना मंगवाते हैं, जो टीचर लगे हुए हैं, एक टीचर पोषाहार पर लगा रहेगा, एक टीचर शाला दर्पण पर लगा रहेगा, एक-दो प्रशिक्षण में जाएंगे तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? हम ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी सूचना मंगवाएं तो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नहीं मंगवाएं, शाम के एक घंटा जो समय रहता है 3 से 4 बजे उस दौरान ही किसी भी प्रकार की सूचना चाहे उस सूचना को मंगवाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। कई बार दु:ख होता है, कांग्रेस में एससी, एसटी सेफ महसूस करते हैं, ऐसा लगता है।

श्री सभापति: अपना वक्तव्य कंक्लूड कर लीजिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय अभी छह मिनट ही हुआ है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, हमारा जो समय है उस समय में हमें बोलने दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, उधर से बात हो रही थी, कन्हैया कुमार पर बात करके उन्होंने गुजरात में बहुत वोट ले लिए लेकिन राजस्थान के अंदर एससी, एसटी पर जो मामले हो रहे हैं, एससी, एसटी को लेकर जो इन्द्र कुमार मेघवाल पानी पीने गया उस पर अत्याचार हुआ, उसको मार डाला। कार्तिक भील को सिरोही में मार डाला। इस पर न तो विपक्ष बोल रहा है और न पक्ष बोल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि इस सरकार में भी अगर एससी, एसटी सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय में एससी, एसटी के लोग कहीं न कहीं नया रास्ता देखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक को लेकर काफी चर्चा चली। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने प्रावधान किया था कि निशुल्क

(श्री राजकुमार रोत)

बस की व्यवस्था की जाएगी लेकिन हर बार जो हमारे डूंगरपुर के लोग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ की तरफ एग्जाम देने जाते हैं लेकिन रिटर्न जाने के लिए उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पोषाहार को लेकर काफी चर्चा हुई। आईसीडीएस विभाग के द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कुपोषित, अति कुपोषित को पोषित करने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम पोषाहार उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन कहीं-कहीं वह पोषाहार पशु आहार बनता जा रहा है। यह वास्तविकता है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज विभाग की बात करूंगा। हमारे डूंगरपुर जिले में मनरेगा की योजना ठप पड़ी हुई है। उसका मूल कारण यह है कि दो पार्टियों के द्वारा मिला हुआ जिला प्रमुख बैठाया हुआ है इसलिए राज्य सरकार के मंत्रीजी डूंगरपुर जिले में पंचायती राज की योजनाओं पर ध्यान दें।

श्री सभापति: थैंक यू। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, बजरी को लेकर सदन काफी चिंतित है। हमारे यहां गुजरात से बजरी लाते हैं और वो बजरी 700 रुपये टन पड़ती है तो बजरी की व्यवस्था की जाए। वैसे तस्करी हो रही है, जैसे गुजरात में ब्लैक मनी तैयार करने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन आज भी शराब दबाकर चल रही है, वह ब्लैक मनी वहां तैयार हो रही है। राजस्थान के अंदर भी बजरी पर प्रतिबंध लगा रखा है और दूसरी तरफ एक ब्लैक मनी तैयार हो रही है, तो हम चाहेंगे जो वास्तविक जरूरतमंद हैं उनके लिए बजरी की व्यवस्था करायी जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक मिनट मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की डिमांड हैं वो रखना चाहता हूं।

सीएचसी सीमलवाड़ा को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए। वहां कन्या महाविद्यालय भी खोला जाए। चिखली में हमारे मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाए। ए ईएन आफिस, धम्बोला को एक्स

(श्री राजकुमार रोत)

ईएन आफिस में क्रमोन्नत किया जाए। झोलरी और चिखली को ए ईएन आफिस में क्रमोन्नत किया जाए। मेरा क्षेत्र आदिवासी बहुल होने के कारण आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाए। कडाणा सिंचाई परियोजना के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया जाए। हमारे क्षेत्र में संत सूरमाव महाराज के अनुयायी ज्यादा हैं तो हम चाहेंगे कि संत सूरमाव महाराज की भक्ति के लिए संरक्षण केन्द्र बने और साथ ही उनका पैनोरमा विकसित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: आपने अपनी पार्टी के पूरे दस मिनट ले लिए हैं।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका आभार।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से मालूम पड़ता है कि सरकार चार वर्षों में सिर्फ कागजों में सिमटी रही है, धरातल पर कोई आधारभूत काम सरकार नहीं कर पाई है। राजस्थान सरकार को सिर्फ असत्य प्रशंसा पसंद है। मेरे क्षेत्र में गत चार वर्षों से हालात खराब हैं। कानून-व्यवस्था फेल है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार, अवैध खनन तेजी से बढ़ा है और सट्टे का कारोबार फल-फूल रहा है, खुले में सट्टा लगा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सरकारी अधिकारी आंख बंद करके अपनी सरपरस्ती में रेत और पत्थर का अवैध खनन करवा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बजट घोषणाओं का दस प्रतिशत भी काम सरकार नहीं करवा पाई है। मुख्य मंत्रीजी सिर्फ असत्य बोलकर मेजें थपथपवाने का काम करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजट घोषणा का एक भी काम नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र की सबसे जरूरी आवश्यकता थी, भीलवाड़ा से सौ किलोमीटर दूर मेरा बिजौलिया कस्बा है, वहां पर बड़ी मुश्किल से ट्रोमा सेंटर की घोषणा हुई परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे बीगोद में मॉडल सीएचसी की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बजट घोषणा में की, परंतु अब तक वहां पर कुछ नहीं हुआ है। नंदी शाला खोलने की घोषणा की गई परंतु मेरे क्षेत्र में एक भी घोषणा पर काम अब तक चालू नहीं हुआ है, यह बहुत ही चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, जो वादाखिलाफी के खिलाफ थे, उन्होंने जनता से वादा किया और फिर खुद वादाखिलाफ हो गए, यह राजस्थान की

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

सरकार ऐसी सरकार है जो जनता की मनोभावनाओं को देखती ही नहीं है। जन घोषणा पत्र में लुभावने वादे कर बनी सरकार को जनता देख रही है, अपने अंतर्विरोधों में उलझी सरकार, जन विरोधी सरकार, जनहित पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकती है, यह बात अब प्रदेश की जनता को समझ में आ रही है। सम्पूर्ण कर्ज माफी मात्र चुनावी जुमला बनकर रह गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना मानो इस प्रदेश की पहचान बन गई है।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। मैं विचार कर रहा हूं कि इस सरकार को धन्यवाद किस बात का दूं? प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, इसका धन्यवाद दूं? बेरोजगारों की आशाओं पर कुठाराघात हुआ, इसका धन्यवाद दूं? महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, इसका धन्यवाद दूं? संविदाकर्मियों से की गई वादाखिलाफी का धन्यवाद दूं? प्रदेश के युवाओं में आत्महत्या व नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति पर धन्यवाद दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि धन्यवाद किस बात का दूं?

माननीय सभापति महोदय, ये महंगाई की बात करते हैं, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है। पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में है। किसानों की सरकार कहलाने वाली सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अभी 28 और 29 जनवरी को ओलावृष्टि, बारिश और पाळे से मेरे क्षेत्र की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसमें सरसों, चना, गेहूं, जौ, फलदार पौधे, सब्जियां, सब बर्बाद हो गई हैं। किसान राहत के लिए सरकार की ओर देख रहा है। जब प्रदेश की आम जनता, महिला वर्ग, युवा, बेरोजगार, किसान और कर्मचारी, सभी उपेक्षित हो रहे हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव किस बात का? इन पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि राज्य की प्रशंसा का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। जो सरकार अपनी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं कर सके और नई घोषणाएं नित्य करती जाए उस सरकार द्वारा पारित अभिभाषण पर धन्यवाद कैसे दिया जाए? यह विचारणीय बिन्दु है।

माननीय सभापति महोदय, अब सरकार की घोषणाओं को देखकर और पढ़कर मन में शायर की पंक्तियां याद आती हैं,

"नाराज नहीं हूं तेरे फरेब से,
गम यह है कि तेरा यकीन कैसे करूं।"

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

जनता इस वादाखिलाफी को समझ चुकी है, जनता समय आने पर जवाब जरूर देगी। प्रदेश में पैराटीचर्स, संविदाकर्मी, आयुष के कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी, बजट से आस कर रहे हैं।

अभी जो प्राकृतिक आपदा मेरे क्षेत्र में आयी है, उसमें आम गरीब किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 व 30 जनवरी को ओलावृष्टि व बारिश से थुडतापेलोस में 40 भेड़ों की मृत्यु हो चुकी है व 61 भेड़ें घायल हो गयी हैं। ग्राम पंचायत मोहनपुरा के दोरेला के राइका समाज, रेबारी समाज के भेड़ पालकों की बरसात में ओलावृष्टि से सौ से डेढ़ सौ भेड़ें रावतभाटा में मर गयी हैं और बहुतसी घायल हैं। ओलावृष्टि, पाले व बरसात से गेहूं, जौ, सरसों, चना, सन्तरे की फसल व सब्जियों की खेती बिलकुल नष्ट हो चुकी है। अत: किसानों को तुरन्त मुआवजा राशि प्रदान करें।

मेरे क्षेत्र बिजौलिया में इस बारिश से, ओलावृष्टि से लाइट-पानी सभी बन्द हो चुका है। अब तक के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजौलिया व दो बड़े कस्बे हैं, दोनों में ट्रोमा सेंटर और हास्पिटल की घोषणा कर रखी है, पर हुआ कुछ नहीं। मैं इन बड़े कस्बों में नगरपालिका की घोषणा के लिए निवेदन करता हूं। मेरे माण्डलगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की घोषणा करें। माण्डलगढ़ में परिवहन कार्यालय भी नहीं है, खोलने की मांग करता हूं।

माण्डलगढ़ में जो भी काम का राज्य सरकार वादा करती है, उसे पूरा नहीं करती है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि अभी मेरे सामने बैठे हुए पक्ष के साथी सरकार की बड़ाई कर रहे थे, मैं भी विधायक हूं, परन्तु एक भी काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं किया गया। मेरे यहां केवल भ्रष्टाचार, रेप और लूट मची हुई है। कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती सफिया जुबेर। श्री लाखन सिंह। श्री बलवीर सिंह जी लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के मुखारविन्द से अपने चार सालों के काम-काज के

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

गुणगान करवाये, पर हकीकत कुछ और ही है। चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बार भी रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई घोषणा नहीं की।

वर्ष 2019-20 के बजट सत्र में वहां के शहीद भगत सिंह कालेज, जो कि एक निजी संस्था है, उसका सरकारीकरण करने की घोषणा की थी। आज तक उसका सरकारीकरण नहीं किया गया है। सत्तापक्ष के विधायक बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कालेज नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, उनमें प्राय: सभी विद्यालयों में कक्षा कक्ष नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है, आम सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र का यह हाल है मेरे विधान सभा क्षेत्र में।

आप देख रहे हैं, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में सोलह बार पेपर लीक हुए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ने की बजाय बड़े-बड़े मगरमच्छ पकड़ें। चोर को पकड़ें, चोर की मां को भी मारें, ताकि इस बुराई को जड़ से खतम किया जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य अन्धकारमय हो चुका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में पांच लाख वेकेंसीज एकमुश्त निकाली जाएं, ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बहुत गम्भीर बीमारियों को नहीं जोड़ा गया है। राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अधिकांशत: इंजेक्शन एवं दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर से लेने की सलाह दी जाती है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह योजना गरीब एवं असहाय लोगों के लिए कारगर साबित नहीं हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मेरे द्वारा पिछले चार वर्षों से हर विधान सभा सत्र में मेरे रायसिंहनगर सीएचसी में ट्रोमा सेंटर खोलने की मांग की जा रही है, पर आज तक ट्रोमा सेंटर नहीं खोला गया है।

सीएचसीज में, सब-सेंटर्स में, पीएचसीज में डाक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, जांच मशीनें नहीं हैं। जो जांच मशीनें हैं, वे प्राय: खराब पड़ी हैं। अधिकतर

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

नाकारा हो चुकी हैं। मेरे द्वारा विधायक कोटे से सीएचसी विजयनगर में एक करोड़ रुपये और सीएचसी रायसिंहनगर में पचास लाख रुपये दिये गये, पर अभी तक दोनों सीएचसीज में इसके लिए काम शुरू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का इलाज समय पर नहीं होता। छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज हेतु उन्हें अन्यत्र जिला मुख्यालय या बीकानेर रैफर कर दिया जाता है। यह उन परिवारों के लिए अत्यन्त दु:खदायी है।

प्रदेश में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाजायज तरीके से वीसीआर भरी जा रही है। वीसीआर भरे जाने की धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों के कृषि कनेक्शंस अभी भी बड़ी संख्या में लम्बित हैं। किसानों को समय पर सामान उपलब्ध नहीं होता। किस्तों में सामान लिया जाता है। कभी खम्भे उपलब्ध करवा दिये जाते हैं, कभी तारें उपलब्ध करवा दी जाती हैं। बहुत लम्बे समय तक ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध नहीं करवाये जाते। समय पर किसानों को कृषि कनेक्शंस उपलब्ध नहीं होते।

वर्तमान में हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में अत्यधिक पाला, कोहरा पड़ने की वजह से सरसों की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सभी किसानों के नुकसान का व्यक्तिगत सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए।

पेयजल के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा, केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन को धरातल पर मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 156 योजनाएं जल जीवन मिशन में स्वीकृत हैं। उनमें से ज्यादातर लम्बित हैं, अधूरी पड़ी हैं। आज भी सर्दी के मौसम में लोग टैंकरों से पानी भरवाने हेतु मजबूर हो रहे हैं। लगभग हर वाटरवर्क्स की आस-पास में बड़ी संख्या में पाइपें पड़ी हैं, मगर उन्हें बिछाने का काम नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी वाटरवर्क्स में पानी की सप्लाई बन्द पड़ी है।

156 योजनाओं में से मात्र 15 योजनाएं कम्प्लीट की गयी हैं। 139 योजनाओं में कुछ में तो काम शुरू ही नहीं हुआ और कुछ योजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं। मेरे रायसिंहनगर में रायसिंहनगर ब्लाक पीएचईडी के जल जीवन मिशन में एक प्रभावशाली कम्पनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैसर्स जीए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, उन्हें करोड़ों रुपये का कार्य दिया गया है, परन्तु इस कम्पनी ने मात्र 13 स्कीम्स पर काम चालू किया।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

इनमें भी मात्र पाइप डालने का काम शुरू किया। गांवों में खाई खोद रखी है, जनता बेहाल है। कहीं भी कनेक्शंस शुरू नहीं किये गये हैं। इस कम्पनी द्वारा ख्यालीवाला 5 एफडी, 25 एफएफ, 9 एमके, 32 बीएसबी, 24 आरबी, 17 आरबी, 4 एसएडी, 42 एनपी, 79 आरबी, 28 एनपी, 62 आरबी, 2 एनपी, 1 एनपीएम, 74 आरबी, गंगूवाला, ऐसी 17 स्कीम्स में अभी काम शुरू नहीं किया गया है।

यह कम्पनी फर्जी बिल आदि का दबाव अधिकारियों पर बनाती है। भुगतान नहीं करने पर उनका ट्रांसफर करवा देती है। उसका जीवित उदाहरण हाल ही में रायसिंहनगर में जे ईएन प्रवीण जाखड़ का है, जिसका ट्रांसफर 14.01.2023 को घड़साणा व 15.01.2023 को बाड़मेर किया गया। मेरे यहां न तो जे ईएन है, न ही ए ईएन है। इस कम्पनी की कार्यावधि भी पूरी हो चुकी है। 31 मार्च से 31 जनवरी तक कार्य पूर्ण करवाया जाना था। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस कम्पनी के कार्यों की जांच करवाकर इसे ब्लैक लिस्ट किया जाए।

श्री सभापति: Thank you.

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर, अभी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ है। दो मिनट का समय और दें। सिंचाई की इतनी समस्या है कि टेलों के किसानों को पूरा पानी नहीं पहुंचता। सिंचाई हेतु बने खाळे भी बड़ी संख्या में कच्चे हैं। ज्यादातर खाळे क्षतिग्रस्त, नाकारा हो चुके हैं। जो नहरें पक्की की जा रही हैं, उनमें पुल भी नहीं बनाये जा रहे। यदि पशु या जानवर गिर जाएं तो उन्हें निकालने हेतु प्लेटफार्म, सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाया गया है। नहरें संकीर्ण बनायी जा रही हैं। किसानों को उनके हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को लम्बे समय तक डीएपी, यूरिया उपलब्ध नहीं होता। उन्हें लम्बी-लम्बी कतारें लगाकर खाद लेनी पड़ती है। कई बार पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती हैं।

श्री सभापति: Thank you.

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): कृषि डिग्गियों की स्वीकृति लाटरी के जरिये की जाती है, जिससे ज्यादातर किसान इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर डिग्गियों का निर्माण तो करवा लिया, मगर उन्हें अनुदान नहीं मिला, वे इस लाभ से वंचित हो गये। लाटरी व्यवस्था बन्द करके सभी पात्र किसानों को वरीयतानुसार...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। हो गया आपका। श्री मनोज कुमार।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार अभिभाषण पर बोलने देने के लिए। आज बड़े फख्र की बात है कि चार साल के एक ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद में हमें बोलने का मौका मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): चार साल में ऐतिहासक काम माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार ने किये हैं और मैं इस कार्यकाल को एक स्वर्णिम कार्यकाल कहूंगा। वह इसलिए कि एक तरह हम आजादी का 75वां साल मनाने जा रहे हैं। जहां 71 सालों के बाद इन चार सालों की तुलना करें तो शायद बहुत कुछ देखने और सुनने को आपको मिलेगा। एक तरफ जहां 71 साल में पूरे राजस्थान में 200 कालेज हुआ करते थे वहां आज इन चार सालों में 240 से ज्यादा नये कालेज खोल दिये गये, तो जब आप तुलना करते हैं तो समझ में आता है कि क्यों मैं इसको ऐतिहासिक कार्यकाल कहने जा रहा हूं।

आज इन चार सालों में चिरंजीवी योजना लागू की है। जहां 70 सालों में हमने परिवारों को इलाज के लिए तड़पते हुए, मोहताज हुए देखा है पर जब से चिरंजीवी योजना आई है और हास्पिटल के नाम से जिनकी हालत खराब हो जाती थी कि कैसे हास्पिटल जाएंगे, हमारी जेब खाली है, पर आज उनको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। जब अस्पताल जाते हैं तो वहां चिरंजीवी योजना के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है।

आज अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि कोरोना जो हुआ उसका टीका मोदी जी लेकर आये जिसकी वजह से वह खतम हुआ। आज तक यही सुना, देखा है कि जब भी कोई महामारी आयी है तो हमेशा केन्द्र की सरकार टीका लेकर आयी है और वह फ्री लेकर आयी पर पहली बार इस महामारी में देखने को मिला कि जो टीका आया उसको युवाओं के लिए पैसे देकर खरीदने को मोहताज किया गया। राजस्थान सरकार आगे आयी और उन्होंने पहल की, एमएलए लैड का पैसा कोरोना के टीके के लिए सरकार को जमा कराना पड़ा। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज सुनिये। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं, वे बता देंगे कि 100 करोड़ रुपये जब जमा कराये थे तब केन्द्र की सरकार ने टीका दिया। जब लोगों का विरोध हुआ तब केन्द्र सरकार बैकफुट पर आयी और उसके बाद में उसको फ्री किया गया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज सुनिये। बैठिये, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): बिलकुल दो महीने बाद में केन्द्र की सरकार बैकफुट पर आयी थी और उसके बाद में उन्होंने निर्णय कर उस टीके को फ्री किया था। उससे पहले चिकित्सा विभाग ने 100 करोड़ रुपये जमा कराये थे तब राजस्थान को टीका मिला था। बिलकुल, आप देख लें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें। आप चालू रखिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): आज अभी पूर्व में वक्ता कह रहे थे कि कश्मीर में राहुल जी झंडा फहरा रहे हैं तो मोदी जी के कारण फहरा रहे हैं। (व्यवधान) हां, बात सही है। 1971 में जब इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं तब पाकिस्तान को घुटनों के बल टेका था, 95 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बन्दी बना लिया गया था। उसके बाद उनको खदेड़ दिया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: जब आप बोल रहे थे तो ये सुन रहे थे, अब ये बोल रहे हैं तो आप भी सुनिये प्लीज। बोलिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): उस पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये तब आज झंडा फहराया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, ये बीच में बोल रहे हैं। हमारे नये एमएलए हैं, आप शान्त रहें नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो हम भी टोकेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना कंटीन्यू करिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): इस चार साल के कार्यकाल में पहली बार गायों की गौशालाओं के लिए जो 6 महीनों का अनुदान था वह 9 महीनों के लिए किया गया है। आप हिन्दुस्तान में कहीं भी चले जाइये, 9 महीने का अनुदान आपको कहीं नहीं मिलेगा और वह माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है। दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान दो रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है जो देखने को मिला है।

श्री सभापति: Please don't disturb him. उनको बोलने में दिक्कत आती है। प्लीज, सुनिये माननीय सदस्य को। (व्यवधान) नहीं-नहीं, इस तरह नहीं। It can not be allowed. This is bad. उनको बोलने का अधिकार है, अपने टर्न पर बोल रहे हैं। आप बीच में मत बोलिये। (व्यवधान) बोलिये आप। आप चुप क्यों हो जाते हैं, बोलिये न, अपना कंटीन्यू करिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): पहली बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक साथ 52 स्कूलें सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत हुईं। आजादी के 71 साल और ये 4 साल जिनमें पहली बार 52 स्कूल क्रमोन्नत हुए। क्या यह राजस्थान के इतिहास का स्वर्णिम काल नहीं है? आज राजस्थान में पिछले चार सालों की बात करें तो एक हजार से ज्यादा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं और अंग्रेजी माध्यम की 1700 से ज्यादा स्कूलें खोली गई हैं। 71 साल में एक भी स्कूल कहीं अंग्रेजी माध्यम की देखी है? पहली बार राजस्थान में हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खुल रही हैं और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइन लगाकर एडमिशन हो रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में अपना समाप्त करें। समय निर्धारित है।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट का कह रहे हैं तो दो मिनट में मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा।

बहुत कुछ मुख्य मंत्री जी ने दिया है पर इस बजट में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग मेरे क्षेत्र के लिए कह रहा हूं और इस बजट से लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि सुजानगढ़ को वह पुराना गौरवशाली इतिहास वापस लौटा दें। पुराना जो उसका जिले का वैभव था उस सुजानगढ़ को पुन: जिला बनाकर उसका जो पुराना इतिहास है वह लौटा दें क्योंकि सुजानगढ़ आजादी से पहले रियासतकाल में जिला हुआ करता था पर 1949 के पुनर्गठन के बाद में उसका जिले का अस्तित्व खतम हो गया। आज समय आ गया है, रामलुभाया कमेटी बनायी गयी है, जिसकी रिपोर्ट जब भी सरकार के पास आये तो आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुन सुजानगढ़ को जिला बनाकर वहां के लाखों लोगों की अपेक्षा इस सरकार से है वह पूरी कर दें। सुजानगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान था और स्टेट टाइम में जब जिला हुआ करता था उस समय वहां एस.पी. बैठा करता था, तो आज पुन: जिला बनाकर वहां एस.पी., कलेक्टर बिठा दें। पिछले चार साल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(श्री मनोज कुमार)

कार्यालय, डीटीओ कार्यालय, सब खुल चुके हैं और सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो एस.पी. और कलेक्टर बिठाना है। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है कि सुजानगढ़ का गौरवशाली इतिहास एक बार पुन: लौटाया जाए। आजादी के बाद रियासतकाल का 1949 में पुनर्गठन हुआ उसमें जिले का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो पुन: जिले का अस्तित्व देकर सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। इसी मांग के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। माननीय महामहिम महोदय ने इस सरकार का पांचवां अभिभाषण 23 तारीख को पढ़ा। इस सरकार की बुनियाद ही एक्चुअली असत्य पर आधारित थी क्योंकि इनकी कांग्रेस पार्टी के उस जमाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने किसानों से यह कहा कि यदि आप वोट देंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी तो सरकार बनने के दस दिन के अन्दर-अन्दर किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों ने बहुत उत्साह से वोट दिये और आज दस दिन क्या चार साल हो गये, पूरे राजस्थान में किसी किसान की एक रुपये की भी केसीसी माफ नहीं हुई। अभी जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हाड़ौती में आये तो झालावाड़ से जब वे कोटा आ रहे थे तो रास्ते में कुछ किसानों ने उनसे मिलकर यह बात याद दिलाने की कोशिश की कि आपने कर्जमाफी की बात की थी, तो आपकी सरकार ने उन किसानों को पुलिस से ऐसे डंडे पिटवाये कि कुछ तो घायल होकर हास्पिटल चले गये और कुछ को आपने थाने में बन्द करा दिया तथा मिलने नहीं दिया।

दूसरा, आपने बेरोजगार युवक-युवतियों से यह वादा किया कि हम आपको रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देंगे तब तक आपको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये महीने का देंगे। मेरे घर से तीन मकान छोड़कर ही रोजगार कार्यालय है, मैं उस टाइम देखता था कि रोज हजारों की संख्या में युवक-युवती रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते थे। उनको यह उत्साह था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नौकरी मिलेगी। वे 8-10 महीने तक तो बैंकों के चक्कर काटते रहे, किसी के एक रुपया नहीं डला तो वे भी निराश होकर बैठ गये। उनके रोजगार की जो बात थी तो आज तक 16 पेपर हुए और 16 के 16 ही आपकी सरकार ने लीक करा दिये। आपने छोटी-मोटी गाजर, मूली

(श्री अशोक डोगरा)

को तो पकड़ लिया और बड़े मगरमच्छों को छोड़ रखा है। आपकी पार्टी के ही बड़े नेता और विधायक यह कहते हैं कि, साहब, बड़े नेताओं को तो पकड़ो। राज्य सभा के माननीय सांसद महोदय सात दिन से इस बात को लेकर धरने पर बैठे हैं कि इसकी सीबीआई से जांच करायी जाए, लेकिन जब आपका कोई मंत्री, आपका मुख्य मंत्री, आपकी सरकार इन्वाल्व नहीं है तो आपको किस बात का डर है, आप उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, परन्तु जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है।

लॉ एण्ड आर्डर की बात करें तो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साढ़े आठ लाख मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हत्या के 5 केस और 17 बलात्कार रोज राजस्थान में हो रहे हैं। पिछले सत्र में आपके मंत्री महोदय ने यहां पर हां की थी कि बलात्कार में हम पूरे भारत में नम्बर एक पर हैं। यह भी बताया था कि क्यों हैं? फिर बाद में उन्हें सदन से और जनता से माफी मांगनी पड़ी थी। आज हालत यह है कि आप गैंगवार में यूपी और बिहार से भी आगे निकल गये हैं। चाहे अलवर हो, करौली हो, भरतपुर हो, हिन्दुओं के धार्मिक जुलूसों पर पथराव हुआ और उन अपराधियों को बचाने के लिए आपकी सरकार ने बीजेपी और आरएसएस पर इसका आरोप लगाया।

मेरे खुद के बूंदी जिले के नैनवां में हालत यह है कि एक महिला के पांव काटकर उसके कड़े निकालकर ले गये। आज 10 महीने हो गये हैं। मुलजिम को पकड़ना तो दूर वह आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि यह किसने किया है। मतलब, ऐसी स्थिति हो गई है कि एंटी-करप्शन वाले बड़ी मुश्किल से मुकदमे बनाते हैं। आपकी सरकार 471 केसों में अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा-पूरा प्रयास कर रही है। उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही है?

आप पैरा संख्या 45 और 46 में कह रहे हैं कि हम बिजली में आत्मनिर्भर हैं। हम 23 हजार 479 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आज बिजली तो है नहीं, शहरों में घंटे, दो घंटे की घोषित और दो-चार घंटे की अघोषित कटौती होती है। आप गांवों में तो बिजली देते ही नहीं हैं। किसान, मजूदर शाम को अपने घर आता है, उसको बिजली की जरूरत होती है, उसके खाना खाने का टाइम होता है, उस समय बिजली गायब हो जाती है। आप श्री

(श्री अशोक डोगरा)

फेज बिजली आधी रात में दे रहे हो। आधी रात को इतनी ठण्ड में किसान खड़ा होकर अपनी फसल को पानी पिलायेगा तो मरेगा नहीं तो और क्या होगा? आज हालत यह है कि एक साल से नये कनेक्शन के लिए लोगों ने पैसा उधार लेकर डिमांड राशि जमा करा रखी है, आप उसे कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने स्कूल तो खोल दिये, शिक्षक तो भर्ती किये ही नहीं। आज महात्मा गांधी स्कूल ऐसी जगह पर खोल दी गई हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मुझे बोलते हुए अभी दो मिनट ही हुए हैं। माइनिंग एरिया में भील बस्ती है, वहां मजदूर रहते हैं। वहां बच्चियों का स्कूल था, आपने उसको उसमें कर दिया। वे मुश्किल से हिन्दी मीडियम में पढ़ाते थे। आपने इंग्लिश मीडियम कर दिया। मैं अभी 5-6 दिन पहले मेरे नमाणा कस्बे में गया था, बड़ा कस्बा है, वहां पर जो मैन हायर सैकण्डरी स्कूल थी, उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया। अब वहां बच्चे पढ़ने के लिए या तो पांच किलोमीटर दूर आमली जाएं या सुन्दरपुरा जाएं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहीं एक किलोमीटर पर हरिपुरा है, कम से कम उस स्कूल को अपग्रेड कर दें ताकि बच्चे तो पढ़ सकें।

वसुन्धराजी ने बच्चों के लिए दूध चालू किया था। आपने चार साल पहले दूध को बन्द कर दिया। अभी दिसम्बर में चालू किया है, वह भी सिर्फ हफ़्ते में दो दिन। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे रेगलुर करें।

मैं आपको पिछले बजट की बात बताता हूं। पिछले बजट में 20 करोड़ की एक घोषणा हुई थी। खटकड़ में एनीकट बनाकर चार गांव केसरपुरा, खड़ीबारा, लोयली और बगली लिफ्ट योजना के लिए 20 करोड़ तो आ गये। आपके वहां के लोकल नेताओं के चक्कर में यह जो खटकड़ के लिए बजट घोषणा थी, यह एनीकट वहां से 15 किलोमीटर दूर ख्यावदा पंचायत में ले जा रहे हैं, जिससे लोगों में भारी रोष है। मेरा निवेदन है कि यह वहीं चालू किया जाए।

एक गरडदा बांध, यह आपकी पिछली सरकार में बना और 15 अगस्त, 2010 को पहली बार पानी भरा, तब टूट गया था। आपकी सरकार ने

(श्री अशोक डोगरा)

कुछ नहीं किया। वसुन्धराजी का राज आया, हम वापस बजट लाये और इसको बना दिया। अब बांध बनकर कम्प्लीट है, भरा हुआ है, नहरों के लिए 60 करोड़ रुपये चाहिये, कई पत्र लिख दिये। 60 करोड़ रुपये में 15 किलोमीटर की मुख्य कैनाल बननी है, बाकी नहरें रिपेयर होनी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 60 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करके 44 गांवों की 9 हजार 161 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने में मदद करे।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मेरे वहां बून्दी, सिलोर, नमाणा, गरडदा की सड़कों की तीन साल से ऐसी बुरी हालत है कि बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। सड़क खराब होने के कारण कोई बस नहीं चलती है। लोगों में भारी आक्रोश है। इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाएं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): वसुन्धराजी के पिछले राज में बरूंधन तिराहे से लक्ष्मीपुरा, डोरा, सूतड़ा, डाबी होते हुए राणा जी के गुढ़ा की एक सड़क..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): उस सड़क को आज तक, उस जमाने की सैंक्शन है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन काम चालू नहीं हुआ है। वहां इतनी बुरी हालत है कि फोर व्हीलर तो क्या टू व्हीलर भी नहीं चलाया जा सकता है। सब जगह खड्ढे ही खड्ढे हैं। पूरा माइनिंग एरिया है, 70-70 टन का लोड लेकर गाड़ियां चलती हैं, रोज पलटी खाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री मदन प्रजापत।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे नगरपालिका क्षेत्र में, यूडीएच मंत्री साहब अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं बैठे थे, वे उस समय आये थे तो जनता से 135 करोड़ का वादा करके गये थे।

श्री सभापति: धन्यवाद, आपका टाइम निर्धारित है।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): दो मिनट में मेरी बात खतम कर रहा हूं। यदि आप कांग्रेस का बोर्ड बनाओगे तो 135 करोड़ की सैंक्शन निकालूंगा। इन्होंने आज तक एक रुपये की एक सैंक्शन नहीं निकाली। मेरा इनसे निवेदन

(श्री अशोक डोगरा)

है कि सैंक्शन निकालें। बून्दी नगरपालिका में भ्रष्टाचार इतना है कि जहां बिल्डिंग को बीएसआर या बीएसआर से डाउन रेट पर कराती है।

श्री सभापति: थैंक यू। अब अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): 000

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घन्टे बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आधे घन्टे बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घन्टे बढ़ाया गया।

श्री मदन प्रजापत।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो दिन से पक्ष-विपक्ष की ओर से सभी ने भावना प्रकट की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन चार सालों में जानदार, शानदार और जनकल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में दी हैं। पूरे देश में मॉडल स्टेट की तरह राजस्थान एक नम्बर पर है। तमाम योजनाओं में लोग कितनी तारीफ करें, वह कम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह साबित कर दिया कि सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म है। सामने से आवाज आ रही थी कि किस बात का धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं, धन्यवाद देने के लिए हम काफी संख्या में हैं, खूब हैं, लेकिन विरोध भी होता है। सामने से एक आवाज और आती है, बुलवाया गया, अभिभाषण पढ़वाया गया, तो क्या आपके समय में कोई नया कानून था? या महामहिम राज्यपालजी कैसे बोलते थे, कैसे पढ़ते थे, मैंने तो अन्तर नहीं देखा। आपका धर्म है। ऐसा लगता है इन चार सालों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, ये बौखला गये हैं और उप चुनाव की हार झेल नहीं पा रहे हैं। जो 2023 का सपना देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको विरोध की प्रैक्टिस भी है, विपक्ष में आपका पुराना अनुभव रहा है तो भगवान करे उसी जगह पर, ये सपने छोड़ें।

(श्री मदन प्रजापत)

बाकी कई बातें आईं, टीके के सम्बन्ध में बात आई। भगवान करे देश में बीमारी नहीं आये। जब-जब भी बीमारी आई है तो जिसकी भी सरकार रही हो, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इलाज के लिए टीके की व्यवस्था की है। यह कोई नई बात थोड़े ही है या कोई घर से थोड़े ही दिया है। जो काम यहां होता है, केन्द्र सरकार ने किया है, नहीं होता है तो वह हमने किया है और नहीं आया तो नहीं किया। यह बात बार-बार जैसे कोई अहसान कर दिया है। ये टीका पहली बार नहीं लगा है, कई बीमारियां आई हैं, कइयों की व्यवस्था सरकारों ने की हैं।

बार-बार एक बात कह रहे थे मोदीजी की ताकत देखी, लाल चौक, ऐसा लगता है श्रीनगर और लाल चौक 2014 के बाद ही बना है। पहले भी आडवाणीजी ने, जवाहर लाल नेहरू जी ने कई झण्डे फहराये हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है लेकिन इतना हव्वा खड़ा कर देते हैं। जैसे कश्मीर अब ही बना है।

रही बात वादों की तो मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। 2022 तो चला गया, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गयी, क्या दो करोड़ नौकरियां युवाओं को दी गईं? हम बार-बार कह रहे हैं, हम सबने कह दिया कि सहकारी समितियों का 15-16 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया है। केन्द्र सरकार के अधीन सेन्ट्रल बैंक हैं। यदि आप किसान हितैषी हैं तो अपन सब मिलकर मोदीजी के पास चलें कि आप किसानों की मदद करें। वह बात तो नहीं की, लेकिन 10 दिन तो 15 हजार करोड़ किया है। आपने भी जाते-जाते सड़कों के एडवांस टेंडर निकाले, दो साल तक हमने पैसे दिये और आप कह रहे हो 2 हजार करोड़ का आपके समय में कर्जा माफ हुआ। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने 15-16 हजार करोड़ के किये हैं। क्या आपने आपके समय में व्यवस्था अलग से की थी? इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कम से कम पूरे हिन्दुस्तान में तारीफ हो रही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है। हमने वह समय भी देखा, बेटे की बीमारी के लिए बाप को खेत बेचने को मजबूर होना पड़ता था, मकान बेचने की मजबूरी थी और आज जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है और भगवान न करे किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख रुपये की गारंटी दी है। यह कोई मामूली बात है, कागजों में है? भगवान को साक्षी मानकर आप थोड़ा तो मान लो और रहम करो और मंथन करो। मैं शर्म की बात नहीं कहता हूं, लेकिन वे समझते हैं कि इतनी शानदार योजनाओं की भी आप बुराई कर रहे हैं। क्या प्रेक्टिकल आपने उस व्यवस्था का लाभ नहीं लिया है?

(श्री मदन प्रजापत)

(समय: 19.00 बजे)

चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे मान-सम्मान के साथ में इन्दिरा रसोई भरपेट भोजन, इन योजनाओं की जितनी तारीफ करें वह कम है। चूंकि समय कम है, चाहे शहरी रोजगार गारंटी हो, ...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दो मिनट ही हुए हैं, माननीय सभापति महोदय।

तो इसलिये तमाम योजनाएं चाहे पालनहार हो, उनकी मैं तारीफ करता हूं। समय कम है इसलिये मैं सीधी मेरी मांग करता हूं कि बालोतरा जिला क्यों जरूरी है। दूरी के लिहाज से राजस्थान में दो सौ किलोमीटर, सौ किलोमीटर बालोतरा है और धार्मिक महत्व से देखें तो विश्वविख्यात नाकोड़ा जैन तीर्थ, राठौड़ों की कुल देवी नागाणा धाम, चाहे परम धाम आसोतरा हो, चाहे रानी भटियाणी हो, चाहे खेड़ हो, चाहे जेतेश्वर धाम हो, चाहे लूमनाथ जी का धूणा हो, चाहे भीमगौड़ा हो, चाहे आशापुरा माता का मन्दिर हो, चाहे हृदयेश्वर हो, इसलिये बालोतरा जिला जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, राव मल्लीनाथ जी की धरती इसलिये बालोतरा जिला जरूरी है। वीर दुर्गादास जी की धरती इसलिये बालोतरा जिला जरूरी है। राव कल्ला, राव वीर नारायण परमार इसलिये बालोतरा जिला जरूरी है। कई ऐतिहासिक महत्व है। सेठ गुलाबचंद सालेचा जिन्होंने खुद के पैसे से रेल लाइन बनवाई, उनकी भावना थी कि जिला बने। हमारे पूर्व विधायक मदन कौर जी की भावना थी। स्वर्गीय चम्पालाल बाठिया जी की भावना थी कि बालोतरा जिला बने। सबकी भावना है और आज मुझे खुशी है कि जिले के हम सातों विधायक हैं सबकी एक ही राय है बालोतरा जिला बने। ऐसी सर्वसम्मति चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हो ही नहीं सकती और धार्मिक लिहाज से हो चाहे विश्व की हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो, उनकी मॉनिटरिंग के लिए बालोतरा जिला जरूरी है और यह हिम्मत अगर कोई कर सकता है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बजट में राजस्थान में यह सौगात होगी और अगर कोई क्रान्तिकारी फैसला ले सकता है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ले सकते हैं। इसलिये बालोतरा जिला जरूरी है।

धार्मिक लिहाज से हो चाहे बालोतरा का सूरत और अहमदाबाद की तर्ज पर कपड़ा उद्योग हो और उसको आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो

(श्री मदन प्रजापत)

पावरलूम और सौर ऊर्जा में राहत दें अस्सी परसेंट की बाध्यता के अलावा फुल सौर ऊर्जा का पावर उद्योग के लिए दिया जाये तो पावरलूम में राजस्थान आत्मनिर्भर बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय और लूंगा। बिठूजा में आरओ प्लान्ट की स्थापना के लिए बजट दिया जाये ताकि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। युवाओं के खेलों के लिए पचपदरा, जसौल, कल्याणपुर, मड़ली, कनाणा में स्टेडियम के लिए बजट दें। बालोतरा के गन्दा नाला फ्लड चैनल का विकास कर चौपाटी का निर्माण करवाया जाये, उसके लिए बजट दें।

बालोतरा में विद्युत स्टोर नहीं है। सौ किलोमीटर जोधपुर और वापस बाड़मेर जाकर माल ट्रांसफार्मर वगैरह आते हैं इसलिये विद्युत स्टोर की स्थापना की जाये। कल्याणपुर में पानी और बिजली का ए ईएन आफिस खोला जाये और बालोतरा में तीन सौ किलोमीटर नहर से पानी आता है, स्थानीय स्रोत नहीं है और तीन सौ किलोमीटर में बार-बार नहर लीकेज होती है। मेरा तो आरोप है कि यह कोई षड्यंत्र है। जान-बूझकर हर तीसरे दिन लाइन फोड़ी जा रही है, इसलिये बालोतरा में 15 दिनों का स्टोरेज बनाया जाता है...

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): तो बालोतरा, जसौल और पचपदरा को लाभ मिल सकता है। पचपदरा को बाबूंडी से सीधी लाइन से जोड़ा जाये। बाबा साहब टाउन हाल के रिपेयरिंग के लिए एकमात्र डाक्टर भीमराव अम्बेडकर टाउन हाल जो तीस साल पुराना है और जर्जर हालात में है, तो बालोतरा में बाबा साहब टाउन हाल के लिए बजट दिया जाये और झेरला में बड़ा गार्डन हो, चाहे बस स्टैंड के पास हो। कई और भी है आगे बजट में। और मैं धन्यवाद देता हूं चिकित्सा मंत्री जी का, एक साथ में पहली बार पचास करोड़ रुपये जिला हास्पिटल निर्माण के लिए बजट दिया है। इतना बड़ा बजट, चाहे 225 करोड़ सीवरेज के लिए हो, कई काम हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि बालोतरा राजस्थान में नया जिला बनेगा और यह खुशखबरी आने वाले बजट में होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद आपका। श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर बोलने का आपने समय दिया, इसके लिए

(श्री हरेन्द्र निनामा)

मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अभिभाषण में, पूरा अभिभाषण मैंने पढ़ा, इसमें पूरा ही कांग्रेसीकरण शब्दों का उपयोग किया गया है, घोषणाएं की गयी हैं इसलिये मैं पुरजोर इसकी बुराई करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं, सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि लम्बे समय से मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में उप खण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां पर पूरा ही जनजाति क्षेत्र है। आदिवासियों के लड़के-लड़कियां वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। प्राइवेट कालेज में जाने पर भारी फीस लगती है, जिससे आगे पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में सरकार से मैं मांग करता हूं कि घाटोल मुख्यावास पर एक सरकारी महाविद्यालय खोला जाये।

साथ ही पूर्व वक्ताओं ने, सत्ता पक्ष के साथियों ने यह बात भी कही कि भारतीय जनता पार्टी का राज बीस साल तक राजस्थान में रहा लेकिन उनके गुणगान आपके सदस्य कोई नहीं गा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर विकास की शुरुआत की तो स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने राजस्थान के गांवों का विकास किया। राजस्थान में पंचायत भवन बनाने का काम किया। राजस्थान में पक्की मिडल स्कूल बनाने का काम किया। काम के बदले अनाज योजना निकाली। आदरणीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हैं गुलाब चन्द जी भाई साहब, ये जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने इन गरीब बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यक्रम, सरकार के खजाने से पैसा देकर के नि:शुल्क वितरण करने का काम अगर किसी ने किया उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता पक्ष के साथियों को एक बात और बताना चाहता हूं, जब मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी थीं उस समय, आज आप तो एक नामी सीनियर स्कूल कालेज गिना रहे हो लेकिन एक लाइन के अन्दर राजस्थान के हर पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल खोलने का आदेश वसुन्धरा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया।

खेल जगत की बात आप कर रहे हो, ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का नाम दिया जा रहा है। करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि एक खिलाड़ी ऐसा पैदा हुआ उदयपुर आदिवासी परिवार का ललित करके नाम है, मैं यह फाइल लेकर आया हूं, जिसने पूरे देश में, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि राजस्थान के दृष्टिबाधित बेटे ने देश के लिए वर्ल्ड कप

(श्री हरेन्द्र निनामा)

जीता। वर्ल्ड कप जीतने वाला भारतीय ब्लाइंड टीम के आलराउंडर प्लेयर उदयपुर के ललित हैं जो अलसीगढ़ पंचायत में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको सम्मान मिले, उसके परिवार को सहयोग मिले और जिला स्तर के अधिकारी के रूप में इनको प्रमोशन देकर सम्मान दे, ऐसी मेरी मांग है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलखूंट का क्षेत्र नॉन-कमाण्ड आता है। हमारी सरकार थी उस समय माही के बैक वाटर से हाई लेवल कैनाल निकालने के लिए 2200 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और सरकार बदलने के बाद वो फाइल दबा दी गई। वहां पर दो-तीन बड़े-बड़े तालाब हैं, बानघटी का तालाब है, डूंगलावानी का तालाब है, इन तालाबों में नहरों की मरम्मत करने की आवश्यकता है।

साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में पीएचसी, सीएचसी में पद रिक्त हैं, डाक्टर नहीं हैं, कोविड में जो कर्मचारी लगाये थे उनको हटा दिया गया, उनको वापस लगाने की मैं मांग करता हूं। संविदाकर्मियों में आंगनबाड़ी में, बिजली विभाग में ठेकेदार प्रथा समाप्त करने की मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री गोपीचंद जी मीणा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस पवित्र सदन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा, जिसके बारे में कहना चाहूंगा कि हम सभी इस सदन में आते हैं और हम सब कहते हैं कि जो भी हम बोलेंगे वह सत्य बोलेंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले चार साल में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो घोषणायें की थीं उन घोषणाओं के बारे में जिक्र किया जाये तो धरातल पर नहीं उतरी हैं। भले ही हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो-जो भी कहा, आप उसके बारे में गौर करें और हमारे जितने भी अधिकारी-कर्मचारी जो हैं उनका ध्यान दें या नहीं दें जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और हमारी जितनी जनता के बीच में घोषणाएं की गई हैं उन सबको पूरा कराने में आपका पूरा सहयोग रहेगा तब जाकर यह हो पायेगा, बाकी नहीं होगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

(श्री गोपीचंद मीणा)

इस विभाग की जितनी प्रशंसा की गई है, मेरे यहां आसपुर विधान सभा क्षेत्र में, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार एक तरफ बोल रही है कि सुशासन कायम किया गया, सुव्यवस्था की गई, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे विधान सभा में चार सीएचसी हैं, आसपुर सीएचसी में 8 डाक्टर की पोस्ट हैं, वहां पर मात्र एक डाक्टर काम कर रहा है और 7 डाक्टरों का ट्रांसफर आपके द्वारा कहां कर दिया, यह मुझे पता नहीं है। नंबर दो, सांवला में 6 डाक्टरों की पोस्ट हैं, वहां भी मात्र एक डाक्टर है और बाकी सारे पद रिक्त पड़े हैं। डामरी जो दोवडा पंचायत समिति में आता है, वहां 6 डाक्टरों की पोस्ट हैं, वहां एक भी डाक्टर नहीं है, वहां एक डाक्टर पदोन्नति करके लगाया गया है और उससे उस हास्पिटल को चलाया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह जनजाति एरिया है और हमारे लोग दूर नहीं जा सकते हैं, मेरी आपसे विनती है कि इन डाक्टरों की भर्ती करके उस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने का काम करें। मंत्री जी, सभी डाक्टर लगा रखे थे लेकिन यह सब ट्रांसफर कराकर अपने-अपने क्षेत्र में चले गये। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे वहां डाक्टर की भर्ती की जाये।

मैं शिक्षा विभाग के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं इस विधान सभा में लगातार 10 साल से आ रहा हूं, मैं कालेज की मांग करता आ रहा हूं। इस अवसर पर मैं सभापति महोदय के माध्यम से इस बात को रखना चाह रहा हूं कि मेरा आसपुर ट्राइबल बैल्ट है, हमारे मालविया जी उपस्थित हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्री जी तक मेरी सिफारिश करें और हमारे यहां एक कालेज खुलवाकर जनजाति लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई दूंगा।

इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब वसुन्धरा जी की पूर्ववर्ती सरकार थी, उस समय जहां-जहां स्कूलें थीं, रमसा के माध्यम से एक-एक विद्यालय में 40-50 लाख रुपये देकर सारे कक्षा कक्ष बनाये थे। आपको बुरा नहीं लगे लेकिन मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि इन चार सालों में इस राजस्थान की सरकार ने एक भी कक्षा कक्ष किसी भी विद्यालय में नहीं बनाया और कहीं बनाया हो तो आप बताएं ताकि हम उसको देख सकें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं जितने भी विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे, वहां दो-दो कक्षा कक्षों में 12वीं तक की स्कूलें चल रही हैं, जो पुरानी स्कूलें थीं, वह 15-15 फीट के कक्षा कक्षों में चल रही हैं। मेरी विनती है आप इसकी भी व्यवस्था

(श्री गोपीचंद मीणा)

कर विद्यालयों में कक्षा कक्ष देने का काम करेंगे तो यह व्यवस्था बच्चों के लिए सुदृढ़ होगी।

मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूंगा। मैं इस विधान सभा के सभी महानुभाव सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं, पंचायती राज मंत्री महोदय अभी यहां उपस्थित थे, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे जितने एमएलए, एमपी, टीएडी हैड के काम हैं, धरातल पर काम नहीं होने का कारण मैं आपको बता रहा हूं, पंचायत लेवल पर अभी जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, वह अनियमितता करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): उनको किसी भी प्रकार से न तो एपीओ कर सकते हैं और न ही उनको निलम्बित कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज के निदेशक महोदय ने 31.5.2021 को एक आदेश जारी किया, उनको एपीओ करने की पावर भी राज्य सरकार लेकर बैठी है। ऐसी स्थिति में न तो विकास अधिकारी इनको एपीओ कर सकता, न सीईओ कर सकता, न कलेक्टर कर सकता है, इसलिए मनमानी काम हो रहा है और धरातल पर काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं इस प्रकार का आदेश करके आपने जो हमारे कर्मचारी को हैवी बनाया है, जिसके बारे में हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और यह कानून व्यवस्था बिगाड़ दी गई है।

मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहूंगा, हमारे बीच जल संसाधन मंत्री जी उपस्थित हैं, मैंने पिछले समय में भी आपसे अनुरोध किया था, मेरे वहां पर सोनार माता का एनिकट स्वीकृत कर उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, यह आपसे विनती करता हूं। हमारे वहां दोवड़ा पंचायत समिति मांडवा खापड़ा दातावाला एनिकट है, उसको रिपेयर करने के लिए दो-ढाई करोड़ रुपया देकर उस एनिकट को आप वापस बहाल कर देंगे तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था होगी।

मैं सभापति महोदय से निवेदन कर रहा हूं अभी वर्तमान की सरकार की स्थिति, आप बुरा नहीं मानें, धरातल पर यह स्थिति है आज की तारीख में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रही है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार हो

(श्री गोपीचंद मीणा)

रहा है। मैं इस अवसर पर कह सकता हूं कि थल में भ्रष्टाचार, जल में भ्रष्टाचार, नभ में भ्रष्टाचार, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर आप कहीं न कही लगाम लगाने का काम करें। यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कालूराम जी।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में 63 एएनएम के पद हैं, उसमें से मात्र 19 एएनएम के पद भरे हुए हैं, बाकी सारे पद खाली हैं। डग ब्लाक में 19 डाक्टरों में से मात्र 3 डाक्टर हैं, महोदय, कैसे चलेगा? हमारे डग ब्लाक में करीब 5 सीएचसी और 5-6 पीएचसी हैं और कई उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। मैं एक दिन मेरी विधान सभा के एक भीमणी गांव में गया, वहां मुझे ग्रामीणों ने कहा कि महारानी वसुन्धरा जी के समय यह सामुदायिक केन्द्र बनाया था, उस दिन ताला खुला था, चार साल में इसका ताला नहीं खुला। यह स्थिति है हमारे क्षेत्र की। कोई एएनएम नहीं है, कोई जीएनएम नहीं है।

आपने पैरा संख्या 21 में कहा कि हम हर घर में स्वास्थ्य कर्मी भेजेंगे, हर राजस्व ग्राम में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी और एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी भेजेंगे। राजस्व ग्राम में तो ठीक, अस्पताल में आप भेजें। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने डग में 50 बेड की बिल्डिंग स्वीकृत की लेकिन उसमें डाक्टर स्वीकृत नहीं हुए हैं उसमें डाक्टर भी स्वीकृत करें ताकि वहां डाक्टर का पद बढ़े और वहां की जनता को इसका फायदा मिले।

हमारी विधान सभा में एंबुलेंस की बड़ी कमी है। चौमेला, झालावाड़ अस्पताल से करीब 150 किलोमीटर दूर है, चौमेला में 108 एंबुलेंस नहीं है, वहां एंबुलेंस की बड़ी दिक्कत है, वहां एंबुलेंस दी जाये।

आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने तीन वर्ष से भामाशाह कार्ड बंद रखा, कितनी जनता को इसका फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, यह आपको

(श्री कालूराम)

याद है। जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने भामाशाह योजना चलाई थी, उसको बंद करके आपने तीन साल बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलाई। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं गुजरात से भी जुड़ा हूं, गुजरात मेरे यहां से 150 किलोमीटर है, इंदौर 150 किलोमीटर है, आपने अभी तक प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अगर लागू हो जाता तो मध्य प्रदेश, गुजरात में जाने वाला व्यक्ति यहां इलाज करा सकता था। वह प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अभी तक किसी व्यक्ति को वितरण नहीं किया, उसका क्या कारण रहा? दूसरे राज्यों में हर जगह प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बंट गये, हमारे राजस्थान में ही ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड अभी तक आपने चालू नहीं किया?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जीएनएम, एनआरएचएम और जो भी संविदाकर्मी हैं, उनको स्थायी किया जाये। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि जितने संविदाकर्मी हैं, हम इनका स्थायीकरण करेंगे। कल्ला साहब की आपने एक कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी का अभी तक क्या हुआ? अभी तक कोई स्थायीकरण नहीं हुआ।

मैं कृषि के मामले में कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी पाला गिरने से, कृषि मंत्री जी यहां नहीं है, अभी कृषि मंत्री जी ने जब जवाब दिया तो झालावाड़ जिले का नाम नहीं लिया, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में पाला गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पाला गिरा, हमारे क्षेत्र में धनिये की फसल होती है, चने की फसल होती है, कलौंजी होती है, मसूर होती है, चना होता है और सरसों होती है, सारी फसलें पाला गिरने से नष्ट हो गयीं। अभी परसों 28, 29 और 30 तारीख के बीच में जो ओलावृष्टि या बारिश हुई है, उससे फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं मांग करता हूं कि तुरन्त गिरदावरी करवाकर किसानों को फसल का मुआवजा दिलाया जाये। जो पाले को फसल बीमा कम्पनियों ने बीमे से बाहर कर रखा है, इसको बीमे में लें, ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। इसके लिए आप केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखें। आप भी प्रस्ताव लेकर पाले को आपदा में घोषित करें, ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके।

किसानों को जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, मैं सहकारिता मंत्री जी

(श्री कालूराम)

से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो अल्पकालीन ऋण देते हैं उसमें छह माह में चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है। किसान छह महीने में ऋण नहीं चुका पाता और छह महीने बाद वह किसान ओवरड्यू हो जाता है और उसके ऊपर ब्याज लग जाता है। इसको आप साल भर करें। बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में साल भर में एक बार पलटी होती है, वह किसान साल भर में एक बार ऋण चुकायेगा तो किसान अवधि पार नहीं होगा। वह किसान यदि ओवरड्यू हो जाता है तो उसको बीमे का फायदा नहीं मिलता और उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कालूराम (डग): साहब, अभी शुरू ही किया है। कोई और नहीं है, दो मिनट बोलने दें।

अभी जिस प्रकार से जब बीमा मिलता है, सहकारी बैंकों में किसानों को वह बीमा नहीं मिल रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के मामले में जो गंगधार से लेकर सुनारी तक एमडीआर सड़क घोषित है, मैं मांग करता हूं कि इस बजट में उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें और वह सड़क एमडीआर में बने, क्योंकि वहां एमपी से कनेक्टिविटी है। वहां के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।

चौमहला क्षेत्र में दो-दो नदियां बहकर जाती हैं, माननीय मंत्री जी विराजमान हैं, वहां पर एक बांध की बहुत बड़ी जरूरत है। इस बजट में आप एक बांध दें, ताकि किसानों को इससे फायदा मिल सके। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। अगर उस क्षेत्र में बांध बन जायेगा तो उस क्षेत्र के किसान खेती कर सकेंगे और क्षेत्र के किसानों को इससे फायदा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से एक रोड सुकेत से लेकर डग की बनी थी, वह सड़क बिलकुल टूट चुकी है, उस पर पांच-पांच टोल लग रहे हैं। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री यदि यहां हैं तो ठीक, नहीं तो उसका टोल बन्द करें या उस सड़क को बनाया जाये।

हमारे क्षेत्र चौमहला में महाविद्यालय है, महाविद्यालय में 21 पद स्वीकृत हैं, उनमें से मात्र 3 व्याख्याता लग रहे हैं। कैसे स्कूल चलेंगे, कैसे महाविद्यालय चलेंगे? मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की यह हालत है कि एक-एक विद्यालय में 20 स्वीकृत पदों की जगह 2-2 ही हैं। आप तुरन्त स्कूलों में पद भरें ताकि उन किसानों को उसका फायदा मिल सके।

बिजली के मामले में सबसे ज्यादा दिक्कत आयी है, हमारे क्षेत्र में बिजली की आयी है। इन चार सालों में किसानों की जितनी ज्यादा बिजली की

(श्री कालूराम)

कटौती हुई है, उतनी राजस्थान में कभी नहीं हुई है। किसानों की आठ-आठ घंटे की बिजली कटौती की गयी। किसान शाम को खाना बनाने के टाइम पर आता था और बिजली की कटौती हो जाती थी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कालूराम (डग): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कटौती को बिलकुल बंद करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 840 डिमांड नोटिस जमा हुए हैं। मार्च के बाद में मात्र 20 कनेक्शन मिले हैं। आप बड़ी-बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि हमने 3 लाख 11 हजार, आपने पैरा नंबर 46 में दे रखा है कि 3 लाख 11 हजार हमने कनेक्शन दे दिये। डिमांड नोटिस जारी कराने से काम नहीं चलेगा। उनके पास आज सामान नहीं है, खम्भे नहीं हैं, इंसुलेटर नहीं है। आदमी एक-एक इंसुलेटर के लिए 50-50 चक्कर काटता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह सामान दे।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): जिस प्रकार से किसान परेशान हो रहे हैं, उन किसानों को सामान देकर उनका काम पूरा करें।

श्री सभापति: थैंक यू। समाप्त कीजिए।

श्री कालूराम (डग): खनन के मामले में प्रधानमंत्री आवास आप बनाते हैं, रेत का ट्रैक्टर एक किसान लेकर जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपये का अवैध खनन होता है तो वह आपको नहीं दिखता। या तो आप मकान बनाना बंद कर दें प्रधानमंत्री आवास के या छोटे-छोटे लीज के पट्टे दें।

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालूराम (डग): खनन का मामला जिस प्रकार से हो रहा है, अवैध खनन भी रोका जाए और किसानों की रेत की ट्रोली को जाने दें और उनको रेती लाने के लिए छूट दी जाए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.24 बजे गुरुवार, दिनांक 02 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का पदस्थापन

68. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के पद पर किस स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तथा उक्त की क्या योग्यता निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कोटा के पद पर वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी उक्त पद की पात्रता नहीं रखते हैं? यदि हां, तो उक्त को उक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का कोई पद नहीं होता है बल्कि प्रत्येक जिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद होता है। जिस पर उपनिदेशक स्तर के अधिकारी का पदस्थापन होता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी कैडर से पदोन्नत होते हैं।

(2) जी नहीं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक का कोई पद नहीं होता है बल्कि प्रत्येक जिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद होता है। कोटा में वर्तमान में इस पद पर श्रीमती निर्मल कुमारी मेहरा कार्यरत हैं जो कि उपनिदेशक स्तर की हैं व इस पद की पात्रता रखती हैं।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरण

78. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत चार वर्षों में भ्रष्टाचार व गबन के प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने प्रकरण कब से किस स्तर पर लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण की सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभियोजन स्वीकृति जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों की स्वीकृति जारी करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत चार वर्षों में कितने प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है? विभागवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में (वर्ष 2019 से 2022 तक) भ्रष्टाचार व गबन के 636 अभियुक्तों के अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लम्बित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" व "ख" संलग्न है।

(2) सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 04 माह की अवधि में अभियोजन स्वीकृति जारी करने का प्रयास करेगा।

(3) विगत चार वर्षो (वर्ष 2019 से 2022 तक) में अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे गए 2475 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों में से 1645 अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी विभागवार सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

79. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनिवास गावड़िया)

क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की पालना में न्यूनतम दो शिक्षकों के पद स्वीकृत कर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग में कुल 418 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 133 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में एक शिक्षक का पद स्वीकृत है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 के प्रावधानानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम दो और नियमानुसार पद सृजन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासों का आबंटन

80. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल ने सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के बिंदु संख्या 7 को विलोपित कर दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब कोई भी व्यक्ति आवासन मण्डल की योजना में एक ही शहर में एक से अधिक मकान ले सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवासन मण्डल ऐसे व्यक्ति को आवास आबंटित कर सकता है, जिसके पास जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का आवास हो? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगढ़ (बूंदी) विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए आबंटित बजट

81. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) विगत तीन वर्ष में बून्दी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए अब तक कितना बजट आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टाइगर रिजर्व के लिए कितने गांवों को पुनर्स्थापित किया गया तथा पुनर्स्थापित लोगों को मुआवजा किस आधार पर देना तय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी को दिनांक 16.05.2022 को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी में वर्ष 2022 23 में 37.93 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बून्दी से अभी तक किसी भी गांव का विस्थापन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण में लम्बित नामान्तरण

82. **श्री अविनाश** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पटवार हल्का अनुसार विगत चार वर्ष में कितने नामान्तरण (म्यूटेशन) दर्ज किये गये तथा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने नामान्तरण वर्तमान में लम्बित हैं? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पटवार हल्का द्वारा उक्त का इन्द्राज सरकार के नियमानुसार प्रपत्रों में दर्ज किया जाता है? यदि हां, तो पटवार हल्कावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत चार वर्ष के नामान्तरणों का विवरण:-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	तहसील	प्राप्त आवेदन	निर्णीत आवेदन	लम्बित
1.	जैतारण	18879	18426	453
2.	रायपुर	12044	11914	130

ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां। पटवार हल्कावार संख्यात्मक सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-ब)

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शेखावाटी की ऐतिहासिक महत्व की हवेलियों का संरक्षण

83. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व की हवेलियों एवं स्थलों के संरक्षण के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं में घरेलू पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन हेतु अनेक स्थल विद्यमान हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थलों के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट 2021-22 अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'शेखावाटी पर्यटन सर्किट' विकसित किये जाने की घोषणा की गई है। शेखावाटी क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों एवं संरक्षण कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। झुंझुनूं जिले में घरेलू पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीण पर्यटन हेतु अनेक स्थल विद्यमान हैं। उक्त स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत 'शेखावाटी

(पर्यटन मंत्री)

पर्यटन सर्किट' में झुंझुनूं जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य बजट 2021-22 की घोषणा की पालना में शेखावाटी पर्यटन सर्किट का विकास प्रोजेक्ट अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभिन्न स्थलों पर विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि**
1	लोहार्गल	36.00 लाख
2	नवलगढ	150.47 लाख
3	डुण्डलोद	200.00 लाख
	योग	386.47 लाख

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों के बिजली बिल की माफी

84. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं आम जन को सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस प्रकार की क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रभावित किसानों व आम जन को बिजली बिल में माफी अथवा छूट से संबंधित प्रावधान भी हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को बिजली में कब-कब कितनी छूट अथवा माफी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं आम जन को एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

नोर्म्स के अनुसार सहायता राशि का भुगतान करता है। एसडीआरएफ नोर्म्स में बिजली बिल माफी का प्रावधान नहीं है।

(3) एसडीआरएफ नोर्म्स में बिजली बिल माफी का प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डार (रेवदर) में गौण मण्डी की स्थापना

85. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार में गौण मण्डी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम मण्डार में गौण मण्डी स्थापना हेतु राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उपमण्डी यार्डो की स्थापना) नियम, 1987 के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त गौण मण्डी खोलने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रतापगढ़ में सुखाड़िया स्टेडियम को विकसित करने की योजना

86. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित सुखाड़िया स्टेडियम को विकसित करने हेतु समय-समय पर युवा वर्ग व जनता द्वारा तीस करोड़ रुपयों की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम को विकसित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। खेल विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सुखाड़िया स्टेडियम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

वर्तमान में उक्त स्टेडियम को विकसित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

नवीन महाविद्यालयों हेतु प्राध्यापकों की भर्ती

87. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2020-21 से 2021-22 के मध्य कितने महाविद्यालय खोले गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नवीन महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए पद भी स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? क्या उक्त पदों पर अध्यापन हेतु सरकार द्वारा प्राध्यापकों की भर्ती भी की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कितने पद भरे गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए भवन बनाने हेतु राशि व भूमि आबंटन की गई है? यदि हां, तो किस-किस महाविद्यालय के भवन हेतु राशि स्वीकृत की गई व किस-किस महाविद्यालय को भूमि का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2020-21 से 2021-22 के मध्य 83 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) उक्त 83 महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए सहायक आचार्य के 631 पद राजसेस सोसायटी के अधीन स्वीकृत किये गये हैं। इन महाविद्यालयों में राजकीय सेवा के नियमित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भी लगाये जाने का प्रावधान रखा गया है।

उक्त महाविद्यालयों में नियमित फैकल्टी को कार्यव्यवस्थार्थ/पदस्थापित कर एवं विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी लगाकर अध्यापन कार्य किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों का संचालन नोडल प्राचार्यों के माध्यम से किया जा रहा है।

उक्त सोसायटी का पंजीकरण हो चुका है, भर्ती के नियम तैयार कर लिये गये हैं जिन्हें कार्मिक विभाग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को राजसेस सोसायटी के माध्यम से यथाशीघ्र भरने की कार्रवाई की जावेगी।

(3) जी हां। उक्त महाविद्यालयों के लिए राशि व भूमि आबंटन का

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है। साथ ही इन महाविद्यालयों के संचालन हेतु बजट का प्रावधान भी किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर में श्रमिक कल्याण योजना के लम्बित आवेदन

88. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत श्रमिकों को देय लाभ किस प्रावधान के तहत दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पंजीकरण करने हेतु कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में उक्त योजना के तहत अनेक आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त लम्बित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। नियोजकों से बीओसीडब्ल्यू सेस एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण लागत की एक प्रतिशत उपकर राशि के रूप में एकत्र कोष से बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 में किये गए प्रावधानों के अनुसार सृजित योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को लाभ दिया जाता है। प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है। योजनाओं हेतु अलग से कोई पंजीयन किये जाने का प्रावधान नहीं है। निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन करने हेतु अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 11.01.2010 को जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(3) बाड़मेर जिले में पंजीयन तथा विभिन्न योजनाओं के लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में जिला कलेक्टरों द्वारा गठित दलों द्वारा पात्र श्रमिकों का सत्यापन करा लिया गया है। मण्डल में उपलब्ध कोष की स्थिति को देखते हुए प्रथम चरण में मण्डल की शुभशक्ति, सुलभ्य आवास एवं सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु सहायता की योजनाओं को छोड़कर शेष 10 योजनाओं के शीघ्र निस्तारण पात्रतानुसार एवं वरीयतानुसार किया जा रहा है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नोहर में लम्बित बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन

41. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नोहर के लिए विगत चार वर्षों की बजट घोषणाओं में से कितनी बजट घोषणायें पूर्ण की गईं व कितनी लम्बित हैं? सरकार द्वारा उक्त लम्बित घोषणायें कब तक पूर्ण कर दी जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

थानागाजी में संचालित पुलिस थाने

42. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्तमान में कुल कितने पुलिस थाने एवं चौकियां संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन पुलिस चौकियां खोलना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्तमान में 04 पुलिस थाने एवं 02 पुलिस चौकियां संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

पुलिस थाने का नाम	**पुलिस चौकी का नाम**
थानागाजी	
प्रतापगढ़	अजबगढ़
नारायणपुर	
टहला	गोला का बास

(2) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

आमजन की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना

43. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में मुख्य स्थान चिन्हित करके आमजन की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो जिला चूरू के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने सीसीटीवी कैमरे लगाये गये तथा वर्तमान में उक्त में से कितने सीसीटीवी कैमरे चालू हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की घोषणा की गई थी, जो निम्नानुसार है:-

बजट घोषणा वर्ष	बजट घोषणा बिन्दु संख्या	बजट घोषणा का विवरण
2019-20	158	थानों में पारदर्शिता लाने बाबत आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा।
2022-23	110 (II)	अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार किया जायेगा। साथ ही, बड़े निजी संस्थानों एवं व्यवसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाकर अभय कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना बनायी जायेगी।

चूरू जिले के शहरी क्षेत्र (मय पुलिस थाना परिसर) में कुल 178 व ग्रामीण क्षेत्र (मय पुलिस थाना परिसर) में कुल 41 सीसीटीवी कैमरे अर्थात् कुल 219 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वर्तमान में कुल 159 सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला कार्मिकों को वर्क फ्रोम होम की सुविधा

44. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रोम होम की सुविधा देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रोम होम की सुविधा देने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रोम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रोम होम की सुविधा दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

देवली-उनियारा के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पद

45. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा जिला टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय-89, राजकीय बालिका उच्च

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक विद्यालय-08 एवं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय-07 इस प्रकार कुल संचालित 104 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार, संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

प्रारंभिक शिक्षा विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा जिला टोंक में कुल 323 राजकीय विद्यालयों शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र एवं चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भी रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा के क्रमोन्नत विद्यालय

46. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक संचालित राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को किस-किस स्तर में क्रमोन्नत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत 03 राप्रावि को राउप्रावि में तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत, 02 राउप्रावि को रामावि, 08 रामावि को राउमावि एवं 02 राउप्रावि को सीधे ही राउमावि में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट क व क1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाडपुरा में राजकीय विद्यालयों में बजट का आबंटन

47. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कमरे, लैबोरेट्री, लाइब्रेरी व आर्ट क्राफ्ट कक्ष के निर्माण हेतु 1181 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है? यदि हां, तो उक्त बजट अनुसार विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कराये गये तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर पूर्ण किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के राजकीय विद्यालयों में कराये गये निर्माण कार्यों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने की योजना

48. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में आईसीटी योजना के अन्तर्गत 3126 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम (स्मार्ट टीवी/इंटरेक्टिव बोर्ड) स्थापित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जाने की प्रगति निम्नानुसार है:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.स.	**कुल उमावि**	**पूर्व में स्थापित**	**निविदा प्रक्रियाधीन**	**शेष विद्यालय**
1	17469	2996	8609	5864

शेष विद्यालयों में वित्तीय उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जायेंगे। पूर्व में स्थापित, निविदा प्रक्रियाधीन एवं शेष रहे विद्यालयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर शहर में गुरू नानक जयन्ती पार्क विकसित करने की योजना

49. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बजट 2020-21 में गुरू नानक देव की 550वीं जयन्ती के उपलक्ष पर अलवर में एक विद्यमान उद्यान व नये उद्यान को गुरूनानक जयन्ती पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस उद्यान को विकसित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त घोषणा अनुरूप गुरूनानक जयन्ती पार्क विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुरूनानक देव की 550वीं जयन्ती के उपलक्ष पर गुरूनानक वाटिका विकास समिति अलवर के प्रतिनिधियों के सहयोग एवं सहमति से नर्सरी मूंगस्का, पुरानी दिल्ली रोड, अलवर में वर्ष 2020-21 में गुरूनानक वृक्ष वाटिका विकसित की गई है।

(2) बिन्दु सख्या 01 के अनुसार है।

राजस्थान उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

50. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय व उसके अधीनस्थ विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 01 जनवरी, 2023 को पोक्सो एक्ट, एससी एण्ड एसटी एक्ट, पीसी एक्ट, रेंट कन्ट्रोल एक्ट, डी.वी. एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट, एन.आई. एक्ट, हत्या एवं बलात्कार के लम्बित प्रकरणों का वर्गवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उच्च न्यायालय एवं उसके अधीनस्थ विभिन्नि न्यायालयों में 01 जनवरी, 2022 से 01 जनवरी, 2023 तक की अवधि में पोक्सो एक्ट व एससी एण्ड एसटी एक्ट के कितने प्रकरण कब तक दर्ज हुए तथा उक्त प्रकरणों में कितनों में फैसले दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

सूरसागर में नगर निगम द्वारा वार्डवार बीट की व्यवस्था

51. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नगर निगम, जोधपुर के अधीन वार्डवार बीट व्यवस्था के आधार पर सफाई व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो क्षेत्र के समस्त वार्डों के समस्त बीट के कार्मिक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त बीट के क्षेत्र के निर्धारण का मापदण्ड क्या है?

(3) क्या नगर निगम, जोधपुर ने उक्त समस्त बीट के विभिन्न स्थानों पर बीट कार्मिक, पर्यवेक्षण एवं प्रभारी अधिकारी के नाम के उल्लेख के सूचना पट्ट आमजन की सुलभ सुविधा हेतु लगाये हैं? यदि हां, तो उक्त संबंध में जारी निविदा प्रक्रिया एवं कार्यादेश मय यू.सी. रिपोर्ट सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर जोधपुर शहर के दोनों नगर निगमों (उत्तर एवं दक्षिण) में बंटा हुआ है।

नगर निगम जोधपुर उत्तर में वार्डों में बीट व्यवस्था के आधार पर सफाई व्यवस्था एवं उसके निरीक्षण हेतु वार्डवाइज पर्यवेक्षण अधिकारी लगाये गये हैं। पर्यवेक्षण अधिकारियों का नाम, पद सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के नगर निगम जोधपुर दक्षिण के अधीन आने वाले वार्डों में बीट व्यवस्था के आधार पर सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है। वर्तमान में वार्ड के अन्दर बीटों की संख्या ज्यादा है और कार्यरत कर्मचारी कम हैं, इसलिए गैंग बनाकर सफाई की व्यवस्था करवाई जाती है।

(2) बीट का निर्धारण बीट की भौगोलिक परिस्थिति, जनसंख्या के आधार और क्षेत्र में उत्पादित होने वाले कचरे की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है, जो MOHUA, GOI गाइड लाइन एवं MSW Rules 2016 के अनुसार है, जो समस्त भारत में लागू है।

(3) नगर निगम जोधपुर दक्षिण के समस्त वार्डों में बीट के विभिन्न स्थानों पर वार्ड में कार्यरत कर्मचारी का नाम, सफाई निरीक्षक/प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर के लिए सूचना पट्ट लगाया गया है।

इसी प्रकार नगर निगम जोधपुर उत्तर में भी बीट आधारित सफाई हेतु वार्डों में कार्मिकों की सूची सूचना पट्ट के माध्यम से आमजन की सुविधा हेतु वार्ड/कार्यालयों में लगायी गयी है।

दोनों ही नगर निगमों में उक्त कार्य हेतु किसी भी प्रकार की निविदा प्रक्रिया एवं कार्यादेश नहीं दिया गया है। वार्ड स्तर पर ही उक्त सूचना पट्ट लगवाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लावारिस पशुओं के पुनर्वास व पोषण की कार्ययोजना

52. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर गोवंश लावारिस है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) प्रदेश में विगत दो वर्षों में भयंकर गर्मी/वर्षा/सर्दी से किस जिले में कितने लावारिस पशु मृत पाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में लावारिस पशुओं के पुनर्वास एवं पोषण हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

फलौदी में सूखे पेड़ों का निस्तारण

53. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक विभाग द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई? उक्त आबंटित राशि का व्यय किन-किन कार्यों में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में सड़क व नहरों के किनारे फैले जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) एवं सूखे पेड़ों का किस प्रकार निस्तारण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों में आबंटित राशि एवं व्यय राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) विधान सभा फलौदी में जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) एवं सूखे पेड़ों के निस्तारण की सूचना शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में उप तहसील कार्यालय का भवन निर्माण

54. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण एवं बिशाला में उप तहसील संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिए भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण में तहसील एवं विशाला में उप तहसील संचालित है।

जी हां। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों के लिए भवन बनाये जाने हैं।

मांडलगढ़ की गांव ढाणियों में खेतों में जाने हेतु रास्तों का इन्द्राज

55. गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अनेक गांव-ढाणियों में खेतों में जाने के लिए रास्ते ऐसे हैं जो मौके पर तो मौजूद हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड व नक्शे में इन्द्राज नहीं हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के अनेक गांव, ढाणियों में खेतों में जाने के लिए रास्ते ऐसे हैं जो मौके पर तो मौजूद हैं, परन्तु राजस्व रिकार्ड व नक्शे में इन्द्राज नहीं हैं। ऐसे रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

(2) उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 जारी किया गया है। परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगानेर तहसील के ग्राम केशवपुरा में मंदिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज भूमि

56. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान देह के नाम ग्राम केशवपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वर्तमान में भूमि दर्ज है? यदि हां, तो खसरा नम्बर एवं रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर के नाम भूमि दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय ने आदेश दिये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की

(गिर्राज सिंह)

पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पालना कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मन्दिर माफी भूमि को सरकार द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किया गया है? यदि हां, तो कब? अधिग्रहण के बदले कितना मुआवजा कब-कब किस-किसको दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम केशोपुरा के खसरा नम्बर 574, 693 से 697, 701 से 705 किता 11 कुल रकबा 1.3836 है. की खातेदारी मन्दिर श्री सीतारामजी खातेदारान दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी में उक्त खसरान के सभी काश्तकारों पर तहसील क्रमांक भूअ/561 दिनांक 01.05.2012 न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/2/2012/1321 दिनांक 11.04.2022 द्वारा राजस्व रेफरेन्स संख्या 37/2012 के खसरा नम्बर 574 मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट लगा हुआ है।

(2) वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज मंदिर श्री सीताराम जी खातेदारी की कुल भूमि 1.3836 है. हाल प्रभावी मिसल बन्दोबस्त सन् 1989-2009 के प्रारम्भ से ही मंदिर के नाम दर्ज है। सक्षम न्यायालय के आदेश से उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज नहीं हुई है।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच.ए.आई. द्वारा खसरा नम्बर 574 में से रकबा 0.0020 है. भूमि अधिग्रहित की गई है। उक्त अधिग्रहण कार्रवाई वर्ष 1996 से प्रारम्भ हुई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी अनुसार मुआवजा देवस्थान विभाग में जमा कराया गया है।

राजसमंद में पर्यटन स्थलों के विकास व संरक्षण की योजना

57. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमंद के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं अन्य पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं? विगत तीन वर्षों में उक्त पर्यटन स्थलों के विकास एवं संरक्षण हेतु कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई एवं उक्त पर्यटन

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

स्थलों पर कितने देशी एवं विदेशी पर्यटक आये व पर्यटकों से कितनी आय प्राप्त हुई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के पर्यटन स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमंद जिले के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं अन्य पर्यटन स्थलों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत तीन वर्षों में राजसमंद जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय स्मारकों पर कराये गये कार्यों एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विगत तीन वर्षों में राजसमन्द जिले के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के आगमन का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

पर्यटकों के आगमन से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त होती है। विभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त होने वाली आय संबंधी सूचना का संकलन नहीं किया जाता है।

(2) राजसमंद जिले के पर्यटन स्थलों के विकास और संरक्षण हेतु स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आर.एस.एल.डी.सी. योजना में अनियमितता पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

58. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आर.एस.एल.डी.सी. योजनान्तर्गत न्यूनतम 50 प्रतिशत लोगों को तीन माह के लिए रोजगार देकर वेतन, मानदेय बैंक से आहरित किया जा रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना में अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आरएसएलडीसी में विभिन्न योजनान्तर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**रोजगार दिए जाने के प्रावधान का प्रतिशत**
	केन्द्र पोषित योजनाएं	
1	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)	रोजगार: 70 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को
2	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	रोजगार: 70 प्रतिशत (अधिकतम 20 प्रतिशत स्वरोजगार)
	राज्य पोषित योजनाएं	
1	मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)	योजना के लाभार्थी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थी हैं। अतः योजना में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
2	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) श्रेणी-1 (RAJKViK)	रोजगार: 70 प्रतिशत
3	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) श्रेणी-2 (SAKSHM)	रोजगार: 50 प्रतिशत (केवल स्वरोजगार)
4	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) श्रेणी-3 (SAMARTH)	योजना के अन्तर्गत कारागार बंदियों, किसानों, भिखारी, सफाईकर्मी, ट्रांसजेन्डर, एकल नारी, विधवा को प्रशिक्षित कर आय सृजन क्षमता में वृद्धि करना है। अतः योजना में रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

क्र. सं.	योजना का नाम	रोजगार दिए जाने के प्रावधान का प्रतिशत
5	I M SHAKTI (इंदिरा महिला शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना)	50 प्रतिशत (25 प्रतिशत रोजगार एवं 25 प्रतिशत स्वरोजगार)
6	MMYSY (मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना)	योजना के लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता पाने वाले प्रशिक्षु हैं। अतः योजना में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
प्रशिक्षणार्थी को रोजगार के अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान की होती है। जिन योजनाओं में मार्गदर्शिका के प्रावधान अनुसार रोजागर देने का प्रावधान है उनमें प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को अंतिम किस्त का भुगतान प्रशिक्षणार्थी के वेतन पर्ची के प्रमाणीकरण के पश्चात् ही किया जाता है। निगम के द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार के मानदेय/वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है।		

(2) जी हां। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है। गड़बड़ी करते हुए पाये जाने पर प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्षों को संविदा पर लगाने की कार्ययोजना

59. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सेवानिवृत्त पुस्तकालयाध्यक्षों को पुन: संविदा पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कार्मिक (क-2) के परिपत्र दिनांक 08 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक

(राज्य मंत्री, भाषा)

वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी।

जसवंतपुरा (जालौर) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की योजना

60. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजकीय महाविद्यालय से वंचित प्रदेश के समस्त उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक कितने उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले गये? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला जालौर के उपखण्ड मुख्यालय जसवंतपुरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा अर्थात "वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उपखण्ड मुख्यालयों पर संभावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जायेंगे" की गयी थी। अब तक 83 उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जालौर जिले के जसवंतपुरा उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

माननीय सदस्य द्वारा सदन पटल पर रखा गया लिखित वक्तव्य

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

आपने पैरा नंबर 194 में उच्च शिक्षा को बेहतर बताने की बात कही लेकिन मेरे यहां 4 लाख की आबादी वाले विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय जो अभी मेरे पिताजी पूर्व विधायक स्व. श्री धर्मपाल चौधरी जी द्वारा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में 2018 में खुलवाया गया, लेकिन आज 5 साल हो गये। वह राजकीय महाविद्यालय प्राथमिक विद्यालय में संचालित है, आज तक इसका भवन नहीं बन पा रहा है। इसके भवन में स्थानीय कांग्रेजजनों द्वारा राजनीति की जा रही है, श्रेय लेने की उनकी आपस में होड़ मची हुई है जिसका शिकार विद्यार्थी हो रहे हैं। साथ ही शिक्षकों की कमी भी अधिक है। इन सभी चीजों से उच्च शिक्षा बेहतर कैसे होगी? सरकार सिर्फ घोषणाएं और खानापूर्ति करने का काम करती है। कार्य को धरातल पर लाने का काम अभी तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ है।

ऐसे ही कृषि महाविद्यालय भी खोला गया, लेकिन इसमें भी राजनीति की गई। यह कहां खोला गया, इसमें कितने शिक्षक हैं, कुछ पता नहीं है। स्थानीय कांग्रेजजन इसमें राजनीति कर विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं।

आपने पैरा नंबर 177 में सड़कों का जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020 दिसम्बर में करीब पूरे एक वर्ष के लिए एक आंदोलन ने एन.एच. 48 को शाहजहांपुर में अवरुद्ध किया था जिसके कारण एन.एच-48 से लगते हुए बहुत सारी सड़कों की हालात दयनीय है, जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं और कुछ जगह तो हालात यह हैं कि सड़कें भी नहीं हैं। इनके नवीनीकरण की घोषणा करें।

आपने पैरा नंबर 152 में कहा कि आम जन को पब्लिक फ्रेंडली वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाए। पहली बात यह कि यह कक्ष सरकार ने नहीं बनाये बल्कि विधायक कोष से बने हैं और सरकार यह मानती है कि स्वागत कक्ष बनाने से आदमी का व्यवहार अच्छा हो जाता है। इस पर कहना चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये कि यह कक्ष क्या काम में आ रहे हैं और क्या वास्तव में पब्लिक फ्रेंडली हैं? क्योंकि थानों में जो परिवादियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह कतई उचित नहीं है।

आपने पैरा नंबर 21 में कहा कि हम राजस्थान प्रदेश को निरोगी राजस्थान प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं लेकिन मेरे मुण्डावर में व्यक्ति निरोगी तो जब होगा जब उसको डाक्टर मिलेगा, चिकित्सा की सम्पूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। मेरे यहां सीएचसी में एक-एक डाक्टर है और उस एक डाक्टर को भी प्रतिनियुक्ति पर कहीं और लगा दिया जाता है। तो यह प्रदेश निरोगी कैसे होगा? मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे यहां डाक्टर की कमियों को पूरा किया जाये। साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों को जो कि पिछले काफी समय से आंदोलनरत हैं, उन्हें स्थायी करने का काम यह सरकार करे, जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान की बिना परवाह किए आम लोगों की जिंदगी को बचाया है।

पैरा नंबर 107 प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत आम जनता से जुड़े मामले अधिकारियों के सामने दर्ज होते हैं पर कहते हुए दुख होता है कि इनका निस्तारण आज भी लम्बित है। आपने 74160 पट्टों का जिक्र तो अभिभाषण में कर दिया लेकिन जो अभियानों में आम लोगों की समस्याएं आई थीं, उनका कोई जिक्र नहीं किया, उन समस्याओं का भी समाधान जल्द से जल्द करवाने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

पैरा नंबर 266 में राजस्थान को शूरवीरों की धरा बताया, देश की रक्षा के लिए सैकड़ों वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसी संदर्भ में मेरे क्षेत्र के कुतीना ग्राम के निवासी हवलदार हजारी लाल को 1948 में वीर चक्र मिला था। मेरा आपसे आग्रह है कि 200 फीट रोड पर स्थित कुतीना चौक का नामांतरण हवलदार हजारी लाल के नाम से किया जाना चाहिए।

देश का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले मीडियाकर्मी भी आज सुरक्षित नहीं हैं, इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही दस साल पहले मुख्य मंत्री जी ने नायला में मीडियाकर्मियों को पत्रकार आवास योजना के तहत प्लाट देने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी 571 आवासी एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भी सुनवाई की जानी चाहिए।

पैरा नंबर 151 में विद्यार्थियों को यूनिफार्म के दो सैट व सिलाई के लिए 200/- रुपये प्रति विद्यार्थियों को दिए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये टेलर मुझे भी बता दें जो 200/- रुपये में दो सैट यूनिफार्म की सिलाई कर देगा, मैं उसी के पास जाकर सिलाई करवा लूंगा। मुझे ऐसा लगा है कि सरकार बच्चों के साथ मजाक कर रही है।

अंत में यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात आज राज्य सरकार की विफलताओं के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और साथ ही पुकार रही है कि जो आपने पैरा नंबर 12 में कहा, सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म है, हमें व प्रदेश की जनता को इस सेवा से मुक्ति चाहिए और आने वाले चुनावों में राज्य की सरकार को पता चल जाएगा कि प्रदेश की जनता इस गूंगी बहरी व कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है।